

राजस्थान सेवा नियम

खण्ड द्वितीय

अनुवादकर्ता —

माथुर एवं जैन

प्रकाशक —

करेन्ट लॉ पब्लिशर्स

चौड़ा रास्ता—जयपुर

संस्करण १९६६

मूल्य १८)

प्रकाशक —

करैन्ट लॉ पब्लिशर्स

चौडा रास्ता जयपुर

सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

('अप्राधिकृत अनुवाद')

मुद्रक

क्रीति प्रिन्टर्स एव पब्लिशर्स

राजस्थान सेवा नियम

भाग २

अनुक्रमणिका

		पेज
परिशिष्ट १	सेवा नियमों के सबंध में प्रशासनिक निर्देश	१-१५
	I पद भार	१-२
	II फौजदारी कार्यवाहियों के चालू रहते, ऋण के लिये गिरफ्तार होने पर (या किसी कानून के अधीन निरोधक नजरबंदी के दौरान) निलम्बन	३-४
	III आकस्मिक अवकाश	४-१२
	IIIक छुट्टी के बदले में क्षतिपूर्ति	१२-१३
	IIIख आर ए सो के जवानों के लिये विशेष क्षतिपूर्ति (आकस्मिक) अवकाश	१३
	IV स्पेशलजन अवकाश (Quarantine leave)	१३-१४
	V वैदेशिक सेवा	१४-१५
	VI यात्रा भत्ता	१५
परिशिष्ट २	सविदा पर नियुक्त अधिकारियों के अवकाश की शर्तें	१६-१८
परिशिष्ट २-क	अवकाश लेखा प्रपत्र	१६
परिशिष्ट ३	आदेश इकरारनामे का प्रपत्र सं १	२०-२३
परिशिष्ट ४	आदेश इकरारनामों का प्रपत्र सं २	२४-२७
परिशिष्ट ५	वैदेशिक सेवा में रुने के दौरान पेशन के लिये च द (अ शदान)की दर तथा अवकाश वेतन	२८-३१
परिशिष्ट ६	भाग १ चोटों का वर्गीकरण	३२
	भाग २ प्रपत्र क-घायल होने के कारण या पेशन उपदान (अचुटी) के लिये आवेदन प्रपत्र	३३

	प्रपत्र ख	परिवार पेशन के लिये आवेदन पत्र का प्रपत्र	३४
	प्रपत्र ग	मेडिकल बोर्ड की कायदाही	३५
परिशिष्ट ७	प्रपत्र क	मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी के लिये मनोनयन	३६
	प्रपत्र ख	मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी के लिये मनोनयन	३६अ
	प्रपत्र ग	मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी के लिये मनोनयन	३६ब
	प्रपत्र घ	मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी के लिये मनोनयन	३७
	प्रपत्र ङ	परिवार पेशन का मनोनयन	३८
	प्रपत्र च	परिवार पेशन के लिये आवेदन पत्र	३९
	प्रपत्र छ	ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जाने वाला घोषणा- पत्र जिसको प्रत्याशित मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी स्वीकृत हुई है	४०-४१
	प्रपत्र छछ	मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी/शेष ग्रेचुटी श्री/ स्वर्गीय श्रीमती के परिवार को प्रदान करने हेतु कार्यालय/विभाग	४१
	प्रपत्र ज	आवेदन पत्र पेशन या ग्रेचुटी के लिये (तथा मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी) के लिये	४२-४६
परिशिष्ट ७	क	पेशन के लिये औपचारिक आवेदन-पत्र	४७
	ख	जमानत का प्रपत्र	४८-४९
	ग	प्रपत्र-क ऐसे मामलों में मृत्यु-तथा-रिटायरमेंट ग्रेचुटी/शेष ग्रेचुटी के लिये प्रपत्र जिनमें वध मनोनयन किया हुआ हो	५०
		प्रपत्र ख-मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी/शेष ग्रेचुटी के लिये प्रपत्र जब कि वध मनोनयन किया हुआ न हो	५१
		प्रपत्र ग-परिवार पेशन का प्रपत्र जबकि वध मनोनयन मौजूद हो	५२
		प्रपत्र घ-परिवार पेशन का प्रपत्र जबकि वध मनोनयन मौजूद न हो	५२-५३
परिशिष्ट ७	घ	प्रपत्र I और II स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी की आज्ञा	५४-५५
परिशिष्ट ८		असनिक पेशन का कम्प्यूटेशन (परिवर्तन) के प्रपत्र	५६-६५

परिशिष्ट ६	विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रयाग में लाई जाने वाली शक्तियों का विवरण	१६-१०१
परिशिष्ट १०	चिकित्सा विभाग के कमचारियों द्वारा अपने निजी पेशे (प्राइवेट प्रैक्टिस में ली जाने वाली फीसों (शुल्क) को निर्धारित सशोधित अनुसूची	१०२-११०
परिशिष्ट ११	राजस्थान सेवा नियमों के नियम ३२७ के अधीन निर्धारित कम्प्यूटेशन (परिवर्तन) तालिका	१११-११४
परिशिष्ट १२	सेवायें जो विशेषतया चतुर्यं श्रेणी सेवाओं (निम्न) के रूप में वर्गीकरण की हुई है सेवायें जो विशेषतया श्रेष्ठ श्रेणी में वर्गीकृत हुई है अ-राज्य सेवें अथवा राज पत्रित पद	११५-१२० १२०-१५३
परिशिष्ट १३	राजस्थान सरकार तथा केन्द्रीय सरकार तथा पंजाब बिहार मद्रास, मसूर मध्य भारत हैदराबाद (दक्षिण), पेप्पू सोराष्ट्र, ट्रावनकोर कोचीन तथा मध्यप्रदेश के मध्य वेतन भत्तो, पेंशन आदि के प्रभार को नियमित करने वाले नियम ।	१५४-१५८
परिशिष्ट १४	विभागाध्यक्षों की सूची (श्रेणी प्रथम)	१५९-१६४
परिशिष्ट १५	ड्यूटी पर स्थानान्तरण अथवा अवकाश से वापसी जैसे मामलों में अंतिम वेतन प्रमाण पत्र की तैयारी को विनियमित करने हेतु नियंत्रक और महालेखा निरीक्षक द्वारा निर्मित नियम	१६५-१६७
परिशिष्ट १६	महगाई भत्ता की दरें तथा महगाई भत्ता उठावे के लिये नियम	१६८-२१४
परिशिष्ट १७	मकान किराया भत्ता स्वीकृति के नियम	२१५-२३४
परिशिष्ट १८	प्रपत्र अ-अध्ययन अवकाश पर रवाना होने वाले स्थायी सरकारी कमचारियों के लिये बच-पत्र (वाड)	२३५-२३६

	प्रपत्र ब-अध्ययन अवकाश पर रवाना होने वाले अस्थायी-सरकारी कर्मचारियों के लिये बच-पत्र (बाड)	२३६-२३७
	प्रपत्र स-राजस्थान सेवा नियमों के नियम ६६ (ब) में शिथिलता देकर असाधारण अवकाश स्वीकृत किये गये अस्थायी सरकारी कर्मचारियों के लिये बच पत्र (बाड)	२३८-२३९
परिशिष्ट १८ अ	प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये बाह्य सरकारी कर्मचारी द्वारा निष्ठादित किया जाने वाला बच-पत्र का प्रारूप (डाफ्ट बाड)	२४०-२४१
परिशिष्ट १९	राजस्थान सेवा नियमों के अधीन अवकाश के लिये प्राथना-पत्र	२४२-२४३
परिशिष्ट २०	राजस्थान सरकार का निरुप-पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, विशनगढ़ के सभी प्रशिक्षणार्थियों (राज पत्रित और भराज पत्रित दोनों) को एक माह का विश्राम माल दिया जा सकने के संबंध में	२४४
परिशिष्ट २१	ए तथा ग श्रेणियों के राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये अधिकारियों की नियुक्ति की शर्तें	२४५-२४७
परिशिष्ट २२	पेशन और मृत्यु सह सेवा निवृत्ति पेंचुटी के मोसत परिलाभों की फवावट के लिये ज्ञाप	२४८
परिशिष्ट २३	पेशनरों या मृतक सरकारी कर्मचारियों की बचाया वेतन, भत्ते या पेशन की राशि प्राप्त करने के लिये क्षतिपूरण-बच पत्र (बाड) का प्रपत्र	२४९-२५०
परिशिष्ट २४	अस्थायी अंतिम वेतन-प्रमाण-पत्र	२५१
परिशिष्ट २५	अवकाश या अस्थायी स्थानान्तरण के दौरान सरकारी भत्ता-बमूली को नियंत्रित करने हेतु नियम	२५२-२५३
परिशिष्ट २६	राज-पत्रित अधिकारियों के वेतन अवकाश संबंधित आदि के संबंध में मांग-दशन हेतु अनुदेश	२५४-२५७

परिशिष्ट घ	अधिकारियों की सूची जिनको अपने वगलो पर पुलिस गाड के क्वाटर्स रखने क हक् हैं	३७७
परिशिष्ट ३०	महग ई भत्त के कुछ अश री महगाई वेतन समझा जाना	३७८-३८२
परिशिष्ट ३१	राजस्थान सेवाए (परियाजना पर रियायत) नियम १९६२	३८३-३८७
परिशिष्ट ३२	राजस्थान असैनिक सेवाए डाक्टरी परीक्षा नियम १९६२	३८८-३९०
परिशिष्ट ३३	मुघावजा (नगर) भत्ते की अनुमति	३९१-३९४
परिशिष्ट ३४	राजस्थान असैनिक सेवाए (पारितोषिक प्रदान) नियम १९६५	३९५
परिशिष्ट ३५	राजस्थान सेवाए (सोमा सडक सघठन पर रियायत) नियम १९६७	३९६-३९८



I	राज पत्रित पद पर नयी नियुक्ति होने पर	२५४-२५५
II	एक राज-पत्रित पद से दूसरे राज पत्रित पद पर स्थानांतरण होने पर	२५५-२५६
III	अ-जब अवकाश के हक के लिये आवेदन करना हो	२५६
	ब-जब अवकाश पर रवाना हो	२५७
	स-जब अवकाश से वापिस उपस्थित होना हो	२५७
IV	जब आप त्याग पत्र दें या सेवा निवृत्त हो	२५७
V	कुछ भय महत्वपूर्ण निर्देश	२५८-२६२

परिशिष्ट २७	राजस्थान सेवा (मेडिकल अटैण्डे स) नियम १९५८ (राजस्थान सेवा स्वास्थ्य उपचार नियम १९५८)	
	तथा राज्य सरकार एवं निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किये गये महत्वपूर्ण परिपत्र एवं आदेश	२६३-३००
	अप्रतिपूति योग्य (inadmissible) भ्रष्टाचारों की अप्रू डेट सशोधित सूची (१९६६) में प्रकाशित की गई सशोधित ऐलैमेण्टल भ्रष्टाचार सूची	३०१-३२६
	आयुर्वेदिक सशोधित भ्रष्टाचार सूची (राजस्थान राजपत्र भाग ४ (ग) दि० २६ मई १९६६ में प्रकाशित की गई)	३२०-३३१
	सशोधित यूनानी दवाओं के फार्मोकोपिया में पूर्व हुई भ्रष्टाचारों की सूची	३३१ए-३३१बी
परिशिष्ट २८	राजस्थान सिविल सेवाएं (राष्ट्रीय सुरक्षा का संरक्षण) नियम १९५४	३३२-३३३
परिशिष्ट २९	राजस्थान भ्रष्टाचार सेवाएं (निवासस्थान का बिराया निश्चित करने तथा वसूल करने के) नियम, १९५८	३३४-३४८
परिशिष्ट ३०	राजस्थान में सरकारी निवास स्थान आवंटन करने के नियम	३४९-३६२
परिशिष्ट ३१	आवास का माप दण्ड [Scale of Accomodation]	३७०
परिशिष्ट ३२	राजकीय कर्मचारियों की सूची जिनको शावजनिह हित में बिराया मुक्त गृह दिये जाते हैं।	३७१-३७६

राजस्थान सेवा नियम

भाग २

परिशिष्ट १

सेवा नियमों के सम्बन्ध में प्राशासनिक निर्देश

इस पारशिष्ट में वे प्राशासनिक निर्देश हिदायतें हैं जो राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा पद के प्रभार फौजदारी कायवाहियों के दरमियान निलम्बन राज्य कर्मचारी द्वारा राज्य के भीतर या भारत में या विदेशी सेवा में रहते हुए अपने पद अधिकार से बाहर जाने स्वीकृति योग्य आकस्मिक अवकाश जिसमें विशेष आकस्मिक अवकाश सम्मिलित है, स्पर्श वर्जन अवकाश आदि के उपयोग से सम्बन्धित मामलों पर कायवाही करने के विषय में अनुसरणीय हैं ।

सेवा नियमों के सम्बन्ध में राज्य सरकार प्रसन्न होकर निम्नलिखित नियम बनाती है —

I पद का भार

१ जब तक कि किसी विशेष कारणों से (जा सावजनिक प्रकृति का होना चाहिये) जिसके आदेश के अधीन स्थानान्तर हई है वह अनुमति प्रदान नहीं करदे अथवा कोई विशिष्ट अथ स्थान अपेक्षित न करदे या कोई अथ आदेश नहीं देदे, तब तक किसी पद का भार उसके मुख्यालय पर हस्तांतरित करना चाहिये, जहां पद भार से मुक्त करने वाला तथा पद सम्हालने वाला दोनों राज्य कर्मचारी उपस्थित हों ।

२ नियम की यह शान कि पद भार ग्रहण करने वाला तथा पद भार से मुक्त होने वाला राज्य कर्मचारी दोनों उपस्थित होने चाहिये, उन राज्यकर्मचारियों के मामले में लागू करना आवश्यक नहीं है जिनको दीर्घावकाश (वेकेशन) के साथ अवकाश जोड़ने की अनुमति दी गई हो । ऐसे मामलों में निम्नलिखित प्रणाली का अनुसरण होना चाहिये —

(क) जब कि दीर्घावकाश (वेकेशन) अवकाश से पहले जोड़ा गया हो, तो बाह्यगमन करने वाला राज्य कर्मचारी मुख्यालय छोड़ने से पहले रिपोर्ट करेगा, अथवा, यदि अत्यावश्यक कारणों से अवकाश वेकेशन में स्वीकृत हुआ हो तो, अवकाश स्वीकृत होते ही वह अपना पद भार, वेकेशन के अन्त से प्रभावशील, हस्तांतरित करेगा । तत्पश्चात् पद मुक्त करने वाला राज्य कर्मचारी वेकेशन का अन्त होने पर पद भार सामान्य तरीके से सभान लेगा ।

(ख) जब कि वेकेशन अवकाश के साथ जोड़ी गई हो, पद भार से मुक्त होने वाला राज्य कर्मचारी वेकेशन से पूर्व सामान्य तरीके से पद भार सुपुर्ब कर देगा, आने

वाला राज्य कमचारी वेकेशन की समाप्ती पर वापस लौटने पर वेकेशन के प्रारम्भ से पद भार ग्रहण कर लेगा ।

राजस्थान सरकार का नियम

१ एक प्रश्न यह उठाया गया कि आया राजपत्रित अधिकारी के पद ग्रहण करने । हस्तांतरित करने को चाज रिपोर्ट पर उच्चतर प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर करना अनिवार्य है । इस प्रश्न पर जांच की गई है और यह संय किया गया है कि निम्नतम उच्च अधिकारी का प्रति हस्ताक्षर केवल तभी आवश्यक होता है जब कि कोई अधिकारी पद हस्तांतरित करता हो या ग्रहण करता हो और ऐसा कोई अधिकारी नहीं हो जिसकी वह हस्तान्तरित करे या जिससे वह ग्रहण करें ।

२ सामान्यतया तथा किसी विशेष मामलो में किसी विशेष प्रतिकूल आदेश के अधिनस्थ, सरकार के कमचारी वग में सरकारी कमचारियों, उदाहरणार्थ राज्य सचिव या राजकीय सचिवालय के लेखक वा मुख्यालय, जिस प्रकार से वह सलग्न है उसका तत्समय मुख्यालय जहां स्थित हो, उसी स्थान पर होगा । किसी अन्य राजकीय कमचारी का मुख्यालय वह स्थान होगा जो उसको नियुक्त करने वाला प्राधिकारी मुख्यालय ना धारित करे अथवा ऐसी घोषणा के अभाव में वह स्थान जहां उसके कार्यालय के अभिलेख रखे जाते हो ।

४ क्षेत्राधिकार से बाहर जाना — सिवाय पुलिस अधिकारी के जो अपनी विधि वत शक्तियों के अंतर्गत काम कर रहा हो, कोई अन्य राज्य कमचारी उस काल के लिये वतन या भत्ता पाने का हकदार नहीं होगा जो समय उसने बिना उचित प्राधिकार के अपने पद की सीमा से बाहर व्यतीत किया हो ।

५ कोई सक्षम प्राधिकारी अपने नियंत्रण में काम कर रहा किसी राज्य कमचारी को कर्तव्यपालन के अंतर्गत चाहे उसके क्षेत्राधिकार में हो या उससे बाहर भारत के किसी भाग में या भारत में स्थित किसी विदेशी उपनिवेश में जाने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा ।

६ इस नियम के अधीन जिस राज्य कमचारी को किसी स्थान पद जाने की अनुमति दी गई हो, वह इतना कमचारी वर्ग एवं अभिलेख अपने साथ ले जा सकेगा जो उसके दक्षता पूरा कर्तव्य पालन हेतु निम्नतम आवश्यक हो ।

७ कोई नियंत्रण अधिकारी (क्वेट्रीलिंग आफिसर) अपने अधीनस्थ काम करने वाले किसी राज्य कमचारी को वतन व्य पालन में राजस्थान क्षेत्र के किसी भी भाग में अथवा नियंत्रण अधिकारी के क्षेत्राधिकार से जुड़ते हुए किसी विदेशी उपनिवेश में जाने को तथा यात्रा भत्ता उठाने की अनुमति दे सकेगा ।

१. पी यू सी नं २४८७ गफ ७ ए (४४) एफ डी एक्स/५७ दिनांक २० ५ १९५८
हुमा ।

II. फौजदारी कार्यवाहियों के चालू रहते, या ऋण के लिये गिरफ्तार होने पर (या ' किमी कानून ' के अधीन निरोधक नजरबंदी के दौरान) निलम्बन

(क) कोई राज्य कमचारी जिस किसी निराधक नजरबन्दी कानून के अधीन हिरासत में लिया गया हो, अथवा किसी फौजदारी अभियोग पर कायवाही के फल स्वरूप अथवा ऋण के लिये गिरफ्तार किये जाने पर यदि हिरासत की अवधि ४८ घंटों से अधिक हो और यदि वह पहले से ही निलम्बित न हो, तो वह गिरफ्तार किये जाने की तारीख से राजस्थान असेनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम, १९५८ के नियम १३ (२) के विचारानुसार अग्रिम आदेशों तक निलम्बित होना समझा जावेगा । कोई राज्य कमचारी जो कद की सजा भुगत रहा हो, उसके साथ भी उसके विरुद्ध अनुशासन कायवाही विचारार्थीन रहते, इसी प्रकार का व्यवहार किया जायगा ।

(ख) कोई राज्य कमचारी जिसके विरुद्ध किसी फौजदारी अभियोग पर कायवाही की गई हो परन्तु जो वास्तव में हिरासत में लिया हुआ न हो (उदाहरणार्थ जमानत पर रिहा व्यक्ति) राजस्थान असेनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम, १९५८ के नियम १३ के उप-खंड (ख) के अधीन मक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निलम्बित किया जा सकेगा । यदि चाज राज्य के कमचारी के राजकीय पद से सम्बन्धित हो या उसके नतिक पतेन का हो तो उसे इस नियम के अधीन निलम्बित किये जाने का आदेश दिया जायगा जब तक कि ऐसा पथ नहीं अपनाते के कोई विशेष (प्रपूर्वादि स्वरूप) कारण हों

(ग) कोई राज्य कमचारी, जिसके विरुद्ध ऋण के लिये गिरफ्तार करने की कोई कायवाही की गई हो, परन्तु जिसे वास्तव में हिरासत में नहीं लिया गया हो राजस्थान असेनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम, १९५८ के नियम १३ उप-खंड (क) के अधीन निलम्बित किया जा सकेगा, अर्थात् केवल उस दशा में जब तक उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कायवाही विचारार्थीन हो

(घ) जब कि कोई राज्य कमचारी उप-खण्ड (क) में उल्लेखित परिस्थितियों में निलम्बित किया जाना समझा गया हो अथवा जो उप-खण्ड (ख) में उल्लेखित परिस्थितियों में निलम्बित किया गया हो उसका पुनः स्थापन उसके विरुद्ध अनुशासन कायवाही किये बिना किया गया हो तो निलम्बन की अवधि में उसके वेतन तथा भत्ते का नियमन नियम ५४ के अधीन होगा अर्थात् कलक से मुक्त हो जाने की दशा में या (उसके विरुद्ध कायवाही ऋण के लिये गिरफ्तार हो जाने के कारण की गयी थी) अथवा ये साबित हो जाये कि उसका दायित्व ऐसी परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ जो उसके नियन्त्रण से परे थी अथवा जब कि किसी मक्षम प्राधिकारी ने निगुण दिया हो कि उसका

प्राथना पत्र में सम्बन्धित कर्मचारी अपने निवास स्थान का पता जहाँ आकस्मिक अवकाश पर हैडक्वार्टर के बाहर रहना चाहते हैं प्रकट करेंगे।

इसी प्रकार और कई कर्मचारी हैडक्वार्टर के बाहर राजपत्रित अवकाश में जाना चाहेंगे तो वे भी अपने निवास स्थान का पता आकस्मिक अवकाश के प्राथना पत्र में प्रकट करेंगे।

१६ परिशिष्ट १, शाखा ३ 'आकस्मिक अवकाश' के अनुच्छेद १ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें अर्थजी के साथ यह प्रावधान किया गया है कि आकस्मिक अवकाश इस प्रकार का नहीं दिया जाना चाहिये जिससे अवकाश के प्रारम्भ तथा अंत के विषय में नियमों से बचाव हो सके। और ए सी के जवानों को इन प्रावधानों से क्लेश हुआ है क्योंकि भोजपुरा नियमों के अधीन वेरियायती (प्रिविलेज) अवकाश पर अपने घरों को प्रस्थान करते हुए रियायती अवकाश से पहले आकस्मिक अवकाश नहीं जोड़ सकते।

इस विषय पर विचार किया गया है और यह आदेश दिया गया है कि और ए सी के जवानों को सारी अवकाश अनुपयोग किया गया शेष आकस्मिक अवकाश को यथा स्थिति रियायती अवकाश में पहले जोड़ने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि इस प्रकार पहले जोड़ा गया आकस्मिक अवकाश किसी भी एक अवसर पर १५ दिन से अधिक नहीं होगा।

गये प्रवेश पाने वालों को आकस्मिक अवकाश प्रदान किये जाने के लिये निर्देशन सामान्यतया किसी राज्य कर्मचारी को एक वर्ष में १५ दिन का आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाता है परंतु यदि कोई व्यक्ति वर्ष के मध्य में कायग्रहण करता है तो उसे पूरे १५ दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता। राज्य कर्मचारियों को सामान्य नियमों के अधीन रहते निम्न लिखित तरीके से आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाना चाहिये—

- (क) ५ दिन तक जिसकी सेवा तीन माह या उससे कम की हो,
 (ख) १० दिन तक जिसकी सेवा तीन माह से अधिक हो परंतु ३ माह से कम हो, और
 (ग) १५ दिन तक जिसकी सेवा छ माह ॥ अधिक हो,

जापन

सोते अवसर आते हैं जब कि राज्य कर्मचारी बिना आकस्मिक अवकाश की पूरा स्वीकृति प्राप्त किये काम पर यह सोचन हुए नहीं आते कि अपना अवकाश यथा समय स्वीकृत कर दिया जायेगा। किन्तु समस्त राज्य कर्मचारियों का ध्यान राजस्थान सेवा नियमों खण्ड २ के परिशिष्ट १ के भाग ३ की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार आकस्मिक अवकाश पर कोई व्यक्ति सेवा में कार्य करता हुआ माना जायेगा और इसलिये आकस्मिक अवकाश प्रदान करना एक ऐसा

१ वित्त विभाग जापन में एक १ (२४) एक दो (ई-आर)/६४ दिनांक ४ ६ ६४ तथा ० ७ ६४।

—२ वित्तविभाग (ई एम पी ब्रुस) जापन में एक १ (४४) एक डा/इ एम पी ब्रुस/ दिनांक २० ५ ६६ द्वारा जोड़ा गया।

विषय है जो मजूर करने वाले प्राधिकारी के स्व विवेक पर पूरातया निर्भर है। अतः यह पहले से ही नहीं मान सकते कि मांगा गया आकास्मिक अवकाश सर्वत्र स्वीकृत कर दिया जाएगा। यदि स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की यह धारणा हो कि राज्यकीय कार्य में हानी होगी, तो वह आकास्मिक अवकाश प्रस्वीकार कर सकता है। जिस राज्य कमचारी का आकास्मिक अवकाश का आवेदन-पत्र प्रस्वीकार कर दिया गया हो और जो नौकरी पर उपस्थित नहीं हो वह जान बुरू कर सेवा से अनुपस्थित हान का दोषी होगा। जान बुरू कर ऐसी अनुपस्थिति सेवा में रुकावट मानी जायेगी जिसमें पूरा सवाबों की जगह तथा दुर्व्यवहार सम्मिलित है।

राजस्थान राज्य का निर्णय

विशेष आकास्मिक अवकाश

प्रादेशिक सना में भर्ती होने के लिये अनुमति प्राप्त राजकीय कमचारियों को विशेष आकास्मिक अवकाश।

उक्त विषय पर भारत सरकार गृह मन्त्रालय के ज्ञापन सं. २५/४२/५१ एम के दिनांक अगस्त १, १९५१ कि प्रतिलिपि पावे दी जाती है। इसी वस्तुओं के साथ भारत सरकार तय किया है कि जब राज्य कमचारियों का जिह्वा प्रादेशिक सेना (ट्रिनिटीयल थर्मि) में कार्य ग्रहण करने की अनुमति दी गई हो उनके द्वारा कम में व्यतीत का गई अवधि सम्बंधित कमचारियों के आकास्मिक अवकाश में से नहीं काटी जावे परन्तु सब मामलों में विशेष आकास्मिक अवकाश शुमार की जावे और प्रादेशिक सेना में भर्ती होने वाले असैनिक राज्य कमचारियों द्वारा प्रशिक्षण में व्यतीत किया गया समय कार्य (ह्यूटी) पर उपस्थिति समझा जावे।

सरकार ने प्रसन्न होकर आदेश प्रदान किया है कि इस राज्य के ऐम सरकारी कमचारियों के साथ भा इसी प्रकार का व्यवहार किया जावे जो प्रादेशिक सेना में भर्ती हों।

प्रतिलिपि गृह मन्त्रालय का ज्ञापन सं. २५/४२/५१ एसेटवे दिनांक १ अगस्त १९५१, भारत सरकार के सब मन्त्रालयों आदि को सम्बोधित।

विषय—प्रादेशिक सना में भर्ती होने के लिये अनुमति प्राप्त असैनिक राज्य कमचारियों द्वारा कैम्प में या पाठ्य क्रम में या प्रशिक्षण में व्यतीत किये गये समय का शुमार।

(१) निम्न हस्ताक्षर कर्ता को आदेश हुआ है कि असैनिक राज्य कमचारियों को प्रादेशिक सेना में भर्ती होने के लिय अनुमति प्रदान करने के विषय में इस मन्त्रालय के ज्ञापन सं. २५/१९/४०—एसेटवे, दि. ७ जुलाई, १९५० का निर्दिष्ट कर्तव्य और यह व्यक्त करू कि एक सुझाव यह प्रस्तुत हुआ है कि चूंकि आकास्मिक अवकाश की मात्रा एक वर्ष में २० दिन से कम करके १५ दिन कर दी गई है, इसलिये प्रादेशिक सना में भर्ती होने के लिय अनुमति प्राप्त राज्य कमचारियों द्वारा कैम्प में व्यतीत किया गया समय सम्बंधित कमचारियों के आकास्मिक अवकाश में से नहीं काटा जावे, परन्तु सब मामलों में विशेष आकास्मिक अवकाश शुमार किया जावे। सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात् भारत सरकार ने यह मुझाव स्वीकार कर लिया है। निम्न हस्ताक्षर कर्ता को यह निवेदन करना है कि यह निर्णय नाट किया जावे और समस्त सम्बंधितों

को सूचित किया जावे । उपर सदभ दिये गये इस मन्त्रालय के कार्यालय जापन मे सार भूत प्रावधान सदनुसार सशोधित समझे जावग ।

(२) भारत सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि प्रादेशिक सना में भर्ती होने वाले असेनिक राज्य कमचारी जो किसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मे उपस्थिति का समय जो पाठ्यक्रम की प्रवृत्तिनुसार बदल सकता है परन्तु जो किसी एक मामले में तीन मास की अर्थात् से अधिक नहीं होगा उसको उसी प्रकार काय पर उपस्थित रहना शुमार किया जावे जैसे कि राज्य कमचारियों को नियमित सेना के पुष्टिकरण मे या पूरक रूप मे समावेश करने के लिये बुलाये जाने पर किया जाता है । किसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भेजे जाने वाले व्यक्ति या 'समावेशित' (embodied) होंगे और इसलिये सब प्रकार से इस मन्त्रालय के उपरोक्त सदभ के कार्यालय जापन के अनुच्छेद ४ मे दी गई शर्तों से शामिल होंगे ।

(३) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उपस्थित होने के लिये भेजे जाने वाले कमचारियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित मुद्दे नोट किये जावे —

(i) यह सम्बन्धित व्यक्ति के पूर्व स्वेच्छा पर निर्भर होगा कि आया कोई पाठ्यक्रम में सम्मिलित होवे अथवा नहीं और

(ii) किसी पाठ्यक्रम के लिये अग्रसर होने की सम्मति देने से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी और सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए यदि आवश्यक समझे तो ऐसी अनुमति अस्वीकार करने के लिये सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष पूर्ण स्वतंत्र होगा किन्तु सामान्यतया, ऐसी अनुमति प्रदान कर देनी चाहिये ।

विश्वविद्यालय सम्बन्धी काय करने के लिये शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश ।

१२ विजहाइनेस राजप्रमुख ने प्रसन हुकर आदेश करमाया है कि शिक्षा विभाग के कमचारियों को आकस्मिक अवकाश प्रदान करने मे सक्षम पदाधिकारी विश्व विद्यालय का काय ग्रहण करने के लिये अनुमति दे सकेगा जसे राजपुताना विश्वविद्यालय की विभिन्न समारोहों की बैठकों मे उपस्थित होना तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षकों के रूप मे जाना आदि आर व काय पर उपस्थित होने समय जायेंगे, जो एक सत्र में अधिक से अधिक राजस्थान मे १५ दिन और बाहर ६ दिन की सीमा के अधीन रहेंगे परन्तु शत यह है कि ऐसी उपस्थिति के लिये कोई पारिश्रमिक निर्दिष्ट अथवा एक मुश्त राशि मे समस्त काय के लिये प्राप्त नहीं करेंगे सिवाय सामान्य यात्रा भत्ते के (जिसमें दैनिक भत्ता भी सम्मिलित है) ।

जो मामले इस नियम के अंतर्गत नहीं आते हों उनके लिये आकस्मिक अवकाश अथवा कोई ऐसा अन्य अवकाश जो नियमानुसार उनको स्वीकृत हो सकता हो उसकी स्वीकृति के लिये अधिकारीगण सक्षम प्राधिकारी को निवेदन करेंगे ।

१ शिक्षा विभाग आदेश एफ १३ (१२) एल्ल/५२ दिनांक १३ अक्टूबर, १९५३ द्वारा जोड़ा गया ।

सम्बन्धित अधिकारियों को उसी श्रेणी में यात्रा करनी चाहिये जिसके लिये विश्वविद्यालय ने उनको पैसा दिया है और ड्यूटी-अवकाश (ड्यूटी लीव) की प्रत्येक दशा में उनको प्रमाणित करता पड़ेगा कि उन्होंने उस श्रेणी में यात्रा की है जिसके लिये विश्वविद्यालय ने उनको पैसा दिया है ।

ऐसे अधिकारियों द्वारा ऊपर बताये गये विश्वविद्यालय के काय से सम्बन्धित यात्रा के लिये यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देने के लिये सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं है ।

यह आदेश इस विषय पर पहले के सब आदेशों का अधिग्रहण करता है ।

राजपाल ने प्रसन्न होकर आदेश फरमाया है कि शिक्षा विभाग के जिन अधिकारियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा संचालित परिक्षाओं के सम्बन्ध में केन्द्र अधीक्षक/मुख्य पर्यवेक्षक नियुक्ति किये गये हों उनको आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकेगा जो एक विद्याध्ययन सत्र में २१ दिन से अधिक नहीं होगा ।

इन आदेशों के अन्तर्गत विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति राजस्थान सरकार के निम्न २ द्वारा राजस्थान सेवा नियम के परिशिष्ट १-पृष्ठ ७ में उल्लिखित शर्तों के अधीन रहगी ।

विधोचित काय करने के लिये चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश

१. हिजहाइनेस राजप्रमुख ने प्रसन्न होकर फरमाया है कि चिकित्सा विभाग के कमचारियों को आकस्मिक अवकाश प्रदान करने में सक्षम पदाधिकारी विधोचित काय ग्रहण करने के लिये अनुमति दे सकेगा जैसे कि परिक्षाओं का संचालन अथवा विद्या परिषद की सभाओं तथा चिकित्सा सभा की कार्यकारिणी समितियों की बैठकों में प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होना आदि/ऐसे कार्य पर अनुपस्थिति के समय में वे ड्यूटी पर होना शुमार किये जावेंगे जिसकी अधिकधिक मात्रा एक विश्वविद्यालय सत्र में, राजस्थान में १५ दिन और बाहर ९ दिन हो सकेगी, परन्तु शत यह है कि ऐसी उपस्थिति के लिये वे कोई पारिश्रमिक निर्दिष्ट अथवा एक मुश्त राशि में समस्त काय के लिये प्राप्ति नहीं कर सकेंगे निवाय यात्रा भत्ते के जिसकी दर सरकार द्वारा स्वीकृत दर से अधिक नहीं होगी ।

जो मामले इस नियम के अन्तर्गत नहीं आते हों उनके लिये आकस्मिक अवकाश अथवा कोई ऐसा अथ अवकाश जो नियमानुसार उनको स्वीकृत हो सकता हो उसकी स्वीकृति के लिये अधिकारी गए सक्षम प्राधिकारी को निवेदन करेंगे ।

१ वित्त विभाग आदेश स एफ १ (७८) एफ डी (ई-एम्स पी क्लस) ६७ दिनांक १३ दिसम्बर १९६७ द्वारा जोड़ा गया ।

२ चिकित्सा तथा सांख्यिक स्वास्थ्य विभाग आदेश स ७७३२/एम एच/५४ एफ २३ (१५०) एम एच/५४ दिनांक २ नवम्बर, १९५४ द्वारा जोड़ा गया ।

ऐसे अधिकारियों द्वारा ऊपर बताये गये विश्व विद्यालय के यात्रा से सम्बन्धित यात्रा के लिये यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते के लिये सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

यह आदेश इस विषय पर पढ़ने के सब प्रदशा का अधिक्रमण करता है।

स्थानिज तथा भूगर्भ विभाग के अधिकारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश

१ हिजहाईनेस राजप्रमुख ने प्रसन्न होकर आदेश फरमाया है कि स्थानिज तथा भूगर्भ विभाग के अधिकारियों का आकस्मिक अवकाश प्रदान करने में सक्षम पदाधिकारी भारतीय विज्ञान कांग्रेस सच के वार्षिक सत्र में उपस्थित रहने के लिये अनुमति दे सकेंगे। और ये कास पर उपस्थित होवे समझे जायेगा जो राजस्थान में १५ दिन और राजस्थान से बाहर ६ दिन को अधिकतम सामान्य अधीन रह्य परन्तु शत यह है कि ऐसा उपस्थिति के लिये वे कोई पारिश्रमिक निर्दिष्ट अथवा एक मुश्त राशि में समस्त काय के लिये प्राप्त नहीं करेग सिवाय सामान्य यात्रा तथा दैनिक भत्ते के जिसकी दर इनको मिलने वाली राजस्थान सरकार की दर से अधिक नहीं होगी।

जो मामले इस नियम के अंतर्गत नहीं आते हों उसके लिये आकस्मिक अवकाश अथवा कोई अन्य अवकाश जो नियमानुसार उनका स्वीकृत हो सकता हो उसको स्व कृति के लिये अधिकारी गण सक्षम प्राधिकारी को निवेदन करेंगे।

ऊपर बताये गये विद्याचित काय सम्बन्ध यात्राया के लिये यात्रा तथा दैनिक भत्ता देने को जिम्मेदारी सरकार पर किसी दशा में नहीं होगी।

बध्याकरण आपरेशन कराने वाले राजकीय कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश

यह आदेश दिया जाता है कि उन राज्य कर्मचरियों को जो बध्याकरण आपरेशन करावें उनका निम्न लिखित आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जावे —

पुरुष

४ दिन

महिलाएँ

१० दिन

३ परिवार नियोजन योजना के अंतर्गत बध्याकरण आपरेशन कराने वाले राजकीय कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश

निम्न हस्ताक्षर कर्त्ता को इस कार्यालय के इसी सहायक आदेश दिनांक ६५-१९६४ का सदम देते हुए यह व्यक्त करने का आदेश हुआ है कि उक्त महिला राजकीय कर्मचारियों को साल्पिगटोमी के आपरेशन (बध्याकरण) बच्चा उत्पन्न होने के बाद अथवा किसी अन्य समय पर कराने पर विशेष आकस्मिक अवकाश के हक के विषय में फिर से विचार किया गया है।

१. ज्योतिष विभाग स एफ ८ (111) (२७) उद्योग (बी) २७ दिनांक २ ५८ द्वारा जोडा गया।

२. वित्त विभाग आदेश स एफ १ (१९) एफ डी (ई-घर) / ६४ दिनांक ६ ५ ६४ द्वारा जोडा गया।

३. वित्त विभाग स एफ १ (१९) एफ डी (ई-घर) / ६४ दिनांक २८ १०-६६ द्वारा जोडा गया।

स्थिति यह है कि महिला को बध्याकरण करने का आपरेशन किसी भी समय किया जा सकता है। जब यह बच्चा उत्पन्न होने के पांच दिन पश्चात् किया जाता है तब वह पुरपरल बध्याकरण कहलाता है। जब यह किसी अन्य समय पर किया जाता है तब इसे नोन पुरपरल अथवा गार्डनेकोनाजिफल (गार्डनेन्स) बध्याकरण कहते हैं। चूंकि पुरपरल बध्याकरण में महिला राज्य कमचारी बच्चा होने की तारीख से ६ सप्ताह अथवा जच्चा अवकाश के प्रारम्भ से तीन महीने तक जच्चा अवकाश पाने की पहले से ही हक्दार हाती है इसलिये यह नियुक्त किया गया है कि परपुरल बध्याकरण कराने वाली महिला राज्य कमचारी को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करने का कोई आवश्यकता नहीं है। अन्य प्रकार के बध्याकरण के विषय में अर्थात् नोनपरपुरल में आपरेशन तथा आपरेशन के पश्चात् विधायक के लिये १४ दिन प्रेषित हैं। अतः उपरोक्त आदेश का आंशिक संशोधन करत हुए यह नियुक्त किया गया है कि नोनपरपुरल बध्याकरण कराने वाली महिला कमचारी को विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जावे जो १४ दिन से अधिक नहीं होगा।

यह तय किया गया है कि उग्राक्त अनुच्छेद १ के अनुसार तथा वित्त विभाग के आदेश दिनांक ६.५.१९६६ के अनुसार पुरुष राज्य कमचारियों को जो विशेष आकस्मिक अवकाश देय हो उस आकस्मिक अवकाश अथवा नियमित अवकाश से साथ जोड़ा जा सकता है, बशर्ते कि विशेष आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अवकाश के लिये सिद्धांतिक डाक्टरी सलाह पर आधारित हो और अवकाश को पुष्टि में सम्बन्धित राज्य कमचारी पर लागू होने वाले नियमों के अधीन उचित चिकित्सा प्राधिकारी का चिकित्सा प्रमाण—यह प्रस्तुत किया गया हो। किंतु जिस भी दशा में, विशेष आकस्मिक अवकाश का किसी आकस्मिक अवकाश तथा नियमित अवकाश दोनों में एक साथ जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाना चाहिये।

‘परिवार नियोजन योजना’ के अधीन आई यू सी-डी (लूप) लगवाने के लिये महिला राज्य कमचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश।

‘राज्यपाल ने प्रसन्न हाकर आदेश’ परमाया है कि महिला राज्य कमचारियों को आई यू सी-डी (लूप) लगवाने के प्रयोजनार्थ एक दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

‘राजस्थान प्रसन्निक सेवार्थ (विभागोप परीक्षा) नियम के अन्तर्गत विभागोप परीक्षा में बैठने के लिये राज्य कमचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश।

राजस्थान असेनिक सेवार्थ (विभागोप परीक्षा) नियम १९५८ के अधीन विभागोप परीक्षा में बैठने वाले राज्य कमचारी को ड्यूटी से अनुपस्थिति का समय किस प्रकार शुमार किया जावे यह प्रश्न पर राज्य सरकार का विचाराधीन है।

१ वित्त विभाग आदेश स एफ १ (२) एफ डी (ई प्रार)/६५ द्वारा जारी किया गया।

२ एफ १ (२३) एफ डी (ई प्रार) ६४ दिनांक २-६-६४ द्वारा जारी किया गया।

यह तय किया गया है कि उन राजकीय कमचारी को जो उपरोक्त नियमोंनुसार विभागीय परीक्षाओं में बैठने के पात्र हों अथवा जिनके लिये परीक्षा देना अपेक्षित किया गया हो उनको विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकेगा। विभागीय परीक्षाओं के लिये सम्बंधित परीक्षा की वास्तविक अवधि और मुख्यालय से बाहर परीक्षा ली जाने की दशा में मुख्यालय से निकटतम परीक्षा केंद्र पर जाने तथा वापिस आने के लिये कम से कम समय की पूर्ति कर इतने समय के लिये विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जायगा किन्तु परीक्षा में बटने वाले राजकीय कमचारी को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

इस प्रयोजन के लिये राजकीय कमचारी विशेष आकस्मिक अवकाश को सामान्य आकस्मिक अवकाश के साथ जोड़ सकेगा (परन्तु नियमित अवकाश के साथ नहीं)।

इन आदेशों के अंतर्गत विशेष अवकाश प्रदान करने की शक्तियों का प्रयोग सम्बंधित विभागाध्यक्ष/पदाधिकारी करेगा।

१ राजपत्रित अधिकारियों को आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के लिये हिवायतें।

विभागाध्यक्षों का आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति सम्बंधित प्रशासनिक विभाग का सचिव दे सकेगा एवं अन्य राजपत्रित अधिकारियों को उनके निकटतम उच्च अधिकारी स्वीकृति प्रदान करेगा। कलेक्टरों के मामले में आकस्मिक अवकाश कमीशनर स्वीकार कर सकेगा परन्तु राजस्व विभाग में सरकार के शासन सचिव को अवश्यमेव सूचना देनी चाहिये।

छुट्टी स्वीकार करने वाले प्राधिकारी को आकस्मिक अवकाश का उचित लेखा रखना चाहिये।

१. III क छुट्टी के बदले में क्षतिपूर्ति (आकस्मिक) अवकाश

१ रविवारों तथा अन्य राजपत्रित छुट्टियों में अनिवार्य लेखवर्गीय कमचारी वगैरे सदस्य को, जितने दिन तक उसे कार्यालय में उपस्थित होने के लिये बाध्य किया गया हो उतने दिन तक उसे क्षतिपूर्ति (आकस्मिक) अवकाश देना उचित होगा, सिवाय उस दशा में जब कि उक्त उपस्थिति शांति रूप में उस पर लागू की गई हो।

२ उक्त अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश का हक्दार किसी राजकीय कमचारी को बनाने हेतु उसकी उपस्थिति प्रभारी राजपत्रित अधिकारी के पूर्व लिखित आदेशों के अधीन होनी चाहिये जिसे उम आदेश में यह निखना चाहिये आया उक्त उपस्थिति अनिवार्य है अथवा नहीं।

३ वास्तव में अर्जित की हुई सीमा तक क्षतिपूर्ति (आकस्मिक) अवकाश की अनुमति उसी अधिकारी द्वारा ली जा सकेगी जो सम्बंधित राजकीय कमचारी को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने में सक्षम है और यह उहाँ शर्तों के अधीन रहेगी जो आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के लिये निर्धारित हैं।

२ वित्त विभाग आदेश स एफ ५ (१) एफ (भार)/ ५६ दिनांक ११ जनवरी, १९५६ द्वारा जोड़ा गया।

१ ओ ए डा सख्या एफ २ (२५७) जी ए/ए/५२ दिनांक ११ मार्च १९५३ द्वारा

निर्देश -

१ उपरोक्त आदेश चतुर्थ श्रेणी कमचारिया पर ११, १९६८ से लागू होगा ।

टिप्पणी

उपरोक्त हिदायत के कारण, रविवार या अन्य छुट्टी के दिन उपस्थित होने के लिये कोई बाह्यन व्यवसाय या अतिरिक्त वतन स्वीकृत नहीं होगा ।

राजस्थान सरकार का निणय

२ क्षतिपूर्ति प्राक्स्मिक अवकाश सम्बन्धी आदेश अधिकारियों के निजी कमचारियों पर लागू नहीं होगा, नामाग्र, निजी सहायता गण, प्राप्ति लिपिक गण, व्यायामियों के बावर्गण (रिडम) प्राप्ति क्योंकि उनसे यह आशा की जाती है कि वे अपने कार्यालयाध्यक्षा के साथ ऐसी छुट्टियों में भी काम करेंगे, और इसलिये वे क्षतिपूर्ति (प्राक्स्मिक अवकाश) पाने के हकदार नहीं हैं ।

३ III ख आर ए सी के जवानों के लिये विशेष क्षतिपूर्ति - (प्राक्स्मिक)

वर्ष १९६६ में आर ए सी के जवानों को, जिनको युद्ध के घाटी रखने के बाद मुक्त किया है, विशेष क्षतिपूर्ति (प्राक्स्मिक) अवकाश, जो ३१ दिन से अधिक नहीं होगा प्रदान किया जा सकेगा । इन आदेशों का प्रभाव १२ १९६६ से प्रारम्भ होगा ।

IV स्पर्शवर्जन अवकाश । (Quarantine Leave)

स्पर्शवर्जन (क्वारेन्टाइन) अवकाश किसी राजकीय कमचारी के, परिवार या घर में किसी छूत का रोग आजाने के फल, स्वरूप, कार्यालय में नहीं आने के, आदेश द्वारा अपेक्षित, कार्य से अनुपस्थित रहने की अनुमति होती है । ऐसा अवकाश कार्यालयाध्यक्ष द्वारा चिकित्सा या सावजनिक स्वास्थ्य अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर दिया जा सकेगा जो २१ दिन की अवधि अथवा विशेष परिस्थितियों में ३० दिन से अधिक नहीं होगा । स्पर्शवर्जन के प्रयोजनाय उक्त अवधि से अधिक अवकाश देना आवश्यक हो तो वह सामान्य अवकाश में शुमार किया जायगा । जब अवकाश हो, तो स्पर्शवर्जन अवकाश अन्य अवकाश से जुड़ता हुआ भी दिया जा सकेगा जो उक्त सीमा के अर्धेन होगा । नीचे टिप्पणी में उल्लेखित मामलों के अतिरिक्त स्पर्शवर्जन अवकाश पर अनुपस्थित राजकीय कमचारी के स्थान पर कोई स्थानापन्न व्यक्ति नियुक्त नहीं करना चाहिये । स्पर्शवर्जित अवकाश में किसी राजकीय कमचारी को काम से अनुपस्थित नहीं मानते और उसका वेतन नहीं रुकता । -

१ वित्त विभाग आदेश न एफ १ (२) एफ डी [ई आर] ६४ ३ १-६४ द्वारा जोड़ा गया ।

२ " " " स एफ ७ (१८) एफ डी ११/११, दिनांक २२ अक्टूबर, १९५६

३ " " " स एफ १ (७६) एफ डी [ई आर] ६६ दिनांक ८ ११ ६६

स्पष्टीकरण

१ स्पष्टावजन अवकाश उस राजकीय कर्मचारी को नहीं दिया जा सकता जो स्वयं छूट के राग से पीड़ित हो जाय। उसे अवकाश के नियमों के अनुसार अवकाश दिया जायगा।

२ इस नियम में निर्धारित २१ या ३० दिन की अधिकाधिक सीमा ऐसे प्रत्येक अवसर के लिये होगी जिसमें अवकाश मांगा गया हो और प्रदान किया गया हो।

टिप्पणी

इस नियम के प्रयोजनाय हैजा, चेचक प्लग, डिप्थीरिया टाइफस बुमार २ [] तथा मरोब्रोसपाइडल मेननजाइटिस, इस नियम के प्रयोजनाय, छूट के रोग समझे जा सकते हैं। चेचक की दशा में स्पष्टावजन अवकाश तब तक नहीं दिया जाना चाहिये जब तक कि उत्तरदायी स्वास्थ्य अधिकारी का यह मत न हो कि चूकि रोग के ठोक विषय के विषय के सदेह हैं उदारहणार्थ, चेचक इसलिए ऐसे अवकाश प्रदान करने का कारण मौजूद है।

३ स्पष्टावजन अवकाश पर अनुपस्थित व्यक्ति के स्थान पर अन्य व्यक्ति अधिकृत अवधि तक रखने की स्वीकृति सरकार या सक्षम प्राधिकृत उस दशा में दे सकेगा जब कि उनका वेतन प्रभावित किये बिना, उसके काय को व्यवस्था नहीं की जा सकती हो बशर्ते कि अनुपस्थिति ३० दिन से अधिक को नहीं हो और अनुपस्थित व्यक्ति का वेतन १००) मासिक से अधिक नहीं हो।

V वैदेशिक सेवा

१ प्रशदान भुगतान करने की प्रक्रिया

(क) किसी राज्य कर्मचारी का स्थानान्तर वैदेशिक सेवा में करने के आदेश का प्रतिलिपि स्थानान्तर स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा लेखाधिकारी को अवश्य भेजी जानी चाहिये राज्य कर्मचारी स्वयं को उसके वेतन की लेखा परीक्षा करने वाले अधिकारी के पास एक प्रति अविलम्ब भेजनी चाहिये और प्रशदान के लिये जिस अधिकारी को लेखा प्रस्तुत करे इस विषय में उससे निर्देश प्राप्त कर लेने चाहियें, तथा उस (बाद में उल्लेखित) अधिकारी के समक्ष समस्त प्रकार स्थानान्तर करें जिसमें उसने भाग लिया हो, समय और दिनांक, वैदेशिक सेवामें रहत हुए तथा वापस लौटते समय की रिपोर्ट प्रेषित करते रहना चाहियें, और समय समय पर उसे वैदेशिक सेवामें प्राप्त वेतन लिया गया अवकाश अपने डाक का पना और अन्य सूचना जो वह अधिकारी मागे उसका विवरण, अधिकारी को सूचित करता रहना चाहिये।

(ख) वैदेशिक सेवा के विषय में जिस लेखाधिकारी को सूचनाएं भेजनी हैं वह महालेखाकार है।

१ वित्त विभाग आदेश सं एक ७ (१८) एक ॥/५५ दिनांक ३ नवम्बर १९५५ द्वारा जारी गया।

२ राज्य 'मोहम्मद' तथा 'मम्मन' वित्त विभाग आदेश सं १००६/प्रार/५७/एक १ (१९५५) एक प्रार/५६ दिनांक २२ फरवरी १९५७ द्वारा नापित किये गये।

२ अवकाश तथा अवकाश प्रदान करने के विषय में नियम ।

वैदेशिक सेवा में रहने वाला राज्य कमचारी सेवा नियमों के अध्याय १३ में दिये गये नियमों के पालन के लिये स्वयं व्यक्तिगत जिम्मेदार है तथा ऐसे अवकाश का उपयोग करने में जिसका कि वह अधिकारी नहीं हो, अनियमितता से उठाया गया अवकाश वेतन वापस जमा कराने का देनदार होगा, और वापस जमा कराने में इन्कार करने की दशा में, सरकार के अधीन भूत पूर्व सेवा की जाती हो सकेगी और तत्पश्चात् पेंशन या अवकाश वेतन के विषय में सरकार पर उसका कोई हक नहीं रहेगा ।

VI यात्रा भत्ता

१ जब किसी राज्य कमचारी का स्थानांतरण सावजनिक सुविधा के प्रतिरिक्त किसी अन्य कारण से हुआ हो तो स्थानांतरण आदेश की एक प्रति महालेखाकार के पास स्थानांतरण का कारण व्यक्त करते हुए प्रेषित करना चाहिये । ऐसे प्रेषित करने के अभाव में महालेखाकार यह समझ लेगा कि स्थानांतरण सावजनिक सुविधा हेतु किया गया है ।

२ अराजपत्रित राज्य कमचारी होने की दशा में नियम १ में निर्दिष्ट आदेश की प्रति के स्थान पर कार्यालयाध्यक्ष का प्रमाण पत्र माँग हो सकेगा ।

३ नियमों के अधीन यात्रा भत्ते कि स्वीकृति यथा संभव उन सार्व मामला में वाञ्छनीय है जिसमें जाच कमीशनर आदि के समक्ष उपस्थित होने वाले व्यक्तियों के यात्रा भत्ते पर शासित होने वाले यात्रा भत्ता नियम लागू होते हैं, क्योंकि इससे पत्राचार में वचन तथा लेखा परीक्षा में सुविधा होती है ।

परिशिष्ट II

सविदा पर नियुक्त अधिकारियों के अवकाश की शर्तें

टिप्पणी

यह उन अधिकारियों के अवकाश की शर्तों के विषय में है जो राज्य सरकार द्वारा अध्यागत राज्य में सविदा के आधार पर नियुक्त किये गये हैं/ये और जिन पर राजस्थान सेवा नियम स्रण्ड १ में नियम सामान्य अवकाश नियम लागू नहीं होते हैं।

राज्य के कृत्यों के सम्बन्ध में सविदा पर रखे गये राज्य कमचारी तत्समय प्रभावशील सेवा नियमों से शापित होंगे, परन्तु वे निम्नलिखित प्रावधानों तथा सविदा में उल्लिखित विशेष प्रावधानों के, यदि कोई हो, अधीन होंगे।

(१) जबकि सविदा की अवधि पांच वर्ष से अधिक न हो, कथित नियम उक्त अधिकारी पर उसही प्रकार लागू होंगे जमा की वे अस्थाई या अर्ध स्थाई कमचारियों पर लागू होते हैं,

परन्तु शत यह है कि सिवाय चिकित्सा प्रमाण पत्र पर उक्त अधिकारी को कोई अग्र वेतन पर अवकाश देय नहीं होगा,

परन्तु आग शत यह भी है कि यदि सविदा एक वर्ष या उससे कम समय के लिए हो तो ऐसे अधिकारी को कोई असाधारण अवकाश नहीं दिया जावगा, और यदि सविदा एक वर्ष से अधिक समय के लिए हो किन्तु पांच वर्ष से अधिक न हो, तो सविदा के समस्त कायकाल की अवधि में असाधारण देय अवकाश तीन मास तक सीमित होगा,

किन्तु शत यह है कि यदि सविदा एक वर्ष या उससे कम समय के लिए हो, तो लोक सेवा की आवश्यकताओं का देखते हुए सविदा की अवधि में जो अवकाश समस्त आशिक उम अधिकारी को दिया जा सकता था वह अम्बोवृत्त हो जाने के बावजूद भी सविदा की अवधि के बाहर उसे कोई अवकाश नहीं दिया जायेगा।

(२) जबकि सविदा पांच वर्ष की अवधि से अधिक की हो और जबकि पांच वर्ष या उससे कम की सविदा की मयाद इस प्रकार बढ़ादी गई हो, जिससे कि सविदा की कुल अवधि पांच वर्ष से अधिक हो गई हो तो उक्त अधिकारी पर कथित नियम उसी प्रकार से लागू होंगे जैसे कि किसी स्थाई सेवा में रहने वाले अधिकारी पर लागू होते हैं।

परन्तु शत यह है कि सिवाय चिकित्सा प्रमाण पत्र पर ऐसे अधिकारी का कोई अग्र वेतन पर अवकाश नहीं दिया जायगा।

परन्तु शर्तें यह भी है कि असाधारण अवकाश के विषय में उक्त अधिकारी पर कथित नियम उसी प्रकार लागू होंगे जस कि किसी अस्थाई या अग्र म्यापी अधिकारी पर लागू होते हैं।

टिप्पणी

किसी सविदा की अवधि बढ़ाकर पाँच वर्ष से अधिक कर देने की अवस्था में अधिकारी के खाते में उतनी रियायती अवकाश जमा कर दिया जायेगा जितना उसको उस दशा में देय होता जब कि उसकी सविदा की अवधि प्रारम्भ से ही पाँच वर्ष में अधिक की होती किन्तु उसमें से पहले से ही उपयोग किया गया अवकाश कम कर दिया जायेगा ।

(३) जब कि सविदा अनिश्चित काल के लिये हो अथवा जब कि कोई निश्चित काल तक की मौलिक सविदा की अवधि बढ़ाकर अनिश्चित काल के लिये कर दी गई हो तो, उस अधिकारी पर कथित नियम उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि स्थायी कर्मचारी पर लागू होते हैं ।

टिप्पणी

किसी सविदा की अवधि बढ़ाकर अनिश्चित काल के लिये कर दी जाने की अवस्था में अधिकारी के खाते में उतना रियायती अवकाश जमा कर दिया जायेगा जितना उसको उस दशा में देय होता जब कि उसकी सविदा की अवधि पहले से ही अनिश्चित समय के लिये होती किन्तु उसमें से पहले से ही उपयोग किया गया अवकाश कम कर दिया जायेगा ।

(४) (1) जो अधिकारी रियायती अवकाश या परिवर्तित (कम्प्यूटेड) अवकाश पर हो उसे उसके औसत वेतन के बराबर अवकाश का वेतन पाने का हक होगा, जो परिवर्तित (कम्प्यूटेड) अवकाश होने की स्थिति में रु० १५०० मासिक की अधिकतम सीमा के अधीन होगा ।

(11) जो अधिकारी अथ वेतन पर या "ऐसे अवकाश पर हो जो शेष न हा, तो उसे अपना आधा औसत वेतन पाने का हक होगा, जो प्रत्येक दशा में रु० ७५० मासिक की अधिकतम सीमा के अधीन होगा ।

टिप्पणी

"औसत वेतन" से तात्पर्य ऐसे औसत मासिक वेतन से है जो उग घटना के मास में पिछले पूरे १२ मास में अर्जित की हुई थी जिसमें कि औसत वेतन के गणना में आवश्यकता उत्पन्न हुई ।

(५) जिस अधिकारी का प्रारम्भ में सविदा के आधार पर नियुक्त किया था, उसको जब स्थायी रूप में कर्मचारी रख लिया जावे तो उसके खाते में उतना रियायती अवकाश जमा कर दिया जायेगा जितना उसको उस दशा में देय होता जो कि प्रारम्भ से ही स्थायी सेवा में नियुक्ति होने की दशा में उसको देय होता किन्तु उसमें से पहले से ही उपयोग किया गया अवकाश कम कर दिया जायेगा ।

(६) जब कि सविदा में इसका उल्लेख न हो कि अधिकारी कौन से वर्ग का अधिकारी है, तो राज्य सरकार अथवा इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत व्यक्ति इस बात की घोषणा करेगा कि अवकाश नियमों के प्रयोजनार्थ वह अधिकारी सेवा के कौन से वर्ग में रहेगा ।

२ यह आदेश दिनांक १४ १९५१ से प्रभावशील होगा परन्तु किसी सविदा पर नियुक्त अधिकारी इन सेवा नियमों के जारी होने की तारीख को यह विकल्प लेने का हक्कदार होगा कि यह चालू सविदा के सम्बन्ध में अवकाश की मौजूदा शर्तों को कायम रखेगा। जो अधिकारी चालू सविदा के सम्बन्ध में मौजूदा अवकाश की शर्तों कायम रखने का निर्णय लेवे, उसे इन आदेशों के जारी होने से तीन मास के भीतर अथवा सेवा नियमों के जारी होने के बाद पहली बार अवकाश आवेदन करने में पूर्व या भी पहले हो जाय लिखित रूप में अपने लेखाखिकारी के या कार्यालयाध्यक्ष को यथा स्थिति, अपने निर्णय की सूचना देनी चाहिये। एक बार प्रयोग में लिया गया विकल्प अंतिम होगा।

३ जो अधिकारी अपना चालू सविदा के सम्बन्ध में मौजूदा अवकाश की शर्त कायम रखे उक्त सविदा की अवधि बढ़ाई जाने की रक्षा में उपरान्त अनुच्छेद १ के प्रावधानों के रहते, उसपर राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत अवकाश के नियम स्वतः लागू होंगे। ऐसे मामलों में बढ़ाई गई अवधि में आगे जमा किये जाने वाले अवकाश की मात्रा वही प्रभावशील हान की तारीख को देय रियायती अवकाश होगा और उसके साथ ऐसा अथ वेतन अवकाश जुड़ेगा जो उस अवस्था में देय होता जब कि वह अपनी चालू सविदा के विषय में मौजूदा अवकाश की शर्तों को ग्रहण करने का विकल्प नहीं लगा।

परिशिष्ट II-क
अवकाश-सेवा प्रपत्र

जम दियाक
पद

राज्य कर्मचारी का नाम
निलम्बर सेवा प्रारम्भ होने का दिनांक
अभियागत सेवा निवृत्ति का दिनांक

रियायती अवकाश		अभ्य-वर्तन अवकाश		निवा कर्मों के लिए तथा चिवित्ता प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश जो लिया गया		दिनांक १९५७									
वय पर	अवकाश लिया	सेवा बाल	अवकाश जो जमा हुआ	कब से	कब तक	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
दिना की सख्या	अवकाश का अंतिम दिना (दिनांक)	कोष २६५ यथापूर्व	सोमा के अंशोन	कब से	कब तक	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
कब तक	अवकाश का अंतिम दिना (दिनांक)	कोष २६५ यथापूर्व	सोमा के अंशोन	कब से	कब तक	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०
कब तक	अवकाश का अंतिम दिना (दिनांक)	कोष २६५ यथापूर्व	सोमा के अंशोन	कब से	कब तक	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०
कब तक	अवकाश का अंतिम दिना (दिनांक)	कोष २६५ यथापूर्व	सोमा के अंशोन	कब से	कब तक	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९	५०
कब तक	अवकाश का अंतिम दिना (दिनांक)	कोष २६५ यथापूर्व	सोमा के अंशोन	कब से	कब तक	५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०
कब तक	अवकाश का अंतिम दिना (दिनांक)	कोष २६५ यथापूर्व	सोमा के अंशोन	कब से	कब तक	६१	६२	६३	६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०
कब तक	अवकाश का अंतिम दिना (दिनांक)	कोष २६५ यथापूर्व	सोमा के अंशोन	कब से	कब तक	७१	७२	७३	७४	७५	७६	७७	७८	७९	८०
कब तक	अवकाश का अंतिम दिना (दिनांक)	कोष २६५ यथापूर्व	सोमा के अंशोन	कब से	कब तक	८१	८२	८३	८४	८५	८६	८७	८८	८९	९०
कब तक	अवकाश का अंतिम दिना (दिनांक)	कोष २६५ यथापूर्व	सोमा के अंशोन	कब से	कब तक	९१	९२	९३	९४	९५	९६	९७	९८	९९	१००

नोट १ अलाधारण अवकाश काल विगण विवरण के लिए नियमित कोटक से २७ म साल स्थाही से अधिक नियो जावे ।

- २ कोटक १० तथा ११ की प्रविष्टिया केवल अथवेतन अवकाश प्रारम्भ होने के समय नवा के पूरे वर्ष का प्रारम्भ तथा घटत म कित करे । अर्ध-वैतन अवकाश पर रहते हुए जब कि कोई राज्य कर्मचारी सेवा का अथ वय पूरा करते तो प्रतिरिक्त जमा, उचित प्रतिरिक्त प्रविष्टियों द्वारा कोटक ११ से १४ म दशांती चाहिये और कोटक २६ पूरा करने समय सेवा में सम्मिलित कर लेनी चाहिये ।
- ३ जर कभी एक भिन्न से दूसरे म परिवर्तन होव उस समय जमा निवृत्तम पूरे दिन के रूप में बरती जावे अर्थात् तब कि भिन्न माथे से कम हो ता उपेक्षित कर दो जावे और माथे अथवा उससे अधिक की हो तो पूरा दिन गिना जावे ।
- ४ जब कभी अवकाश प्रार्जन की दर बदल जावे, तो पहल की दर से एकत्रित रियायती अवकाश निवृत्तम पूरे दिन के रूप में दवा लिया जावे, अर्थात् माथे से कम की भिन्न उपेक्षित करदी जावे तथा माथे और उससे अधिक को पूरा एक दिन गिना जाव ।

परिशिष्ट III

1. आदेश इकरारनामे का प्रपत्र स १

भारत में सेवा में भारती के लिये प्रारम्भिक इकरारनामा निश्चित अवधि के लिये आगे पुन नियुक्ति के ज्ञापन समित ।

सूचना

यह समझनेना आवश्यक है कि यद्यपि कानून द्वारा अपेक्षित इकरारनामा, रूप में राजस्थान के राज्यपाल के साथ एक इकरारनामा है, फिर भी यह नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा की जाती है । जो व्यक्ति इसे भरने के लिये चुना जायगा, वह हर तरह से अपने सम्पूर्ण सेवा काल में उक्त सरकार के आदेशों के अधीन रहेगा ।

सविदा पत्र जो दिनांक 1 मास सन् एक हजार नौ सो और 1 को द्वारा प्रथम पक्ष की और से तथा द्वितीय पक्ष में राजस्थान के राज्यपाल जिनको आगे 'सरकार' कहेंगे हुआ ।

चू कि सरकार न प्रथम पक्ष के व्यक्ति को सेवा में नियुक्त किया है और प्रथम पक्ष के व्यक्ति ने आगे दी हुई शर्तों पर सरकार की सेवा करने का इकरार किया है—

अथ अभिलेख माक्ष्य करता है और दोनों पक्ष जमश निम्नलिखित इकरार करता है—

१ प्रथम पक्ष का व्यक्ति अपने आपको सरकार के अथवा सरकार द्वारा जिन जिन अधिकारियों तथा प्राधिकारियों के अधीन उसे समय समय पर रखा जाव उनके अधीन रहेगा और निम्नलिखित प्रावधानों के अधीनस्थ वष तक, दिनांक 1 मास 1९ से सवामे रहेगा ।

२ प्रथम पक्ष का व्यक्ति अपना सारा समय कर्तव्य पालन में अर्पित करगा और सावजनिक सेवा का जिस शाखा में वह रहे उसके नियमों, जिसमें समय समय पर निर्धारित राज्यकर्मचारियों के आचरण नियमों सम्मिलित है उनका सदैव पालन करेगा और जब कभी अपेक्षित हो, राजस्थान अथवा भारत के किसी भाग में जावेगा और जो कर्तव्य उसको सौंपे जावें उनका पालन करेगा ।

३ प्रथम पक्ष के व्यक्ति की सेवा निम्न प्रकार से समाप्त की जा सकेगी —

(i) किसी भी पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष की समाप्ति पर विना नोटिस दिये ।

(ii) किसी भी समय यदि सरकार की राय में प्रथम पक्ष का व्यक्ति इस इकरारनामे के अधीन सेवा के समय दक्षता पूर्ण कर्तव्य का पालन करने के लिए अनुपयुक्त मानित हो तो राज्यसरकार द्वारा तीन केलण्डर महीना का नोटिस देकर ।

१ वित्त विभाग आदेशस एक ७ (१५) एफ ११/५५ दिनांक ५ मितम्बर १८५५ द्वारा मंगेयित आदेश इकरारनाम के प्रथम द्वारा स्थानापन किया गया ।

(iii) सरकार द्वारा, बिना पूर्व नोटिस दिये, यदि सरकार को चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर सतोष हो जाय कि प्रथम पक्ष का व्यक्ति खराब स्वास्थ्य के कारण राजस्थान या भारत में अपने कर्तव्य पालन करने में काफी समय तक असमर्थ रहेगा। परन्तु यह शत सदैव रहेगी कि सरकार का यह निर्णय कि प्रथम पक्ष के व्यक्ति का काफी समय तक असमर्थ रहने की संभावना है, प्रथम पक्ष के व्यक्ति पर अन्ततः बाध्य होगा।

(iv) सरकार अथवा, उससे प्राप्त उचित प्राधिकार रखने वाले अधिकारी द्वारा बिना पूर्व नोटिस के, यदि प्रथम पक्ष का व्यक्ति अविनय, अनियम या अन्य दुराचरण अथवा इस इकरारनामे, या सार्वजनिक सेवा से सम्बंधित, जिस सेवा की शाखा में वह हो उसके नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन या कर्तव्य हीनता का दोषी हो।

(v) छ मास के लिखित नोटिस द्वारा, जो किसी भी समय इस इकरारनामे के अधीन सेवा के दौरान (सिवाय इकरारनामे के प्रथम वर्ष में) जो उसके द्वारा सरकार को दिया जावे या जो सरकार या उसके अधिकृत अधिकारी द्वारा बिना कारण बताये उसको दिया जावे।

परन्तु शत सदैव रहेगी कि इस इकरारनामे में प्रावधानित किसी नाटिम के वजाय राज्य सरकार प्रथम पक्ष के व्यक्ति को उस महीने के वेतन के बराबर राशि अथवा कम नोटिस होने की दशा में उस महीने से नोटिस की अवधि जितनी कम पड़ती है उस समय के वेतन के बराबर राशि नोटिस के वजाय दे सकेगी। परन्तु शत यह भी होगी कि इस क्लॉज के उप खण्ड (२) के अधीन नोटिस दिये जाने की अवस्था में, उपरोक्त परन्तु में शब्द 'छ' के स्थान पर शब्द 'तीन' पढ़ी जायगा। इस क्लॉज (उप खण्ड) के प्रयोजनार्थ शब्द 'वेतन' से तात्पर्य उस वेतन (जिसमें विशेष वेतन तथा व्यक्तिगत वेतन, यदि कोई हो सम्मिलित है), से होगा जो इस इकरारनामे के अन्तगत तत्समय प्रथम पक्ष का व्यक्ति प्राप्त करता है, सिवाय उस दशा में जब कि वह स्थानापन्न वेतन प्राप्त कर रहा हो और उस दशा में वेतन से तात्पर्य उस वेतन (विशेष वेतन तथा व्यक्तिगत वेतन सहित यदि कोई हो) से होगा जो उसके मालिक नियुक्ति का वेतन है।

४ उपरोक्त उपखण्ड २ (४) में उल्लिखित किसी दुराचरण व आरोप की अवधि में यदि प्रथम पक्ष का व्यक्ति सेवा से निलम्बित कर दिया गया हो, तो वह निलम्बित की अवधि में कोई वेतन पाने का हक्दार नहीं होगा, परन्तु वह, निर्वाह राशि पाने का हक्दार होगा जिसकी दर वह होगी जो सरकार स्वीकृत करना निर्णय करे।

५ के पद की जिस पर प्रथम पक्ष व्यक्ति की नियुक्ति हुई है वेतन श्रु खला प्रत्येक १२ मास की सेवा समाप्त करने पर निम्नलिखित मासिक दर की होगी—

स्टेज	वेतन। रुपये
१	
२	
३	
आदि	

से उसको रुपये

मासिक की दर

से वेतन उपरोक्त श्रृंखला में प्रदान किया जायगा और जो उस श्रृंखला में बताये गये स्टेजों के अनुसार तथा समय समय पर प्रभावशील उस पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार होगा, और उसकी सेवा के स्टेजों की तारीख की गणना उपरोक्त तारीख से की जायगी। इस इकरारनामों के अधीन जो वेतन उसको समय समय पर उस काल के लिये दिया जायेगा जिसमें वह इस इकरारनामों के अधीन सेवा करे और उपरोक्त तारीख को प्रारम्भ होने वाले कत्त व्यो का वास्तविक पालन करे और उसकी समाप्ति राजस्थान में सेवा छोड़ने की तारीख से होगी अथवा उस दिन से होगी जिस दिन वह सेवा से प्रथक कर दिया जावे अथवा उस दिन से जिस दिन सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाय। यदि किसी समय प्रथम पक्ष का व्यक्ति राजस्थान से बाहर प्रतिनियुक्ति पर चला जावे तो प्रतिनियुक्ति की अवधि में उसका वेतन प्रतिनियुक्ति सम्बंधित सामान्य नियमों द्वारा नियमित होगा।

६ प्रथम पक्ष का व्यक्ति सावजनिक सेवा की आवश्यकता के अधीन रहते, राजस्थान सेवा नियमों के अधीन जैसे कि वह समय समय पर सशोधित हो, अवकाश तथा अवकाश का वेतन प्राप्त करने का पान होगा।

७ प्रथम पक्ष के व्यक्ति, जिसको राजस्थान सेवा नियमों के नियम ६४ के अधीन सरकार अथवा किसी निजी नियोजक के अधीन अंतिम अवकाश के दौरान अथवा ऐसे अवकाश के समय जिसकी समाप्ति के पश्चात् उसके वापस लौटने की आशा न हो, नौकरी प्राप्त करने की अनुमति दी गई हो उसका अवकाश वेतन अर्ध वेतन अवकाश की मात्रा तक सीमित रहेगा।

८ यदि प्रथम पक्ष के व्यक्ति के लिये सावजनिक सेवा के हितों में यात्रा करना अपेक्षित हो तो वह उस श्रृंखला का यात्रा भत्ता पान का अधिकारी होगा जिसका उसके मामले में लागू होने वाले समय समय पर सरकार द्वारा बनाये गये यात्रा भत्ता नियमों में प्रावधान हो।

९ प्रथम पक्ष का व्यक्ति चिकित्सक बुलाने तथा चिकित्सा कराने के विषय में ऐसी रियायतें पाने का पात्र होगा जो सरकार उस स्थान पर कार्य करने वाले ऐसे अधिकारियों के वर्ग के लिये निर्धारित करे जिसके अनुरूप पद वाला हो या सेवा की शर्तों के मामले में समान होना सरकार घोषित करे।

१० ऊपर कुछ भी लिगे होने के अतिरिक्त इस इकरारनामों के अंतर्गत माय वेतन तथा अवकाश वेतन जो चाह राजस्थान में अथवा किसी अन्य स्थान पर देय हो ऐसी आपतनालीन कटौती के अधीन रहने जिसका सरकार उसी अवधि के लिये तथा उही शर्तों पर सरकार के प्राशासनिक नियंत्रण में अन्य अधिकारियों के लिये आदेश देवें। -

१० किसी ऐसे मामले के विषय में, जिसके सम्बन्ध में इस इकरारनामे में कोई प्रावधान न हो, असेनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम उसके अंतर्गत बनाये गये हैं। कोई नियम तथा सविधान के अनुच्छेद ३०६ या अनुच्छेद ३१० के अंतर्गत बनाए गये या बनाये गये समझ जाने वाले नियम उस सीमा तक लागू होंगे जिस सीमा तक एतद् द्वारा जिस सेवा के लिये प्रावधान किया गया है उन पर वे लागू हैं, तथा उनके लागू होने के सम्बन्ध में सरकार को निर्णय अंतिम होगा ।

इसको साक्ष्य हेतु, प्रथम पक्ष का व्यक्ति तथा राजस्थान सरकार का

और से, स्थान में तथा उसका-काय करते हुए, उपरोक्त दिनांक तथा वर्ष में अपने हस्ताक्षर करते हैं ।

हस्ताक्षर

प्रथम पक्ष के व्यक्ति द्वारा,

मे,

हस्ताक्षर

द्वारा कथित सरकार का

के राज्यपाल की और से, विभाग में, राजस्थान की उपस्थिति में ।

सापन

इसमें लिखे गये नाम वाला

किया गया है एवं उसकी सेवाकाल

पुन नियुक्त

जाता है और

वय के लिये और बढ़ाया

और दिनांक

इस इकरारनामे की शर्तों के अधीन रहेगा

महीने की एक के बाद दूसरी स्टेज पर निम्नलिखित मासिक दर के वेतन से होगी —

स्टेज

वेतन-रूपये

१

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

४६

४७

४८

४९

५०

५१

५२

५३

५४

५५

५६

५७

५८

५९

६०

६१

६२

६३

६४

६५

६६

६७

६८

६९

७०

७१

७२

७३

७४

७५

७६

७७

७८

७९

८०

८१

८२

८३

८४

८५

८६

८७

८८

८९

९०

९१

९२

९३

९४

९५

९६

९७

९८

९९

१००

१०१

१०२

१०३

१०४

१०५

१०६

१०७

१०८

१०९

११०

१११

११२

११३

११४

११५

११६

११७

११८

११९

१२०

१२१

१२२

१२३

१२४

१२५

१२६

१२७

१२८

१२९

१३०

१३१

१३२

१३३

१३४

१३५

१३६

१३७

१३८

१३९

१४०

१४१

१४२

१४३

१४४

१४५

१४६

१४७

१४८

१४९

१५०

१५१

१५२

१५३

१५४

१५५

१५६

१५७

१५८

१५९

१६०

१६१

१६२

१६३

१६४

१६५

१६६

१६७

१६८

१६९

१७०

१७१

१७२

१७३

१७४

१७५

१७६

१७७

१७८

१७९

१८०

१८१

१८२

१८३

१८४

१८५

१८६

१८७

१८८

१८९

१९०

१९१

१९२

१९३

१९४

१९५

१९६

१९७

१९८

१९९

२००

२०१

२०२

२०३

२०४

२०५

२०६

२०७

२०८

२०९

२१०

२११

२१२

२१३

२१४

२१५

२१६

२१७

२१८

२१९

२२०

२२१

२२२

२२३

२२४

२२५

२२६

२२७

२२८

२२९

२३०

२३१

२३२

२३३

२३४

२३५

२३६

२३७

२३८

२३९

२४०

२४१

२४२

२४३

२४४

२४५

२४६

२४७

२४८

२४९

२५०

२५१

२५२

२५३

२५४

२५५

२५६

२५७

२५८

२५९

परिशिष्ट IV

• प्रादेशी इकरारनामों का प्रपत्र स II

[अनिश्चित काल के लिये सेवा की अवधि बढ़ाने का इकरारनामा]

सूचना

यह समझनेना आवश्यक है कि यद्यपि कानून द्वारा अपेक्षित इकरारनामा, रूप में राजस्थान के राज्यायुक्त के साथ एक इकरारनामा है फिर भी, यह नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति इसे भरने के लिये चुना जायगा, वह हर तरह में अपने सम्पूर्ण सेवा काल में उक्त सरकार के आदेशों के अधीन रहेगा।

मविदा-पत्र जा दिनांक	मास	सन
एक हजार नौ सौ और	को	"

द्वारा प्रथम पक्ष की ओर से द्वितीय पक्ष में राजस्थान के राज्यपाल के मध्य जिनको प्रागे सरकार कहेंगे हुआ। चूं कि प्रथम पक्ष का व्यक्ति सरकार द्वारा दिनांक

मास	एक हजार नौ सौ और	के
-----	------------------	----

अन्तर्गत सेवा में नियुक्त किया गया था और चूं कि कथित इकरारनामा समाप्त हो गया है चूं कि प्रथम पक्ष ने प्रथम पक्ष के व्यक्ति को पुन नियुक्त किया है और प्रथम पक्ष का व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों पर सरकार को सेवा करने के लिये सहमत हुआ है।

यह यह प्रतिज्ञा करेगा है और दोनों पक्ष क्रमशः निम्न प्रकार से इकरार करते हैं —

१ प्रथम पक्ष का व्यक्ति अपने आपको सरकार के अथवा सरकार द्वारा जिन जिन अधिकारियों तथा अधिकारियों के अधीन उसे रखा जावे, उनके अधीन रहेगा। वह अपना सारा समय वक्त व्य पालन में अर्पित करेगा और सावजनिक सेवा की जिस शाखा में वह रहे, उसके नियमों का जिसमें समय समय पर निर्धारित राज्य कमचारियों के आचरण नियम सम्मिलित हैं, सदैव पालन करेगा और जब कभी अपेक्षित हो राज स्थान अथवा भारत के किसी भाग में जायेगा और जो वक्त व्य इसकी सविधि करें उनका पालन करेगा।

२ जब तक कि प्रथम पक्ष के व्यक्ति की सेवा प्रागे विखें प्रावधानों अनुसार समाप्त न कर दी जावे तब तक वह राज्य की सेवा में ५५ वर्ष की आयु तक रहेगा जब कि वह सेवा निवृत्त हो जायगा। परन्तु उक्त आयु प्राप्त करने के बाद भी उसे सरकार सेवा में उस अवधि तक रख सकेगी जिसके लिये सहमति हो जाय और वह समय समय पर उस पर लागू नियमों के प्रावधानों के तथा इसमें निम्ने प्रावधानों के अधीनस्थ रहेगा।

• वित्त विभाग आदेश स एक (१५) दिनांक ५ दिसम्बर १९५५ द्वारा संशोधित आदेश इकरारनामों के प्रपत्र II द्वारा स्थानापन्न किया गया।

३ प्रथम पक्ष के व्यक्ति की सेवा निम्नलिखित तरीके से समाप्त की जा सकेगी -

१ किसी भी समय, यदि सरकार की राय में प्रथम पक्ष का व्यक्ति इस इकरारनामे के अधीन सेवा की अवधि दसतापूर्ण कर्तव्य का पालन करने के लिये अनुपयुक्त साबित हो तो राज्य सरकार द्वारा तीन कैलेण्डर महीनों का नोटिस देकर ।

२ सरकार द्वारा बिना पूर्व नोटिस दिये, यदि सरकार को चिकित्सा साध्य के आधार पर सतोष हो जाय कि प्रथम पक्ष का व्यक्ति श्रवण स्वास्थ्य के कारण राजस्थान या भारत में अपना कर्तव्य पालन करने में काफी समय तक असमर्थ रहेगा । परन्तु यह शत सदैव रहेगी कि सरकार का यह निर्णय कि प्रथम पक्ष के व्यक्ति की काफी समय तक असमर्थ रहने की संभावना है, प्रथम पक्ष के व्यक्ति पर अन्ततः बाध्य होगा ।

३ सरकार अथवा उससे प्राप्त उचित प्राधिकार रखने वाले अधिकारियों द्वारा, बिना पूर्व नोटिस के यदि प्रथम पक्ष का व्यक्ति अविनय, असयम या अन्य दुराचरण अथवा इस इकरारनामे या सार्वजनिक सेवा से सम्बंधित जिस सेवा की शाखा में वह हो उसके नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन या कर्तव्य हीनता का दायी हो ।

४ छ मास के लिखित नोटिस द्वारा, जो किसी भी समय इस इकरारनामे के अधीन सेवा की अवधि (सिवाय इकरारनामे के प्रथम वर्ष में) जो उसके द्वारा सरकार को दिया जावे या जो सरकार या उसके अधिकृत अधिकारी द्वारा बिना कारण बताये उसको दिया जाव ।

परन्तु शत यह सदैव रहेगी कि इस इकरारनामे में प्रावधानित किसी नोटिस के एवज राज्य सरकार प्रथम पक्ष के व्यक्ति का छ महीने के वेतन के बराबर राशि अथवा कम नोटिस होने की दशा में छ महीने से नोटिस की अवधि जितनी कम पड़ती है उस समय के वेतन के बराबर राशि, नोटिस के बजाय दे सकेगी । परन्तु शत यह भी होगी कि क्लॉज के उप-खंड (१) के अधीन नोटिस दिये जाने की अवस्था में, उपरोक्त परंतु क में शब्द "छ" के स्थान पर शब्द "तीन" पड़ा जायगा ।

इस उप-खंड के प्रयोजनार्थ शब्द 'वेतन' से तात्पर्य उस वेतन (जिसमें विशेष वेतन तथा व्यक्तिगत वेतन, यदि कोई हो सम्मिलित हैं) से होगा जो इकरारनामे के अंतर्गत तत्समय प्रथम पक्ष का व्यक्ति प्राप्त करता है, सिवाय उस दशा में जब कि वह स्थानापन्न वेतन प्राप्त कर रहा हो और उस दशा में वेतन से तात्पर्य उस वेतन (विशेष वेतन तथा व्यक्तिगत वेतन सहित, यदि कोई हो) से होगा जो उसके मौलिक पद का वेतन है ।

४ यदि उप खंड ३ (३) में उल्लिखित दुराचरण के आरोप की जाच के दौरान प्रथम पक्ष के व्यक्ति को काय से निलम्बित कर दिया जावे तो वह ऐसे निलम्बित काल में कोई वेतन पाने का अधिकारी नहीं होगा परन्तु वह उस दर पर निर्वाह अनुदान पाने का अधिकारी होगा जो सरकार स्वीकृत करे ।

५ इस अभिलेख के अधीन सेवा में रहते हुए, प्रथम पक्ष का व्यक्ति उस दर तथा श्रमला से मौलिक वेतन प्राप्त करेगा, जो समय समय पर प्रभावशाली तथा लागू नियम के प्रावधानों के अधीनस्थ समय समय पर उसके द्वारा धारण किये गये पद के लिये सरकार के आदेशों के अधीन सलग्न किया जावे। इस अभिलेख के अधीन समय समय पर देय वेतन उसका उस काल के लिये दिया जायगा जिसमें उसने इस इकरारनामे के अंतर्गत सेवा की हो और वास्तव में अपने कसब्या का पालन किया हो और उस दिन से बढ़ हो जायेगा जिस दिन से उसने राजस्थान में नौकरी त्याग दी हो अथवा जिस दिन से उसे सेवा से हटा दिया गया हो अथवा उसकी मृत्यु की तारीख से यदि सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाय। यदि किसी समय प्रथम पक्ष का व्यक्ति राजस्थान से बाहर प्रतिनियुक्ति पर जावे तो प्रतिनियुक्ति के काल में उसका वेतन प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी, सामान्य नियमों से शामिल होगा।

६ इस अभिलेख के अंतर्गत सेवाके दौरान सार्वजनिक सेवा की आवश्यकताओं के अधीनस्थ रहते प्रथम पक्ष का व्यक्ति दिनरात एक हजार नौ सौ और के इकरारनामे में निर्दिष्ट अवकाश तथा अवकाश वेतन पाने का पात्र होगा।

७ प्रथम पक्ष के व्यक्ति जिसकी अंतिम अवकाश या ऐसे अवकाश के दौरान जिसकी समाप्ति पर उसके लौटने की आशा न हो राजस्थान सेवा नियमों के नियम ६४ के अधीन सरकार या किसी गिजी (प्राइवेट) नियोजक के अधीन नौकरी प्राप्त करने की अनुमति दी गई हो उसका अवकाश वेतन आधे असत वेतन या अर्धवेतन अवकाश यथास्थिति तक सीमित रहेगा।

८ यदि प्रथम पक्ष का व्यक्ति को अपने सेवा काल में, सार्वजनिक सेवा के हित में यात्रा करनी प्रपक्षित हो तो वह उस दर से यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हक्दार होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर बनाये गये यात्रा भत्ते नियम में प्रावधानित हो और जो उस पर लागू होती हो।

९ प्रथम पक्ष का व्यक्ति चिकित्सक बुलाने तथा इलाज कराने के सम्बन्ध में वह। रियायतें पाने का पात्र होगा जो सरकार द्वारा उसी स्थान पर कार्य करने वाले ऐम अधिकारियों के लिये निर्धारित हो जिनके पद या सेवा की शर्तों को सरकार प्रथम पक्ष के व्यक्ति के समक्ष होना घोषित करे।

१० आगे कुछ भी लिखा होन के बावजूद जब तक कि सरकार अन्यथा तय नही करदे, प्रथम पक्ष के व्यक्ति को ऐसी उन्नति का लाभ पूरातया या आंशिक रूप से उठाने का हक् होगा जसा भी सरकार स्वीकार करे जो इस अभिलेख की तारख के बाद, सरकार तत्समय उसी शाखा के पद धारियों की सेवा की शर्तों के लिये मजूर करे, और ऐसी उन्नति के विषय में सरकार का निर्णय, उस हद तक इस अभिलेख के प्रावधानों को मशोघित करने का प्रभाव रखेगा।

१० ऊपर कुछ भी लिखा होने के बावजूद, इस अभिलेख के अन्तर्गत मा-य वेतन तथा अवकाश-वेतन, जो चाहे राजस्थान में या किसी अन्य स्थान पर देय हो किसी आपतकालीन कठौती के अधीन रहेगा जो उही शर्तों पर उसी काल के लिये सरकार के प्राशासनिक नियन्त्रण के अधीन अन्य अधिकारियों पर सरकार किसी आदेश द्वारा लागू करे।

११ किसी मामले के सम्बन्ध में जिसके बारे में इस इकरागनामें कोई प्रावधान किया हुआ नहीं है, असतिक सेवार्यें (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम तथा उनके अधीन बनाये गये नियम तथा सविधान के अनुच्छेद ३०६ के अधीन बनाए गये या मसभे जाने वाले नियम या जो अनुच्छेद ३१३ के अधीन जारी हो उस हद तक लागू होंगे जिस हद तक वे एतद्वारा सेवा के लिये प्रावधानित हैं और उनके लागू होने के सम्बन्ध में सरकार का नियम अंतिम होगा। -

इसकी साक्ष्य के लिये प्रथम पक्ष का व्यक्ति और विभाग में राजस्थान सरकार का शासन सचिव " के आदेश तथा निर्देशन द्वारा इस स्थान पर राजस्थान के राज्यपाल की ओर स काय करते हुए अपने हस्ताक्षर ऊपर लिखी तारीख और वष में करते हैं।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष के व्यक्ति का
की उपस्थिति में।

हस्ताक्षर

शासन सचिव, राजस्थान सरकार,
राजस्थान के राज्यपाल की ओर से

विभाग

की उपस्थिति में।

परिशिष्ट V (पाँचवा)

वैदेशिक सेवा में रहने के दौरान पेशन के लिये बढ़े (अशदान) की दर तथा अवकाश-वेतन

यह उन नियमों के विषय में हैं जो विदेशी नियोजक द्वारा पेशन के खाते में अशदान को शासित करते हैं और जो वैदेशिक सेवा में रहते राज्य के बन्सोलिडेटेड निधि के अतिरिक्त किसी अन्य निधि से राज्य कर्मचारी द्वारा अवकाश वेतन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में हैं।

पेशन के लिये अशदान के प्रयोजनाय राज्य कर्मचारियों का वर्गीकरण निम्न लिखित ग्रोहों में किया गया है —

- (क) सब भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं के प्रथम श्रेणी के सदस्य।
- (ख) राज्य सेवाओं के सदस्य।
- (ग) अधीनस्थ सेवाओं के सदस्य।

टिप्पणी

१ 'इस परिशिष्ट के प्रयोजनाय अधीनस्थ सेवा से तात्पर्य राजस्थान भ्रमनिक सवाए (वर्गीकरण नियन्त्रण तथा अपील) नियम, १९५८ में परिभाषित अधीनस्थ सेवक वर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारियों से है।

कोई राज्य कर्मचारी जो कंटीन्यूटरी प्राविडेंट फंड में चढ़ा देता हो और जो वैदेशिक सेवा में स्थानांतर कर दिया गया हो वह वैदेशिक सेवा में प्राप्त वेतन की गणना के आधार पर मासिक चढ़ा देगा। विदेशी नियोजक अथवा अधिकारी स्वयं नियम १४५ के उपखंड (ग) के अधीन की गई व्यवस्थानुसार, फौजी वैदेशिक सेवा काल के लिये सूत्र क्ष + क्ष त्र द्वारा निर्धारित राशि से इतने गुणा अतिरिक्त चढ़ा देगा जो प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा निर्धारित हो, जब कि क्ष उस राशि के बराबर है जो चढ़ा देने वाल के खाते में उम दशा में मासिक जमा की जाती जब कि वह वैदेशिक सेवा में नहीं गया होता और इस प्रयोजन के लिये उसके द्वारा वैदेशिक सेवा में उठाये गये वेतन को उसकी 'इमोल्यूमेंट्स' (परिलब्धि) माना जायगा, और त्र उस भिन्न के बराबर है जो अवकाश वेतन के रूप में वसूली योग्य राशि वैदेशिक सेवा में उठाए गये वेतन अनुपात रखती हो।

पेन्शन के लिये निम्नलिखित भासिक दरे फौजी वदेशिक सेवा के दौरान देय होगी—

सेवा काल	सब भारतीय सेवाधारी [] के सदस्या के लिये	राज्य सेवाधारी के सदस्यो के लिये	ग्रामीणस्थ सेवाधारी के सदस्या के लिये
०-१ वष	६३	भौतिक रूप से धारण ग्रेड में सर्वाधिक भासिक वेतन का ५%	भौतिक रूप से धारण ग्रेड में सर्वाधिक भासिक वेतन का ४%
१-२ वष	७०	५	४
२-३ ,	७८	५	५
३-४ ,	८६	६	५
४-५ ,	९६	६	५
५-६ "	१०२	७	६
६-७ "	११०	७	६
७-८ "	११७	८	७
८-९ "	१२५	८	७
९-१० "	१३३	९	७
१०-११ ,	१४१	९	८
११-१२ "	१४९	१०	८
१२-१३ ,	१५७	१०	८
१३-१४ ,	१६४	१०	८
१४-१५ "	१७२	११	८
१५-१६ "	१८०	११	१०
१६-१७ "	१८८	१२	१०
१७-१८ ,	१९६	१२	१०
१८-१९ "	२०४	१३	११
१९-२० "	२११	१३	११
२०-२१ ,	२१८	१४	१२
२१-२२ ,	२२७	१४	१२
२२-२३ ,	२३५	१५	१२
२३-२४ ,	२४३	१५	१३
२४-२५ ,	२५१	१५	१३
२५-२६ ,	२५८	१६	१४
२६-२७ ,	२६६	१६	१४
२७-२८ ,	२७४	१७	१४
२८-२९ ,	२८२	१७	१५
२९ वष से ऊपर	२९०	१८	१५

१ "तथा केन्द्रीय प्रथम श्रेणी की शतावली विन विभाग ग्रादेन म० एफ १ (३५) (ग) रुस्त/६१ दिनांक ७-२-६२ द्वारा लापित की गई ।

फौजी सेवा में अवकाश वेतन के लिये मासिक दर राज्य कर्मचारियों के सारे वर्गों के लिये वदेशिक सेवा में उठाये गये वेतन का ११% होगा [] ।

२ [उपराक्त परा में शब्दावली ' सिवाय चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों के ' जो लोपित की गई है उसका प्रभाव इसके बाद वदेशिक सेवा प्रारम्भ होने वाले मामलों पर पड़ेगा । जो व्यक्ति पहले से ही वदेशिक सेवा में हो, ये सशोधन निम्न प्रकार से प्रभावशील होंगे —

(क) उनकी वदेशिक सेवा की मौजूदा अवधि की समाप्ति पर यदि मौजूदा अवधि निश्चित समय के लिये हो और इसके बाद बढ़ाई गई हो ।

(ख) प्रारम्भिक वदेशिक सेवा की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति पर जब कि वदेशिक सेवा अनिश्चित काल के लिये थी ।]

श शर्तों' फौजी वदेशिक सेवा में किसी अधिकारी को दिया गया पदग्रहण करने का समय (जाइनिंग टाइम) भी सम्मिलित है जो वदेशिक सेवा में जाने के अवसर पर तथा वहां से वापस लौटने के समय दिया जाता है और तदनुसार ऐसे काल के लिये भी चन्दा वसूली योग्य है ।

३ सेवा काल से तात्पर्य सम्बंधित राज्य कर्मचारी की पूरी निरंतर सेवा है जिसमें पश्चिम युक्त पद पर अस्थायी सेवा सम्मिलित है ।

किसी अस्थायी राज्य कर्मचारी हाने की दशा में जिसका स्थानांतर वदेशिक सेवा में हो जावे, सरकार यह तय कर सकती कि उक्त राज्य कर्मचारी के पेशान योग्य हान की सम्भावना पर ध्यान रखते हुए आया पश्चिम का चन्दा वसूल किया जावे अथवा नहीं । यदि उसे चन्दा वसूल करने का नियम लिया जावे तो उसकी गणना निम्नलिखित तरीके से सेवा काल के सदृश की जानी चाहिये —

(क) यदि वह वेतनमान श्रेणी पर हो तो वेतन मान श्रेणी में सब में ऊंचे वेतन के आधार पर

(ख) यदि वह निश्चित वेतन दर पर हो तो उस वेतन के आधार पर ऐसे मामले में अवकाश वेतन के लिये चन्दे को वसूली में कोई कठिनाई उपस्थित नहीं होगी क्योंकि गणित की गणना वदेशिक सेवा में उठाई गई वास्तविक वेतन के आधार पर होगी ।

१ [] शब्दावली सिवाय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विभिन्न गद्यांश स एण्ड १ (३५) एण्ड डा (ए) एल्स/६१ दिनांक ७-२-६२ द्वारा लोपित की गई ।

२ विभिन्न विभाग गद्यांश स एण्ड १ (३५) एण्ड डा (ए) एल्स/६१ दिनांक ७-२-६२ द्वारा जोड़ा गया ।

३ शब्दावली सेवाकाल में तात्पर्य उस समस्त काल से है जो पेंशन वाली सेवा के प्रारम्भ या प्रारम्भ होने की सम्भावित तिथि से चला होता हो जिसमें वह सेवा भी सम्मिलित है जिसका गणना किया जा सका नियम के आधार पर तब के लिये होता है के स्थान पर वित्त विभाग गद्यांश स एण्ड १ (३५) एण्ड डा (ए) एल्स/५८ दिनांक २८ फरवरी, १९५६ द्वारा शब्दावली की गई ।

अवकाश वेतन तथा पेंशन के प्रयोजनार्थ क्रमशः अंशित वेतन तथा अंशित वरिन्विधि की गणना करते समय साक्षरता तथा अन्य भत्तों जो राज्य कमचारियों द्वारा उठाये गये हों, लेखे में सम्मिलित किये जाने चाहियें और उनको धारण किये हुए मौलिक ग्रेड में उच्चतम मासिक वेतन का भाग समझना चाहिये ।

राजस्थान सरकार का निर्णय

१ राजस्थान सेवा नियमों के नियम १८८ के अधीन, ऐसी ग्रन्थायी सेवा जिसकी समाप्ति पर कृटिकरण (क्वैटरमेंट) हो जाय, उसकी आधी मात्रा की गणना पेंशन के लिये की जायगी । ग्रन्थायी सेवा की गणना पेंशन के लिये करने की समावना अधिक् हो गई है । और यह उचित ही है कि ऐस सब मामलों में चंदा वसूल किया जावे । तदनुसार यह निश्चय किया गया है कि जब किसी ग्रन्थायी कमचारी का वदधिक सेवा में स्थानान्तर किया जाय, तो पेंशन का चंदा उसी प्रकार से वसूल किया जावे जिस प्रकार स्थायी राज्य कमचारियों के मामले में किया जाता है । उस ग्रन्थायी राज्य कमचारी के विषय में भी पेंशन के चंदा की वसूली की जायगी जिसका स्थानान्तर वदधिक सेवा में हो गया हो ।

इस प्रश्न पर भी विचार किया गया है आया स्थायी राज्य कमचारियों के विषय में निवे जाने वाले पन्थान चन्दे की दर से कम दर वदशिक सेवा में जाने वाले ग्रन्थायी कमचारियों के लिय निर्धारित की जावे । ऐसी कमी अनावश्यक समझी गई है, क्योंकि कम से कम चन्दे की दर माट तौर पर ही तय की जा सकती है, और ग्रन्थायी कमचारियों के लिये भिन्न आधार बनाने से संका करने में जटिलता आ जायगी ।

परिशिष्ट VI (छठा)

भाग I

चोटों का वर्गीकरण

प्रथम भाग में ऐसी विभिन्न चोटों तथा साधना (devices) का समावेश है जिसमें राज्य कर्मचारी अपने कर्तव्यों के पालन में असमय हो जाता है (राजस्थान सेवा नियम के नियम २६१-क(४)) और जिसके कारण उसको असामान्य पेशन पाने का हक हो जाता है। अग्रे भाग में पेशन के विभिन्न रूप दिये हुए हैं।

अ गभ ग के बराबर हैं—

पश्चात्त जिसमें बोलो बंद न हो।

गले की नली का स्थायी उन्नयन

कृत्रिम मलद्वार

दोनों कानों से पूरा बहरापन।

अत्यंत गंभीर—

मुख के एक तर्फ का पूरा पश्चात्त जिसके स्थायी रहने को संभावना हो।

गुर्दे मूत्र-प्रणाली या मूत्राशय की चोट।

कम्पाउंड फ्रैक्चर (सिवाय अंगुली के पोरों के)

कौमल भागों का अत्यधिक घ्वस जिससे स्थायी शारीरिक अयोग्यता हो जाय या काम करना बंद कर दें।

गंभीर जिनके स्थायी होने की संभावना हो—

निम्नलिखित जोड़ा का एंकाइलोसिस (Ankylosis) या उनके गति में अधिक रुकावट—

घुटना, कुहनी, कंधा, कूल्हा जबड़ा, या रीढ़ के डोर्सलिसिम्बर या प्रीवा सम्बंधी भागों में बंधारता।

एक आंख की दृष्टि में प्राणिक त्रिगुण।

एक अङ्गुली का विनाश या नुस्नान।

बाहरी वस्तुओं का शरीर में भीतर रह जाना, जिसके कोई स्थायी या गंभीर लक्षण न हों।

भाग २

प्रपत्र क

धायल होने के कारण या पेन्शन या उपदान [प्रेचुटो] के लिये

आवेदन-प्रपत्र

- १ प्रार्थी का नाम ।
- २ पिता का नाम ।
- ३ कुल धर्म तथा जाति ।
- ४ निवास स्थान, ग्राम और परगना बताते हुए ।
- ५ मौजूदा या पिछला नियोजन, कमचारी वग के नाम सहित ।
- ६ सेवा प्रारम्भ करने की तारीख
- ७ सेवा काल, अवरोध सहित

उच्च श्रेणी

जिसमें निम्न श्रेणी

अ ग्रहकारी सेवा (Non qualifying)

सेवा में अवरोध

- ८ चोट का वर्गीकरण ।
- ९ चोट लगने के समय वेतन ।
- १० प्रस्तावित पेन्शन या उपदान (प्रेचुटो) ।
- ११ चोट का दिनांक ।
- १२ भुगतान का स्थान ।
- १३ विशेष विवरण, यदि कोई हो
- १४ आवेदन कर्ता के जन्म का दिनांक (ईसवी सै)
- १५ उँचाई ।
- १६ चिन्ह

अगूठे तथा अगुलियों के चिह्न ।

अगूठा, तजनी अगुली, बिचली अगुली, अगूठी वाली अगुली कनिष्ठ अगुली

१७ दिनांक, जिस दिन आवेदन कर्ता ने पेन्शन के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया ।

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर ।

नोट—यूरोपीय महिलाओं राजपत्रित अधिकारियों सरकारी उपाधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों जिन्हें सरकार विनापतया मुक्त करदे, उनके अगूठे तथा अगुलियों तथा अन्यगत चिह्न के विवरण अपेक्षित नहीं है ।

प्रपत्र ख

परिवार पेशान के लिये आवेदन-पत्र का प्रपत्र

स्वर्गीय श्री क ख जो कार्यालय के विशेष जोखम के फनस्वरूप मारा गया, या जिमका हताहत होने से देहात होगया उसवे कुटुम्ब के लिये अमाधारण पेशान के लिये आवेदन ।

प्रस्तुत कर्ता

दावेदार का विवरण —

- १ नाम तथा निवास स्थान, ग्राम तथा परगना बताते हुए ।
- २ आयु
- ३ ऊँचाई
- ४ कुल, जाति या जनजाति
- ५ पहचान के चिह्न ।
- ६ वत्त मान व्यवसाय तथा आर्थिक परस्थितिया ।
- ७ मृतक से सम्बन्ध की डिगरी ।
- ८ नाम
- ९ व्यवसाय तथा नौकरी (सेवा)
- १० सेवा की अवधि ।
- ११ मृत्यु के समय वेतन ।
- १२ आबात की किस्म जिससे मृत्यु हुई ।
- १३ प्रस्तावित पेशान या मंचुटी को राशि ।
- १४ भुगतान का स्थान ।
- १५ तारीख जिस दिन से पेशान प्रारम्भ हानी हो ।
- १६ विशेष विवरण ।

मृतक के पीछे उसके कुटुम्ब वाली क नाम तथा आयु

पुत्र

विधवाए

पुत्रिया

पिता

माता

नोट — यदि मृतक के पीछे कोई सटका, विधवा, पुत्री, पुत्र या माता नहीं हो तो प्रत्येक ऐसे सम्बन्ध के आगे शब्द 'कोई नहीं' या 'मृत' लिख देना चाहिये ।

प्रपत्र ग

मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही

गोपनीय

मेडिकल बोर्ड (त्रिकीर्त्मक मंडल) जो के आदेश में
 द्वारा (आघात लगने का स्थान) पर दिनांक
 " को (आघात लगने का दिनांक) आदि आघात लगने/रोगग्रस्त
 होने की वक्त मान अवस्था की जाच तथा प्रतिवेदन करने के लिये बैठा ।

(क) संक्षेप में आघात/रोगग्रस्त होने की परिस्थितियाँ बताइये ।

(ख) राज्य कर्मचारी की वक्त मान दशा कैसी है ?

(ग) क्या राज्य कर्मचारी की वक्त मान दशा संस्था इस आघात/रोग के कारण ही हुई है ?

(घ) रोगग्रस्त हो जाने की दशा में कौनसी तारीख से राज्य कर्मचारी अयोग्य होना प्रतीत होता है ?

नीचे लिखे प्रश्नों पर मंडल को राय निम्नलिखित है —

भाग क

प्रथम जाच

आघात की गंभीरता निम्नांकित वर्गीकरण तथा नीचे के विशेष विवरण के स्तंभ में दिये गये विवरण के अनुसरण में आनी जानी चाहिये —

(१) क्या आघात	हां	नहीं
१ (क) एक आख या किसी अंग का विनाश होता है ?		
(ख) एक से अधिक आख या अंग का विनाश है ?		
२ एक आख या अंग भंग से अधिक गंभीर है ?		
३ एक आख या किसी अंग भंग के समकक्ष है ?	--	--
४ बहुत गंभीर तथा स्थायी रहने की संभावना है ?		
५ गंभीर तथा स्थायी रहने की संभावना है ?		
६ अत्यंत गंभीर है परन्तु स्थायी रहने की संभावना नहीं है ?		
७ साधारण है परन्तु स्थायी रहने की संभावना है ?		

(२) आघात की तारीख से किस अवधि तक—

(क) राज्य कर्मचारी सरकारी काम करने से अयोग्य रहा ?

(ख) राज्य कर्मचारी सरकारी काम करने के अयोग्य रहेगा ?

परिशिष्ट VII (संतरा)

प्रपत्र क

मृत्यु-तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी के लिये मनोनयन

(जब कि अधिकारी के परिवार हो और उनमें से एक सदस्य को मनोनीत करना चाहता हो।)

मैं एनद द्वारा निम्न लिखित व्यक्ति को, जो कि मेरे परिवार का एक सदस्य है, अधिकार प्रदान करता हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में, सरकार द्वारा स्वीकृत की जाने वाली ग्रेचुटी प्राप्त करले।

मनोनीत व्यक्ति का नाम तथा पता	अधिकारी से सम्बन्ध	हस्ताक्षर	ऐसी घटना जिसके घटने से मनोनयन अवधि हो जायगा	मनोनीत व्यक्ति को मृत्यु अधिकारी की मृत्यु में पहले ही जान की दशा में एक व्यक्ति यदि कोई था का नाम पता तथा सम्बन्ध जिसके हक में मनोनयन करा जायगा।

आज दिनांक " " मास " १९६९ को
स्थान " " " " पर।

हस्ताक्षर के साक्ष्य

१

२,

अधिकारी के हस्ताक्षर

(अ राजपत्रित अधिकारी होने की दशा में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा भरा जायगा)
द्वारा मनोनयन।

पद

कार्यालय

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
दिनांक
पद

१ निम्नलिखित शब्दावली वित्त विभाग आर.सी.एफ. सं० २५ (६) धार/५० दिनांक ११ जून, १९५२ द्वारा नोपित की गई—

२ "वह ग्रेचुटी जो मेरा भ रहन हुए मेरी सेवा निवृत्ति होने पर देय हो और जो मेरी मृत्यु तक कुतानी गप रहे उसको प्राप्त करने का हक।

प्रपत्र-ग

मृत्यु-तथा-रिटायरमेंट प्रेषुटी के लिये मनोनयन (जब अधिकारी कि कोई परिवार नहीं है। और एक व्यक्ति को मनोनीत करता हो।)

मेरे कोई परिवार नहीं होने में, मैं एतद द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति को मनोनीत करता हूँ और अधिकार प्रदान करता हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में सरकार द्वारा स्वीकृति की जाने वाली प्रेषुटी प्राप्त करले।^१

मनोनीत व्यक्ति का नाम व पता	अधिकारी से सम्बन्ध	पाठ	ऐसी घटना जिसके घटने से मनोनयन अवस्य हो जायगा	मनोनीत व्यक्ति की मृत्यु अधिकारी की मृत्यु से पहले हो जाने की दशा में ऐसे व्यक्ति यदि कोई हो, का नाम पता तथा सम्बन्ध जिसके हक में मनोनयन बसा जायगा।
-----------------------------	--------------------	-----	--	---

आज दिनांक

मास

१९६

स्थान

हस्ताक्षर के साथी

१

२

अधिकारी के हस्ताक्षर

(य-राज पत्रित होने की दशा में कार्यालयध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा)

१ ***

द्वारा मनोनयन

पद

कार्यालय

कार्यालयध्यक्ष के हस्ताक्षर

१ निम्नलिखित सम्भावनी वित्त विभाग आदेश स एफ ३५ (६) भाग/५२ दिनांक ११ जून १९५२ द्वारा लोपित —

“वह प्रेषुटी जो सेवा में रहते हुए मेरी सेवा निवृत्ति होने पर देय हो और जो मेरी मृत्यु बुकाने से पहले उसे प्राप्त करने का हक है।

प्रपत्र—घ

[मृत्यु-तथा रिटायरमेण्ट प्रेचुटी के लिये मनोनयन]

(जब कि अधिकारी के कोई परिवार नहीं है और एक से अधिक व्यक्तियों को मनोनीत करता हो ।)

मेरे कोई परिवार नहीं होने से, मैं एतद द्वारा, निम्नलिखित व्यक्तियों को मनोनीत करता हूँ और नीचे निर्धारित की गई सीमा तक उनको अधिकार प्रदान करता हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में सरकार द्वारा जो प्रेचुटी मजूर की जावे वह राशि प्राप्त करल ।^१

मनोनीत व्यक्ति का नाम तथा पता	अधिकारी से सम्बन्ध	प्रत्यक्ष को लिया जाने वाला भाग प्रेचुटी ^२	ऐसी घटनाएँ जिनके घटित होने पर मनोनयन अवध होगा	मनोनीत व्यक्ति की मृत्यु अधिकारी की मृत्यु पहले हो जाने की दशा में जिस व्यक्ति के पक्ष में यह हक चला जायगा उसका नाम पता तथा सम्बन्ध
—				

नोट—प्रतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान पर अधिकारी को तिरछी लकीरें खींच देनी चाहियें ताकि उसके हस्ताक्षर करने के पश्चात कोई नाम जोड़ा नहीं जा सके ।

आज दिनांक _____ मास _____, १९६६
स्थान _____
हस्ताक्षर के साक्षी _____

१

२

अधिकारी के हस्ताक्षर ।

(अ-राजपत्रित अधिकारी होने की दशा में वायानियन्त्रक द्वारा भरा जायगा ।
१ _____ द्वारा मनोनयन ।

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर ।

पद _____ दिनांक _____
कार्यालय _____ बंद

- १ निम्नलिखित गणवली दित्त विभाग अधिसूचक सं० एफ २४ (६) आर/२२ दिनांक ११ जून १९५२ द्वारा घोषित —
'वह प्रेचुटी जो सेवा में रहते हुए मेरी सेवा निवृत्ति होने पर देय हो और जो मेरी मृत्यु तक बुकानी गप रह उसको निम्नलिखित सीमा तक प्राप्त करने का हक ।
- २ नोट—यह वाचक इस प्रकार से भग्ना चाहिये जिसमें प्रेचुटी की बुरा खतम नाम में आजाव ।

प्रपत्र-ड

परिवार पगन वा मनोनयन

म, तत्तद द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियाँ वा, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, नीचे उल्लेखित गण में परिवार पगन प्राप्त करने व लिये मनोनयन करता हूँ जो २६ वर्ष की अधिकारी सेवा सम्पन्न हो जाने के पश्चात् मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में सरकार को दत्त करे।

मनोनयन व्यक्ति का नाम उल्लेख करना	अधिकारी के सम्बन्ध	प्राप्त	घाया विकल्पी है या अघाया

प्रपत्र-व-१

श्री - की, जो विगत में - विभाग
- मन्त्रालय में एक - था, परिवार
पन्शन के लिये आवेदन-पत्र ।

- १ प्रार्थी का नाम ।
- २ मृत्यु राजकीय कर्मचारी/पेंशनारी ।
से सम्बन्ध
- ३ सेवा निवृत्ति का दिनांक, यदि
मृतक पेंशनधारी था ।
- ४ राजकीय कर्मचारी/पेंशनारी ,
को मृत्यु का दिनांक
- ५ क्रमांक जिस पर आवेदनक का नाम
मनोनयन-पत्र प्रपत्र 'ड' में दर्ज है ।
- ६ मृतक के पीछे बाल कुटुम्बियों के नाम
तथा माय
नाम

जन्म का दिनांक
[इसकी से]

(क) विधवा/पति

पुत्र
अविवाहित पुत्रिया
विधवा पुत्रिया

(ख) पिता

माता
भ्रातागण
अविवाहित बहनें
विधवा हुई बहन

७ नाम कोष/उप कोष जहां से भुगतान
प्राप्त करने की इच्छा हो ।

विवरण-पत्र

स्वर्गीय श्री - की
विधवा/पुत्र/पुत्रिया आदि का

(i) जन्म दिनांक (इसकी से)

(ii) ऊँचाई

(iii) व्यक्तिगत चिन्ह यदि

कोई हाथ, मुँह आदि पर हो ।

(१) हस्ताक्षर या बाए हाथ के

अंगूठे तथा अंगुलिया के निशान ।

कनिष्ठिका अंगूठीवाली अंगुली,

बोच की अंगुली, तजनों, अंगूठा ।

६ प्रार्थी का पूरा पता ।

तत्सदीक वर्त्ता—

साक्ष्य—

(१)

(१)

(२)

(२)

टिप्पणी

१ विवरण पत्र तथा हस्ताक्षर/अंगूठे तथा अंगुली के चिह्न जो परिवार पेंशन के आवेदन पत्र से संलग्न हो व दो प्रतियों में होने चाहिये और प्रार्थी के निवास स्थान के नगर ग्राम या जिले के दो या अधिक आदरणीय व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित होने चाहिये ।

२ यदि प्रार्थी क्रमांक ६ (ख) में उल्लेखित वर्गीकरण में आता हो तो उसको मृतक राजकीय कर्मचारी/पensionधीन पर अपनी निभरता का सबूत प्रस्तुत करना चाहिये ।

३ यदि प्रार्थी राजकीय कर्मचारी/pensionर का अवयस्क आता हो तो क्रमांक ८ (१) के सामने प्रकृत लघु का पुष्टिकरण आयु के प्रमाण पत्र (सबब) स होना चाहिये और उसके साथ प्रार्थी की आयु बनाने वाली दो प्रमाणित प्रतियां हानी चाहिये । आवश्यक तत्सदीक के पश्चात् असल प्रमाण पत्र प्रार्थी को लौटा दिया जायगा ।

प्रपत्र छ

ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जाने वाला घोषणा-पत्र जिसको प्रत्याशित मृत्यु तथा रिटायरमेंट प्रेचुटी स्वीकृत हुई है

चू कि

अधिकारी का पद लिखिये] मुझे श्री

(यहां अग्रिम राजि स्वीकृत करने वाल

बंध उत्तराधिकारी के रूप में) सरकार द्वारा मृत्यु तथा रिटायरमेंट देय प्रेचुटी निश्चित

करने के लिये आवश्यक जांच पूरी होने के प्रत्याशन में फिलहाल रु०) अग्रिम देने

की स्वीकृति देने को राजी हुए हैं, मैं एतद द्वारा स्वीकार करता हूँ कि इस अग्रिम राजि

को स्वीकार करने में, मैं पूर्णतया समझता हूँ कि मुझ को देय मृत्यु तथा रिटायरमेंट

प्रेचुटी आवश्यक औपचारिक जांच के पूरी होने पर परिवर्तनशील है, और मैं वायदा

१ वित्त विभाग आदेश स एफ ३५ (६) आर/६२ दिनांक ११ जून, १९५२ द्वारा जोड़ा गया ।

१ वित्त विभाग की धाना स एफ ३३ [६] आर/५२ दिनांक ११ जून १९५२ द्वारा प्रत्याशित किया गया ।

२ नोट — बोधक में निम्न बातें जो सामान्य नहीं होने से उल्लिखित किये गये हैं :

करता है कि ऐसे परिवर्तन जो राशि अन्तर्ग स्वीकृत हो उस पर मैं मृत्यु तथा रिटायर-
मेन्ट की प्रत्याशित ग्रेचुटी के आधार पर कोई आपत्ति नहीं उठाऊंगा। मैं यह भी
बायदा करता हूँ कि मृत्यु तथा रिटायरमेन्ट ग्रेचुटी जो अतत मुझे स्वीकृत हो, अग्रिम
दी गई राशि से कम होगी तो बड़ी हुई राशि वापिस चुका दूंगा।

हस्ताक्षर के गवाहान (पते सहित)

१ हस्ताक्षर
२ — पद
(राजकीय कर्मचारी का)

स्थान
दिनांक

प्रपत्र छछ

आवेदन—यत्र मृत्यु तथा रिटायरमेन्ट ग्रेचुटी/शेष ग्रेचुटी प्रदान करने के लिये
विभाग में स्वर्गीय श्री/श्रीमती के परिवार हेतु।

- १ प्रार्थी का नाम।
- २ स्वर्गीय राजकीय कर्मचारी/पेंशनधारी से सम्बन्ध।
- ३ जन्म का दिनांक।
- ४ यदि पेंशन धारी था तो उसके सेवा निवृत्ति का दिनांक।
- ५ राजकीय कर्मचारी/पेंशनधारी की मृत्यु का दिनांक।
- ६ नाम कोष/उप-कोष जहाँ में भुगतान लेने का इन्दुर है।
- ७ प्रार्थी का पूरा पता।
- ८ प्रार्थी का हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह।
- ९ तसदीक कर्ता।

(i)

(ii)

१० साक्षी —

नाम	पूरा पता	हस्ताक्षर
(i)		
(ii)		

१ वित्त विभाग आता ग एफ ७ (ए) (८१) एफ डा ए/ब्ल/५७-१ दिनांक १ मार्च
१९६० द्वारा जोड़ा गया।

२ तत्प्राक्त प्रार्थी के निवास स्थान के तम्र नाम या परमने म स्थित दा या अथवा अन्य
साम्य व्यक्तियों द्वारा की जाना चाहिये।

प्रपत्र ज^१

प्रावेदन—पत्र पेशन या ग्रेचुटी के लिये [तथा मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी] के लिये ।

- १ प्रार्थी का नाम ।
- २ पिता का नाम (तथा महिला राजकीय कमचारी होने की दशा में उसके पिता का नाम भी)
- ३ धर्म तथा राष्ट्रियता
- ४ स्थायी निवास का पता, ग्राम/नगर, जिला तथा राज्य बताते हुए ।
- ५ वत्त मान या पिछली नियुक्ति, कमचारी वर्ग का नाम सहित ।
- ५क वत्त मान या पिछली मौलिक नियुक्ति ।

६ सेवा काल के प्रारम्भ का दिनांक ।

७ सेवा—समाप्ती का दिनांक ।

(क) सैनिक सेवा का कुल काल

प्रत्येक सैनिक सेवा काल के प्रारम्भ

का दिनांक

(ख) सरकार जिसके अधीन सेवा की

गई नियोजन के क्रम में ।

८ सेवा की अवधि, अवरोधो

तथा अ-अहकारी अवधिया के विवरण सहित वर्ष, मास दिन

९ आवेदित पेशन या ग्रेचुटी का वर्ग तथा

आवेदन का कारण ।

१० औसत उपलब्धिया ।

११ प्रस्तावित पेशन ।

१२ प्रस्तावित ग्रेचुटी ।

(क) प्रस्तावित मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी ।

१३ तारीख जिस दिन से पेशन प्रारम्भ होनी हो ।

१४ भुगतान का स्थान ।

१ वित्त विभाग चापन स एफ ७ ग (४१) एफ डी/ए/ क्लर्क/५६-१४ दिनांक १९६६ तथा वित्त विभाग आन्ना स एफ ७ ग[४१] एफ डी/क्लर्क/५६ दिनांक २२-११-१९६६ जाड़ा गया ।

(सरकारी कोष या उप-कोष)

[क] पेंशन नियम जो विकल्पित हैं। जिसका पात्र है।

[ख] मनोनयन किस के लिये किया—

[१] पारिवारिक पेंशन के लिये या

[२] मृत्यु तथा—रिटायरमेंट ग्रेचुटी के लिये

११ प्रार्थी का जन्म दिनांक [ईसवी से]

१६ ऊँचाई

१७ पहचान चिन्ह—

[क] अगूठे तथा अगुलियों के चिन्ह

अगूठा	तजनी	बीचवाली अगुली	अगूठीवाली अगुली	कनिष्ठअगुली
-------	------	------------------	--------------------	-------------

नोट—जिन व्यक्तियों के लिये इस आवेदन-पत्र के साथ पास पोर्टे आकृति की फोटू की प्रमाणित प्रतियाँ प्रेषित करनी अपेक्षित हो और यदि वे अपना नाम अंग्रेजी हिन्दी या क्षेत्रीय सरकारी भाषा में हस्ताक्षर करने हेतु पर्याप्त शिक्षित हो तो वे बाएँ हाथ के अगूठे तथा अगुलियाँ के चिन्ह अंकित करने से मुक्त होंगे।

१८ तारीख जिस दिन प्रार्थी ने पेंशन के लिये आवेदन किया।

हस्ताक्षर कार्यालयध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।

१ राजपत्रित राजकीय कमचारी, सरकारी उपाधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों को जिनको सरकार विशेष तथा मुक्त करदे, ऊँचाई तथा व्यक्तिगत चिन्ह के विवरण देना अपेक्षित नहीं है।

[क] प्राप्त करने वाले प्राधिकारी के रिमाक्स [अभ्युक्ति]

१ प्रार्थी के चरित्र तथा पिछले आचरण के विषय में।

२ किसी निलम्बन या पदावनति का स्पष्टीकरण।

३ प्रार्थी द्वारा कोई ग्रेचुटी या पेंशन पहले से ही प्राप्त करने के विषय में।

४ कोई अन्य विवरण।

५ प्राप्त कर्ता प्राधिकारी कि निश्चित राय आया जिस सेवा का दावा किया गया है वह साबित है और उसे माना जावे या नहीं [देखिये नियम १८६ [१] तथा २६१ [क] [१]]

[ख] पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की आज्ञा ।

अधोहस्ताक्षर कर्ता को सतोष हो जान पर कि श्री/श्रीमती/कुमारी की सेवा पूरातया सतोषजनक थी एतद द्वारा ऐसी पेंशन तथा/या ग्रंथुटी प्रदान करने की आज्ञा देता है जो महालेखाधिकारी नियमा के अन्तगत देय होना स्वीकार करे । इस पेंशन तथा/या ग्रंथुटी की स्वीकृती से प्रभावशील होगी ।

१ शेष देनदारी निर्धारित की जाने तथा मृत्यु-तथा-रिटायरमेंट ग्रंथुटी में से समायोजन [adjustment] हो जाने तक, लेखे
स्पष्ट) की राशि रोकली जावे ।

अथवा

अधोहस्ताक्षर कर्ता को सतोष हो जान में कि श्री/श्रीमती/कुमारी की सेवा पूरातया सतोषजनक नहीं है । एतद द्वारा आज्ञा देता है कि जो पूरी पेंशन तथा/या ग्रंथुटी नियमा के अन्तगत महालेखाधिकार देय होना स्वीकार करे, वह निम्नलिखित निश्चित राशिया से या प्रतिशत पर कम कर दी जावे —

पेंशन में कम की जाने वाली राशि या प्रतिशत
ग्रंथुटी में कम की जाने वाली राशि या प्रतिशत
इस पेंशन तथा/या ग्रंथुटी का प्रदान
से प्रभावशील होगा ।

१ शेष देनदारी निर्धारित की जाने तथा मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रंथुटी में से समायोजना [adjustment] हो जाने तक, लेखे ह]
की राशि रोकली जावे ।

पेंशन और मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रंथुटी कीप पर
मुग्तान की जावेगी और से
से व्यय हागी ।

यह आज्ञा इस शत के आधीन है कि यदि महालेखाधिकार द्वारा प्राधिकृत पेंशन तथा/या ग्रंथुटी की राशि उस राशि से ब्राद में अधिक होनी पाई जावे जितनी कि प्रार्थी नियमानुसार पाने का हकदार है तो उसे अतिरिक्त राशि वापस लौटानी हागा । यह शत स्वीकार करने की घोषणा उक्त अधिकारी में प्राप्त करनी गई है/यह शत स्वीकार करने की घोषणा उक्त अधिकार से प्राप्त करली जावेगी और पथक प्रेषित कर दी जावेगी ।

नोट — पापन स एक ७ ए (४१) एक डी /ए/कलम/ ५६ ग्लान १ ३ १८६० के अनुच्छेद ४ के उप अनुच्छेद (1) तथा (11) में प्रावधान की हुई जमानत अवका उपबन्धन नकल जमा प्राप्त नहीं होन का दगा में भरा जाव ।

पेंशन स्वीकार करन वाल प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा पत्र ।

(ग) ऑडर (लेखा परीक्षा विभाग) द्वारा एन फेममेट (लेखा)

१ अधिवापिक (सुपर एन्प्लूएशन)/सेवा निवृत्ति/शारीरिक अयोग्यता (इनवैलिड) मुआवजा/मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी प्रदान करने के लिये, ग्रहकारी सेवा की कुल अवधि जो मानी गई यदि कोई अमान्य है तो उसके कारणों सहित अमान्य के अति रिक्त, यदि कोई हो तो उसके कारणों सहित जो ऑडिट द्वारा द्वितीय पृष्ठ में अभिलेखित है।

नोट—१ दिनांक से प्रारम्भ होने वाली तथा सेवा निवृत्ति की तारीख तक का सेवा काल अभी तक तस्दीक नहीं किया है, पेंशन भुगतान आज्ञा जारी करने से पूर्व यह तस्दीक कर लिया जावे।

२ वह अधिवापिक (सुपर एन्प्लूएशन)/सेवा निवृत्ति/ शारीरिक अयोग्यता/मुआवजा/पेंशन/मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी जो की माय राशि

३ वह राशि जो अधिवापिक/सेवा निवृत्ति/शारीरिक अयोग्यता/मुआवजा पेंशन मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी में पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा पेंशन तथा ग्रेचुटी में कमी करने हेतु लेखे में ली गई।

४ तारीख जब से अधिवापिक/सेवा निवृत्ति/ शारीरिक अयोग्यता/मुआवजा पेंशन/मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी माय है।

५ लेखे का शीर्षक जिसमें से अधिवापिक/सेवा निवृत्ति/पेंशन/मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी भुगतान की जायगी।

महानेखापाल

नोट—यदि ग्रहकारी सेवा अधिकतम पेंशन प्राप्त करने के लिये पर्याप्त अवधि में अधिक होना प्रमाण—पत्र में - वर्षों से अधिक के लिये प्रमाणित इस प्रकार लिखा जा सकता है। (वर्षों की संख्या वह लिखी जावे जो अधिकतम पेंशन प्रर्जित करने के लिये अपेक्षित हो)।

[जो बात लागू न हो वह लोपित कर दी जावे]

पेंशन अवकाश ग्रेचुटी और मृत्यु-तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी के लिये आवेदन पत्र

नोट—यदि ग्रहकारी सेवा अधिकतम पेंशन प्राप्त करने के लिये पर्याप्त अवधि में अधिक होतो प्रमाण पत्र - वर्षों से अधिक के लिए प्रमाणित —इस प्रकार लिखा जा सकता है। (वर्षों की संख्या वह लिखी जावे जो अधिकतम पेंशन प्रर्जित करने के लिये अपेक्षित हो)।

(जो बात लागू न हो वह लोपित कर दी जावे ।)

१ वित्त विभाग पापन में एक ७ ए (४१) एक डी /ए/कम्स/ ५६ १८ दिनांक ११ ७ ६०) तथा वित्त विभाग आदेश में एक ७ ए (४१) ए डी/ए/कम्स/५८ दिनांक २१ ११-६०) द्वारा स्थानापन्न किया गया।

आवेदन की तारीख
 प्रार्थी का नाम ।
 पिछली नियुक्ति ।
 पेन्शन या ग्रेचुटी का वर्ग ।
 स्वीकृती प्रदान करने वाला प्राधिकारी ।
 स्वीकृत पंशन राशि ।
 स्वीकृत ग्रेचुटी की राशि ।
 स्वीकृत मृत्यु-तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी ।
 राशि ।
 प्रारम्भ होने की तारीख ।
 स्वीकृति की तारीख ।

हस्ताक्षर ।

परिशिष्ट VII -रू (मातर्मा-रू)

पेशन के लिए औपचारिक आवेदन-पत्र

आर स

सेवा में

विषय —पेशन स्वीकृत हेतु आवेदन

मायवर,

मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि मेरा जन्म दिवस का होने सँ, मैं, दिनांक " को सेवा निवृत्त होने वाला हूँ । अतः मैं प्रार्थना करता हूँ कि उचित कायवाही कराने की अनुकम्पा करें जिससे मेरी सेवा निवृत्ति होने की तारीख तक मुझे देय पेशन तथा प्रेचुटी स्वीकृत हो सके । मैं कोष से मेरी पेशन उठाने का इच्छुक हूँ ।

२ मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने अब तक किसी ऐसी पेशन या प्रेचुटी के किसी भाग के लिए आवेदन नहीं किया है जिसके लिए मैंने इस आवेदन पत्र द्वारा पेशन तथा/ या प्रेचुटी को माग की है न मैं इसके बाद भी इस आवेदन-पत्र तथा इस पर जारी किय गये आदेशों का हवाला दिये बिना कोई आवेदन प्रेषित नहीं करूँगा ।

३ मैं निम्नलिखित सलग्न करता हूँ —

(१) दस नमूने के मेरे हस्ताक्षर, विधिवत प्रमाणित,

२ (२) एक पासपोर्ट आकार की फोटो, वह भी विधिवत प्रमाणित,

३ (३) दो पंचिया जिसमें प्रत्येक में मेरे बाएँ हस्त क अंगूठे तथा अंगुलिया के चिन्ह हैं ।

४ मेरा वर्तमान पता " है और सेवा निवृत्ति के पश्चात् पता होगा ।

दिनांक —

हस्ताक्षर
पद

१ वित्त विभाग कार्यालय आपन स०एफ ६ए (४१) एफ । डी । ए । क्लर्क दिनांक १-३-१९६० द्वारा जोड़ा गया ।

२ राजपत्रित अधिवारी होने की दशा में यह आवश्यक नहीं है ।

३ यह केवल उन व्यक्तियों के लिये अपेक्षित है जो अनपढ़ हैं और अपन नाम का हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं ।

४ इस पत्र पश्चात् पता परिवर्तन की सूचना कार्यालयाध्यक्ष को दनी चाहिये ।

परिशिष्ट VII स (सातवां स)

१ जमानत का प्रपत्र

राजस्थान के राज्यपाल की (जो आगे 'भरकार' कहा गया है तथा जिस शब्द में उसके उत्तराधिकारी तथा अभिहस्ताक्षरिता सम्मिलित होंगे) श्री / श्रीमता

का मावजनिक निमाण विभाग के अधिकारियों से कोई माग नहीं होने का प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत किये बिना अंतिम हिसाब चुकाने के लिए सहमति होने के कारण, कथित

द्वारा उसको अभी धावटन किये गये । आवास गृहों के लिये तथा समय समय पर कथित को धावटन किये गये । आवास गृहों के सम्बन्ध में किराया तथा अन्य देय राशियों के भुगतान के लिये मैं एतद् द्वारा जामिन खड़ा होता हूँ (इस कथन में मेरे उत्तराधिकारी निष्पादक गण तथा प्रशासक गण सम्मिलित हैं) । मैं जामिन, सहमत होता हूँ और यह भी इकरार करता हूँ कि उपरोक्त आवास गृहों का खाली बन्ना सरकार को हस्तांतरित नहीं कर दिया जावे तब तक मैं समस्त हानि और क्षति की पूर्ति सरकार का करने का इकरार करता हूँ ।

मैं एतद् द्वारा, उन राशियों के लिए भी जामिन खड़ा हूँ जो कथित श्री—

द्वारा सरकार को अधिक वेतन भत्ता अवकाश-वेतन दिये जाने से या वाहन भवन निर्माण अथवा अन्य प्रयोजन के लिए दिये गये प्रग्रिम के कारण या कोई अन्य माग के रूप में देय हो ।

मेरे द्वारा ग्रहण दायित्व सरकार द्वारा अवधि या कोई अन्य मागे बढ़ाने में समाप्त नहीं होगा तथा निम्नी अन्य प्रकार से प्रभावित नहीं होगा ।

मेरे द्वारा ग्रहण दायित्व अवधि बढ़ाने से तथा सरकार द्वारा कथित—

को कोई अन्य अनुग्रह प्रदान से समाप्त नहीं होगा न किमी भी प्रकार से प्रभावित होगा ।

यह गारंटी तब तक जारी रहेगी जब तक कि—

(i) कथित के पक्ष में सावजनिक निर्माण विभाग 'कोई माग नहीं का प्रमाण पत्र' जारी नहीं करदे तथा

(ii) वह कार्यान्वयाध्यक्ष जिसके कार्यालय में कथित — " नियोजित था और यदि वह राजपत्रित राज्य अधिकारियों के विल के प्रपत्र पर बनन तथा भत्ता उठाता था/उठाती थी, उन दशा सम्बन्धित लेखा परिक्षण अधिकारी (आडिट अधिकारी गण) यह प्रमाणित नहीं करद कि कथित द्वारा सरकार को अब कोई देय भेष नहीं है ।

इस लिखित पर स्टाम्प शुल्क सरकार वहन करेगी । -

जामिन के हस्ताक्षर

व्यक्ति जामिन द्वारा हस्ताक्षर किया गया तथा दिया गया । स्थान
पर आज दिनांक मास को, निम्न लिखितों की उपस्थिति में

१ हस्ताक्षर

साक्षी का पता तथा व्यवसाय

"

२ हस्ताक्षर

"

साक्षी का पता तथा व्यवसाय

"

"

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्री मती एक स्थायी
राजकीय कर्मचारी है ।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर,

अथवा कार्यालयाध्यक्ष के जहाँ जामिन काम करता है । उपरोक्त जमानत
नामा स्वीकार किया जाता है ।

हस्ताक्षर

पद

(राजस्थान के राज्यपाल के वास्ते या ओर से)

परिशिष्ट VII - ग (मातृगं ग)

प्रपत्र "क"

ऐसे मामलो मे मृत्यु-तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी/शेष ग्रेचुटी के लिये प्रपत्र, जिनमे वैध मनोनयन किया हुआ हो ।

स०

राजस्थान सरकार

विभाग

दिनांक

विषय — मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी/शेष ग्रेचुटी का भुगतान स्वर्गीय श्री/श्री मती के विषय मे ।

महोदय

मुझे यह व्यक्त करने का निदेशन है कि कार्यालय/विभाग में
एक " " का कार्य करने वाले स्वर्गीय श्री/श्री मती

द्वारा किये गये मनोनयन की शर्तों के अनुसार, एक मृत्यु-तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी/शेष ग्रेचुटी उसके मनोनीत व्यक्ति (व्यक्तियों) को देय है । कथित मनोनयन पत्र की एक प्रतिलिपि सलग्न है ।

२ मुझे यह निवेदन करना है कि मृत्यु तथा-रिटायरमेंट ग्रेचुटी प्रदान करने हेतु सलग्न प्रपत्र 'छ छ' में यथा सम्भव शोधातिशीघ्र एक औपचारिक दाव (क्लेम) आप प्रस्तुत करें ।

३ मनोनयन करने के पश्चात यदि कोई ऐसी घटना हो गई हो जो मनोनयन की पूर्णतया या आंशिक रूप से अवैध बना दे, तो कृपया उस घटना का ठीक विवरण व्यक्त करें ।

वास्ते

भवदीय

प्रपत्र ख'

मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी/शेष ग्रेचुटी के लिये प्रपत्र ज वकि वैध
मनोनयन किया हुआ न हो

सम्या

राजस्थान सरकार

विभाग

दिनांक ***

विषय — मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी/शेष ग्रेचुटी का भुगतान स्वर्गीय
श्री/श्रीमती के विषय में

महोदय

मुझे यह व्यक्त करने का निदेशन हुआ है कि वित्त विभाग के ज्ञापन सं०
डी० ३५६१/५७/एफ ७ ए (१०) एफ० डी०/ए/कलस, ५७ दिनांक १६-६ ५७ के
अनुसार कार्यालय/विभाग के विग श्री/श्रीमती के परि-
वार के निम्नलिखित सदस्यों का सम भागो में मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी/शेष
ग्रेचुटी देय है —

(i) धर्मपत्नी/पति

(ii) पुत्रगण

सीतेले बालको सहित

(iii) अविवाहित पुत्रिया

२ यदि उक्त परिवार में ऊपर लिखे में से कोई जीवित सदस्य न हो तो
मृत्यु-तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी/शेष ग्रेचुटी, परिवार के निम्नलिखित सदस्यों को सम
भागो में देय होगी —

(i) विधवा पुत्रिया ।

(ii) १८ वर्ष से कम आयु का भ्राता तथा अविवाहित या विधवा बहनें ।

(iii) पिता, माता

(iv) भ्राता

३ निवेदन है कि मृत्यु तथा रिटायरमेंट ग्रेचुटी/शेष ग्रेचुटी का औपचारिक
दावा [क्लेश] संलग्न प्रपत्र छ छ में यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित किया जावे ।

दिनांक

भवदीय ।

प्रपत्र 'ग'

परिवार पेंशन का प्रपत्र जबकि वैध मनोनयन मौजूद हो

सं०

राजस्थान सरकार ।

विभाग

दिनांक

विषय —श्री/श्रीमती
का भुगतान ।

के विषय में परिवार पेंशन

महोदय

मुझे यह व्यक्त करने का निदेशन हुआ है कि स्वर्गीय श्री/श्रीमती
विभाग में विगत (पद) द्वारा किये गये मनोनयन की शर्तों के अनुसार
और उसका/उसकी मनोनीत होने के रूप में आपको परिवार पेंशन देय है।

२ तदनुसार मुझे सुझाव देना है कि आप सलग्न प्रपत्र 'घ' में यथासम्भव
शीघ्रातिशीघ्र औपचारिक क्लेम (भाग) स्वीकृति हेतु प्रेषित करें।

६ मनोनयन करने के पश्चात् यदि कोई ऐसी घटना हो गई हो/जो मनोनयन
को पूर्णतया या आंशिक रूप से अवैध बनादे, तो कृपया उस घटना का ठीक विस्तृत
विवरण व्यक्त करें।

भवदीय,

वास्ते

प्रपत्र 'घ'

परिवार पेंशन का प्रपत्र जबकि वैध मनोनयन मौजूद न हो

सं०

राजस्थान सरकार

विभाग

दिनांक -

विषय —श्री/श्रीमती
का भुगतान ।

के विषय में परिवार पेंशन

महोदय,

मुझे यह व्यक्त करने का निदेशन हुआ है कि
(पद) स्वर्गीय श्री/श्रीमती

विभाग के विगत
के परिवार को

न देय है। मनोनयन के अभाव में राजस्थान सेवा नियमों के नियम २६५ के
१८, परिवार पेंशन निम्नलिखितों को देय है।

- (क) (i) ज्येष्ठतम जीवित विधवा को या पति को,
 (ii) विधवा/पति नहीं होने की दशा में ज्येष्ठतम जीवित पुत्र को ।
 (iii) यदि (i) तथा (ii) न हो तो ज्येष्ठतम जीवित अविवाहित पुत्री को,
 (iv) ये कोई भी न हो तो, ज्येष्ठतम विधवा पुत्रीको और

(ख) यदि उपरोक्त उपखंड (क) के अधीन कोई परिवार पेंशन देय नहीं हो तो—

- (i) पिता को
 (ii) पिता न हो तो माता को
 (iii) पिता तथा माता भी न हो, तो १८ वर्ष से कम आयु वाले जीवित भ्राता को,
 (iv) ये भी न हो तो ज्येष्ठतम जीवित अविवाहित बहन को,
 (v) कोष्ठक (i) से (iv) विफल रहे तो, ज्येष्ठतम जीवित विधवा बहन को ।

उपरोक्त उपखण्ड (ख) में उल्लिखित किसी व्यक्ति को परिवार पशन ऐसे उपयुक्त सबूत प्रस्तुत किये बिना नहीं मिलेगी कि वह व्यक्ति अपने निर्वाह के लिये स्वर्गीय पर निर्भर था ।

२ मुझे यह सुझाव देना है कि परिवार पशन हेतु यदि उपरोक्त वर्गीकरण के अनुसार आपका प्राथमिक हक हो तो आप सलमन प्रपत्र च' में औपचारिक दावा (क्लेम) प्रेषित करें । आपको निवेदन है कि आप इस विषय का एक हलफनामा भी प्रस्तुत करें । उपरोक्त क्रम में आपसे पहले स्थान पाने वाली श्री के परिवार में कोई सदस्य जीवित नहीं है । आपकी यह समझ लेना चाहिये कि इस विषय में यदि कोई असत्य सूचना अथवा घोषणा दी गई, तो आप कानूनी कार्यवाही के भागी बनेंगे, यदि उपरोक्त वर्गीकरण के प्रकाश में, यदि आपका परिवार पेंशन के लिये कोई प्राथमिक हक न हो तो आपसे निवेदन है कि आप ऐसे व्यक्ति के नाम, पते तथा उक्त मृतक से सम्बन्ध की सूचना भेजें, जो आपकी जानकारी के अनुसार पेंशन का प्राथमिक हक रखता हो तथा उस यह पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु आगे भेज दें ।

भवदीय

परिशिष्ट = (आठवां)

प्रपत्र क

असैनिक पेशन का कम्प्यूटेशन [परिवर्तन]

मे मेरी पशन के रु []' र []'
प्रतिमास मे कम्प्यूट (परिवर्तन) कराने का इच्छुक हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैने नीचे के सब प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया है।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
पद
पता

प्रश्न

- १ आपकी जन्म तारीख क्या है ?
- २ आप अपनी कितनी पेशन कम्प्यूट करवाना चाहते हैं ?

नोट

पेशन प्रत्याशित होने की दशा में पेशनधारी, यदि चाहे तो अपनी इस इच्छा का सबैत भी दे सकेगा कि उसकी ■ तिम पेशन, प्रत्याशित पेशन से अधिक होने की दशा में कम्प्यूट (परिवर्तन) कराना चाहेगा।

यदि पेशनधारी रुपये २५) के अधिक राशि कम्प्यूट कराना चाहता हो तो उस दशा में वह यह भी संकेत दे सकता है कि आया वह यह प्रत्याशा करता है कि पेशन की वह प्र तिम राशि जो वह कम्प्यूट करान का हक्दार है रुपये २५) से अधिक हो सकती है।

- ३ (क) क्या आपने अपनी पशन का कोई अश पहल से ही कम्प्यूट करा रखा है। यदि हाँ तो विवरण दीजिये।

(ख) क्या कभी आपका कम्प्यूटेशन का आवेदन पत्र खारिज किया गया या क्या कभी चिकित्सा प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर आपकी वास्तविक आयु में वय जोड़े जाने से

१ वित्त विभाग आदेश सं एफ १ [१०] [एकथ-रुलस]/६७ दिनांक २० १२ ६७ द्वारा विलोपित।

२ वित्त विभाग आदेश सं डी १०५७/५६ एफ ७ ए [ii] एफ डा [ए] रुलस ५८ तथा पापन सं २४६७/५६/एफ ७ ए [i] एफ वो [ए] रुलस/५८ II दिनांक नमस १ जून ५६ तथा १० अगस्त, ५६ द्वारा जोड़ा गया।

आपने पेंशन कम्प्यूटेशन कराना स्वीकार किया था/अस्वीकार किया था ? यदि ऐसा है तो विवरण दीजिये ।

- ४ किस कोष से आप अपनी पेंशन या कम्प्यूटेशन राशि प्राप्त करना चाहते हैं ?
- ५ यदि आप अपनी पेंशन पहले से ही उठा रहे हैं, तो पेंशन भुगतान आज्ञा या कोलोनियल धारट की सच्चा लिखिये ।
- ६ स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी के स्व-विवेक को बिना प्रभावित किये, इस कम्प्यूटेशन को आप किस दिनांक से चालू कराना चाहते हैं ? (असैनिक पेंशन नियम देखिये)
- ७ कौन से स्थान (आपके सामान्य निवास क्षेत्र के निकट) पर आप अपनी मेडिकल परीक्षा कराना चाहेंगे ?

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

[कार्य प्रक्रम हिदायत १ (१) द्वारा शासित मामलों में प्रयोज्य हेतु]

को प्रतिवेदन हेतु प्रेषित

(यहां लेखधिकारी का पद तथा पता लिखिये)

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

पद

नोट

*पेंशन का यह भाग जो कम्प्यूट कराना है, पूरे रूपों में होना चाहिये । []

भाग २

को प्रेषित

(यहां स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी का पद तथा पता लिखिये)

२ चिकित्सक प्राधिकारी की कम्प्यूटेशन से सम्बन्धित सिफारिश के अधीन रहते, एक मुश्त देय राशि निम्नलिखित होगी —

१ वित्त विभाग आदेश सत्या ४७५२/एफ ७ ए (३) एफ डी (ए) हस्त/५७ दिनांक ३० ५७ द्वारा जोड़ा गया ।

२ वित्त विभाग आदेश सत्या एफ १ (१०) एफ डी (एकम नियम) ६७ दिनांक २० १२ ६७ द्वारा हटाया गया ।

भुगतान योग्य राशि यदि वॉम्पूटेशन प्रार्थी के अगले जन्म दिवस तक [जो दिनांक को आता है] पक्का हो जाय

सामान्य धातु के आधार पर	
अर्थात्	वप ह
” ”	जिसमें जोड़िये
१ वप अर्थात्	वप ह
” ”	जिसमें जोड़िये
२ वप अर्थात्	वप ह
” ”	जिसमें जोड़िये
३ वप, अर्थात्	वप ह
” ”	जिसमें जोड़िये
४ वप, अर्थात्	वप ह
” ”	जिसमें जोड़िये
५ वप, अर्थात्	वप ह

भुगतान योग्य राशि यदि कम्प्यूटेशन प्रार्थी के अगले जन्म दिवस तक पक्का होजाय परंतु उससे एव नै सिवाय अगले जन्म दिवस से पूर्व

सामान्य आयु के आधार पर	
अर्थात्	वय रु
”	इसमे जोड़िये
१ वय, अर्थात्	वय रु
”	इसमे जोड़िये
२ वय, अर्थात्	वय रु
”	इसमे जोड़िये
३ वय, अर्थात्	वय रु
”	इसमे जोड़िये
४ वय, अर्थात्	वय रु
”	इसमे जोड़िये
५ वय अर्थात्	वय रु

३. देय राशि निम्नलिखित पर प्रभार होगा —
केन्द्रीय राजस्व

की सरकार

(राज्य सरकार)

स्थान

दिनांक

लेखाधिकारी के हस्ताक्षर तथा पद

भाग ३

उपरोक्त कम्यूटेशन के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस प्रपत्र के भाग २ के अनुच्छेद २ की एक प्रमाणिक प्रति प्रपत्र ख पर आवेदक को भेज दी गई है।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

पद

१ मूल दिनांक को [यहा मुख्य प्रशासनिक चिकित्सक अधिकारी का पद तथा पता लिखिये]
को

प्रेषित करके निवेदन है कि वह प्रार्थी को डाक्टरों जाच उचित चिकित्सक प्राधिकारी द्वारा दिनांक से तीन मास के भीतर यथा सभव शीघ्राति [यहा दिनांक लिखिये]

शीघ्र कराने की व्यवस्था करे परन्तु दिनांक से पहले [यहा सेवा निवृत्ति का दिनांक लिखें]

नही करावे और प्रार्थी को पर्याप्त समय देकर सूचना सूचित करें कि उसे कहा तथा किम स्थान पर जाच हेतु उपस्थित होना चाहिये ।

२ आवेदक का आगामी जन्म दिवस को आता है । और उसका डाक्टरों जाच उस दिनांक से पूर्व परन्तु स्वीकृती आज्ञा में निर्धारित अवधि के भीतर कराने की व्यवस्था करें ।

स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा पद

प्रपत्र ख

भाग १

चिकित्सक प्राधिकारी की कम्प्यूटेशन करने की सिफारिस के अधीनस्थ रहते तथा इस प्रपत्र के भाग १ में निर्धारित शर्तों के अधीन रहते, एक मुश्त भुगतान योग्य राशि निम्ननुसार होगी —

भुगतान योग्य राशि यदि कम्प्यूटेशन प्रार्थी के आगामी जन्म दिवस से पहले पक्का होजाय जो दिनांक को आता है ।

सामान्य आयु के आधार पर अर्थात्	वय रु
१ वय, अर्थात्	वय रु
२ वय, अर्थात्	इसमें जोड़िये वय रु
३ वय, अर्थात्	इसमें जोड़िये ३ वय रु
४ वय, अर्थात्	इसमें जोड़िये ४ वय रु
५ वय, अर्थात्	इसमें जोड़िये ५ वय रु
६ वय, अर्थात्	इसमें जोड़िये ६ वय रु

१ जब आगामी जन्म दिवस निर्धारित दिनांक से बाद में आता है तो इसे काट दिया जाय ।

२ एक वापी फाम सी को और एक एकरी कोपी इसी फाम की बाड III की साथ ।

भुगतान योग्य राशि यदि कम्प्यूटेशन	सामान्य आयु के आधार पर
प्रार्थी के आगामी जन्म दिवस के बाद	अर्थात् - वष र
पक्का हो जावे परन्तु एक के सिवाय	” ” इसमें जोड़िये
अगले जन्म दिवस से पहले	१ वष, अर्थात् वष र
	” ” इसमें जोड़िये
	२ वष अर्थात् वष र
	” , इसमें जोड़िये
	३ वष, अर्थात् वष र
	” , इसमें जोड़िये
	४ वष, अर्थात् वष र
	” इसमें जोड़िया
	५ वष अर्थात् वष र

स्थान	हस्ताक्षर
दिनांक	लेखाधिकारी के हस्ताक्षर तथा पद।

भाग २

की पे शान का एक मुश्त भुगतान के लिये कम्प्यूटेशन की प्रशासकीय स्वीकृति, उपरोक्त भाग १ में लिखित लेखाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर प्रदान की जाती है। वर्तमान मूल्यों की तालिका, जिसके आधार पर लेखाधिकारी के प्रतिवेदन में गणना की गई है, वह बिना नोटिस दिये किसी भी समय परिवर्तनशील है, और तदनुसार भुगतान करने से पूर्व उनका सन्शाधित किया जा सकता है। भुगतान योग्य राशि प्रार्थी की उस आयु के उपयुक्त राशि होगी जो कम्प्यूटेशन पक्का होने के दिनांक के बाद प्रार्थी के आगामी जन्म दिवस की उसकी आयु हो, अथवा यदि चिकित्सा प्राधिकारी निदेशन दे कि उक्त आयु में वय जोड़े जावे तो उसके फल स्वरूप प्राप्त आयु के आधार पर उक्त राशि होगी।

(यहा मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पद तथा पता भरा जावे) को डाक्टर

परीक्षा की व्यवस्था करने तथा श्री को परीक्षा का स्थान तथा समय जब वह परीक्षा हेतु उपस्थित होवे निदेशन देन के लिये निवेदन कर दिया गया है। उसे अपने साथ सलग्न प्रपत्र ग लाना चाहिये जिसमे भाग १ मे अपेक्षित विवरण सिवाय हस्ताक्षर के पूरा भर लेना चाहिये।

स्थान	हस्ताक्षर
वास्ते	पद

[प्रार्थी का नाम तथा पता]

दिनांक

प्रपत्र (ग)

द्वारा

(चिकित्सा प्राधिकारी का नाम तथा पद भरिये)

डाक्टरों परीक्षा

भाग १

पेशान का एक भाग कम्प्यूटेशन करने के लिये प्रार्थी द्वारा विवरण
प्रार्थी को यह विवरण—पत्र

(यहाँ चिकित्सा प्राधिकारी का नाम भरिये)

द्वारा परीक्षा होने से पहले भर लेना चाहिये और इससे सलग्न घोषणा—पत्र पर प्राधि-
कारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर करना चाहिये ।

(क) उन प्रार्थियों द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र जो १ [अध्याय २७ पेशान का
कम्प्यूटेशन (परिवर्तन) द्वारा शासित होत हो ।]

१ अपना पूरा नाम (बड़े ब्लॉक अक्षरों में लिखिये)

२ जन्म-स्थान लिखिये

३ अपनी आयु तथा जन्म दिनांक लिखिये

४ अपने परिवार के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण दीजिये —

पिता की आयु, यदि जीवित हो और स्वास्थ्य की दशा	मृत्यु के समय पिता की आयु तथा मृत्यु का कारण	जीवित भ्राताओं की संख्या उनकी आयु, तथा उनके स्वास्थ्य की दशा
१	२	३

माता की आयु यदि जीवित हो और स्वास्थ्य की दशा	मृत्यु के समय माता की आयु तथा मृत्यु का कारण	जीवित बहनो की संख्या उनकी आयु तथा स्वास्थ्य की दशा
४	५	६

मृतक बहनो की संख्या और मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

५ क्या आपके निकट सम्बन्धियों में से किसी को
क्षयरोग (कजप्शन, म्योफुना) के संसार, दमा

१ गवर्निंग राजस्थान सेवा नियमों के अध्याय २८ के नियम, पेशान का कम्प्यूटेशन के
स्थान पर वित्त विभाग की सहायता से २८ । ५-एफ ए (३०) एक डी (ए) ब्लॉक
२७ दिनांक ११ ३ ५८ द्वारा स्थानापन्न किया गया ।

भाग II (द्वितीय)

(जांच करने वाले चिकित्सा, प्राधिकारी द्वारा भरा जायगा)

१ आयु जो नजर आती है

२ ऊँचाई

३ वजन

४ पेट का घेरा नाभि के स्तर पर

५ नब्ज की रफ्तार—

(क) बँटे हुए।

(ख) खटे हुए।

नब्ज की प्रवृत्ति क्या है।

६ शुद्ध रक्त वाहिनी नलिकाओं की क्या दशा है।

७ रक्त चाप (blood pressure)—

(क) हृदय या घमनी का सिद्धांत (Systolic)

(ख) डायमटोलिक (Diastolic)

८ क्या मुरग्य में गो में कोई रोग का लक्षण है—

(क) हृदय

(ख) फेफड़े

(ग) बलेजा

(घ) तिरलो

९ क्या मूत्र की रासायनिक जांच से

(i) अल्ब्यूमेन (ii) शक्कर होना बताती है

विशिष्ट गुरुत्व (Specific gravity)

बताइये।

१० क्या प्रार्थी के भात उतरने (रफचर) का रोग

है? यदि है तो उसका प्रकार लिखिये और

क्या वह कम हो सकता है?

११ कोई धाव के चिह्न वा पहचान के निशाना का

वर्णन दीजिये।

१२ कोई अतिरिक्त सूचना

भाग III (तृतीय)

मने/हमने कस की सावधानी से परीक्षा की है और इस राय का है/कि
“(या तो अच्छी शारीरिक तंदुरस्ती का है/नही है और औसत आयु की
अवधि होने की सम्भावना है। कम्युटेशन के लिये उचित व्यक्ति नहीं है।

अथवा (विप्लव जीवन होते हुए भी कम्युटेशन के योग्य व्यक्ति होने की दशामे)

‘चू कि , से पीड़ित है

इसलिये कम्प्यूटेशनके प्रयोजन के लिये उसकी आयु ग्रन्थार्थ आगामी जन्म दिवस को उसकी आयु वास्तविक आयु से - वर्ष अधिक हानी समझी जावे ।

स्थान

दिनांक

प्रति हस्ताक्षरित
होता हो ।

(उस दशा में जव वि-नियमन-

लागू-

जाच करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी
का हस्ताक्षर तथा पद

पुनरावलोकन चिकित्सा प्राधिकारी

परिशिष्ट IX नमू

इसमें विभिन्न सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली शक्तियों का विवरण है। ये शक्तियाँ राजस्थान सेवा नियमों के नियम ७ (६) (२) के मदभ में सौंप गये हैं --

(क) सामान्य (जनरल)

क्रमांक	सेवा नियम का मांक	शक्ति की विस्म	प्राधिकारी जिसका शक्ति सौंपी गई	सौंपा गई शक्ति की सीमा
१	२	३	४	५
११	७	(क) ऐसी आज्ञा जारी करने की शक्ति जो कतिपय परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारी का ड्यूटी पर होना माना जावे	सरकार के प्रशासकीय विभाग सिवाय उन सब (cadre) से सम्बंधित मामलों के जो नियुक्ति विभाग द्वारा नियंत्रित होत हों जिन में यह शक्ति उस विभाग द्वारा प्रयोग में लाई जावेगी।	पूरा शक्तियाँ निम्नलिखित शर्तों के अधीनस्थ होगी अर्थात्— (क) प्रशिक्षण तथा शिक्षा भारत में होनी चाहिये। (ख) प्रशिक्षण या शिक्षा राज्य कर्मचारी द्वारा प्रशिक्षण या ट्रेनिंग में लगाने के समय धारण किये हुए पद से सम्बंधित होगी। (ग) यह कि सरकार के लिये उस व्यक्ति को प्रशिक्षण या शिक्षा के लिये भेजना अनिवार्य है। (घ) प्रशिक्षण या व्यय-सायिक या तकनीकी विषय में नहीं होनी चाहिये जो सामान्यतया अध्ययन अवकाश से सम्बंधित बचाना के अधीन आता है तथा

१ वित्त विभाग आता म० एक डा १७३१/६० एक १६ (४) एफ डी ए (रूल्स)/६० दिनांक २१ ४-६० द्वारा स्थापना।

२ वित्त विभाग आपन स एक ७ ए (५) एफ डी ए /रूल्स/६० दिनांक २१ ३ ६१ और वित्त विभाग आपन स एक १ (२३) एक डी ई अ २/६३/नियम/६२ दि० ४-११-६३ द्वारा निमित।

१	२	३	४	५
				<p>(ड) प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये ।</p> <p>(च) केवल म्यानीय कम-चारियों को ही प्रशिक्षण के लिये भेजना चाहिये । जहाँ वाछित योग्यता धारण करने वाला कोई स्थायी सरकारी-कर्मचारी किसी विभाग में प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध न हो, तो प्रशिक्षण हेतु डेपुटेशन पर अस्थायी कर्मचारी को भेजने हेतु विचार किया जा सकेगा वशर्त कि —</p> <p>(१) उक्त अस्थायी सरकारी कर्मचारी ने सेवा काल में कम से कम ३ वर्ष पूरे कर लिये हों ।</p> <p>(२) उक्त अस्थायी सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति नियमित रूप से हुई हो, अर्थात् जिस पद को वह धारण करता है उसके लिये निर्धारित शिक्षा तथा आयु की योग्यताओं की वह पूर्ति करता हो, तथा जहाँ सेवा नियमों के अधीन अपक्षित हो वहाँ राजस्थान लोक सेवा आयोग के सहमति प्राप्त कर ली गई हो ।</p>
११६	=	नियुक्ति पद या पदां पर नियुक्ति के लिये	नियुक्ति विभाग	पूरी शक्तियाँ ।

१ वित्त विभाग अधिमूखन सं. एफ १ (८०) एक, दो ए (घर) ६२ दिनांक ४ १२ ६३ द्वारा जारी किया ।

१	२	३	४	५
१४	२०	अधिकारियों के स्थानांतर का आदेश देना	विभागाध्यक्ष श्रेणी प्रथम विभाग अध्यक्ष जो प्रथम श्रेणी के न हों।	वे समस्त पदधारी जिनके पदों का अधिकृततम वेतन ^२ रु० ८००) से अधिक न हो विनाय उनके प्रभार के अन्तर्गत भराज पत्रित कमचारियों के सम्बन्ध में पूरी शक्तियाँ। जिलाधीश जिले के भीतर तहसीलदारा के स्थानांतर आदेश जारी करने के लिये प्राधिकृत हैं।
४४	२३	पारस्परिक सहमति से नोटिस की व्यवधि कम करना अथवा सरकारी कमचारी की ओर से नोटिस की बात परित्याग करना।	नियुक्ति प्राधिकारी	संपूर्ण शक्तियाँ
५५	२५	उन सरकारी कमचारियों का वेतन तथा भत्ता निर्धारित करने की शक्ति जो नियम ७ (८) (५) के अधीन ड्यूटी पर होने समझे गये हों।	कोई भी प्राधिकारी जिसको उस पद पर मौलिक नियुक्ति करने की शक्ति है जिसके सदभूम सरकारी कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ता निर्धारित किया जाना है।	संपूर्ण शक्तियाँ

- १ वित्त विभाग आदेश स० एफ० ६ (६) एफ० डी० ए० (हल्स)/५८ दिनांक १६ ९ ५८ द्वारा भोजपुर समग्र के स्थान पर स्थानापन।
- २ रु० ७५० के स्थान पर रु० ८००) स्थानापन किये गये—वित्त विभाग आदेश स० एफ० (१) (८३) एफ० डी० ए० (हल्स)/६२ दिनांक ३१ १२ ६० द्वारा।
- ३ वित्त विभाग आदेश स० एफ० ६ (सी) (२) एफ० डी०/ए० आर०/६१, दिनांक १४ ६ ६१ द्वारा जोड़ा गया।
- ४ वित्त विभाग आदेश स० डी० ६००५/५८/एफ० ए० (१४) एफ० डी० ए० (हल्स)/५६ दिनांक २७ जून ५६ द्वारा जोड़ा गया।
- ५ वित्त विभाग आदेश III I डी० १७३१/६०/एफ० १६ (८) एफ० डी० ए० (हल्स)/६० दिनांक २१-४-६० द्वारा स्थानापन।

१	२	३	४	५
---	---	---	---	---

धृक् ७ (८) यह आदेश जारी ममस्त विभागाध्यक्ष संपूर्ण सक्त्तिया

(ख) तथा करने का शक्तिया

२५ कि जिला स्तर
तक के राजपत्रित
अधिकारी धार
ए एस अधि
कारियों के अति-
रिक्त जिनको
विकास विभाग
द्वारा प्रशिक्षण के
के लिये भेजा गया है
ड्यूटी पर होना समझे
जावे तथा उनके
वेतन तथा भत्ते
प्रशिक्षण काल के
लिये निर्धारित
करना ।

धृक् ७ (८) यह आदेश जारी

(ख) करने की शक्ति
जिसमें किसी सर
कारी कमचारी
को जिते भारत
में प्रशिक्षण हेतु
या अध्ययन पाठ्य
क्रम के लिए भेजा
गया है ड्यूटी पर
होना समझा जावे ।

महानिरीक्षक,
भारती,
राजस्थान

पूरी सक्त्तिया उन सरकारी कम
चारियों के विषय में जो वेतन
श्रृंखलाएं १ से २६ तक में
वेतन उठाते हों और निम्नलिखित
शर्तों के अधीन रहत हुए —

(१) यह कि प्रशिक्षण कार्यक्रम
प्रशिक्षण दिये जान वाले व्यक्तियों
की सूच्या सहित सरकार द्वारा
अनुमोदित हो चुका है ।

(२) महानिरीक्षक भारती की
अधिकार है कि प्रशिक्षण के
लिये व्यक्तियों का चुनाव किसी
अनुमोदित प्रणाली द्वारा कर
सकया ।

२ वित्त विभाग आदेश सूच्या एक १ (८३) एक डी ए रुल्स/६२, दिनांक १७-११
६२ द्वारा जोड़ा गया ।

१	२	३	४	५
६	२६	देना वृद्धि सेन की गति	कोई भी प्राधिकारी जिस उस पद पर मौलिक नियुक्ति करन का अधिकार है जो पद सरकारी कमचारी धारण किए हुए है ।	सम्पूर्ण शक्तियाँ

नोट

१ उन अधिकारियों के विषय में जो राजस्थान याचिक सेवा में डिस्ट्रिक्ट जज से निम्नतर पद धारण किये हुए हो (जिसका भारतीय सविधान के अनुच्छेद २३६ (क) में परिभाषित है) ऐसी शक्तियाँ का प्रयोग राजस्थान उच्च न्यायालय करेगा ।

२६क ३१(ख) सेन वृद्धियों हेतु सरकारी कमचा रियों की प्रसाधा रण प्रवकाश गणना करन की अनुमति देना—

(i) बीमारी के कारण कोई भी प्राधिकारी जिस उस पद पर मौलिक नियुक्ति करन का अधिकार जो उक्त सरकारी कमचारी धारण किए हुए है ।

(ii) विपण कारणों से जो सरकारी कमचारी के नियमन में परे है ।

२६ख ३५ तथा ३६ स्पष्ट अस्थायी विभागाध्यक्ष प्रथम अणी अधिक से अधिक ४ मास तक के लिए जबकि उक्त पद का उच्च सम्बन्ध में स्थाना । तम सेन ६० ८००) से अधिक

१ सामान्य प्रशासन विभाग आदेश स एफ २(२६) जा ए / ५२ निर्दिष्ट अर्थ ५४ द्वारा जारी किया ।

२ प्रोवेट से ६-के वित्त विभाग आदेश स । हा १७३१/६० एफ १६ (४) एफ हा ए स्स/६० लिंक २१-४ ६० द्वारा वक्त मान क्रमांक ६-क को ६-स के रूप पुनर्गणना करके जोड़ा गया ।

६ वित्त विभाग आदेश स एफ ६ (६) एफ हा ए । आर/ ५८ दि० १६-६-५८ द्वारा स्थान पन्ने किया गया ।

१	२	३	४	५
	पल्ल नियुक्तता करने का अधिकार			व हो, 'सिवाय' उस पद के- लिये जो ग्राट ए एस अधिकारी द्वारा धारण किया गया हो या किया जाना हो।
		राजस्थान में मेडिकल कालेज के मुख्य प्राध्यापक		अधिक से अधिक ४ मास तक के लिये जबकि वेतन श्रृंखला की अधिकतम राशि रु० १००० मासिकसे अधिक न हो। यह १-१९६२ से प्रभावशील होगा।
	II किसी स्थायी रिक्त स्थान पर अस्थायी श्रेणी नियुक्ति करने का अधिकार जब कि नीचे के पद-स्तर से स्थानापन्न पदोन्नति करना संभव न हो	विभागाध्यक्ष प्रथम		४ मास तक जब कि पद की उच्चतम वेतन रु० ८०० से अधिक न हो सिवाय उस पद के लिये जो ग्राट ए एस अधिकारी द्वारा धारण किया गया हो या किया जाना हो।
	III स्थायी रिक्त स्थान पर अस्थायी श्रेणी नियुक्ति नीचे के पद-स्तर से स्थानापन्न पदोन्नति करके करना	विभागाध्यक्ष प्रथम		४ मास तक जब कि पद का उच्चतम वेतन रु० ८०० से अधिक न हो बशर्त कि उसी स्थान पर उपलब्ध सब से वरिष्ठ व्यक्ति की पदोन्नति की गई हो।

नोट

यदि वरिष्ठता की उपेक्षा की जाती हो तो निकटतम उच्च प्राधिकारी की कारणों सहित पत्र भेजा हेतु साथ ही भेज देना चाहिये और ऐसे प्राधिकारी की सहमतों लिखित रूप में प्राप्त की जानी चाहिये तथा उसे अभिलेख (रिकॉर्ड) पर रखना चाहिये।

स्थानापन्न नियुक्ति करने की शक्ति का उपयोग विभागाध्यक्ष उन मामलों में भी कर सकते जब कि दो पदों का प्रभाव एक व्यक्ति को धारण करना हो जिससे वह भत्ता, या स्थानापन्न

१ (क) रु ७५० की जगह रु ८००) स्थानापन्न किये गये-वित्त विभाग आदेश स एफ १ [८५] एक डी-ए रुस्त/६२ दिनांक ३१-१२-६२ द्वारा।

२ विन विभाग आदेश स एफ ७ (ए) (४३) एक डी (A) रुस्त/५६ दिनांक ३१-७ ६२ द्वारा जारी गया।

३ रु ७५० की जगह रु ८००) स्थानापन्न किये गये-वित्त विभाग आदेश स एफ १ (८५) एक डी ए (रुस्त) ६२ दिनांक ३१-१२-६२ द्वारा।

या विशेष वेतन पाने का हक्कदार हो जावे ।^१ जब कि अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियों करने के विषय में, संविधान के अनुच्छेद ३०६ के परमपुत्र के अधीन किसी पद-स्तर के लिये सेवा नियमों में प्रावधान किये हुए हो तो ऐसे प्रावधान ही लागू होंगे और इसके अधीन समग्र किये गये अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जायगा ।

१	२	३	४	५
७	३६	किसी स्थानापन्न सर-कारी कर्मचारी का वेतन कम करने की शक्ति ।	कोई भी प्राधिकारी जिसे सब धित पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति करने का अधिकार हो	संपूर्ण शक्तियां
७क	३७	कतिपय सीमाओं के भीतर किसी ऐसे सर-कारी कर्मचारी का वेतन निर्धारित करने की शक्ति जिसका वेतन व्यक्तिगत हो और जो किसी पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो	कोई भी प्राधिकारी जिसे उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति करने का अधिकार हो जिस पर सरकारी कर्मचारी नियुक्त किया गया है	संपूर्ण शक्तियां
७ ख - ३८		सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर समझे जाने के बजाय स्थानापन्न [कर्मचारी] पदोन्नतियां करने के सामान्य या विशेष आदेश जारी करने की शक्ति	सरकार का प्रशासन विभाग	संपूर्ण शक्तियां
८	४१	किसी अस्थायी पद का वेतन निश्चित करने की शक्ति जो समय तथा किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा भरा जायगा ।	कोई भी प्राधिकारी जिसे निश्चित किये गये वेतन पर अस्थायी पद निर्मित करने का अधिकार हो	संपूर्ण शक्तियां

१ वित्त विभाग आदेश स एफ १ (८५) एफ डी (ए)/६२ दिनांक ५-३-६३ द्वारा जोड़ा गया ।

२ वित्त विभाग के आदेश स एफ डी १७३१/६०/एफ १६ (४) एफ डी ए (स्लस) ६० दिनांक २१-४-६० द्वारा जोड़ा गया तथा स्थानापन्न किया गया ।

<p>१६४३ (क) किसी काय को हाथे । समस्त विभागध्यक्ष मे लेने की स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति जिसने श्रुत्य देने का प्रस्ताव पौरश्रुत्य मंजूर किया गया हो</p>	<p>पूरी शक्तिया जो प्रत्येक मामले मे अधिकाधिक ५००) हो । आवर्ती (रिटर्निंग) श्रुत्य होने की दशा मे यह सीमा किसी व्यक्ति को वर्ष भर मे कुल दिये गये आवर्ती व्यय (recurring payments) की जोड़ पर लागू होगी ।</p>
<p>१०४३ (ग) किसी ऐसे काय, समस्त विभागध्यक्ष को हाथ मे लेने की स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति जो कभी कभी होता हो या जो विशेष दक्षता का हो</p>	<p>परराजपत्रित सरकारी कमचारियों के सम्बन्ध मे पूरी शक्तिया परन्तु इस छत के अधीन कि मान्यदेश की स्वीकृति प्रत्येक मामले मे निम्न लिखित सीमाओं से अधिक नहीं होगी ।</p>
<p>जिसमे किसी विशेष (३) परराजपत्रित सर १६० घंटा से कम अनिवार्य कमचारियों को रिक्त काय करने के लिये अत्याधिक लम्बे समय २ अतिरिक्त काय के (घंटो) तक काय लिये जो ६० घंटा या करना हो तथा मान उस से अधिक नहीं पर देय (प्रोत्तरेयम) १२० घंटो से कम प्रदान करने की शक्ति हो</p>	<p>कुछ नहीं एक मास के वेतन से बीवाई [जिसमे विशेष वतन तथा महगाई वेतन यदि कोई हो तो सम्मिलित है]</p>
<p>(३) अतिरिक्त काय के लिये जो १२० घंटो का हो परन्तु १८० घंटो से कम हो ।</p>	<p>आधे मास का वेतन (जिसमे विशेष वेतन तथा महगाई वेतन यदि कोई हो तो सम्मिलित है ।)</p>
<p>(४) अतिरिक्त काय के लिये जो १८० घंटो का हो परन्तु २४० घंटो से कम हो</p>	<p>मास का पौन वेतन (जिसमे विशेष वेतन तथा महगाई वेतन सम्मिलित है, यदि कोई हो ।)</p>
<p>(५) अतिरिक्त काय जो २४० घंटो या इससे अधिक का हो ।</p>	<p>एक मास का वेतन (जिसमे विशेष वेतन तथा महगाई वेतन सम्मिलित है यदि कोई हो ।)</p>

१. राजस्थान सेवा नियम भाग द्वितीय के परिशिष्ट नवम (IX) के क्रमांक १० (जैसा कि वित्त विभाग आदेश सं एफ १ (३७) एफ डी (ई एक्स पी रुल्स)/६७ दिनांक १६-५-१९६७ द्वारा संशोधित है) की ओर आवर्षित किया जाता है जिसके अधीन अ-राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को मानदेय (ग्रोनोरेरियम) प्रदान करने की शक्ति उपरोक्त आदेश की शर्तों के अधीन रहते विभागाध्यक्षों को सौंपी गई है।

२. मानदेय के स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट विशेषताओं की यथार्ता की जांच करते समय ऑडिट (लेखा परीक्षा) करने वालों को सुगमता दिलाने की दृष्टि से, यह नियम किया गया है कि स्थायी रूप से उपयुक्त अभिलेखा (रेकड) जिसमें निम्नलिखित विवरण हो समस्त रूपों का निकालने वाले/वितरण करने वाले अधिकारी रखे।

३. अतः समस्त रूपों का निकालने वाले/वितरण करने वाले अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वे एच. रजिस्टर 'राजस्थान सेवा नियम भाग द्वितीय के नवम परिशिष्ट की प्रविष्टि १० के अधीन मानदेय की स्वीकृति/भुगतान का रजिस्टर' नामक निम्नलिखित प्रपत्र में अपने अपने कार्यालयों में तत्कालिक प्रभाव से रखें जिसे मागने पर लेखा परीक्षा दलों के समक्ष प्रस्तुत किया जावे—

क्रमांक	वृत्ति भोगों का नाम—	आवृत्ति काय/विशेष योग्यता वाले काय का विवरण	अतिरिक्त कार्य का समय (घंटे)
१	२	३	४

अधिसूचित जिस समय अतिरिक्त काय किया गया दिनांक	कब से कब तक	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति का हवाला सं. तथा दिनांक	देय राशि
५	६	७	८

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर	विल की सं. तथा दिनांक का हवाला और वाचर की संख्या तथा दिनांक	कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर	विशेष विवरण
१०	१०	१२	१३

१	२	३	४	५
११	५०	किसी सरकारी कमचारी का किसी पद का अस्थायी रूप से धारण करन अथवा एक से अधिक पदों पर कायकारी रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त करने की शक्ति तथा सहायक पदों का वेतन तथा मुष वजा भत्ता निर्धारित करना	समस्त विभागाध्यक्ष	समस्त शक्तियां उशर्त कि उनका सम्बधित प्रत्येक पद के लिये किसी सरकारी कमचारी को मौलिक रूप से नियुक्त करने के अधिकार हो, और वशर्त यह भी कि पद का स्पष्ट तथा पूरी तरह परिभाषित प्रभार हो अथवा उत्तरदायित्व का क्षेत्र हो।
११क	५०	ऐसे राजपत्रित पद को भरने की शक्ति जो वृत्तिभोगी के अवकाश पर जाने से रिक्त हुआ हो और जिसके लिये किसी अधिकारी को उसके कार्य के अतिरिक्त कायभार सौंपना और उसे वित्त विभाग आदेश स एफ ८ (२८) एफ ११/४५ दिनांक ६ = १९६३ के अन्वये ५ (१) क अनुसार विशेष वेतन स्वीकार करना।	समस्त विभागाध्यक्ष तथा जिला स्तर के अधिकारीगण	शक्तियों का प्रयोग निम्न लिखित शर्तों के अधीन रहते किया जा सकेगा - (१) अवकाश रिक्त ६० दिन से अधिक समय के लिये न हो। (२) रिक्त स्थान को भरने के लिये नियुक्त व्यक्ति का मुख्यावाम परिवर्तित न हो। (३) रिक्त पद को पूर्ण उम्मीद पद स्तर के अधिकारी द्वारा ही जाव।
१२	७१	अवकाश स लौटने से पूर्व स्वास्थ्य का चिकित्सक प्रमाण पत्र मागने की शक्ति	समस्त अधिकार कमचारी को अवकाश प्रदान करने के लिये सक्षम प्राधिकारी	समस्त शक्तियां
१३	८६	किसी अ राजपत्रित सरकारी कमचारी को वापस ड्यूटी पर लेने के लिये, स्वास्थ्य के	अवकाश प्रदान करने के लिये सक्षम प्राधिकारी	समस्त शक्तियां

१ पित विभाग आदेश स, एफ ८ (२८) एफ ११/४५/११ दिनांक ११-१-६३ तथा २८-१-६३ द्वारा जोड़ा गया।

१	२	३	४	५
		संवृत में किसी पजीवृत व्यवसायिक चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र को स्वीकार करने की शक्ति		
११४	सब प्रकार का अवकाश प्रदान करने की शक्ति (अध्ययन अवकाश) तथा विशेष असमयता अवकाश के	१ मौलिक नियुक्ति करने केलिये सक्षम प्राधिकारी	१ समस्त शक्तियाँ । उनकी यह शक्तियाँ अधीनस्थ प्राधिकारियों को सौंपने का भी प्राधिकार दिया जाता है (राजपत्रित अधिकारीगण उस सीमा तक जो आवश्यक समझी जावे) ३ []	
		टिप्पणी		

१ निम्नलिखितों को सामान्यतया (अधिकार) पुनः समर्पित किया जाना समझा जावे —

४ (1) इस घट के अधीन रहते कि किसी स्थानापन्न व्यक्ति (सफ्टीट्यूट) को प्रावश्यकता न हो, निम्नलिखित प्राधिकारियों द्वारा बोर्ड २ में बताये गये अधिकारियों के विषय में दो मास तक का अवकाश (अध्ययन) तथा असमयता अवकाश के प्रतिरिक्त) प्रदान किया जा सकगा —

प्राधिकारी	अधिकारीगण जिनके विषय में अवकाश प्रदान कर सकेंगे
विभागाध्यक्ष तथा अतिरिक्त विभागाध्यक्ष जो विभागाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करते हैं	(i) समस्त राजपत्रित अधिकारीगण जो विभागाध्यक्ष के मुख्यालय पर तैनात हैं अथवा अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के पृथक मुख्यालय पर तैनात हैं । (ii) समस्त समुक्त तथा उप (डिप्टी) विभागाध्यक्ष जो क्षेत्रीय स्तर पर तैनात हैं ।
समुक्त/उप (डिप्टी) विभागाध्यक्ष जो विभागाध्यक्ष के कार्यालय से सलग्न न हों ।	(i) समस्त राजपत्रित अधिकारीगण जो समुक्त/उप विभागाध्यक्ष के मुख्यालय पर तैनात हैं और जो सीधे उसके अधीनस्थ हों ।

(१) वित्त विभाग आदेश स १ डी ३१५६/५६/एफ ६ (१६) एफ डी ए (रत्स) ५६ गिनाक २० ६ ५८ तथा वित्त विभाग आपन स १५७५/६० एफ ६ (१६) एफ डी ए (रत्स)/५६ दिनांक २० ४ ६० तथा वित्त विभाग आदेश स एफ ६ (१६) एफ डी ए (रत्स)/५६ दिनांक १७ १० ६० तथा एफ १ (४१) एफ डी (ई एक्स पी रत्स)/६३/दिनांक ५ १२ ६३ द्वारा स्थानापन्न किया गया ।

२ वित्त विभाग आदेश स एफ १ (४१) एफ डी (ई एक्स पी रत्स)/६३ दिनांक ५ १२ ६३ द्वारा जोड़ा गया ।

३ गलत 'सिवाय अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने की शक्ति' वित्त विभाग आदेश स एफ १ (४१) एफ डी (ई एक्स पी रत्स)/६३ गिनाक ५ १२ ६३ द्वारा सौंपित किये गये ।

४ वित्त विभाग आदेश स एफ डी १ (६८) एफ डी (ई भार)/६५ दिनांक १४ १२ ६५ द्वारा स्थानापन्न किया गया ।

(ii) उसके अधीनस्थ समस्त जिला स्तर के अधिकारी-गण ।

जिला स्तर अधिकारी

समस्त राज पत्रित अधिकारीगण जो उनके अधीनस्थ हो ।

जब कि स्थानापन्न व्यक्ति (सेक्स्टीट्यूट) की आवश्यकता हो, अवकाश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिया जा सकेगा या ऐसे नीचे के प्राधिकारी द्वारा जिसको पदाधिकारियों को स्थानान्तर करने की शक्ति सुपुर्द की हुई हो ।

(iii) समस्त विभागाध्यक्ष अधीनस्थ लेखकवर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी सेवाभा के सदस्यों को २ मास तक का अवकाश प्रदान कर सकेंगे ।

२ उपरोक्त नोट १ में बताये गये सामान्य पुन समपण के परे भी सम्बंधित प्राधिकारियों द्वारा जैसे आवश्यक समझी जावे सिवाय अध्ययन अवकाश के विषय में, अधीनस्थ राजपत्रित प्राधि कार्या को अधिकार पुन समपण किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण १ राजस्थान सेवा नियम, भाग II के परिशिष्ट IX (नवम) म क्रमांक १४ क नोट १ के उप खंड (i) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है—(जसा कि वह वित्त विभाग आदेश स एफ १ (६८) एक डी (ई आर)/६५ दिनांक १४ १२-१९६५ द्वारा संशोधित है) ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि शब्द अनिर्वक्त/संयुक्त उप (डिप्टी) विभागाध्यक्ष जा उपरोक्त उप खंड म प्रयोग किये गये हैं उनका अर्थ लगाते समय उनस तात्पर्य उन अधिकारियों में समझा जावे जिनका पद इस नाम का है ।

२ राजस्थान सेवा नियम, भाग II के परिशिष्ट IX (नवम) म क्रमांक १४ के नोट १ के उप खंड (i) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है (जसा कि वह वित्त विभाग आदेश स एफ १ (६८) एक डी (ई आर)/६५ दिनांक १४ १२ १९६५ तथा १३ ७-१९६६ द्वारा संशोधित है) ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि अधीनस्थ अभियंता उप मुख्य अभियंता सामाजिक निर्माण विभाग को सभी गारान्ती के अवकाश प्रदान करने की उन्ही शक्तिया का प्रयोग करेंगे जो उपरोक्त आदेशों के अधीन उप विभागाध्यक्षा को समपण किये गये हैं ।

अपवाद १—जिला स्तर अधिकारीगण (१ जिलाधीन २ जिलाधुपि अधिकारी, ३ अधाशक भारही ४ अधिशासी अभियंता, ५ जिला वन अधिकारी, ६ जिला निरिक्षा तथा

१ वित्त विभाग आदेश स एफ (६८) एक डी (ई आर) ६६ दिनांक १३ ७ ६६ द्वारा जोड़ा गया ।

२ वित्त विभाग आदेश स एफ १ (६८) एक डी [ई एम् एच पी ब्लूम]/६५ दिनांक ७-१० ६६ द्वारा जोड़ा गया ।

स्वास्थ्य अधिकारी ७ मनिज अभियन्ता, ८ जिला तथा सत्र यायाधीश, ९ जिला पशु तथा पशु-पालन अधिकारी, १० समस्त महाविद्यालयों के मुख्य प्राध्यापक, तथा ११ भू-बन्धोदस्त अधिकारी को उनके अधीनस्थ अधिकारियों उप क्षेत्रीय अधिकारी [एस डी आ], उप अधीक्षक भारक्षी सहायक अभियन्ता आदि] को २ मास तक के लिये सिवाय असमयता अवकाश के, सब प्रकार के अवकाश प्रदान करने के अधिकार है बशर्त कि यदि उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता हो तो सक्षम प्राधिकारी की सहमति पत्र या तार द्वारा या टेलीफोन पर प्राप्त करतनी चाहिये ।

२ कार्यालयीय उनके अधीनस्थ समस्त व राज पत्रित कमचारियों को सिवाय अध्ययन और असमयता अवकाश के, सब प्रकार का अवकाश दो मास तक प्रदान करने के लिये अधिकृत है ।

१	२	३	४	५
२१४व २६ से १०२	विनैय असमयता अवकाश देने को शक्ति	सरकार विभाग म । ३ राजस्थान सशस्त्र पुलिस के उपमहा निरीक्षक भारक्षी	प्रशासनिक	पूरी शक्तियां
२१४व	किसी ऐसे राज पत्रित सरकारी कमचारी को अवकाश प्रदान करने की शक्तियां जो भारत म विदेशी सेवा म हो ।	१ विदेशी नियोजक २ बहुश्राधिकारी जिसने विदेशी सेवा म स्थाना		रियायती अवकाश प्रदान करने की पूरी शक्तियां जा १२० दिनों तक अधिक न हों और जो सेवानिवृत्ति से पूर्व दिया जान वाले अवकाश न हों । पूरी शक्तियां

१ वित्त विभाग आर्य स एफ ६ (१६) एफ डी ए [भारत]/५६ दिनांक २७ ४ ६१ द्वारा जोड़ा गया । इसका प्रभाव २० ८ ६० स होगा ।

२ प्रविष्टि स १४ तथा १८ वित्त विभाग आर्य स एफ १ (१६) एफ डी ए [भारत]/५६ दिनांक २७ ४ ६१ द्वारा जोड़ा गया तथा स्थानापन्न किया गया ।

३ वित्त विभाग आर्य स एफ १ (५७) एफ डी [ई एम पी रस्त] ६५ III/III दिनांक २ नवम्बर १९६६ द्वारा जोड़ा गया । इसका प्रभाव २६ ६५ स होगा ।

४ वित्त विभाग आर्य स एफ १ (७) एफ डी (१) एम्स/६१ III दिनांक ११ ५ ६२ द्वारा जोड़ा गया ।

१	२	३	४	५
---	---	---	---	---

न्तर करने कीस्वीकृति
विदेशी की नियोजक

११४ग	किसी ऐसे अ राजपत्रित सरकारी कर्मचारी को अवकाश प्रदान करने की शक्तिया जो भारत में विदेशी सेवा में हो।	रियायती अवकाश प्रदान करने की पूरी शक्तिया जो १२० दिनों से अधिक न हो, और जो सेवा निवृत्ति में पूरा दिया जाने वाला अवकाश न हो।
------	--	--

टिप्पणी

विदेशी सेवा में अ राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को रियायती अवकाश के अतिरिक्त अवकाश उस प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायगा जो उस व्यक्ति में स्वीकृति प्रदान करता यदि सरकारी कर्मचारी राज्य में ड्यूटी पर होता।

११४घ	अध्ययन अवकाश प्रदान करने की शक्ति	विभागाध्यक्ष प्रशासन विभाग	अ राजपत्रित कर्मचारियों के विषय में पूरी शक्तियां राजपत्रित अधिकारियों के विषय में पूरी शक्तियां
११४ङ नियम	सावजनिक सेवा की शक्तिया के कारण सेवा निवृत्ति से पूर्व देय तथा आवेदित अवकाश पूर्णतया या आंशिक रूप से अस्वीकार करना	निवृत्ति विभाग	पूरी शक्तियां

१५ से १७ लोपित किये गया।

११८	(1) किसी राज्य न्याय अधिकारी की विदेशी सेवा (जिसमें अन्य राज्य भी शामिल हैं)	सरकार के प्रशासकीय विभाग निम्न लिखित शर्तों के अधीन रहते -	पूरी शक्तियां
-----	--	--	---------------

१ वित्त विभाग आदेश स एफ १ (१७) एफ डी (ए) वल्ल ६१ 111 दिनांक ११ ५ ६२ द्वारा जोड़ा गया।

२ वित्त विभाग आदेश स एफ १ (११) एफ डी [ई एक्स पी वल्ल] ६२ दिनांक ५-१२ ६२ द्वारा जोड़ा गया।

३ वित्त विभाग आदेश स, एफ १ (११) एफ डी [ई एक्स पी वल्ल] ६७/11 दिनांक २१ मार्च ६७ द्वारा जोड़ा गया।

४ वित्त विभाग आदेश स एफ १६ (४) एफ डी ए (वल्ल) ६० दिनांक १४ ६० द्वारा स्थापित।

१	२	३	४	५
	सम्मिलित ह) में स्थाना	१(१) प्रतिनियुक्ति		
	न्तर करने की शक्ति	(डिप्यूटेसन) पर रखे		
	तथा उसके वेतन तथा	गये कमचारी को		
	भत्ते निर्दिष्ट करना।	निम्नलिखित में से		
		कोई विकल्प द्वारा		
		द्रव्य उठाने की अनुमति		
		दी जा सकेगी —		

(क) उस पद थसला में वेतन जिस पद पर उसे प्रतिनियुक्ति किया गया है, ^२जैसा कि राजस्थान सेवा नियम के प्रावधानों के अधीन निर्दिष्ट किया जावे अथवा

(ख) मूल विभाग में मौलिक वेतन, उसका व्यक्तिगत और उसके मौलिक वेतन का २०% प्रतिनियुक्ति भत्ते की दर से। प्रतिनियुक्ति भत्ता इस प्रकार से प्रतिबंधित रखा जायगा कि कमचारी का समय समय पर मूल वेतन प्रतिनियुक्ति भत्त की मिलाकर उस पद के उच्चतम शृंखला से अधिक न हो जो पद प्रतिनियुक्ति पर धारण किया हुआ हो अथवा जब कि प्रतिनियुक्ति वाले पद का एक निर्दिष्ट वेतन हो ता वह निर्दिष्ट वेतन, (वर्षों कि हर हाज़त में प्रतिनियुक्ति भत्ता रुपये ३००) मासिक से अधिक न होगा)।

टिप्पणियाँ

१ उक्त प्रयोजन के लिये मौलिक वेतन से तात्पर्य उस वेतन से होगा जो धारण की गई मौलिक नियुक्ति की शृंखला में उठाया जाता हो अथवा स्थानापन्न नियुक्ति की शृंखला में कमचारी को मौलिक पद स्तर पर वेतन वसूतें कि नियुक्ति प्राधिकारी यह प्रमाणित करदे कि यदि तत्ति युक्ति नहीं होती तो वह कमचारी अनिश्चित समय के लिये स्थानापन्न नियुक्ति पर जारी रहता। किसी विशेष नियुक्ति पर उठाया गया विशेष वेतन निम्नलिखित परस्थितियों में मौलिक पद का भाग होना सम्मत्ता जावेगा वसूतें कि वह दो वर्ष तक निरंतर उठाया गया हो।

(क) विशेष वेतन राजस्थान असेनिक सेवा (सशोधित वेतन) नियम १९६१ की अनुसूची स २ के भाग ४ में निर्दिष्ट हो या

(ख) विशेष वेतन निर्दिष्ट पद के लिये हो जो पद के वेतन शृंखला में प्रतिरिक्त हो।

(ग) विशेष वेतन निर्धारित योग्यताएं प्राप्त करने के लिये स्वीकृत किया गया हो।

२ मृगाई भत्ता मौलिक राज्य के या अन्य सरकार/विदेशी सेवा के नियमानुसार होगा

१ मासिक बार वित्त विभाग आदेश स एफ १ (२२) एफ डी ए (नूतन) ६१ दिनांक ४ ३ ६७ द्वारा स्थानापन्न किया।

२ वित्त विभाग आदेश स एफ १ (२२) एफ डी (ए) ६१ दिनांक ७-८-६३ द्वारा जोड़ा गया।

अर्थात् वेतन मौलिक वेतन अथवा मे उठाया गया है या प्रतिनियुक्ति पर धारण किये हुए पद के वेतन अथवा मे उठाया गया है, उसके अनुसार नियमित होगा। प्रोजेक्ट (योजना) भत्ता जो याजना क्षेत्र में माय हो, प्रतिनियुक्ति भत्ते के अतिरिक्त उठाया जा सकेगा यदि वह अन्य सरकारी/विदेशी सेवा के कर्मचारियों को स्वीकृत हो।

३ उपरोक्त उप खंड में उल्लेखित व्यक्तिगत वेतन प्रतिनियुक्ति भत्ते में सविशेष नही किया जायेगा परन्तु अन्य वेतन वृद्धियों में गविलीन किया जायगा उदाहरणार्थ वेतन वृद्धिया या पदोन्नति या किसी अन्य कारण से वेतन में वृद्धि होना।

४ यदि प्रतिनियुक्ति के पश्चात् कर्मचारी का मौलिक वेतन प्रतिनियुक्ति पर धारण किये गये पद के अधिकतम वेतन से अथवा पद के निश्चित वेतन से बढ जावे, तो जिस तारीख का उसका वेतन ऐसी अधिकतम सीमा से बढ जावे उस दिन से छ महिने को अवधि के लिये परिसीमित हो जायेगा और कर्मचारी को उसके मौलिक विभाग में वापस भेज देना चाहिये।

५ जब किसी राज्य कर्मचारी का मौलिक वेतन उस पद के अधिकतम वेतन से अधिक हो जहा पर कि उसे प्रतिनियुक्ति क्या जाना हो तो उसे प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजना चाहिये।

६ उप खण्ड (१) (ख) उन अधिकारियों पर लागू नहीं होता जिनको प्रतिनियुक्ति पर पचायत समितियों/जिला परिषदों, (राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल तथा राजस्थान राज्य सड़क परिवहन नियम) या किसी ऐसे अन्य संस्था में भेजा जावे जो सरकार विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर दे।

७ किसी राज्य कर्मचारी को जिसे प्रतिनियुक्ति पर राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम में अथवा किसी ऐसी सरकारी कम्पनी में भेजा गया हो जिसकी परिभाषा कम्पनी अधिनियम की धारा ६१७ में दी गई है तो प्रतिनियुक्ति भत्ते के अतिरिक्त बोनस भी दिया जायगा, यदि कोई हो, जब कि ऐसा बोनस राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन अथवा सम्बंधित सरकारी कम्पनी के कर्मचारियों को पेमेन्ट आफ बोनस अधिनियम (केन्द्रिय अधिनियम २१, १९६५) या द्वारा अथवा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल तथा राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के किसी निर्णय द्वारा बोनस अधिनियम की परिधी के बाहर देय हो बगैरे कि उक्त बोनस ऐसी प्रतिनियुक्ति पर की गई सेवा से सम्बंधित हो जो कि सा ऐसे लक्षा वष में हुई हो जा १९६४ में या उसके बाद में किसी दिन प्रारम्भ हुआ हो।

यह जानाएँ उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी जो पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर है उनसे यामसे उन आगामो से नियमित होंगे जो इन आगामो के जारी होने से पहले से लागू हैं। जब उनकी वर्तमान प्रतिनियुक्ति अवधि और धामे बढाई जाव तो प्रतिनियुक्ति पर उनका वेतन प्रभाव कीय विभागों द्वारा सहायित प्रतिनियुक्ति के अनुसार पुन निश्चित किया जायेगा।

राजस्थान सेवा नियम, भाग २ के परिशिष्ट नवम में क्रमांक १८ के सामने कोष्टक सख्या चार में बताया गये उप खण्ड [१] के नोट ६ (वित्त विभाग का इसी सख्या का आदेश दिनांक १३ १० ६१) के अनुसार म राज्यपाल ने प्रसन्न होकर आदेश करमाया है कि उपरोक्त उप खण्ड () उन राज्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो राजस्थान होटल निगम में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जावें।

इन आदेशों का प्रभाव होटल निगम के निर्माण की तारीख से होगा।

टिप्पणियाँ

(1) यह उप खण्ड उन अधिकारियों पर लागू नहीं होगा जो प्रतिनियुक्ति पर सरकारी अथवा सरकार द्वारा नियमित निगम निवास और पचायत समितियों/जिला परिषदा ऐसी अन्य संस्थाओं में भेजे जावें जो सरकार विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे।

(ii) यात्रा भत्ता—उधार लेने वाली सरकार तथा विदेशी नियोजक, यथा स्थिति, के नियमों के अनुसार।

(iii) अवकाश तथा पेंशन चढ़े का भुगतान—विदेशी नियोजक या उधार लेने वाली सरकार द्वारा, राजस्थान सेवा नियम के परिशिष्ट पंचम के अनुसार।

¹(iv) मुभावजा भत्ता—उधार लेने वाली सरकार अथवा विदेशी नियोजक के नियमों के अनुसार बशर्ते कि यदि कथित भत्ते राज्य के नियमों के अधीन देय मुभावजा (नगर) भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा यात्रा भत्तों से कम हो तो प्रतिनियुक्ति पर गये हुए व्यक्ति राजकीय नियमों के अनुसार ऐसा मुभावजा भत्ता उठाने का विकल्प चुन सकेंगे।

(v) चिकित्सा व रियायतें—राजकीय नियमों के अधीन जो देय हो उससे कम नहीं होंगे।

(vi) अवधि—एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं।

१	२	३	४	५
(ii)	अन्य सरकारी से प्रतिनियुक्ति पर व्यक्ति प्राप्ति करने की शक्ति	सरकार का प्रशासन	उन शर्तों के अनुसार जो उपरोक्त (1) में व्यक्त शर्तों से अधिक उदार न हों।	

^२राजस्थान सरकार का निणय सं १—(सोपित किया गया)।

^३राजस्थान सरकार का निणय सं २

उपरोक्त उप खण्ड (1) उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो प्रतिनियुक्ति पर राजस्थान में मगर विकास यात्री पर भेजे जावें। यह आदेश इसके बाद प्रारम्भ होने वाले प्रतिनियुक्ति के मामले पर लागू होंगे और ऐसे राज्य कर्मचारी पर लागू होंगे जिसके मामले में प्रतिनियुक्ति भत्ता प्रदान करने के आदेश जारी नहीं हुए हैं।

यह आदेश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर हैं और जिनकी प्रतिनियुक्ति भत्ता मिल रहा है। वे प्रतिनियुक्ति भत्ता उनके वर्तमान प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने तक उठाना जारी रखेंगे। उनकी वर्तमान अवधि समाप्त होने पर यह आदेश लागू हो जायेगा।

१ वित्त विभाग आदेश सं एफ १ (१६) एफ डी (इ एक्स पी रत्स)/६७ दिनांक ३१ ३ १९६७ द्वारा स्थापनापत्र।

२ वित्त विभाग आदेश सं एफ १ (३०) एफ डी (ए) रत्स/६२ दिनांक ११ ५ १९६२ द्वारा जोड़ा गया, १३ १० ६४ से लागू तथा वित्त विभाग आदेश सं एफ १ (२२) एफ डी ए/आर ६१ दिनांक २१ दिसम्बर १९६६ द्वारा निरस्त किया गया लागू दिनांक १ ३ ६६ से।

३ वित्त विभाग आदेश सं एफ १ (२२) एफ डी ए (आर)/६१ दिनांक १६ ४ १९६६ द्वारा जोड़ा गया।

अपवाद—राजस्थान ने प्रसन्न होकर आदेश कगमाया है कि अब से आगे सेवापाला को विदेशी सेवा में स्थानांतर करने की तथा वेतन तथा भत्ते निश्चित करने की गतिविधि मुख्य सेवाधिकारी राजस्थान द्वारा, कथित परिशिष्ट के क्रमांक १८ में निर्धारित शर्तों के अधीन रहते प्रयोग में लाई जायेगी।

१	२	३	४	५
१८क	अस्थाई पद निर्माण करने की गतिविधि	सरकार के प्रशासन विभाग	४ मास तक —	
			(क) वज्रट में विशिष्ट प्रावधान के अन्तर्गत योजना के लिये आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन रहते, जो जारी हो चुकी हो।	
			(ख) कमकारी बग शिपक के अधीन वचन में से बरातें हैं कि पद का अधिकतम वेतन रुपये दो सौ से अधिक न हो। परन्तु बात यह है कि	
			(i) यह शक्ति मौजूदा बतमान अस्थाई पद की अवधि बढ़ाने के लिए पदवा इस शक्ति का प्रयोग करते हुए अस्थाई पद का निर्माण करने के लिए न हो।	
			(ii) पदा के निर्माण करने में जो व्यय हो उसकी पूर्ति किसी अन्य शिपक II निधि हटाकर नहीं की जावे।	
			(iii) वज्रट पद किसी ऐसी बड़ी योजना का भार न हो जिसमें अनेक पद निर्माण करने हो, जिसमें से किसी एक का भी वेतन रुपये २००) से अधिक हो।	

१ किन विभाग आदेश स एफ ११(२०) एफ डी (ई चार)/६७ दिनांक ३१-३-१९६७ द्वारा जोड़ा गया।

२ किन विभाग आदेश स एफ ६-(६) एफ डी/ए/आर/५८ दिनांक १९-६-५८ द्वारा जोड़ा गया।

१-२	३	४	५
			१(1V) प्रस्थाई प* के वेतन की दर उसी प्रकार के अन्य पदा के लिए निर्धारित वेतन श्रृंखला में हो ।
२१८म १३६ काय ग्रहण अवधि (जोईनिंग टाइम) बढ़ाने की शक्ति	(१) सरकार का प्रशासन विभाग		पूरी शक्तिया ३० दिन की अधिकतम सीमा के भीतर, राजस्थान सेवा नियमों के नियम १३६ में वर्णित परिस्थितियों में ।
	(२) विभागाध्यक्ष थैली प्रथम		सामान्य काय ग्रहण अवधि के अतिरिक्त सात दिन तक, राजस्थान सेवा नियमों के नियम १३६ में वर्णित परिस्थितियों में । यह शक्तिया केवल अ राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रयोग में लाई जायेंगी और काय ग्रहण अवधि बढ़ाने का कारण आदेश में अभिलिखित किया जायगा ।
३१८म १७५ असन्वित, या युद्ध सेवा को, नियमों में निर्धारित शक्तों की पूर्ति के अधीन रहते असे निरन्तर सेवा की पेशन के लिये अनुमति देने की शक्ति	सरकार का प्रशासनिक विभाग		पूरी शक्तिया

१ वित्त विभाग आदेश सं ५५२/५६ एफ ६ (६) एफ डी ए (रुस्स) ५७ दिनांक २६ ११ ५६ द्वारा जोड़ा गया ।

२ वित्त विभाग आदेश सं एफ ६ (२२) एफ डी ए रुस्स/५६ दिनांक १८-७-५६ द्वारा जोड़ा गया तथा वित्त विभाग आदेश सं १ (३२) एफ डी (ई वस भी रुस्स)/६३ दिनांक १-१०-६३

— निरास्त किये जा चुके आदेशों के अधीन की गई कार्यवाही यथोचित आदेश के अन्तर्गत की गई समझी जायगी । —

१	२	३	४	५
१८४ २४४	राज्य कमचारी की			पूरी शक्तियां बशर्ते कि नि-
	५५ वर्ष की नौकरी			युक्ति (ए-II) विभाग
	के पश्चात् सेवा			आदेश सं एफ १ (३६)
	निवृत्त करने की			नियुक्ति [ए-II]/ ६३
	शक्ति—			दिनांक २५-१-६३ में निर्धारित प्रक्रम पालन किया गया हो ।
	(१) राज्य सेवा	राज्य सरकार का		
	(२) अधीन सेवा	प्रशासन विभाग		
	(३) राजपत्रित तथा	विभागाध्यक्ष		
	अराजपत्रित पद)			
	(१) लेखा वर्गीय सेवा	नियुक्ति प्राधिकारिण		
	(राजपत्रित तथा			
	अराजपत्रित पद)			
	२५ वर्ष की गृहवारी			
	सेवा के पश्चात् राज्य			
	कमचारी की सेवा			
	निवृत्त करने की			
	शक्तियां—			
	(१) राज्य सेवा	सरकार का प्रशासन	पूरी शक्तियां बशर्ते कि—	
		विभाग	(1) किसी सेवा के राज-	
			पत्रित अधिकारियों के	
			सम्बन्ध में—सं-प्रक्रम का	
			पालन कर लिया गया है जो	
			नियुक्ति 'ए' विभाग के परिपत्र	
			सं एफ २४ [५५] नियुक्ति	
			[ए]/५७ दिनांक १८-८-५८	
			का पठन बाद के परिपत्र	
			दिनांक १७-११-१९५८ तथा	
			४-१०-१९६३ के साथ करने	

१ वित्त विभाग आदेश सं एफ ७ ए (४३) एफ डी ए रुल्स/५७, दिनांक ३-५-६० तथा आई डी २८८०/६० एफ ६ ए एफ डी ए/रुल्स/५७ दिनांक १-७-६० द्वारा जोड़ा गया तथा एफ डी आदेश सं एफ डी ७ ए (४३) एफ डी ए धार ५७, दिनांक १३-३-१९६६ द्वारा स्थानांतरित किया गया तथा वित्त विभाग आदेश सं एफ १ (२४) एफ डी ए (रुल्स) ६२ दिनांक १३-१२-६३ द्वारा अतिप्रमाण किया गया ।

१	२	३	४	५
				से निर्धारित है और जैसा वा- मे समय समय-पर सशोधित किया जावे ।
	(२) अधीनस्थ सेवा [राजपत्रित तथा अ- राजपत्रित]	नियुक्त प्राधिकारीगण		(II) अधीनस्थ [अ राजपत्रित कर्मचारी वाग के सम्बन्ध में उक्त प्रक्रम का पालन कर लिया गया है जो नियुक्ति ए II सी और विभाग के परिपत्र सं एक २४ (५५) नियुक्ति (ए) ५७ की एत आई/प्र.प II/ सी और दि० १६, १ १९६३ द्वारा निर्धा- रित है और जैसा समय समय-पर सशोधित किया जावे ।
	(३) सेल्व कर्मीय सेवा (राज पत्रित तथा अ राजपत्रित पद]	नियुक्ति प्राधिकारीगण		(III) नियुक्ति (ए II) विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रम (अ राज- पत्रित) कर्मचारीगण के विषय में पालन कर लिया जावे ।
				राजस्थान सरकार का आदेश
				१ [लोपित]

ख-पेशान

क्रमिक	सेवा	नियमों	का	शक्ति की विस्म	अधिकारी	जितका	मुपदसी की सीमा
क्रमांक					शक्ति सुपु	की हुई	
१६	२७०	असाधारण पेशान					
		स्वीकार करने की					
		शक्ति					
१	वित्त विभाग आदेश सं एक	१ [४२]	एफ डी	[ई एक्स-पी क्लस] दिनांक १३ ६ ६७			
	द्वारा लोपित किया गया ।						
२	वित्त विभाग आदेश सं एक	१ [७२]	एफ डी	[ई आर] ६३-11 दिनांक २६ १२			
	६५ द्वारा स्थानांतरित किया गया ।						

— १ — २ — ३ — ४ — ५ —

प्रशासन विभाग तथा लोक सेवा आयोग के मध्य कोई मतभेद न हो ।

(11) (क) अध्यक्ष राजस्व भूखे ।

(ख) महानिरीक्षक भारती ।

(ग) महानिरीक्षक, कारागार

(घ) निदेशक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएँ ।

उन राज्य प्रशासकीय के विषय में पूरी क्षमताओं के पद की वेतन श्रृंखला में अधिकतम वेतन रु ३ ५) से अधिक नहीं बर्तों कि स्वीकृति पूर्णतया नियमों के तथा महापेक्षापाल के प्रतिवेदन के अनुसार हो और शत यह भी होगी कि उसके, महापेक्षापाल के तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग के मध्य नियम की मायता तथा माय राशि के सम्बन्ध में कोई मतभेद न हो ।

११६क ५६ जिन व्यक्तियों ने नियुक्ति विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग (1) २३६ अधिकाधिक आयु प्राप्त करनी हो उनके सेवा बाल में वृद्धि करना ।

निम्नलिखितों के सम्बन्ध में २८ फरवरी १९७१ तक प्रथम उम सारीख तक जिस दिन वह ५८ वर्ष की आयु प्राप्त करे इनमें से जो कोई पहले घटित हो जाय —

(१) चिकित्सा अधिकारी जिसमें मेडीकल कालेजों का शिक्षक वग मेडीकल कालेज का अधिकाधिक शिक्षक वग चीफ पब्लिक एनेलिस्ट और चिकित्सा विभाग का महिला नर्सिंग प्रशासकीय वग ।

२ जी ए डी आदेश सं० एफ २(२६)/५५/जी ए/५२ दिनांक २८ १२ ५४ १३ ७ ५७ के स्थान पर आदेश सं० एफ/१८/ (७) एफ II (आर) ५५ दिनांक ११ ५६ द्वारा स्थानापन्न किया गया । ।

१	२	३	४	५
---	---	---	---	---

१(२) निम्नलिखित धोरणों में स्थित व्यक्ति जो भौतिकशास्त्र रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र (वनस्पति तथा जन्तु) पढ़ाते हैं—

(क) शिक्षा विभाग, कालेजिए शिक्षा शाखा —

(i) विज्ञान में स्नातकोत्तर योग्यता रखने वाला स्नातक या स्नातकोत्तर कानूनों के प्रशिक्षण में उस विषय में विभाग के अध्यक्ष (हैड) का काम कर रहे हो।

(ii) विभागा के अध्यक्ष (हैड)

(iii) बरिष्ठ व्याख्याता (लेक्चरर)

(iv) डेमोन्स्ट्रेटर।

(ख) शिक्षा विभाग प्राथमिक तथा माध्यमिक शाखा —

(i) निर्धारित योग्यता रखने वाले बरिष्ठ अध्यापकगण।

(ii) वेतन गृहला सं० २१ या १७ में एल टी सी में विज्ञान के प्रशिक्षक जो विज्ञान में स्नातक हो।

(iii) द्वितीय धोरण के शिक्षक गण जो विधान में स्नातक हो।

(iv) तृतीय धोरण के शिक्षक गण जिनके मूलिक में वकल्पिक विषय विज्ञान हो।

(v) स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस ऐजुकेशन में निदेशक

१ वित्त विभाग आदेश सं० एफ १ (१२) एफ डी, (ई एक्स पी रुल्स)/६७/१ क्रमशः दिनांक १३ ७ ६७ तथा ३० ६ ६७ द्वारा स्थानापन्न किया गया। संशोधन दिनांक ३० ६ ६७ दिनांक १ जनवरी १९६८ के सम्माननीय अध्यापकगण।

१	२	३	४	५
---	---	---	---	---

वरिष्ठ व्याख्याता, व्याख्याता,
१ (सहायक निदेशक तथा रिसर्च
ऐसिमटन्टस् ।

३ सिर्वांगित योग्यता रखने वाले
व्यक्ति जो पोलीटेक्निक तथा
इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टी-
ट्यूट में विद्युत यांत्रिक तथा
सिविल इंजीनियरिंग के विषय
पढ़ाते हों ।

४ पोलीटेक्निक तथा इन्डस्ट्रीयल
ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट में शिक्षण
मण जो विद्युत, यांत्रिकरणी
तथा सिविल इंजीनियरिंग के
विषय पढ़ाते हों ।

१२ मास से अधिक अवधि
के लिये नहीं ।

११६क (11) उन व्यक्तियों के नियुक्ति विभाग
सेवा बाल में बुद्धि
करना जिन्होंने
अधिवापिकी आयु
प्राप्त करली हो ।

११६ख ३४६ (1) जिन व्यक्तियों प्रशासन विभाग नियुक्ति
(1) का ५८ वर्ष की विभाग की सहमति से
आयु प्राप्त करने
के दिनों तक सेवा
बाल में बुद्धि
मिल गई हो उन्हें
६० वर्ष तक की
आयु तक पुनः
राज्य सेवा में
नियुक्त करने की
स्वीकृति प्रदान

निर्वाक २८ फरवरी १९७१
तक पूरी गतिमा इस शत के
अधीन रि वेतन का
नियम बिना किसी रियायत
के निम्नलिखिता के विषय
में राजस्थान वित्त विभाग
आदेश सं० एफ १७६०/५६/
एफ १ (१६)/एफ डी/ए/
५७ दिनांक ३० १० ५२ तथा
डी ६५१०/५६/एफ १ (एफ)
(१६) एफ डा/ए/५६ दिनांक

१ गव 'सहायक निदेशक', वित्त विभाग सं० एफ० १ (४२) एफ० डी० (ईएक्सपीकल्स)
६७ निर्वाक १६ मई १९६८ द्वारा जोड़ा गया ।

२ वित्त विभाग आदेश सं० एफ० ६ (२२) एफ० डी० ए एल्स ५६ निर्वाक १८-७ ५६
तथा (एफ० डी० (ईएक्सपी० एल्स) आदेश सं० एफ० १ (४२) एफ० डी० (ईएक्सपी०
एल्स)/६७ I दिनांक १३ ६ १९६७ द्वारा स्थानापन्न किया गया ।

१ - २

३ -

- ४

५ -

करने की शक्ति ।

२०-११ ५६ द्वारा निर्धारित सिद्धान्त के अनुसार तय किया जावे —

(i) चिकित्सक अधिकारीगण जिसमें मेडिकल कालेज के शिक्षक वग मेडिकल कालेज के प्र-चिकित्सक शिक्षक वग, चीफ पब्लिक ऐनेलिस्ट तथा पब-लिक ऐनेलिस्ट और चिकित्सा विभाग का महिना नर्सिंग कमचारी वग ।

पूरी शक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते—

(i) यह कि प्रत्येक मामले में पुन नियुक्ति करने की अनुमति एक एक वष के लिये दी जावे और जबकि उक्त शिक्षक शारीरिक तथा मानसिक रूप में सक्षम (स्वस्थ) हो ।

(ii) जबकि पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र में हो तो दो वष की पुन नियुक्ति के पश्चात् राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (निमित्तदान आफ फक्स श रेक्युलेशन के अनुसार लोक सेवा आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया हो ।

(iii) वेतन का निश्चय राजस्थान सेवा नियमों के नियम ३३७ में लिखे प्रावधानों के अनुसार किया जावे ।

१(२) पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित व्यक्तियों को ६० वष तक की आयु तक पुन नियुक्ति करने की शक्ति जिन्होंने १९५२ से पूर्व राजस्थान या प्रजमेर में शिक्षक के रूप में सेवा का पद ग्रहण किया हो और जो अधिवा पिकी आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त हो गये हो ।

राजस्थान का प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा का प्रतिरिक्त निर्देशक

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| १ नर्सिंग गुपरटेन्ट । | २ सिस्टस । |
| सिस्टर ट्यून्स । | ४ स्ट.प नर्स । |
| ५ सही हैम्य विजिटर । | ६ प्राविमेरो नर्सिंग मिड्य इफ । |

टिप्पणी

द इ मे प्रादाक्षिन नही है इसलिये उनका मर्हता नर्सिंग कमरारिया म होना नही माना जाय ।

१	२	३	४	५
१६५	उन म मचा को पुन नियुक्त प्रदान करवे नियमित परन को दक्षित जिनम धनिय मित रूप स माध बापिकी माधु के दाद भी व्यक्तियों को सेवा मे रल लिया गया हो ।	विमायाध्यक्ष		उन म राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के विषय म पूरी शक्तिया जो १ १२ १९६२ मे पूर्व सेवा निवृत्त हो गये हा । बशर्ते कि पुन नियुक्ति पर बतन पेंशन को जाड कर जिनम मृत्यु तथा रिटायरमेन्ट प्रेषुटी के बराबर की राशि सम्मिलित है, पिछली बार लठ ये गये वेतन म अधिक न हो और अन्य शर्तें वही होगी जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जावें ।

२ ज्ञापन

राजस्थान सेवा नियम धारा २ के परिशिष्ट IX (नवम) में क्रमांक १६६ (१) तथा १६६ (१) के सामने कोष्क ५ म लिखित शब्दावली 'मेडिकल कालेजो का शिक्षक वर्ग' (वित्त विभाग अधिसूचना म० एफ १ (४२) एफ डा० (ईएससी रुल्स)/६७ I दिनांक १३ ६ १९६७ द्वारा जोड़ा गया) के अंतर्गत समाविष्ट सरकारी कर्मचारियों की पत्र श्रेणी के विषय म कहीं कहीं सुधार प्रकट किया गया है । एतद् द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि शब्दावली "मेडिकल कालेजो का शिक्षक वर्ग" स ल गय उन अधिकारियों से है जिनकी गणना राजस्थान मेडिकल सर्विस (कालेजियट ब्राच) नियम, १९६२ से सलग अनुसूची म की हुई है ।

- | |
|--|
| १ वित्त विभाग सं एफ १ (४) एफ डी (ई एस सी रुल्स)/६४ दिनांक १८ १२ ६४ द्वारा जोड़ा गया । इसकी प्रभाव केवल २८ २ ६६ तक ही होगा । |
| २ वित्त विभाग फादेश सं एफ १ (३५) एफ डी- (ई एस सी रुल्स)/६७ दिनांक २७ मई, १९६८ द्वारा जोड़ा गया । |

१	२	३	४	५
२०	२६२	सरकारी कमचारियों के () नियम २६३ की पेन्शन (परिवार (1) (ख) के प्रावधानानुसार पेन्शन सहित स्वीकृत करना।		
१२०क	२१३	सेवा की कमी क्षमा (फर्गोन) करना (1) विभागाध्यक्ष ३ मास तक (II) प्रशासन विभाग १२ मास तक वित्त विभाग के परामर्श से		निम्नलिखित शर्तों के अधीन (1) यह शक्तियाँ केवल उन निम्न वेतन कमचारियों के विषय में प्रयोग में ली जायेंगी जो असमर्थता तथा मुप्रावजा पेन्शनो (ईनवेलिड एण्ड कम्पेन्सेशन पेन्शन) पर अप्रसर हो रहे हैं। (II) जबकि (सेवा काल) समा करने (फर्गोनेशन) का प्रभाव अष्टवारी सेवा ५ वर्ष या २० वर्ष बनने का हो, जिसके कारण सरकारी कमचारी या उसका परिवार मरुतु तथा रिटायरमेंट प्रेरुटी या परिवार पेन्शन राजस्थान सेवा नियमों के नियम २५७ तथा २६१ के अधीन प्राप्त करन का पत्र बन जाता है, तब इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
			टिप्पणी	
			राजदावली / निम्न वेतन कमचारियों से तात्पर्य उन कमचारियों से समझना चाहिये इनका वेतन (जिसमें वेतन के हिस्से की सब उपलब्धिया सम्मिलित है) सेवा निवृत्त होते समय ० २००) से अधिक नहीं था।	
			२० स २१२ सेवा की रुकावट के लिये क्षमा करना (जो चाहे)	सरकार के प्रशासन विभाग पूरी शक्तियाँ, जो निम्न लिखित शर्तों के अधीन होगी —

१ () जी ए डा आन्ध्र स एफ २ (३६) जी ए/ए/५२ दिनांक १३.५.५५
द्वारा सौंपित किया गया।

२ वित्त विभाग आदेश सं० आई डी /५२३३/५४ एफ I (एफ) ६३ एफ डा ए/ ५७ II निर्मांक १५१६० द्वारा स्थगनापन किया गया

१ वित्त विभाग आदेश सं एफ १ (७५) एफ डी ए स्लस/६२/II दिनांक २६ ११ ६२ द्वारा स्थानापन्न किया गया।

१	२	३	४	५
---	---	---	---	---

स्थापित या संपन्न
 दो २१ सेवाकारों
 ४ बीच में ११
 संपन्न या संपन्न
 सेवा और संपन्न
 सेवा के बीच
 का समय ॥ या
 समय उक्त है ।

(i) सेवा में संपन्न मर-
 गरी समय के दिनांक
 के आधार के दिनांक का एक
 बार है। बाह्ये,

(ii) सेवा में सेवा के पूर्व का सेवा
 का 'संपन्न' में समय संपन्न
 का नहीं होता बाह्ये और
 या या संपन्न संपन्न होने
 के समय में, सेवा के
 सेवा का समय संपन्न में
 संपन्न या संपन्न (संपन्न)
 नहीं की जाय ता सेवा
 सेवा की जाय ता जायगी,
 याय काय से समय नहीं जाना
 बाह्ये ।

(iii) सेवा में एक वर्ष में
 संपन्न समय की नहीं जानी
 बाह्ये । सेवा में दो या
 संपन्न होने को संपन्न में
 सेवा की जाय ता संपन्नियों
 का समय और एक वर्ष में
 संपन्न नहीं जानी बाह्ये
 परन्तु इन संपन्नियों का प्रयोग
 ऐसे मामलों में नहीं किया
 जायता जिनमें राजस्थान
 राज्य के पुनर्गठन से पूर्व
 किसी संपन्नियों Co-cha-
 nted) राज्य (उप ईकाई
 में संपन्न होने वाले किसी
 राजा के राज्य संपन्न) की
 सेवा ॥ या किसी जागीर के
 संपन्न की किसी सेवा से
 या पुनर्गठन से पूर्व के संपन्न
 में, संपन्न तथा मध्यभारत
 की सेवा से संपन्नियों परकी

१	२	३	४	५
				यत्र सम्मिलित हो घोर बाद में विसो विभिन्न राय ईसाई, राजा के राज्य या डिपार्चमें में निगुनित हो गई हो ।
१२१ ३२	असन्निव बमबा रियों की वेनान को सम्पूर्णन (परिवर्तन वरन का स्वीकृति देना ।			नियमों की पालना के अधीन रहने, अधीनस्थ सारक वर्गीय तथा अनुय श्रेणी समचारियों के सम्बन्ध में विभागाध्यक्षा की पूर्ण शक्तिता हैं ।
१२२	सोपित किया गया ।			नियमों की पालना के अधीन रहने अधीनस्थ सारक-वर्गीय तथा अनुय श्रेणी समचारियों के सम्बन्ध में विभागाध्यक्षों की पूर्ण शक्तिता हैं ।
२३ २४	किसी सरकारी बर्मबारी को उस का अविव्य निधि (Provident Fund) में जमा राशि में न प्रत्येकी रूप से राशि स्वीकृत करना—			

राजस्थान सरकार के आदेश

अस १—पन्थन के मामल शीघ्रता से निपटाना सुनिश्चित करने हेतु डिप्लोमेटिक राज प्रमुख ने, राजस्थान सेवा नियमों के नियम २६३ की टिप्पणी का प्राथिक संगोपन करते हुए, प्रमत्त होकर निम्नलिखित अधिचारियों को उनके क्षेत्र के उन समस्त श्रमिका के अ राजपत्रित कमचारियों के सम्बन्धित वेतन स्वीकृत करने की शक्ति प्रदान की है जो १४५० से पूर्व सेवा निवृत्त हो गये थे परन्तु इस बात के अधीन रहने कि यह शक्ति केवल उन मामलों में प्रयोग में ली जायगी जिसमें पन्थन तथा/प्रथवा प्रेचुटी की देयता के सम्बन्ध में महासत्तापाल का बिना गस्त का प्रमाणपत्र अभि निहित कर दिया गया हो, और इस प्रकार से प्रमाणित राशि को सामो लेक —

१ भारती (पुनिस) विभाग — अधीक्षक भारती ।

२ राजस्व विभाग — जिलाधीन

१ वित्त विभाग आदेश स एफ ६ (११) एफ डी ए (स्लम)/५८, दिनांक २८ ८ ५८ द्वारा स्थापित किया गया ।

२ वित्त विभाग का आदेश स एफ १६६१/५८ एफ १८ (७) एफ II/५५ दिनांक २८ ४ ५८ द्वारा स्थापित किया गया ।

३ वित्त विभाग आदेश स एफ २१ २ एफ II, ५३ दिनांक २१ फरवरी ५६५१ ।

- ३ शिक्षा विभाग "पाठशाळा के निरीक्षण।
- ४ निम्नलिखित तथा स्वाभ्युप विभाग विवरण तथा स्वाभ्युप सराया के सहायक निदेश।
- ५ सावजनिक निर्माण विभाग (पी डब्लू डी) " अधीनस्थ अभियन्ता।
- ६ वन विभाग " वनों के सरदार (क्वार्टरमास्टर)
- ७ सामर तथा आवारा रो विभाग उप आयुक्त, पुगी तथा आवारा रो

स २—वित्त विभाग आदेश स एफ २१ (२) एफ II/५३, दिनांक २१ फरवरी १९५३ जो राजस्थान सरकार के आदेश स १ के रूप में है, के भागे हिज हाईनेस राज प्रमुख ने प्रमत्त होकर जिला तथा सत्र न्यायाधीशों को उन समस्त थ्रिप्टियों के प्र राज पत्रित राजपत्रियों से सम्बंधित पेशन स्वीकृत करने का शक्ति प्रदान की है जो उनके अधीन कार्य कर रहे थे और जा १४५० से पूर्व सेवा निवृत्त हो गये थे यह शक्तियां उल्लेखित प्रसंग के आदेश में निर्धारित शर्तों के अनुसार हागा।

स ३—वित्त विभाग आदेश स एफ २१ (२) एफ II/५३, दिनांक २१ २ ५३ तथा ६ ५ ५३ के भागे हिज हाईनेस राज प्रमुख ने प्रसन्न होकर की उक्त आदेश में उल्लेखित जिन विभिन्न अधिकारियों को जो मौजूदा पेशन शीघ्रता से निपटाने हेतु शक्तियां दी गई हैं वे अधिकारी वक्तमान कटोव्यूटरी प्रोविडेंट फंड के जेर तजवीज मामलों को निपटाने के सम्बंध में भी इस शक्ति का प्रयोग करेगे।

स ४—हिज हाईनेस राज प्रमुख ने प्रसन्न होकर आदेश प्रदान किया है कि श्री बी सी दत्त को, जिन्हें १४५५ से पूर्व सेवा निवृत्त होने वाले तथा जो रु २५ से अधिक पेशन सम्भवतया प्राप्त करेगे उनके पेशन के दावे निपटाने हेतु नियुक्त किया गया है ऐसे समस्त मामले निपटाने की पूर्ण शक्तियां प्रदान की जाये। वह उक्त मामला को अंतिम रूप से निपटाने के लिये सरकार को तथा समस्त अधीनस्थ प्राधिकारियों की शक्तियां प्रयोग करेंगे।

स ५—अ-राजपत्रित सेवा निवृत्त सरकारी कमचारियों के पेशन के मामले शीघ्र गति से निपटाने की दृष्टि से, राज्यपाल ने प्रसन्न होकर निम्नलिखित शक्तियां विशेषाधिकारी (पेशन) को प्रदान की है। यह शक्तियां उसी मामले में प्रयोग में लायी जावेगी जबकि पेशन की सम्भावित राशि रुपये १०० मासिक से अधिक न हो।

१ वित्त विभाग आदेश स एफ २१ [२] एफ II/५३ दिनांक ६ मई १९५३।

२ वित्त विभाग आदेश स एफ २१ (२) एफ II/५३, दिनांक १० जुलाई १९५३।

३ एफ ४ (६३) पी एस ओ/०५ (आर)/५५, दिनांक ११ मई १९५५।

४ वित्त विभाग सख्या एफ ६ (२५) एफ डी ए (रुस) ५६ दिनांक २२ ६ ५६,

५ ११ ५६ तथा ६ ४-६० द्वारा जोड़ा गया।

क्रमांक	शक्ति की किस्म	शक्ति की सीमा
१	सेवा के क्रम भंग को कण्डोन (क्षमा) करने की शक्ति	निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते, प्रत्येक अवसर पर एक वष तक के लिए— [१] क्रमभंग, सेवा से त्याग पत्र देने, वसर्खाशुल्की या पृथकीकरण, दुराचरण या दिवालीया होने या अदक्ष होने के कारण नहीं हुआ हो [२] सेवा का क्रमभंग एक सत्रा वित्त राज्य से भ्रय में सेवा परिवर्तन के फलस्वरूप नहीं हुआ हो ।
२	व्यक्तिगत मामलों में राजस्थान सेवा नियमों के नियम २८६ के अधीन कार्यालयाध्यक्ष द्वारा दी गई समानांतर गवाहों ग्रहण करने का अधिकार	पूरी शक्तियां ।
३	असमर्थता [अशक्तता] की तारीख के पश्चात् सहकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवा को सहकारी सेवा के रूप में ग्रहण करने की शक्ति जिसकी अवधि एक वष से अधिक नहीं होगी ।	पूरी शक्तियां ।
४	अक्षतता प्रमाण पत्र उचित प्रपत्र में नहीं होने पर भी ग्रहण करने की शक्ति	पूरी शक्तियां ।
५	ऐसे मामलों को पुनर्नियोजन प्रदान करने नियमित बनाने की शक्ति जिनमें सेवा निवृत्ति की आयु से परे किन्हीं व्यक्तियों की अनियमितता से सेवा में रखा लिया हो ।	पूरी शक्तियां । पुनर्नियोजन समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर स्वीकृत किया जावेगा ।

१	२	३
६	सर्विस नुक में अभिलिखित जन्म तिथि में काट कूट तथा उपरिलिखन (over writing) समा करने की शक्ति तथा घतत जन्म तिथि ग्रहण करना	पूरी शक्तियाँ
७	राजस्थान सेवा नियमों के निर्णय २६३ के अधिन पेशन स्वीकृत करने की शक्ति।	उन मामलों में पूरी शक्तियाँ जिनमें सम्बन्धित व्यक्ति १६५६ से पूर्व सेवा निवृत्ति हो गये थे और जबकि पेशन की राशि रु २५ प्रति मास से अधिक होन की सम्भावना न हो।

टिप्पणियाँ

शक्ति का प्रयोग महालेखापाल द्वारा पेशन के हक का प्रतिवेदन दिये जाने के पश्चात् किया जावेगा।

१२४	राजस्थान सेवा नियमों के नियम ३०८ के अधिन किसी पेशन धारी को व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्ति प्रदान करना।	जिस जिसे से पेशन उठाई जाती है उसके जिलाधीश की पूरी शक्तियाँ
२२५	राजस्थान सेवा नियमों के नियम ३१२ (ख) के प्रयो जानाथ किसी एजेंट का अनमोदन करना	व्यक्तिगत पेशनधारी होने के मामले में एजेंटों के सम्बन्ध में पूरी शक्ति या जिलाधीश को है बशत कि पेशन की राशि अस्थायी वृद्धि के अतिरिक्त रु १००/ प्रति मास से अधिक न हो जो निम्नलिखित शर्तों के अधिन होगी — [१] एजेंट ने पेशन उठाने के लिए पेशनधारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुस्तार नामा प्राप्त कर लिया हो।

१ जी ए डी आदेश संख्या एफ २/१६६) ४ ए/ए/५१ दिनांक १८ ५ १९५४ द्वारा प्राप्त।

२ जी ए डी आदेश संख्या एफ २ (३६) जी ए/ए/५४ दिनांक २६ १२ ५४ द्वारा प्राप्त।

१	२	३
		(२) अधिक भुगतान वापस जमा कराने के लिये तथा नियम ३१२ की अथवा अपेक्षाओंकी पूर्तिके लिये एजेन्ट ने सचित इकरारानामा निष्पादित कर दिया हो ।
		(३) अपना कर्तव्य पालन करने तथा अधिक भुगतान की गई राशि वापस जमा करने के योजनार्थ जिलाधीश को एजेन्ट की आर्थिक स्थिति पर सतोष हो जावे ।
		(४) इस मद् के अधीन दिये गये अनुमोदन का पुनरावलोकन उपरोक्त शर्तों के निरन्तर पालन के विषय में प्रति वर्ष किया जायगा ।

१	२	३	४	५
१२६ ३५६	किसी वेतनधारी को किसी वाणिज्य सम्बन्धी नियन्त्रण ग्रहण करने की अनुमति देने की शक्ति	नियुक्त (ए) विभाग	पूरी शक्ति	

परिशिष्ट X (दसवां)

राजस्थान सरकार ने, चिकित्सा विभाग के कमचारियों द्वारा अपने निजी पेते (प्राइवेट) प्रैक्टिस में ली जाने वाली निम्नलिखित फीसों (शुल्क) की सशोधित अनुसूची निर्धारित की है —

अनुसूची क'

राजस्थान सरकार ने चिकित्सा अधिकारियों द्वारा उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस में ली जाने वाली फीसों की अनुसूची ।

	दिन (प्रातः ६ से साय = बजे तक)	रात (साय = से प्रातः ६ बजे तक)
१ (१) विशेषज्ञ जो रु० ५०० से १००० के वेतन अखला में हो	रु० १५/—	रु० २०/—
(२) जिला चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी जो रु० ४०० से ८०० के वेतन अखला में हो	रु० १०/—	रु० १५/—
— (३) सिविल एसिस्टेंट-सजन श्रेणी प्रथम	रु० ५/—	रु० ७/—
(४) सिविल एसिस्टेंट सजन श्रेणी द्वितीय	रु० ३/—	रु० ५/—
२ (क) जबकि डाक्टर द्वारा जांच करने में समय ३ घंटे तक लगे	नगर पालिका की सीमाओं के भीतर उपरोक्त फीसें लागू होंगी प्रथम जहाँ नगर पालिका की सीमाये न हों वहाँ ५ मील के अर्ध व्यास [घेरे] के भीतर यही फीसें लागू रहेंगी । ५ से १० मील के अर्ध व्यास में फीसें उपरोक्त हैं १३ गुणा होंगी । उपरोक्त दूरी से तीन गुणा । उपरोक्त दूरी से पांच गुणा ।	
[ख] जबकि समय ३ से ६ घंटों के बीच में हो		
[ग] जबकि समय ६ से १२ घंटों के बीच में हो,		

[घ] जबकि समय १२ घण्टों से पारस्परिक इकरार के अनुसार अधिक लगे ।

३ वाहन व्यय निर्धारित फीस के अतिरिक्त होगा और यदि वाहन रोजी द्वारा दिया हुआ न हो तो निम्नलिखित दर से लिया जायगा —

[क] ५ मील तक के घर्ष व्यास [घेरे] में रु १) दोनों ओर का ।

[ख] ५ से २० मील तक के घर्ष व्यास में रु २) दोनों ओर का ।

[ग] २० मील से अधिक टेक्सी की दर से ।

४ राजस्थान सरकार के कमचारियों तथा उनके परिवारों को ५० प्रतिशत रियायत मिलेगी, उनके वाहन को व्यवस्था अथवा वाहन व्यय उपरोक्त नोट में निर्धारित दरों के अनुसार पूरा लिया जायगा ।

‘परिवार’ में सरकारी कमचारी की पत्नी [महिला राज्य कर्मचारी होने की दशा, में पति] पुत्र, माता, पिता, अवयस्क भ्राता अविवाहित बहनें या पुत्रिया, विधवा बहनें या पुत्र वधुएं सम्मिलित हैं, यदि वे उक्त सरकारी कर्मचारी पर पूरातया निर्भर हों ।”

५ केन्द्रीय सरकार के कमचारी भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों से शासित होंगे ।

अनुसूची ‘अ’

राजस्थान सरकार के नसिंग कमचारी वगैरे द्वारा ली जाने वाली फीस की अनुसूची —

	दिन [प्रातः ६ बजे से साय ८ बजे तक]	रात [साय ८ बजे से प्रातः ६ बजे तक]
१ स्टाफ नर्स तथा कम्पाउंडर प्रथम श्रेणी के	रु० २/—	रु० ३/— सारे दिन के लिये रु० ८ सारी रात्रि के लिये रु० १५/—
२ मिडवाइज तथा कम्पाउंडर द्वितीय श्रेणी के—	रु० १/५०	रु० २) (सारे दिन के लिये रु० २/— (सारी रात्रि के लिये रु० ८/—
५ कम्पाउंडर श्रेणी तृतीय तथा चतुर्थ के नस दाइया तथा दाइया	रु० १/—	रु० १/५०/—

टिप्पणियाँ

१ राजस्थान सरकार के कमचारियों तथा उनके परिवार वालों को ५० प्रतिशत रियायत मिलेगी ।

२ ‘परिवार’ में सरकारी कमचारी की पत्नी [महिला राज्य कमचारी होने की दशा में, पति] पुत्र माता पिता, अवयस्क भ्राता, अविवाहित बहनें या पुत्रिया विधवा बहनें, या पुत्र वधुएं सम्मिलित हैं यदि वे उक्त सरकारी पर पूरातया निर्भर हों ।

३ उनके वाहन की व्यवस्था या वाहन व्यय नहीं होगा जो अनुसूची 'क' में निर्धारित है।

अनुसूची 'ग'

प्रसव के संचालन करने के लिये फीम की अनुसूची —

	प्रसव के मामले	
	सामान्य रु०	प्रसामान्य रु०
१ विशेषज्ञ जो ५०० १००० की वेतन श्र खला में हो।	१००/—	१५०/—
२ जिला चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी या कनिष्ठ विशेषज्ञ जो ४०० ८०० की वेतन श्र खला में हो।	५०/—	७५/—
३ डाक्टर जो सी ए एस प्रथम श्रेणी के पद स्तर पर हो।	३०।—	४५।—
४ डाक्टर जो सी ए एस द्वितीय श्रेणी के पद-स्तर पर हो।	२५।—	३७।५०
५ स्टाफ नर्स तथा कम्पाउंडर प्रथम श्रेणी।	१०।—	१५।—
६ मिडवाइज तथा कम्पाउंडर, द्वितीय श्रेणी।	५।—	६।५०
७ कम्पाउंडर श्रेणी तृतीय तथा अनुप, और नर्स दाइया तथा दाईया।	४।—	६।—

टिप्पणियाँ

१ राजस्थान सरकार के कर्मचारियों तथा उनके परिवार वालों को ५० प्रतिशत रियायत मिलेगी।

२ उनके वाहन की व्यवस्था या वाहन व्यय नहीं होगा जो अनुसूची 'ख' में निर्धारित है।

३ "परिवार में सरकारी कर्मचारी की पत्नी (महिला राज्य कर्मचारी होने की दशा में पति) पुत्र, माता पिता, अवयस्क भ्राता, [] पुत्रियाँ या बहनें, विधवा बहनें या पुत्र वधुए सम्मिलित हैं यदि वे उक्त सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतया निर्भर हो।

१ शब्द 'अविवाहित' घोषित किया गया; २ वित्त विभाग आदेश सं० एफ १ (बय) एफ डी (ईएसपी-पी रुल्स) ६६ दिनांक ३३-१२-६७

अनुसूची 'घ'

आयुर्वेदिक विभाग के कर्मचारियों द्वारा उनकी ग्राइवेट प्रेक्टिस में ली जाने वाली फीसों की अनुसूची ।

	दिन (प्रातः ६ बजे से - सायं ८ बजे तक)	रात्रि के पश्चात् (सायं ८ बजे से प्रातः ६ बजे तक)
(क) आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य	५/-	७/-
(ख) प्रोफेसर्स तथा ओपधि विशेषज्ञ	४/-	६/-
(ग) लेक्चरर्स (व्याख्याता), वैद्य श्रेणी 'क' निरीक्षक तथा सहायक ओपधि (अनुसंधान)	३/-	५/-
(घ) वैद्य श्रेणी 'ख' तथा 'ग'	२/-	४/-
(ङ) नर्स तथा कम्पाउण्डर्स	१/-	२/-

२ वाहन, व्यय निर्धारित फीस से अतिरिक्त होगा और अनुसूची 'क' के मद सं ३ में उल्लेखित दर से यदि रोगी वाहन उपलब्ध नहीं करे, तो लिया जायगा ।

II अनुसूची 'ग' के नीचे वर्तमान टिप्पणी ३ में लिखित शब्द 'पुत्रिया' से पूर्व शब्द 'अविवाहित' लोपित किया जायगा ।

(१) भारतीय सविधान के अनुच्छेद ३०६ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल प्रसन्न होकर निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्

'(१) ये नियम राजस्थान चिकित्साधिकारी फीस नियम १९६४ कहलाएंगे ।

(२) ये राज्य सरकार के काम काज से सम्बन्धित सेवा करने वाले समस्त चिकित्साधिकारियों (Medical officers) पर लागू होंगे ।

टिप्पणी

शब्द चिकित्साधिकारी में इन नियमों के प्रयोजनाय 'चीफ पब्लिक हेल्थिस्ट' सम्मिलित है ।

(३) (१) उप खण्ड (II) के प्रावधान के सिवाय, ये नियम २१ नवम्बर १९२६ से लागू होने समझे जावेंगे ।

(II) अनुसूची में निर्दिष्ट दरें 'इन नियमों के सरकारी राज पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावशील होंगी ।

१ निर्देश, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य की पक्षों से ३७ एफ डी ऐरेटिन से एफ १ (४६) एफ डी/ए/भार/६१ निम्नांक ३१ १० ६१, से एफ १ (६) (ए) जेन/५५ दिनांक ५ मार्च १९५५ द्वारा जोड़ा गया तथा राजस्थान राज्य पत्र भाग २ व निम्नांक २३ अप्रैल १९५५ में प्रकाशित हुआ ।

२ विन विभाग आदेश से एफ १ (७७) एफ डी (ई) भार) ६५/४ निम्नांक ६ १ ६६ द्वारा जोड़ा गया । इसका प्रभाव २१ ११ ६२ से होगा ।

- १(1) 'पेशेवर उपस्थिति' से तात्पर्य किसी सरकारी अस्पताल में चिकित्सा के दौरान चिकित्सा के करने या शल्य चौर फाड़ (प्रोपरेशन) करने से है।
- (11) पेशेवर उपस्थिति से अतिरिक्त' सेवा में विभिन्न प्रयोजनों के लिये डाक्टरों जाच तथा सरकारी प्रयोगशालाओं और सरकारी अस्पतालों में किया हुआ कीटाणु सम्बन्धी, (Bacteriological) रोग निदान (Pathological) तथा विश्लेषण (analytical) कार्य सम्मिलित है।

३ चिकित्साधिकारियों द्वारा प्राइवेट व्यक्तियों से, जो अस्पताल के विराये के बाड़ों में भर्ती किये गये हों, पेशेवर उपस्थिति के लिये कोई फीस नहीं ली जायगी।

४ (१) निदेशक चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान की सामान्य या विशेष पूव स्वीकृति से, चिकित्साधिकारीगण जनता के द्वायी तथा अन्य राज्य सरकारी तथा राज्य सरकार के किसी व्यापारिक विभाग या सरकारी उद्योगों की सेवा, पेशेवर उपस्थिति से अतिरिक्त दे सकेंगे जो इन नियमों की अनुसूची में बताई गई है और उसी में निर्दिष्ट दरों से फीस वसूल कर सकेंगे।

परन्तु शत यह है कि कोई चिकित्साधिकारी, किसी ऐसे सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते जो इस विषय में राज्य सरकार जारी करे, उस विशेष स्थिति में दर कम कर सकेगा जिससे वो वह सवित व्यक्ति की अधिक परस्थितियों के कारण, या सावजनिक हित के किसी अन्य कारण से, वह ऐसा करना आवश्यक समझे।

१(२) इस प्रकार से प्राप्त की गई फीस राज्य सरकार तथा सेवा देने वाले चिकित्साधिकारी के बीच ३ तथा २ के अनुपात में विभाजित करली जायगी अथवा जब कि सेवा प्रयोगशाला में दी गई हो तो सरकार और प्रयोगशाला (लेबोरेटरी) के अध्यक्ष के बीच ऐसा विभाजन होगा जो अपने भाग का वटवारा अपने सहायकों के साथ इस प्रकार से करेगा जो वह न्यायोचित समझे।

परन्तु शत यह है कि किसी विश्व विद्यालय या अन्य परीक्षक संस्था को परीक्षक या व्याख्याता के रूप में दी गई सेवा के लिये प्राप्त पूरी फीस सेवा देने वाला चिकित्साधिकारी अपने पास रख सकेगा।

(३) इस नियम में व्यक्त कोई बात चिकित्साधिकारियों को सरकारी अस्पतालों के बाहर जनता को ऐसी सेवा देने से वजित करती हुई नहीं मानी जायगी जो पेशेवर उपस्थिति न हो और जो इन नियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट सेवाएँ न हों, और राज सरकार द्वारा निर्धारित फीस प्राप्त करने से वजित करती हुई नहीं मानी जायगी।

परन्तु शत यह है कि राज्य सरकार किसी भी समय किसी निर्दिष्ट चिकित्साधिकारी या चिकित्साधिकारियों को जनता को पेशेवर उपस्थिति के अतिरिक्त कोई अन्य विशिष्ट सेवा या सेवाएँ देने से वजित कर सकेगी।

५ (१) सरकार के पक्ष में गवाही देने के लिये न्यायालय द्वारा बुलाया गया (सम्मन से बुलाया गया) कोई चिकित्साधिकारी ड्यूटी पर होना समझा जावेगा और कोई फीस पाने का हकदार नहीं होगा ।

(२) सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य पक्ष में न्यायालय द्वारा सम्मन से बुलाया गया चिकित्साधिकारी वह फीस प्राप्त करेगा जो उक्त न्यायालय निश्चित करे परन्तु उसका केवल उनना अंश स्वयं रख सकेगा जितना उसके आवेदन करने पर निदेशक चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवामें स्वीकृत करे और शेष राशि राज्य सरकार के खाते में जमा करायेगा ।

अनुसूची

टिप्पणी

यह अनुसूची माधारण ड्यूटी के दौरान किये गये काय पर लागू नहीं होती ।

क्रमांक	काय की किस्म	फीस की दर
१	शारीरिक योग्यता का प्रमाणपत्र	रु ५/- यदि एक डाक्टर जाच करे।
(क)	सरकारी सेवा के लिये प्रत्याशी के नाम का	रु १६ मंडल द्वारा जाच होने की दशा में । (चुनाव करने वाले तथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भेजे गये प्रत्याशी की जाच नि शुल्क की जायगी ।
(ख)	शिक्षण सस्थानों, जैसे सरकारी तकनीकी कालेजो या प्रशिक्षण स्कूलों में प्रवेश हेतु प्रत्याशी के नाम का	रु ४
२	पेशान में परिवर्तन (क्रम्यूटेशन) के लिये डाक्टरी जाच ।	रु १६
३	(क) विश्वविद्यालय या किसी अन्य परीक्षण सस्था में परीक्षक की सेवा के लिये ।	वह फीस जो विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षक सस्था निश्चित करे ।
(ख)	व्याख्याताओं के रूप में सेवा	वह फीस जो अधिकारियों को नियोजित करने वाली सस्था निश्चित करे ।
४	प्रयोगशाला में जाच	
५	बचड (रक्त)	
१	वाशरमन का रिएन्शन	रु १०
२	रक्त का टेस्ट	रु ८

क्र.सं.	विवरण	दर
३	टोटल डब्लू बी सी काउन्ट	रु ५
४	टोटल आर बी सी काउन्ट	रु ५
५	हेमोग्लोबिन पी सी	रु २
६	ब्लड फिल्म फार डिफरेंशियल काउन्ट	रु ५
७	वाइटल टेस्ट टु ऐनी कम्बिनिशन ग्राफ आरगेनिज्मस्	रु ५
८	ब्लड फिल्म फार पेरेसाइट्स	रु २
९	ब्लड कलचर स्टराइल	रु १०
१०	ब्लड कलचर विद आइसोलेशन एंड इनवेस्टिगेशन ग्राफ स्पेसिफिक आरगेनिज्मस्	रु ५
११	वाइन बज टेस्ट	रु ५
१२	ओपसोनिक इन्डेक्स	रु ५
१३	एलडेहाइड टेस्ट	रु २
१४	ब्लड यूरिया	रु ८
१५	ब्लड कोय्यूलेशन टाइम एण्ड ब्लीडिंग टाइम	रु २
१६	ब्लड क्लोराइड	रु ८
१७	ब्लड कैल्शियम	रु ८
१८	ब्लड एलकली रिजर्व	रु ८
१९	ब्लड कोलोस्ट्रियल	रु ८
२०	ब्लड ग्रूपिंग	रु ५
२१	फास्टिंग ब्लड शुगर	रु ५
२२	शुगर टोलेरेन्स टेस्ट, पूरा	रु १५
२३	सेडिमेन्टेशन रेट	रु २
२४	एबसोल्यूट वेल्थुज	रु १०
२५	धूरान (मूत्र)	
१	क्वालिटेटिव केमीकल एण्ड फीजीकल	रु २
२	क्वालिटेटिव शुगर, एलब्यूमन, यूरिया, ऐसिडिटी, आदि	रु २
३	कलचर इफ स्टराइल	रु १०
४	केमीकल एण्ड माइक्रोसकोपिकल—दोनों के लिये	रु २
५	कलचर विद आइडेन्टिफिकेशन ग्राफ आरगेनिज्मस्	रु १०
६	यूरिया कन्सेंट्रेशन टेस्ट	रु ५

१	२	३
७	स्टूल (ट्टी)	
१	माइक्रोसकोपिकल	रु २
२	केमीकल (फिट ऐनेलिसिस)	रु ५
३	थोक्ल्ट ब्लड	रु २
४	कलचर	रु १०
८	स्पुटम (घूर)	
१	फिल्म एग्जामिनेशन	रु २
२	कलचर ग्राफ टी वी ग्रादि	रु १०
३	एल्यूमिन टेस्ट	रु २
६	पस एण्ड एग्ज्यूटेड्स	
१	माइक्रोसकोपिक	रु २
२	कलचर विद ग्राइडेंटिफिकेशन	रु १०
३	के एल वी फिल्म एण्ड कलचर स्वाब	रु १०
१०	थ्रोमोस्पानल पल्यूइड	
१	माइक्रोसकोपिक	रु ५
२	सैल काउन्ट	रु ५
३	केमीकल फार इनप्रेटिएटस	रु ५
४	कलचर विद ग्राइडेंटिफिकेशन ग्राफ	
	ग्राउन्डिन्गस	रु १०
५	ले-जेस कोलाइडल कोल्ड टेस्ट	रु १०
११	सेरस पल्यूइड	
१	माइक्रोसकोपिकल	रु २
२	सैल काउन्ट	रु ३
३	केमीकल	रु ५
४	डाक ग्राउन्ड इल्यूमिनेशन	रु २
५	कलचर विद ग्राइडेंटिफिकेशन	रु १०
६	ज डेकेशचियम रिएक्शन	रु १५
१२	टिश्यू शेक्शन	रु १५
१३	फक्शनल टेस्ट मील	रु १०
१४	एनीमल एक्सपेरिमेंट	रु १५
१५	वेसाइन्स एटोजेनस	रु १५

	२	३
६	सरकारी अस्पतालों में उन व्यक्तियों की जाच जब ऐसे जाच की फीस प्राइवेट कम्पनियों द्वारा प्रतिपूर्ति (Reimbursed) की जाती हो।	वह फीस, जो यदि उपरोक्त प्रविष्टियाँ में समाविष्ट न हो तो ऐसी दर से जो, राजस्थान सेवा नियमों (भाग द्वितीय) के परिशिष्ट २ दसवें में निर्दिष्ट की हुई हो।
७	जीवन बीमा के प्रयोजनों से व्यक्ति की डाक्टरों जाच	जीवन बीमा निगम द्वारा समय समय पर निर्धारित फीस।
८	प्रिवेशन आफ फूड एडलट्रेशन अधिनियम १९५४ के अधीन निजी खरीददारों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा भेजे गये खाने की वस्तुओं के नमूने का चीफ/पब्लिक ऐनेलिस्ट द्वारा विश्लेषण।	
	(1) घाटा गुड, गन्ना, चीनी, तथा चाय का परीक्षण	रु ५
	(II) दूध का रासायनिक परीक्षण	रु ५
	(III) घी, मक्खन तथा खोया का विश्लेषण	रु ५
	(IV) अन्य खाने की वस्तुओं का विश्लेषण	रु १०
II	इन आदेशों का प्रभाव २१ नवम्बर १९६२ से होगा।	

परिशिष्ट XI (ग्यारहवां)

राजस्थान सेवा नियमों के नियम ३२७ के अधीन निर्धारित कम्यूटेशन (परिवर्तन) तालिका

आगे की जन्म तिथि को आयु	कम्यूटेशन (परिवर्तन) मूल्य जो खरीद के वर्षों की सत्या के रूप में व्यक्त है	आगे की जन्म तिथि को आयु	कम्यूटेशन मूल्य जो खरीद के वर्षों की सत्या के रूप में व्यक्त है
१७	२१ ७७	५२	१२ ७७
१८	२१ ६१	५३	१२ ४०
१९	२१ ४४	५४	१२ ०३
२०	२१ २६	५५	११ ६५
२१	२१ ०९	५६	११ २७
२२	२० ९१	५७	१० ८९
२३	२० ७२	५८	१० ५०
२४	२० ५३	५९	१० १२
२५	२० ३३	६०	९ ७४
२६	२० १३	६१	९ ३७
२७	१९ ९३	६२	९ ००
२८	१९ ७२	६३	८ ६४
२९	१९ ५०	६४	८ २८
३०	१९ २८	६५	७ ९३
३१	१९ ०६	६६	७ ५८
३२	१८ ८३	६७	७ २४
३३	१८ ५९	६८	६ ९१
३४	१८ ३५	६९	६ ५८
३५	१८ १०	७०	६ २६
३६	१७ ८४	७१	५ ९५
३७	१७ ५८	७२	५ ६४
३८	१७ ३१	७३	५ ३५
३९	१७ ०३	७४	५ ०६
४०	१६ ७४	७५	४ ७९
४१	१६ ४५	७६	४ ५२
४२	१६ १५	७७	४ २७
४३	१५ ८४	७८	४ ०२
४४	१५ ५२	७९	३ ७९
४५	१५ २०	८०	३ ५७
४६	१४ ८७	८१	३ ३७
४७	१४ ५३	८२	३ १८
४८	१४ १९	८३	३ ०१
४९	१३ ८४	८४	२ ८६
५०	१३ ४९	८५	२ ७३
५१	१३ १३		

टिप्पणी—यह तालिका ३ ५ प्रतिशत प्रति वर्ष की व्याज की दर पर आधारित है तथा २४ २ ५९ से लागू हुई है।

१ वित्त विभाग आदेश सं २३६/६० एक ७ ए (११) एक डी ए/एल/५९
 तिथि १६ मार्च १९६० द्वारा स्थानापन्न किया गया।

कम्प्यूटेशन तालिका जा राजस्थान सेवा नियमो के नियम ३२७ के अधीन निर्धारित है तथा १ अप्रैल १९६२ क प्रभावशील है ।

र० १) प्रति वर्ष की पेशन के लिये कम्प्यूटेशन (परिवर्तन) मूल्य

आगामी जन्म तिथि का आयु	कम्प्यूटेशन (परिवर्तन) मूल्य जो खरीद के वर्षों की संख्या के रूप में व्यक्त है	आगामी जन्म तिथि का आयु	कम्प्यूटेशन मूल्य जो खरीद के वर्षों की संख्या के रूप में व्यक्त है
१७	२१ १०	५१	१३ ०५
१८	२० ०७	५२	१२ ७०
१९	२० ०५	५३	१२ ३६
२०	२० ०२	५४	१२ ०१
२१	२० १८	५५	११ ६५
२२	२० ५४	५७	११ ३०
२३	२० ४०	५८	१० ९५
२४	२० ०४	५९	१० ५९
२५	२० ०८	६०	१० २३
२६	१९ ९२	६१	९ ८८
२७	१९ ७३	६२	९ ५२
२८	१९ ५७	६३	९ १७
२९	१९ ३८	६४	८ ८२
३०	१९ १८	६५	८ ४७
३१	१८ ९८	६६	८ १२
३२	१८ ७७	६७	७ ७८
३३	१८ ५५	६८	७ ४५
३४	१८ ३३	६९	७ ११
३५	१८ ०९	७०	६ ७९
३६	१७ ८५	७१	६ ४७
३७	१७ ६०	७२	६ १६
३८	१७ ३४	७३	५ ८६
३९	१७ ०८	७४	५ ५७
४०	१६ ८०	७५	५ २८
४१	१६ ५२	७६	४ ९९
४२	१६ २३	७७	४ ७४
४३	१५ ९४	७८	४ ४८
४४	१५ ६४	७९	४ २४
४५	१५ ३३	८०	४ ००
४६	१५ ०२	८१	३ ७८
४७	१४ ७०	८२	३ ५७
४८	१४ ३८	८३	३ ३६
४९	१४ ०५	८४	३ १७
५०	१३ ७२	८५	२ ९९
५१	१३ ३८		

१ कम्प्यूटेशन तालिका, जो नियम ३२७ के अधीन निर्धारित है और जो १ नवम्बर १९६३ से प्रभावशील है।

२ (१) प्रतिवर्ष की पेसन के लिए कम्प्यूटेशन (परिवर्तन) मूल्य

आगामी जम तिथि कम्प्यूटेशन मूल्य जो आगामी जम कम्प्यूटेशन मूल्य जो खरीद को आयु ; खरीद के वर्षों की तिथि को - के वर्षों की सख्या के रूप सख्या के रूप में आयु में व्यक्त है।

१७	२० ३३	५२	१२ ७५
१८	२० २२	५३	१२ ४२
१९	२० ११	५४	१२ ०९
२०	१९ ९९	५५	११ ७५
२१	१९ ८७	५६	११ ४२
२२	१९ ७५	५७	११ ०८
२३	१९ ६३	५८	१० ७३
२४	१९ ५०	५९	१० ३९
२५	१९ ३३	६०	१० ०५
२६	१९ १८	६१	९ ७०
२७	१९ ०२	६२	९ ३६
२८	१८ ८६	६३	९ ०२
२९	१८ ६९	६४	८ ६८
३०	१८ ५१	६५	८ ३४
३१	१८ ३२	६६	८ ००
३२	१८ १३	६७	७ ६७
३३	१७ ९३	६८	७ ३४
३४	१७ ७२	६९	७ ०२
३५	१७ ५०	७०	६ ७०
३६	१७ २८	७१	६ ३९
३७	१७ ०५	७२	६ ०९
३८	१६ ८०	७३	५ ८०
३९	१६ ५६	७४	५ ५१
४०	१६ ३०	७५	५ २३
४१	१६ ०४	७६	४ ९६
४२	१५ ७७	७७	४ ७०
४३	१५ ४९	७८	४ ४५
४४	१५ २१	७९	४ २०
४५	१४ ९२	८०	३ ९७
४६	१४ ६२	८१	३ ७५
४७	१४ ३२	८२	३ ५४
४८	१४ ०२	८३	३ ३४
४९	१३ ७१	८४	३ १५
५०	१३ ३९	८५	२ ९७
५१	१३ ०७		

१ वित्त विभाग आदेश स एफ १ (४६) एफ डी एफ (व्यय नियम) ६३ दिनांक १९ १२ ६३ द्वारा स्थानापन्न किया गया।

१ राजस्थान सेवा नियमों के नियम ३२७ के अधीन निर्धारित कम्यूटेशन (परिवर्तन) तालिका जो १-१ १९६७ से प्रभावशील हुई

ह १) प्रतिवर्ष की पेन्शन के लिए कम्यूटेशन (परिवर्तन) मूल्य

आगामी जन्म तिथि को आयु	कम्यूटेशन मूल्य जो खरीद के वर्षों की संख्या के रूप में व्यक्त है।	आगामी जन्म तिथि को आयु	कम्यूटेशन मूल्य जो खरीद के वर्षों की संख्या के रूप में व्यक्त है।
------------------------	---	------------------------	---

१७	१६ २४	५२	१२ ५०
१८	१६ १५	५३	१२ २०
१९	१६ ०६	५४	११ ८६
२०	१८ ६६	५५	११ ५८
२१	१८ ५६	५६	११ २९
२२	१८ ७६	५७	१० ९४
२३	१८ ६४	५८	१० ६२
२४	१८ ५३	५९	१० ३६
२५	१८ ४०	६०	९ ९७
२६	१८ २८	६१	९ ६४
२७	१८ १४	६२	९ ३१
२८	१८ ००	६३	८ ९९
२९	१७ ८५	६४	८ ६६
३०	१७ ७०	६५	८ ३४
३१	१७ ५४	६६	८ ०१
३२	१७ ३७	६७	७ ६९
३३	१७ २०	६८	७ ३७
३४	१७ ०१	६९	७ ०६
३५	१६ ८२	७०	६ ७५
३६	१६ ६२	७१	६ ४४
३७	१६ ४२	७२	६ १५
३८	१६ २०	७३	५ ८६
३९	१५ ९८	७४	५ ५८
४०	१५ ७५	७५	५ ३०
४१	१५ ५२	७६	५ ०३
४२	१५ ७२	७७	४ ७८
४३	१५ ०२	७८	४ ५२
४४	१४ ७६	७९	४ २८
४५	१४ ५०	८०	४ ०५
४६	१४ २३	८१	३ ८३
४७	१३ ९६	८२	३ ६२
४८	१३ ६८	८३	३ ४२
४९	१३ ३९	८४	३ २३
५०	१३ १०	८५	३ ०४
५१	१२ ८०		

टिप्पणी — यह तालिका ४७५ प्रतिशत प्रतिवर्ष की व्याज की दर पर आधारित है।

१ वित्त विभाग आदेश सं एफ १ (१०) एफ डी (व्यय नियम)/६७ दिनांक २१ मार्च

परिशिष्ट (बारहवाँ)।

भाग १

सेवायें जो विशेषतया चतुर्थश्रेणी सेवाओं (निम्न) के रूप में वर्गीकरण की हुई हैं समस्त विभागों में इन वर्षों के पद धारी, जैसे कि —

१ कारीगर (लोहार, सुधार, वेल्डिंग करने वाले, टनर्स, रंगसाज, आदि)।

२ ऐंटेडेंट (हाजरिये)—गेलेरी या दीर्घा एंटेन्डेंट, वाड एंटेन्डेंट, प्रसपतास एंटेन्डेंट, रिपोटर एंटेन्डेंट सब स्टेशन एंटेन्डेंट सम्मिलित हैं।

३ नाई (बारबर)

४ बरब-दाज।

५ निश्ची।

६ जिल्दसाज तथा सहायक जिल्दसाज।

७ बोहारिया।

८ बॉयज—पुस्तकालय बॉयज, टेलीफोन बॉयज, पेट्रोल बॉयज, तथा वाड बॉयज सम्मिलित हैं।

९ बडल लिफ्टर्स (बडल उठाने वाले)।

१० पॉलिश करने वाले (बनिशर्स)।

११ गाडी वाले।

१२ गाडी हाकने वाले।

१३ बवालिये।

१४ चौकीदार।

१५ जैनमैन (जजीर उठाने वाले)।

१६ सिनेमा के नौकर।

१७ खलासी (क्लीनर्स)।

१८ रसोइये (कुक्स)

१९ कूली।

२० दफेदार।

२१ दफ्तरी।

२२ दाइयें तथा मिडवाइफें।

२३ डारू—वाहक।

२४ कपड़े पहनाने वाले (ड्रेसर्स)

२५ फर्शीश।

२६ फिट्टर ऑपरेटेस।

२७ गाडनर्स (हाली, माली चौधरी, आदि)।

२८ गैंग भेट तथा गैंग मैन (गैंग में काम करने वाले)

२९ गेटपास चैक करने वाले।

३० गेट कीपस तथा गेट साजि-ट्रस (फाटक पर पहरा देने वाले) ।

३१ पहरदार (गाडस्) खजाने के पहरदार वन के पहरदार, घासेट के पहरदार रिजव गाडम् मम्मिलिस् हे।।।।।

३२ हरकार ।

५ भाग

३३-हेल्थस, (महायन्त्र) ।

३४ होशनाक ।

३५ जमादार ।

३६ कर्णवारिये ।

३७ खलनामी ।

३८ मजदूर-स्थायी मजदूर तथा दक्ष मजदूर (प्रवीणश्रमिक) ।

३९ लिफ्ट मैन (लिफ्ट पर काय करने वाला) ।

४० लाइन बलदार ।

४१ मेट तथा ड्रेड (मुख्य) मेट ।

४२ लोपित ।

४३ मोघिया ।

४४ निग्रान तथा निग्रानेदार सहायक निग्रान तथा निग्रानेदार सहित ।

४५ अदली ।

४६ पेकम (पेकिंग करने वाले) ।

४७ पैदल ।

४८ पैट्रोलस ।

४९ पीओस (चपरासीगण) ।

५० रेकड-लिफ्टस (रेकड उठाने वाले) ।

५१ मडक के जमादार ।

५२ शेहरा ।

५३ शिकारी ।

५४ सवार जैसे साइकल सवार, कैमल सवार, शुतर सवार, धुड सवार, डाक सवार ।

५५ भाडू लगाने वाले (स्वीपस) ।

५६ सईम ।

५७ दर्जी (टेनस) ।

५८ टनकीज तथा सहायक टनवीज ।

५९ वाक्स ।

६० वाड मेट ।

६१ घोवी (वॉशरमन) ।

६२ पानी वाला (वाटरमैन) ।

१ नित विभाग अधिभूषी स एफ १३ (एवीस्टस ऐ)/५६ दिनांक ११ ४ ५६ द्वारा

सोपित किया गया ।

- ६३ कृपक (कल्टीवेटर) ।
- ६४ गडरिये ।
- ६५ डोल ।
- ६६ मूर्ता ।
- ६७ मडारो ।
- ६८ वेटर (बेहरे) ।
- ६९ मशालची ।
- ७० बवर्ची (पेट्रीमैन) ।
- ७१ स्टीवार्डस या बटलर ।
- ७२ आवदार ।
- ७३ हलवाई ।
- ७४ बेक्स (डबलरोटी पकाने वाले) ।
- ७५ बेयरस् (बेहरे) ।
- ७६ डेलदार ।
- ७७ बोइलर एटेंडन्ट्स ।
- ७८ लोपित ।
- ७९ खनिजों के पहरेदार (माइन्स गार्ड्स)
- ८० पापस्तिपा ।
- ८१ मिस्त्री ।
- ८२ पहरायती ।
- ८३ सरवण ।
- ८४ टिनमैन (टिन का काम करने वाले)
- ८५ लोपित ।
- ८६ स्टोर मैन (मठार गृह का भ्रादमी) ।
- ८७ पदों भ्रादि बनाने वाले (अपहोल्ट्सटस)
- ८८ चमकार (चमड़े का काम करने वाला) ।
- ८९ रगरेज ।
- ९० लश्कर ।
- ९१ सेनिटरी सुपरवाइजर (सफाई पर्यवेक्षक) ।
- ९२ सिनेमा ऑपरेटर (सिनेमा की मशीन चलाने वाला)
- ९३ नादर डयोडी ।
- ९४ नादर लिडरिया ।
- ९५ दरवान ।

१ अधिवृत्तना स एफ ३ (१७) एपोइन्ट्स-ए/६२ दिनांक २१-८-६२ द्वारा लोपित किया गया ।

२ नियुक्ति विभाग आदेश स एफ १८ (१६) एपोइन्ट्स ए/५६, दिनांक ११-४-५६ द्वारा लोपित किया गया ।

- ६६ हाजारो ।
 ६७ ग्योर्गा ।
 ६८ प्रोवीजन पीपन (खाद्य सामग्री पर चररासी) ।
 ६९ कोच बनाने वाला ।
 १०० ढालने वाला ।
 १०१ बुलकेनाइज करने वाला ।
 १०२ इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने वाला ।
 १०३ बैटरी वाला आदमी ।
 १०४ मोची ।
 १०५ रंग करने वाला या चित्रकार (पेन्टर) ।
 १०६ कीठारी देवस्थान विभाग ।
 १०७ भडारी, देवस्थान विभाग ।
 १०८ रोकडिया, देवस्थान विभाग ।
 १०९ तोपाखानी । " "
 ११० अविशोखी " "
 १११ बालभोगी । " "
 ११२ शुभ चिन्तक । " "
 ११३ रसोइया । " "
 ११४ टहलवा । " "
 ११५ भूमटिया । " "
 ११६ कीर्त्तानिया । " "
 ११७ चौददार । " "
 ११८ हरकारा । " "
 ११९ पोशाकी देवस्थान विभाग ।
 १२० जल धारी ।
 १२१ बैयर टेकर (रखवाला) ।
 १२२ टेक्स कलेक्टर ।
 १२३ सहायक ववर्ची (पेट्रीमन) ।
 १२४ मशीन मैन (मशीन पर काम करने वाला) ।
 १२५ फार्म बीएज (खेत पर काम करने वाला) ।
 १२६ मुख्य हान्सी ।
 १२७ हाली ।
 १२८ मछुवा ।
 १२९ हैड मेट (देखासा)
 १३० घोड़ी ।
 १३१ प्रोसेस सर्विस (तामोल कुनदा) ।
 १३२

- १६३। (१)पोर्टस (कुली) ।
 १६४। (२)सुपर ।
 १६५। (३)प्रयोगशाला के लडके ।
 १६६। (४)मरम्मत करने वाले (मेडस) ।

सेवाये जो विशेषतया श्रेष्ठ श्रेणी में वर्गीकृत हुई हैं क-राज्य सेवाये
 अथवा राज-पत्रित पद

I निम्नलिखित सेवाओं में सम्मिलित पदधारी ।

- १ राजस्थान प्रशासकीय सेवा ।
- २ राजस्थान यायिक सेवा ।
- ३ राजस्थान पुलिस सेवा ।
- ४ राजस्थान लेखा सेवा ।
- ५ राजस्थान सचिवालय सेवा ।

II नीचे गणना किए हुए अन्य पदाधिकारी ।

कृषि विभाग

क-कृषि शाखा

- १ कृषि निर्देशक ।
- २ उप निर्देशक ।
- ३ कृषि के सहायक निर्देशक ।
- ४ प्रशासन सहायक ।
- ५ आयिक वनस्पतिज्ञ ,
- ६ कृषि रसायनज्ञ ।
- ७ एटोमोलोजिस्ट (कृषि वैज्ञानिक) ।
- ८ माइक्रोलोजिस्ट (शोध व्याधिविज्ञ) ।
- ९ साम्यिकी ।
- १० कृषि अभियन्ता ।
- ११ सहायक कृषि अभियन्ता ।
- १२ हाइड्रोबोलोजिस्ट (जल विशेषज्ञ) ।
- १३, युनिवर्सिटी कृषि पाठशाला का अध्यापक ।
- १४ जिला कृषि अधिकारी ।
- १५ पत्त विभाग ।

१ कृषिशाखा में एड ३ (१) एटोमोलोजिस्ट (A) III/६४ निम्न ७ १ ६४

२ " " एड ३ (२३) " (७) III/६३ निम्न १२ ६ ६३ "

३ " " एड ३ (१२) " (९)/६४ निम्न ३ ८ ६४ "

४ " " एड ३ (१६) " (III)/२३ निम्न ८ ११ ६३ "

- १६ क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अधिकारी ।
- १७ पशु-पालन अधिकारी ।
- १८ दुग्धशाला विकास अधिकारी ।
- १९ प्रधानाचार्य राजस्थान पशु चिकित्सा उच्च विद्यालय, बीकानेर ।
- २० जिला पशु चिकित्सा अधिकारी ।
- २१ सहायक पौध संरक्षण अधिकारी ।
- २२ 'महायक भू संरक्षण अधिकारी ।
- २३ 'प्रभार अधिकारी, कनिष्ठ कमचारियों का प्रशिक्षण केंद्र ।

ख-पशुधन शाखा

- १ उप निदेशक ।
- २ सहायक निदेशक, पशु चिकित्सा ।
- ३ अधिकारीगण प्रथम श्रेणी ।
- ४ " " द्वितीय श्रेणी ।
- ५ गोशाला विकास अधिकारी ।
- ६ पशु धन विकास अधिकारी ।
- ७ अधीनस्थ पशु चिकित्सक
- ८ सहायक पशु चिकित्सक ।

पुरातत्व तथा प्रजायन्त्रघर विभाग

- १ मुख्य अधीक्षक ।
- २ अधीक्षक ।
- ३ क्वैरेटर (प्रजायन्त्रघर का अध्यक्ष) ।
- ४ 'पुरातत्व' सार्वजनिक ।
- ५ 'कोज तथा खुदाई' अधिकारी ।
- ६ 'यूनिजमेन्टिस्ट (मुद्रा विशेषज्ञ) ।

उद्घटन विभाग

- १ मुख्य चालक (पाइलट) ।
- २ चालक (पाइलट) ।
- ३ भूमि अभियन्ता ।
- ४ रेडियो आपरेटर (रेडियो पर काम करने वाला) ।

आयुर्वेदिक विभाग

- १ निदेशक, आयुर्वेदिक विभाग ।
- २ आपधशाला का प्रभारी व्यवस्थापक ।

१ नियुक्ति विभाग अधिसूचना स एफ २ (१) एपोस्टल ए/६२ दिनांक २५ ३ ६२ द्वारा प्रकाशित किया गया ।

२ " " " स एफ २ (१) एपोस्टल (ए)६४ दिनांक १७ ६-६४ द्वारा जारी किया ।

३ " " " स एफ ३ (१) , (ए)/६५, दिनांक अप्रैल ५५ द्वारा जारी किया ।

३ आयुर्वेदिक महा विद्यालय का प्राध्यापक (प्रोफेसर) ।

४ उप निदेशक ।

जनगणन विभाग—^१सोपित ।

सर्किट हाउसेज

१ अधीक्षक, राजस्थान स्टेट होटल, जयपुर ।

२ भंडारग्रहो के निराक्षक (इंसपेक्टर आफ स्टोस)

नागरिक पूर्ति विभाग

१ विशेष लेखाधिकारी ।

२ लेखाधिकारी ।

३ सहायक लेखाधिकारी ।

४ साक्ष्यकी ।

सहकारी विभाग

१ उप रजिस्ट्रास ।

२ सहायक रजिस्ट्रास ।

३ शिक्षा अधिकारी ।

४ प्रचार अधिकारी ।

^२भावकारी विभाग

१ उप आयुक्त, भावकारी ।

२ प्रशासकीय अधिकारी ।

३ जिला भावकारी अधिकारी ।

४ सहायक भावकारी अधिकारी ।

५ मुख्य प्रासीक्यूटिंग निरीक्षक (कोट इन्सपेक्टर)

६ उप आयुक्त (भवरोधक दल)

७ सहायक भावकारी अधिकारी (भवरोधक दल)

^४वाणिज्यकर विभाग

१ उप आयुक्त, वाणिज्यकर (प्रशासन) ।

२ उप आयुक्त, वाणिज्यकर (अपील)

३ प्रशासकीय अधिकारी ।

४ वाणिज्यकर अधिकारी ।

५ उप प्रधानाचार्य, वाणिज्यकर परिसरा शाळा ।

६ सहायक वाणिज्य कर अधिकारी ।

१ नियुक्ति विभाग अधिगूचना सं एक ३ (१२) एपोइन्टस (ए)/६२, दिनांक ३ न ६२ द्वारा सोपित किया गया ।

२ अधिगूचना सं एक ३ (१६) एपोइन्टस (ए)/६४ नि० १६-८ ६५ द्वारा जोडा गया ।

” ” ” ” दि० २२-८ ६५ द्वारा स्थानापन्न किया गया ।

” ” ” ” नि० १६ ४ ६४ ” ”

- ७ सहायक वाणिज्यकर अधिकारी (अवरोधन दल)
 ८ सहाय्यकी अस्थायिक अधिकारी ।

शिक्षा विभाग

- १ निदेशक ।
- २ उप निदेशक ।
- ३ पाठशालाओं के निरीक्षक, सहायक निदेशक सहित ।
- ४ सम्स्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक ।
- ५ प्रौढ शिक्षा अधिकारी ।
- ६ रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षार्थी ।
- ७ कन्याशालाओं की निरीक्षिकाएँ ।
- ८ पाठशालाओं के उप निरीक्षक जिनमें निदेशक का निजी सहायक, सम्स्कृत पाठशालाओं की उप-निरीक्षक सम्मिलित हैं ।
- ९ कन्याशालाओं की उपनिरीक्षिकाएँ ।
- १० सरकारी प्रथम श्रेणी की महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य ।
- ११ लोपित ।
- १२ सरकारी प्रथम श्रेणी के महाविद्यालयों के प्राचार्यगण ।
- १३ " " " " के व्याख्यातागण ।
- १४ सरकारी इन्टरमीडिएट महाविद्यालयों के व्याख्यातागण ।
- १५ सरकारी उच्च विद्यालयों तथा इसी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं के मुख्य अध्यापक ।
- १६ लोपित ।
- १७ प्रधानाचार्य, कला तथा हस्तकौशल पाठशाला, जयपुर तथा कला संस्थान जयपुर ।
- १८ उप प्रधानाचार्य कला तथा हस्तकौशल पाठशाला जयपुर ।
- १९ विशेष शिक्षा अधिकारी (योजना) ।
- २० प्रधानाचार्य, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बीकानेर ।
- २१ प्रधानाचार्य, सादुल पब्लिक स्कूल, बीकानेर ।
- २२ मोटसरी स्कूलों की मुख्य अध्यापिकाएँ ।
- २३ मुख्य अध्यापिका, गंगा शिशु शाला, बीकानेर ।
- २४ " " शिशु शाला, कोटा ।
- २५ " " " " उदयपुर ।
- २६ " " " " भरतपुर ।
- २७ " " " " जोधपुर ।
- २८ शारारिक प्रशिक्षक, राजस्थान महाविद्यालय जयपुर ।
- २९ पुस्तकालयाध्यक्ष, " " " " जयपुर ।

१ अधिमूचना सं० एफ ३ (१६) एपोइन्ट्स (ए)/६४ दि० २२ ४ ६५ द्वारा जोड़ा गया ।

२ नियुक्ति विभाग अधिमूचना सं० एफ ३ (१३) एपोइन्ट्स, (ए) III/६३ दि० ६ ८ ६२ द्वारा लोपित किया गया ।

पुरातन मंडिर (राजस्थान प्राविष्टम रितन इगटोन्स)

१ निर्देशक ।

२ उप निर्देशक ।

३ परिष्कृत भाष (अनुमोदित) अधिकारी ।

विद्युत् निरीक्षणसम

१ विद्युत् निरीक्षक ।

२ महामन्त्र विद्युत् निरीक्षणगण ।

विद्युत् नगरपालिका विभाग

१ सहायक निरीक्षक ।

वा विभाग

१ वा ५ मुख्य मरक्षक ।

२ वा ६ मरक्षकगण ।

३ क्षत्रीय वा अधिकारीगण ।

४ वा उपयोग अधिकारी ।

५ वा मरक्षक वा अधिकारीगण ।

६ वा मरक्षक अधिकारीगण ।

७ मरक्षक वा अधिकारीगण ।

८ वा ५ मुख्य मरक्षक वा निजी सहायक, जो क्षत्रीय वा अधिकारी के पद पर होते हैं ।

९ अधिकृत वा अधिकारीगण (वायु यात्रा अधिकारीगण) ।

१० निरीक्षणपरिष्कृत प्राविष्टम (वायु यात्रा अधिकारीगण) ।

गैरेज विभाग

१ गैरेज का मुख्य अधिकारी ।

२ माटर अधिकारी ।

३ गैरेज का प्रमुख ।

राजकीय मुद्रणालय तथा सेवान सामग्री विभाग

१ निदेशक, मुद्रण तथा सेवान सामग्री ।

२ अधिकारीगण राजकीय मुद्रणालय ।

३ सहायक अधिकारीगण, राजकीय मुद्रणालय ।

४ लेखाधिकारी ।

उद्योग तथा वाणिज्य

१ निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य ।

२ उप निदेशकगण ।

१ नियुक्ति विभाग, अधिकृतना स एक ३ (१) एप्रील १९४७ (२) ११/६७ तारीख १९४७ द्वारा स्थानापन्न किया गया ।

२ आदेश स एक ३ [१४] एप्रील १९४७ (२) ११/६७ तारीख १९४७ द्वारा स्थानापन्न किया गया ।

- ३ मारकेटिंग (क्रम विक्रम) अधिकारी ।
- ४ ऊन प्रयोगशाला अधिकारी ।
- ५ अभियन्ता ।
- ६ तकनीकी सहायकगण ।
- ७ भेड अनुसंधान अधिकारी ।
- ८ ऊन वर्गीकरण अधीक्षकगण ।
- ९ सयुक्त निर्देशक ।
- १० सहायक निर्देशक, उद्योग तथा वाणिज्य ।
- ११ अधीक्षक, हस्त कौशल मंडल ।
- १२ मैटेल्जिस्ट (धातु शोधक) ।
- १३ जिला अधीक्षकगण ।
- १४ लेखाधिकारी ।
- १५ अधीक्षक कुटीर उद्योग संस्थान ।
- १६ तांड गुण सगठक ।
- १७ व्यवस्थापक ऊन सवारने तथा पूरण करने की संस्थान ।
- १८ अधीक्षक क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन ।
- १९ तकनीकी सहायक, भेड तथा ऊन विभाग ।
- २० ऊन वर्गीकरण अधीक्षक ।
- २१ सामान्य अधीक्षक ।
- २२ ^१उप अधीक्षक,
- २३ ^१पाली अभियन्तागण ।
- २४ ^२प्रधानाचार्य, हस्त कौशल प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर ।
- २५ ^३प्रयोगशाला अधिकारी ।

सोडियम सल्फेट, सयन्न, डोडवाना के लिये ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग-सिचाई

- १ मुख्य अभियन्ता ।
- २ मुख्य विकास अभियन्ता ।
- ३ अधीक्षक अभियन्तागण ।
- ४ अधिशासी अभियन्तागण ।
- ५ मुख्य अभियन्ता का तकनीकी सहायक ।
- ६ सहायक अभियन्तागण ।
- ७ यांत्रिक अभियन्ता ।
- ८ भूगर्भ विशेषज्ञ ।
- ९ सब अभियन्ता (अधोनस्थ अभियन्ता) ।

१ नियुक्ति विभाग अधिसूचना स एफ ३ (२) एपोइटस (ए)/६३ दिनांक ५ २ ६३ द्वारा जोड़ा गया ।

२ " एफ ३ (११) " " ८-२-६२ " "

३ एफ ३ (२२) " " १२ १२ ६३ " "

- १० सहायक लेखाधिकारी ।
- ११ जल विद्या सहायक ।
- १२ श्रम कल्याण अधिकारी ।
- १३ सहायक असनुधान अधिकारी ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन तथा पथ

- १ मुख्य अभियंता ।
- २ अधीक्षक अभियन्तागण ।
- ३ अधिसासी अभियन्तागण ।
- ४ सहायक अभियन्तागण ।
- ५ विशेषाधिकारी जल प्रदाय ।
- ६ धरिष्ट वास्तुविद (सीनियर आरचिटेक्ट) ।
- ७ कनिष्ठ वास्तुविद (जूनियर आरचिटेक्ट) ।
- ८ राजकीय केमिस्ट (रसायनज्ञ)
- ९ लेखाधिकारी ।
- १० उद्यान शास्त्रज्ञ (हॉर्टीकल्चरिस्ट) ।
- ११ अधीक्षक, उद्यान ।
- १२ रसायनज्ञ (जल विभाग)
- १३ विशेषाधिकारी ग्राम जल प्रदान (जल विभाग) ।

जेल विभाग

- १ कारागृहों के महा निरीक्षक ।
- २ कारागृहों के उप-महा निरीक्षक ।
- ३ केन्द्रीय जेलों के अधीक्षकगण ।
- ४ जिला जेलों के अधीक्षकगण ।
- ५ केन्द्रीय तथा जिला जेलों के उप अधीक्षकगण ।
- ६ जेल उद्योगों के निदेशक ।
- ७ चिकित्साधिकारीगण (सिविल एससिस्टेंट सजन थैली प्रथम तथा द्वितीय) ।

श्रम विभाग

- १ सहायक श्रम आयुक्त ।
- २ कारखानों तथा बोइलरो के मुख्य निरीक्षक ।
- ३ श्रम साख्यिकी अधिकारी ।
- ४ महिला कल्याण अधिकारी ।
- ५ श्रम अधिकारी ।
- ६ कारखानों के निरीक्षकगण ।
- ७ खनिजों के निरीक्षकगण ।

१. नियुक्ति विभाग अधिसूचना स एफ ३ (१४) एपइन्ट्स (ए)/६३ दिनांक ३ नवम्बर १९६३ द्वारा
गया ।

८ वोइलरो का निरीक्षक ।

९ कारखानो का चिकित्सा निरीक्षक ।

१० अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ।

चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग

क-चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ।

१ चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक ।

२ उप निदेशक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएँ ।

३ सहायक निदेशकगण, , ,

४ मुख्य नर्सिंग अधीक्षक ।

५ प्रांतीय क्षयरोग (टी बी) अधिकारी ।

६ जीवन-मरण सम्बन्धी सार्वजनिक अधिकारी ।

७ लेखाधिकारी ।

८ प्रिन्सीपल (प्रधान) चिकित्सा अधिकारीगण ।

९ अस्पतालो के अधीक्षकगण ।

१० वरिष्ठ शल्य चिकित्सक ।

११ वरिष्ठ चिकित्सक ।

१२ वरिष्ठ स्त्री रोग चिकित्सक ।

१३, वरिष्ठ नेत्र रोग चिकित्सक ।

१४ शल्य चिकित्सकगण (सर्जन्स) ।

१५ चिकित्सकगण (फिजीशियन्स) ।

१६ स्त्री रोग चिकित्सक ।

१७ नेत्र रोग चिकित्सक ।

१८ एक्स रे विशेषज्ञ ।

१९ दातो का शल्य चिकित्सक ।

२० जिला स्वास्थ्य तथा चिकित्सा अधिकारीगण ।

२१ सिविल ऐसिस्टेंट सर्जन्स श्रेणी प्रथम (४ दातो के चिकित्सक सम्मिलित हैं) ।

२२ नर्सिंग अधीक्षकगण ।

२३ मेट्रन्स ।

२४ स्वास्थ्य अधीक्षकारीगण (एम बी बी एस) ।

२५ महिला अधीक्षक, स्वास्थ्य पाठशाला ।

२६ औषधि रसायनज्ञ ।

२७ विटाणु विशेषज्ञ ।

२८ मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक ।

२९ रसायनिक परीक्षक ।

- ३० व्यवस्थापक, केन्द्रीय चिकित्सालय भण्डार गृह ।
- ३१ राजस्थान चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएँ, श्रेणी प्रथम । (सेलेक्शन ग्रेड)
- ३२ राजस्थान चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएँ, श्रेणी प्रथम ।
- ३३ राजस्थान चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएँ, श्रेणी द्वितीय (वरिष्ठ श्रवला)
- ३४ राजस्थान चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएँ, द्वितीय श्रेणी (कनिष्ठ श्रवला)
- ३५ सहायक स्वास्थ्य अधिकारीगण ।
- ३६ सचिव भण्डार सामग्री त्रय संगठन ।
- ३७ प्रशासनिक अधिकारी ।
- ३८ डेमोन्स्ट्रेटर (प्रनदशक) ।
- ३९ ग्राह्य प्रभारी ।
- ४० सावजनिक विशेषक ।

ए-सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज

- १ प्रधानाचार्य सवाई मानसिंह कालेज ।
- २ निम्नलिखित विषयो के प्राध्यापक—
 - (क) शरीर विज्ञान ।
 - (ख) शरीर रचना (बीर फाड)
 - (ग) औषधि विज्ञान
 - (घ) रोग निदान ।
- ३ रीडर—निम्नलिखित विषयो मे—
 - (क) रोग निदान ।
 - (ख) औषधि विज्ञान (क्लिनिकल) ।
 - (ग) बायो केमिस्ट्री ।
- ४ सहायक प्राध्यापक, निम्नलिखित विषयो मे—
 - (क) शरीर विज्ञान ।
 - (ख) शरीर रचना (बीरफाड) ।
- ५ निम्नलिखित विषयो मे प्रदशन कर्ता—
 - (क) शरीर विज्ञान ।
 - (ख) शरीर रचना (बीरफाड) ।
 - (ग) औषधि विज्ञान ।
 - (घ) रोग निदान ।
- ६ व्याख्यातागण ।

खनिज तथा भूगर्भ विभाग

- १ निदेशक ।
- २ सयुक्त निदेशक (प्रशासन) ।

१ आदेश स एफ ३ (२८) एपोइड/(ए) III/६३ दिनांक १५.६.६५ द्वारा स्थानापन्न किया गया ।

२ आदेश सख्या एफ ३ (२३) एपोइड (ए III) ६३ दिनांक २३.३.६६ द्वारा जोडा गया ।

- ३ खनिज अभियन्तागण ।
- ४ सहायक खनिज अभियन्तागण ।
- ५ रसायनिक-तथा मिट्टी विशेषज्ञ ।
- ६ खनिज व्यवस्थापक ।
- ७ सहायक खनिज व्यवस्थापक ।
- ८ उप-छेदन (ड्रिलिंग) अभियन्ता ।
- ९ रसायनज्ञ ।
- १० सहायक मिट्टी विशेषज्ञ ।
- ११ सहायक अभियन्ता (सर्वेक्षण) ।
- १२ व्यवस्थापक पाटन परियोजना ।
- १३ श्रम कल्याण अधिकारी ।
- १४ वरिष्ठ भू-गर्भ-विशेषज्ञ ।
- १५ कनिष्ठ भू-गर्भ विशेषज्ञ ।
- १६ रसायन तथा मिट्टी अभियन्ता ।

अधिकारी प्रशिक्षण शाला, जयपुर

- १ प्रशासन अधिकारी ।

भारक्षी (पुलिस विभाग)

- १ भारक्षी मोटर अधिकारी गण
- २ निदेशक विधिसम्बन्धी प्रयोग शाला (फोरेसिक लेबोरेट्री) -
- ३ सहायक निदेशक विधि सम्बन्धी प्रयोग शाला ।
- ४ अधीक्षक भारक्षी, रेडिओ सगठन ।
- ५ उप अधीक्षक भारक्षी, रेडिओ सगठन ।

सावजनिक सम्पक निदेशालय

- १ निदेशक ।
- २ उप निदेशकगण
- ३ सहायक निदेशकगण
- ४ छान्ने बीन अधिकारी (स्कर्टिनि ऑफिसर)
- ५ वरिष्ठ फोटोग्राफर ।
- ६ सहायक सम्पादक ।
- ७ मेल (सेजन) अधिकारी ।
- ८ सावजनिक सम्पक अधिकारी ।
- ९ पूछ ताछ अधिकारी ।

सहायता तथा पुनः संस्थापन विभाग

- १ वित्तीय सलाहकार ।
- २ ऋण अधिकारीगण

राज्य बीमा

- १ निदेशक ।
- २ उपनिदेशक ।
- ३ सहायक निदेशक ।

आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय

- १ आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशक ।
- ४ सांख्यिकी ।
- ३ १ उप निदेशक ।
- ४ १ सहायक निदेशक ।

स्थानीय स्वायत्त शासन (स्थानीय सस्याएं)

- १ क्षेत्रीय निरीक्षकगण ।
- २ डिवीजनल पंचायत अधिकारीगण
यातायात विभाग
- १ सहायक क्षेत्रीय यातायात अधिकारीगण । (भार टी भी)
- २ व्यवस्थापक, राजस्थान यातायात सेवा ।
विकास विभाग ।

- १ खण्ड विकास अधिकारी ।
- २ पशु प्रजनन अधिकारी ।
- ३ कृषि प्रसार अधिकारी ।
- ४ २ सम्पादक, "राजस्थान विकास" ।
- ५ २ प्रधानाचार्य ग्राम सेवक केन्द्र ।

उपनिवेशन विभाग

- १ उपनिवेशन के सहायक निदेशक ।
- २ उपनिवेशन के सहसमीक्षक ।

राजस्थान उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट)

- १ उप रजिस्ट्रार (प्रशासन) ।
- २ सहायक रजिस्ट्रार तथा मुख्य न्यायाधीश का सचिव ।

विधि तथा न्याय विभाग

- १ पूरे समय के लिये पब्लिक प्रोसीक्यूटस ।
- २ ४ गवर्नमेन्ट एडवोकेट ।

१ नियुक्ति (ए III) अधिसूचना सस्या एफ ३ (१८) एपो० (ए)/६१ दिनांक २०-३ ६२ द्वारा जोड़ा गया ।

२ नियुक्ति (ए III) विभाग अधिसूचना स, एफ ३ (७) एपोइन्टस (ए)/६३ दिनांक २५ ३ ६३ द्वारा जोड़ा गया ।

३ " " " " " " " " एफ ३ (३) " (ए) III/६४ " २७ ४ ६४ द्वारा जोड़ा गया ।

४ " " " " " " " " एफ ३ (२२) " (ए)/६२ दिनांक ८-११-६२ द्वारा जोड़ा गया ।

- ६ मुख्य यात्रिक अभियन्ता ।
- ७ दायीय यात्रिक अभियन्ता ।
- ८ वक्स मनेजर ।
- ९ भंडार का नियन्त्रक ।
- १० सहायक यात्रिक अभियन्ता ।
- ११ सहायक वक्स मनेजर ।
- १२ तकनीकी सहायक ।
- १३ सहायक अभियन्ता (सिविल) ।
- १४ स्टोर्स अधिकारी ।
- १५ श्रम अधिकारी ।
- १६ वरिष्ठ लेखाधिकारी ।

राजस्थान भूमिगत जल मंडल

- १ प्रभारो अभियन्ता तथा सचिव ।
- २ अधिशासी अभियन्ता (ड्रिलिंग) (खेदन क्रिया)
- ३ अधिशासी अभियन्ता (प्लास्टिक) (भक्त में उडाना)
- ४ भूगर्भ जल विशेषज्ञ ।
- ५ सहायक अभियन्ता ।
- ६ कनिष्ठ भूगर्भज्ञ ।
- ७ रसायनिक ।
- ८ ड्रिलिंग फोरमेन ।

जिला गजेटियर का निदेशालय

- १ अनुसंधान अधिकारी ।
- २ प्राचीन लेखों का निदेशालय (डाइरेक्टोरेट आफ आरकाइव्स)
- ३ प्राचीनलेखों के निदेशक ।
- ४ प्राचीन लेखों के सहायक निदेशक ।

सु-अधीनस्थ सेवार्थी

- नौचे गणना किए हुए पद तथा इसी प्रकार के पद धारण करने वाले
- १ कनिष्ठ लेखा सेवा ।

१ अधिमूचना स एफ ३ (६) एपेंडिक्स (ए) III/६५ दिनांक १५.६.६५ द्वारा अत-
न्यासित किया गया ।

२ " " (६) " (ए)/६५ " २३.७.६५ द्वारा अत-
न्यासित किया गया ।

३ " ३ (१६) " (ए-III)/६५ " ६-११-६५ द्वारा अत-
न्यासित किया गया ।

४ " (१६) (ए) ६२ " १२-१०-५३ द्वारा
अत-न्यासित किया गया ।

नागरिक उद्बुधन विभाग

१ यांत्रिकी ।

१ सहाय्यक विभाग

- १ क्षेत्रीय रसद अधिकारी ।
- २ प्रवर्तन अधिकारी ।
- ३ गोदाम अधिकारी ।
- ४ सहायक जिला रसद अधिकारी ।
- ५ प्रवर्तन निरीक्षक ।

सहकारी विभाग

- १ निरीक्षक ।
- २ सहायक निरीक्षक ।
- ३ क्षेत्र प्रचारक सहायक ।
- ४ मशीन चलाने वाला (मॉपरेटर) ।
- ५ ग्राम सेवक ।
- ६ ग्राम्य पुनर्निर्माण विभाग के शिक्षक ।
- ७ दल ।
- ८ व्यवस्थापक नाटक इकाई ।
- ९ चित्रकार (आर्टिस्ट) नाटक इकाई ।
- १० कलाकार (एक्टर) नाटक इकाई ।
- ११ संगीतकार नाटक इकाई ।
- १२ सहकारी प्रसार अधिकारी ।

व्यवसायिक कर विभाग

- १ बानूनी सहायक ।
- २ निरीक्षक ग्रैंड प्रथम ।

१ अधिसूचना संख्या एफ ३ (२१) एपोइटस् (ए III)/६५ दिनांक ४ २ ६५ द्वारा नागरिक रसद विभाग के लिये निर्विण्ट किया गया ।

२ अधिसूचना सं एफ ३ (२६) एपोइटस्/(ए)/६२ ग्रुप III दिनांक ३०-१०-६३ द्वारा जोड़ा गया ।

३ (६) " /६१ दिनांक १३-१०-६३ द्वारा जोड़ा गया ।

४ (२६) " /६२ ग्रुप III दिनांक ३० १० ६३ द्वारा जोड़ा गया ।

५ (१६) " (ए) III /६४ दिनांक १६ ८ ६१

- २ निरीक्षक, ग्रेड द्वितीय ।
- ४ निरीक्षक ग्रेड तृतीय ।
- ५ पेट्रोलिंग अधिकारी ।
- ६ जमादार ।
- ७ मिपाही ।
- ८ चानक ।

२ प्राधिकारी विभाग

- १ निरीक्षक ग्रेड प्रथम ।
- २ निरीक्षक ग्रेड द्वितीय ।
- ३ निरीक्षक ग्रेड तृतीय ।
- ४ कोट इन्स्पेक्टर (प्रोवीडेंटिंग निरीक्षक) ।
- ५ पेट्रोलिंग अधीक्षक (निरोधक दल) ।
- ६ पेट्रोलिंग अधिकारी ग्रेड प्रथम (निरोधक दल) ।
- ७ पेट्रोलिंग अधिकारी, ग्रेड द्वितीय (निरोधक दल) ।
- ८ जमादार (निरोधक दल) ।
- ९ मिपाही तथा मचार (निरोधक दल) ।

धर्माय विभाग

- १ निरीक्षक ।
- २ सहायक निरीक्षक ।

शिक्षा विभाग

- १ सहायक-उप निरीक्षक ।
- २ उच्च विद्यालय तथा इसी प्रकार की शिक्षा संस्थाओं से अथ राजकीय पाठ-शालाओं के प्रधानाध्यापक ।
- ३ महाराजा सांस्कृतिक पुस्तकालय, जयपुर किंग ज्योज पथम मिलवर जुबलि पुस्तकालय ग्रीकानर तथा सुमेर सांस्कृतिक पुस्तकालय जोधपुर के प्रभारी पुस्तकालयाध्यक्ष ।
- ४ राजकीय संस्थाओं के समस्त अध्यापक ।
- ५ अधीक्षक शारीरिक शिक्षा ।
- ६ चिकित्सा अधिकारी ।
- ७ सामाजिक शिक्षा मंडलक ।
- ८ प्रोवन्सियर ।
- ९ उप प्रधानाचार्य कला संस्थान जयपुर ।
- १० शारीरिक प्रशिक्षक ।

१ अधिसूचना स एफ ३ (१६) एण्ड टम (ए)/६४ दिनांक १०-८-६४ द्वारा जोड़ा गया ।

२ अधिसूचना स एफ २ (१६) एण्ड टम (ए)/६४ दिनांक १६-८-६४ द्वारा जोड़ा गया ।

३ अधिसूचना स एफ २ (२२) एण्ड टम (ए III)/६१ दिनांक २४-१-६२ द्वारा जोड़ा गया ।

- ८ पर्यवेक्षक ।
- ९ प्लान रेकड कीपर ।
- १० फेरी छापने वाले तथा फेरीवाले ।
- ११ सेवा फोरमन ।
- १२ यात्रिकी फोरमन ।
- १३ प्रशिक्षक ।
- १४ मुख्य सिगनेलर (सक्सेक) तथा सक्सेकण ।
- १५ जिलेदार तथा नायब जिलेदार ।
- १६ उप कलेक्टर ।
- १७ यात्रिकी तथा विद्युत ओवरसीयर ।
- १८ अनुसंधान सहायक ।
- १९ मुख्य प्रयोगशाला सहायक ।
- २० प्रयोगशाला सहायक ।
- २१ ओवरसीयर ।
- २२ नहर तहसीलदार ।
- २३ स्पीड सहायक ।
- २४ बालू बिप्लेशक (सिल्ट एनेलिस्ट) ।
- २५ ऑब्जर्वर ।
- २६ मिस्त्री ।
- २७ धर्म कल्याण निरीक्षक ।

सहायता तथा पुनः स्थापन विभाग

- १ तहसीलदार ।
- २ सहायक ग्राम्य पुनः स्थापन अधिकारी ।
- ३ ऋण निरीक्षक ।
- ४
- ५ नायब तहसीलदार ।
- ६ द्विक्रय निरीक्षक ।

समाज कल्याण विभाग

- १ सहायक अनुसंधान अधिकारी ।
- २ सहायक प्रचार अधिकारी ।
- ३ सहायक सांख्यिकी अधिकारी ।
- ४ फोटोग्राफर तथा कलाकार ।

१ अधिसूचना ग एफ ३ (१) एण्डेंट्स (ए III)/६७ दिनांक १० ४ ६७ द्वारा जोड़ा गया ।

२ अधिसूचना ग एफ ५ (१०) एण्डेंट्स (ए II)/६५ दिनांक १६ ८ ६६ द्वारा जोड़ा गया ।

- ५ कल्याण तथा पुन मन्थापन निरीक्षक ।
- ६ लेखा निरीक्षक ।
- ७ प्रचार सहायक ।
- ८ कल्याण वायकता ।
- ९ महिला कल्याण वायकत्ती ।
- १० ओवरसियर तथा ड्रापटस्मेन ।
- ११ प्रचारक ।
- १२ ओपरेटस ।
- १३ मुख्य निरीक्षक ।
- १४ वरिष्ठ आवास निरीक्षक ।
- १५ औद्योगिक निरीक्षक ।
- १६ पाठशालाया के पयवक्षक ।
- १७ आवास निरीक्षक ।
- १८ कूप निरीक्षक ।
- १९ वद्य ।
- २० कम्पाउण्डस ।
- २१ छात्रालय अधीक्षक ।
- २२ महिला छात्रालय अधीक्षिका ।
- २३ सिलाई प्रशिक्षक ।
- २४ बडईगिरी प्रशिक्षक ।
- २५ जूते बनाने का प्रशिक्षक ।
- २६ दास तथा बत काय प्रशिक्षक ।
- २७ कृषि प्रशिक्षक ।
- २८ लोहारगिरी प्रशिक्षक ।
- २९ प्रशिक्षक (युनियादी पाठशालायें) ।
- ३० कला सुविधादी पाठशालाया के अध्यापक ।
- ३१ अध्यापक गण ।
- ३२ सहायक अधीक्षक ।
- ३३ महिला कल्याण अधिनारी ।
- ३४ जिला ममाज कल्याण अधिनारी ।
- ३५ अनुसंधानकता (मेत सयवक्षण) ।
- ३६ परीक्षण अधिनारी (प्रोवेनान ऑफिसर) ।
- ३७ सहायक महिला कल्याण अधिनारी ।
- ३८
- ३९ प्रमाणित पाठशाला के प्रधानाध्यापक ।

- ४०
४१ महायक गरीक्षण (प्रोवेणन) अधिकारी ।
४२ वरयाणाधिकारी (कारागार) ।
४३ अनुसंधानकर्त्ता (गृह) ।

साधजनिक निर्माण विभाग—भवन तथा पथ

- १ अधीनस्थ अभियन्ता वरिष्ठ तथा कनिष्ठ ।
२ तकमीना बनाने वाले (एस्टीमेटर्स) ।
३ कम्प्यूटर्स ।
४ ड्राफ्टस्मेन जिसमे मुख्य ड्राफ्टस्मेन वरिष्ठ ड्राफ्टस्मेन, कनिष्ठ ड्राफ्टस्मेन तथा सहायक ड्राफ्टस्मेन सम्मिलित है ।
५ फरीवाला ।
६ कारखाने के पर्यवेक्षक ।
७ कारखाने के फोरमन ।
८ जल निरीक्षक ।
९ मीटर निरीक्षक ।
१० मीटर पढ़नेवाले ।
११ प्रयोगशाला सहायक ।
१२ फिटर एंटे-डेट ।
१३ पम्प एंटे-डेट ।
१४ ट्रेस करने वाले ।
१५ उद्यानो के निरीक्षक ।
१६ उद्यानो के सहायक निरीक्षक ।
१७ विधि सहायक ।
१८ सहायक आर्किटेक्ट (किल्पकार) ।
१९ सहायक सांख्यिकी ।
२० मिस्त्री ।
२१ पम्प खालक ।

अन्य विभाग

- १ निरीक्षक ।
२ जानवकर्त्ता ।
सांख्यिकी सहायक ।
४ कम्प्यूटर ।
५ कम्पाउंडर ।

- ६ मिडवाइफ ।
- ७ नर्स ।
- ८ डाप्टस् मैन ।
- ९ मिनेमा मशीन चालक ।
- १० व्यवस्थापक केन्द्रीय चिकित्सा भंडार कमचारीगण राज्य बीमा योजना ।
- ११ फोरमन प्रशिक्षक ।
- १२ पर्यवेक्षक प्रशिक्षक ।
- १३ विद्यकारी तथा कला प्रशिक्षक ।
- १४ श्रम तकनी की प्रशिक्षक ।

जेल विभाग

- १ जेलर ।
- २ उप-जेलर ।
- ३ सहायक जेलर ।
- ४ मुख्य प्रधान पहरेदार ।
- ५ मेट्रन ।
- ६ मुख्य पहरेदार ।
- ७ कारखाने का व्यवस्थापक ।
- ८ कारखाने का सहायक व्यवस्थापक ।
- ९ अध्यापक ।
- १० मुख्य कम्पाजिटर ।
- ११ कम्पोजिटर ।
- १२ छापने वाले (प्रिन्टर्स) ।
- १३ जेली तथा हवालाती का निरीक्षक ।
- १४ कब्जाउ-डर ।
- १५ नर्स बाइ ।

राजस्व उपनिवेशन तथा भू-अभिलेख विभाग

- १ नायब तहसीलदार ।
- २ सहायक भू-अभिलेख अधिकारी ।
बंदावस्त विभाग में निरीक्षक या चर्करा ।
- ४ निरीक्षक भू-अभिलेख विभाग ।
- ५ मुख्य डाप्टस् मैन तथा डाप्टस् मैन ।
- ६ सीमा निरीक्षक ।

१ निर्मुक्ति विभाग अधिसूचना सं एफ २(१६) एपोस्टम ए/६१/जी प्रार ३३३ दिनांक २१ ६४ द्वारा जोड़ा गया ।

२ निर्मुक्ति विभाग अधिसूचना सं एफ ३ (१०) एपोस्टम ए/६२ दिनांक ७-६ ६२ द्वारा जोड़ा गया ।

- ७ सदर कानूनगो, सहायक सदर कानूनगो तथा कार्यालय कानूनगो ।
- ८ सहायक कार्यालय कानूनगो ।
- ९ वरिष्ठ सोमा निरीक्षक ।
- १० राजस्व लेखा निरीक्षक
- ११ ट्रेस करने वाले ।
- १२ फेरो निकालने वाले ।
- १३ तहसीलदार ।

पजीकरण तथा स्टाम्प विभाग

- १ उप पजीयक (सब रजिस्ट्रार) ।

स्थानीय सस्थाओं का निदेशालय

- १ सहायक क्षेत्रीय निरीक्षक ।

क— चिकित्सा तथा सावजनिक स्वास्थ्य विभाग

- १ अस्पतालो के सहायक अधीक्षकगण ।
- २ सहायक औषधि निर्माण रसायनज्ञ ।
- ३ सहायक मैट्रन ।
- ४ सिस्टर्न तथा कनिष्ठ सिस्टर्न ।
- ५ नर्सों नर्स-दाई जिसमे पुरुष नर्सों सम्मिलित है ।
- ६ कम्पाउण्डर ।
- ७ औषधि बनाने वाले (फारमासिस्ट) ।
- ८ तकनीकज्ञ (टेक्नीशियन) ।
- ९ एक्स-रे सहायक ।
- १० प्रचार सहायक ।
- ११ कलाकार ।
- १२ महिला स्वास्थ्य अधिकारी ।
- १३ प्रयोगशाला सहायक ।
- १४ मीडिया मन ।
- १५ स्वास्थ्य निरीक्षक ।
- १६ सैनीटरी निरीक्षक ।
- १७ मलरिया सर्वेक्षक ।
- १८ हैज विजिटर्स ।
- १९ टीका लगाने वाला ।
- २० मिन्त्री ।
- २१ विजली का काम करने वाले (इलेक्ट्रीशियन) ।
- २२ सिस्टर ट्यूटर (शिक्षिका) ।
- २३ स्टाफ नर्स ।
- २४ मिड वाइफ ।

- २५ पशुघर का रखवाला ।
- २६ फोटोग्राफर्स ।
- २७ ध्वजसाथी औपधिशाल्त्र वेत्ता (ओक्यूपेशनल थेराप्यूटिस्ट) ।
- २८ नमूना बनाने वाले (मॉडलर्स) ।
- २९ शारीरिक प्रशिक्षक ।
- ३० माटर यात्रिकी ।
- ३१ मलेरिया इन्फेक्शन् अधिकारी ।

ख—सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज

- १ कनिष्ठ प्रदर्शनकर्ता (डेमोन्स्ट्रेटर्स) ।
- २ क्यूरेटर ।
- ३ पुस्तकालयाध्यक्ष ।
- ४ शारीरिक प्रशिक्षक ।

ग्लेनज तथा भू गभ विभाग

- १ ड्रिल यान्त्रिकी ।
- २ प्रयागशाला सहायक (वरिष्ठ) ।
- ३ फील्ड सहायक ग्रेड प्रथम ।
- ४ ड्राफ्ट्समन ग्रेड प्रथम ।
- ५ ओवरमैन (वरिष्ठ) ।
- ६ सर्वेक्षक ।
- ७ बिजली का काम करने वाला (इलेक्ट्रीशियन) ।
- ८ ग्लेनज फारमन ग्रेड प्रथम ।
- ९ अजायबघर सहायक ।
- १० मास्टरकी सहायक ।
- ११ ग्लेनज सर्वेक्षक ।
- १२ कम्प्यूटर्स ।
- १३ प्रयागशाला सहायक (कनिष्ठ) ।
- १४ रामायनिक सहायक ।
- १५ ओवर डे मर ।
- १६ यात्रिकी ।
- १७ व्यवस्थापक भाकरी पट्टिया की खानें ।

- १ नियुक्ति विभाग अधिसूचना एफ ३ (२१) एपोइटस (ए) ६१/ जी द्वार III दिनांक १-४-६ द्वारा जोड़ा गया ।
- २ नियुक्ति विभाग अधिसूचना स एफ ३ (२) एपोइटस (ए-III)/६६ दिनांक २३ ३-६ द्वारा जोड़ा गया ।
- ३ नियुक्ति विभाग अधिसूचना स एफ ३ (२३) एपोइटस (ए III)/६३ दिनांक २-६ ६ द्वारा स्थानापन्न किया गया ।

- १८ कारखाने का यात्रिकी ।
- १९ खनिज फोरमन ग्रेड द्वितीय ।
- २० कम्प्रेसर चालक ।
- २१ भावी-सभावना सर्वेक्षक ।
- २२ पम्प चालक ।
- २३ जेनेरेटर चालक ।
- २४ चट्टान ड्रिल चालक ।
- २५ ड्रिलिंग सहायक ।
- २६ रिगमन ।
- २७, सौक्ष्म कटने वाला ।
- २८ ट्रेस करने वाला ।
- २९ कम्प्रेसर चालक ।
- ३० ड्रिलर, ग्रेड प्रथम ।
- ३१ ड्रिलर ग्रेड द्वितीय ।
- ३२ सहायक ड्रिलर ।
- ३३ ड्रापट्मन ग्रेड द्वितीय ।
- ३४ फील्ड सहायक, ग्रेड द्वितीय ।
- ३५ ओवरमन कनिष्ठ ।
- ३६ फिल्टर, ग्रेड द्वितीय ।
- ३७ जोप ट्रक तथा ट्रैक्टरों के चालक ।

आरक्षी (पुलिस) विभाग

- १ निरीक्षक (इन्सपेक्टर) ।
- २ उप निरीक्षक (सब इन्सपेक्टर) ।
- ३ हैड कांस्टेबल ।
- ४ कांस्टेबल (सिपाही) ।
- ५ सहायक उप निरीक्षक ।
- ६ फोटोग्राफर ।
- ७ कम्पाउण्डर ।
- ८ वर्ल्डिंग करने वाला ।
- ९ टनर ।
- १० पटर ।
- ११ कम्पनी कमांडर ।
- १२ प्लटून कमांडर ।
- १३ बैलिस्टिक विशेषज्ञ ।
- १४ वैज्ञानिक सहायक ।
- १५ आरक्षी फोटोग्राफर तथा निरीक्षक ।

जन मध्यक निदेशालय

- १ फोटोग्राफस ।
- २ डाक रूम सहायक ।
- ३ कलाकार ।
- ४ यान्त्रिकी तथा चालक (ग्रॉपरेटर) ।
- ५ चालक (ग्रॉपरेटर) ।
- ६ मिस्त्री ।

आर्थिक तथा सांख्यिक निदेशालय

- १ मागिकी अनुसंधान सहायक ।
- २ वरिष्ठ कलाकार ।
- ३ कनिष्ठ कलाकार ।
- ४ ड्राफ्ट्समन ।
- ५ कम्प्यूटस ।
- ६ फोल्ड/सांख्यिकी निरीक्षक ।
- ७ प्रगति प्रसार अधिकारी ।
- ८ पुस्तकालयाध्यक्ष ।
- ९ प्रयत्नक (आर्थिक तथा सांख्यिकी) ।

यातायात विभाग

- १ यातायात निरीक्षक ।
- २ यातायात उप निरीक्षक ।
- ३ सर्वेक्षण निरीक्षक ।
- ४ फोरमन ।
- ५ चालक ।
- ६ यान्त्रिकी निरीक्षक ।

विकास विभाग

- १ सहकारी तथा पचायत अधिकारी ।
- २ सामाजिक शिक्षा अधिकारी ।
- ३ आवरसियर ।
- ४ चालक ।

१ नियुक्ति विभाग अधिसूचना न एफ ३ (२१) एपोइन्टस ए III/६३ दिनांक १२ १२-६३ द्वारा जोडा गया ।

२ नियुक्ति विभाग अधिसूचना न एफ ३ (१८) एपोइन्टस ए/६१ ब्र III, दिनांक २० ३-६२ द्वारा जोडा गया ।

३ अधिसूचना न एफ ३ (१) एपोइन्टस ए-III) ६७, दिनांक १२ ४ ६७ द्वारा जोडा गया ।

पचायत विभाग

- १ पचायत प्रसार अधिकारी, ग्रेड प्रथम ।
- २ पचायत प्रसार अधिकारी ग्रेड द्वितीय ।

पयटक सुविधा विभाग

- १ पयटक सहायक ।

नियोजन निदेशालय

- १ सारियकी सहायक ।

चक्रवर्दी विभाग

- १ सहायक चक्रवर्दी अधिकारी ।
- २ मुं सिरम ।
- ३ निरीक्षक ।

उद्योग विभाग

- १ मेल (सम्पक) अधिकारी तथा छात्रावास अधीक्षक ।
- २ व्यवसायिक (तकनीकी), ग्रेड प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय ।
- ३ सोडियम सल्फेट, त्रिजटोसेशन कारखाना डीडवाना के लिए यात्रिकी ।
- ४ उद्योग प्रसार अधिकारी ।
- ५ कलात्मक शिल्प प्रशिक्षण संस्था जयपुर में डिजाइन बनाने वाला ।
- ६ लघु उद्योगों के गुणात्मक चिह्न अंकित करने वाला अधीक्षक ।
- ७ अधीक्षक नमक (तकनीकी) ।
- ८ अधीक्षक तथा कलात्मक डिजाइनर, डिजाइन प्रसार केन्द्र जयपुर ।

मूल्यांकन संगठन

- १ अनुमोचन सहायक ।
- २ प्रक्षेपणवर्ती ।
- ३ कम्प्यूटर ।

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन विभाग

- १ डीपो मैनेजर ।
- २ महायक डीपो मैनेजर ।
- ३ ट्रेफिक निरीक्षण ।
- ४ सहायक ट्रेफिक निरीक्षण ।
- ५ सहायक मास्यिकी ।

-
- १ अधिमूर्चना ग एक ३ (२) एपोइटन (ए-III) ६३, निर्माक ५ २ ६३ द्वारा जोड़ा गया ।
 - २ अधिमूर्चना म एक ३ (२६) एपोइटन (ए-III) ६२, निर्माक ३०-१०-६३ द्वारा जोड़ा गया ।
 - ३ अधिमूर्चना ग एक ३ (४) एपोइटन (ए-III) ६४, निर्माक ८-७-६३ द्वारा जोड़ा गया ।
 - ४ अधिमूर्चना म एक ३ (४) एपोइटन (ए-III) ६३, निर्माक ५-६ ६७ द्वारा जोड़ा गया ।
 - ५ अधिमूर्चना म एक ३ (१६) एपोइटन (ए-III) ६४ निर्माक २६-४ ६४ द्वारा जोड़ा गया ।

- ६ श्रम कल्याण निरीक्षक ।
- ७ भंडार अवीक्षक ।
- ८ भंडार निरीक्षक ।
- ९ भंडार उप-निरीक्षक ।
- १० सहायक भंडार उप निरीक्षक ।
- ११ वरिष्ठ फोरमैन ग्रंथ प्रथम ।
- १२ वरिष्ठ फोरमैन ग्रंथ प्रथम ।
- १३ कनिष्ठ फोरमैन (यात्रिकी) ।
- १४ कनिष्ठ फोरमैन (विद्युत्) ।
- १५ मोबरसीमर ।
- १६ चालक ।
- १७ कंडक्टर ।
- १८ यात्रिकी ।
- १९ विजली का काम करने वाला, ग्रंथ प्रथम ।
- २० टनर (खरादी) ग्रंथ प्रथम ।
- २१ बुल्केनाइजर ग्रंथ प्रथम ।
- २२ लुहार, ग्रंथ प्रथम ।
- २३ टीन का काम करने वाला ग्रंथ प्रथम ।
- २४ जूते बनाने वाला ग्रंथ प्रथम ।
- २५ वल्डर (वर्ल्डिंग करने वाला) ।
- २६ पेटर (रंग करने वाला) ग्रंथ प्रथम ।
- २७ सुधार, ग्रंथ प्रथम ।
- २८ सहायक यात्रिकी ।
- २९ सीटें तथा पर्दे बनाने वाला ग्रंथ द्वितीय ।
- ३० टायर चढाने वाला, ग्रंथ द्वितीय ।
- ३१ सुधार ग्रंथ द्वितीय ।
- ३२ सहायक विजली वाला, ग्रंथ द्वितीय ।
- ३३ पेटर (रंगने वाला) ग्रंथ द्वितीय ।
- ३४ टिन का काम करने वाला/जूते बनाने वाला, ग्रंथ द्वितीय ।
- ३५ वल्डर ग्रंथ द्वितीय ।
- ३६ बुल्केनाइजर, ग्रंथ द्वितीय ।
- ३७ टनर (खरादी) ग्रंथ द्वितीय ।
- ३८ लुहार, ग्रंथ द्वितीय ।
- ३९ प्रशासक तथा वातानुबलन तकनीकी ।
- ४० होस्टेस तथा पयटक पय प्रदर्शक (वातानुबलित गाडियों) ।

ग—लेखक वर्गीय सेवार्थ

समस्त विभागों में इस श्रेणीयों के पद धारी करने वाले जैसे कि —

- १ लेखापाल जिसमें क्षेत्रीय लेखापाल वरिष्ठ लेखापाल सब एकाउन्टेन्ट्स उप लेखापाल, वनिष्ठ लेखापाल सहायक लेखापाल भण्डार लेखापाल तथा सहायक भण्डार लेखापाल सम्मिलित हैं। जिला राजस्व लेखापाल तथा तहसील राजस्व लेखापाल।
- २ ग्रहलमद वरिष्ठ कनिष्ठ भयवा सहायक ग्रहलमद।
- ३ लेखा-लेखक तथा वनिष्ठ लेखा-लेखक।
- ४ लेखा सक्लनकर्त्ता।
- ५ सहायक गण जिसमें राजस्व सहायक न्यायिक सहायक अमला सहायक विविध सहायक सम्मिलित हैं।
- ६ अकेशण चिट्ठीयात लेखक।
- ७ अकेशण लेखक।
- ८ अकेशण (प्रॉडिटस) जिसमें क्षेत्रीय अकेशण सम्मिलित हैं।
- ९ बिल लेखक।
- १० विल्टीयात लेखक।
- ११ जिल्दसाज।
- १२ रोकडिया तथा सहायक रोकडिया।
- १३ लेखक गण जिसमें दिवानी लेखक, फौजदारी लेखक विविध लेखक, अपील लेखक, पुनरीक्षण लेखक अग्रेजी लेखक सम्मिलित हैं।
- १४ गणना-मशीन का चालक।
- १५ केम्प लेखक।
- १६ सूचिपत्र लेखक (केटलोगस)।
- १७ कम्पाइलर (सक्लनकर्त्ता जिसमें निदेशालय तथा जिला गेजेटियस विभाग का मुख्य सक्लनकर्त्ता सम्मिलित हैं)।
- १८ गोपनीय लेखक।
- १९ नक्श नवीस।
- २० कोर लॉगिंग लेखक।
- २१ काउन्टर लेखक।
- २२ डाक लेखक।
- २३ डाक भेजने वाले लेखक (डिस्पच क्लर्क्स)।
- २४ डायरिस्ट (रोजनामचा लेखक)।
- २५ क्षेत्रीय लेखक।
- २६ अमला लेखक।
- २७ आधिकारी लेखक।
- खेत (फार्म) के लेखक।

- २६ फील्डमैन तथा स्टोर कीपस आर कनिष्ठ फील्डमैन तथा स्टारकीपस ।
- ३० फोल्ड सहायक ।
- ३१ दल (फोर्स) के लेखक ।
- ३२ फर्नीचर लेखक ।
- ३३ गजधर ।
- ३४ राज-पत्र लेखक ।
- ३५ प्रधान लेखक ।
- ३६ जनगणना विभाग के निरीक्षक ।
- ३७ गुप्त समाचारों के निरीक्षक, सब इम्पक्टर सहायक निरीक्षक, सायर तथा आदकारी विभाग ।
- ३८ भोजार लेखक ।
- ३९ कनिष्ठ अथवा निम्न श्रेणी लेखक ।
- ४० खाता जमाबंदी लेखक ।
- ४१ लीग लेखक ।
- ४२ लदान करों तथा भाल बाहर भेजने वाले लेखक ।
- ४३ कार्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्ष या पुस्तकालय लेखक ।
- ४४ उन पुस्तकालयों के पुस्तकालयाध्यक्ष जिनका उल्लेख अनुसूची प्रथम या द्वितीय में न हो शाखा पुस्तकालयाध्यक्ष रेफरेन्स पुस्तकालयाध्यक्ष ।
- ४५ श्रवकाश पर जाने वालों के स्थान पर काम करने वाले (लीव रिजर्व) लेखक ।
- ४६ मु सरिम ।
- ४७ मुशौ तथा प्रधान मुशौ ।
- ४८ माहरिर ।
- ४९ मुबद्दम ।
- ५० नाकदार ।
- ५१ नाजिर ।
- ५२ सहकारी विभाग के पत्रावला विशेषज्ञ ।
- ५३ पामल लेखक ।
- ५४ पटवारी ।
- ५५ वतन लेखक ।
- ५६ पत्रागण लेखक ।
- ५७ विभागान्यक्षों अथवा विभाग के पदा के अतिरिक्त अधिकारियों के निजी सहायक ।
- ५८ पशकार तथा कनिष्ठ सहायक पशकार ।
- ५९ याचिका लेखक ।
- ६० प्रूफ पढ़ने वाले ।
- ६१ जन सम्पर्क निदेशालय के निम्नलिखित पद —
पूछताछ अधिकारी ।

- समाचार सम्पादक ।
 समाचार सहायक ।
 पत्रकार (जर्नेलिस्ट) ।
 छानवीन करने वाले (स्कूटिन।ईजम) ।
 उत्पादन अधिकारी ।
 व्याख्याता ।
- ६३ रीडर तथा मुख्य रीडर ।
 ५३ पत्र प्राप्ति (रिसीट) लेखक ।
 ६४ रकड कीपस, सहायक रकड कीपस तथा अभिलेख लेखक ।
 ६५ रिफ ड (रकम वापसी)लेखक ।
 ६६ रोजनामचा क्लक ।
 ६७ रेफरे स लेखक ।
 ६८ शाखा प्रभारी तथा शाखा (सेक्शन) के लेखक ।
 ६९ वरिष्ठ अथवा अग्र श्रेणी लेखक जिसमे जागोर विभाग के निरीक्षक ।
 ७० नेखन-सामग्री लेखक ।
 ७१ सारियकी लेखक ।
 ७२ आणुलिपिक
 ७३ स्टौक बरीफायर्स ।
 ७४ स्टोर कीपस तथा सहायक स्टोरकीपस ।
 ७५ उप-खण्ड या उप क्षेत्रीय लेखक ।
 ७६ अधीक्षक जनरल अधीक्षक तथा शाखा अधीक्षक जिसमे मगनीराम बागड मेमोरियल इजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर का कार्यालय अधीक्षक तथा रजिस्ट्रार सम्मिलित है ।
 ७७ सुपरवाइजस (पयवेक्षक) ।
 ७८ टेम्प्लेटम ।
 ७९ टाइम कीपस तथा सहायक टाइम कीपस ।
 ८० कार्यालय मे अनुवादकर्ता ।
 ८१ यात्रा भत्ता लेखक ।
 ८२ कार्यालयो के खजांची सहायक खजांची तथा कनिष्ठ खजांची ।
 ८३ टक्का लेखक (टाइपिस्ट) ।
 ८४ हिन्दी (वनाक्यूलर) लेखक ।
 ८५ लेखक (राइटस) ।
 ८६ ग्राम-स्तर कायकर्ता (ग्राम-सेवक) ।
 ८७ मुहाफिजा ।
 ८८ विभागीय परीक्षाप्रा के उप पञ्जीयक ।
 ८९ प्रीमा निरीक्षक ।
 ९० दुर्बिग क्लक तथा राजकीय यातायात सेवा सिराही का कन्डक्टर ।

- ८१ देवस्थान विभाग का व्यवस्थापक ग्रेड प्रथम तथा द्वितीय ।
 ८२ , के दरोगाह " "
 ८३ , का ओहदेदार
 ८४ का महंत
 ८५ का मुखिया , ,
 ८६ का पुजारी , ,
 ८७ , , का गोस्वामी , ,
 ८८ उप सम्भादक ।
 ८९ रिपोटर ।
 १०० वरिष्ठ प्रूफ पढ़ने वाला ।
 १०१ कृषि निदेशक का निजी सहायक ।
 १०२ स्टोर सुपरवाइजर (भंडार पयवेक्षक) ।
 १०३ खेल (या आक्ट) पयवेक्षक तथा सहायक ।
 १०४ महिला पयवेक्षिका ।
 १०५ महिला दर्जी ।
 १०६ ग्टास तथा लखा निरीक्षक ।
 १०७ सिवार्ड विभाग के अमीन ।
 १०८ पथ प्रदर्शक (गाइड) ।
 १०९ कनिष्ठ स्वागतकर्त्ता ।
 ११० कारिन्दा ।
 १११ सचिवालय तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय के शाखा अधिकारी (मेकेशन आफिसर्स) ।
 ११४ नैवा निरीक्षक ।
 ११५ अभिलेख सहायक ।
 ११४ अ. सघातकर्त्ता ।
 ११५ अभिनय कर्मचारी (रेकड एट्रैक्ट) ।
 ११६ निर्दाता (अभिलेख छोटने वाला) ।
 ११७ सुरक्षण सहायक ।
 ११८ प्रयोगशाला सहायक ।
 ११९ सचिवालय के मुख्य अनुवादक ।

१ परिशिष्ट १३

राजस्थान सरकार तथा केन्द्रीय सरकार तथा पंजाब विहार, मद्रास मसूर मध्य भारत हैदराबाद (दक्षिण) पेप्पू सौराष्ट्र ट्रेवनकोर, कोचीन तथा मध्यप्रदेश के मध्य वेतन भत्तो, पेशन आदि के प्रभार को नियमित करने वाले नियम ।

ये नियम प्रत्येक सरकार के सामने अर्जित दिनांक से लागू होंगे

भाग ए' के राज्य

१ पंजाब	२१—५—१९५५
२ विहार	१—१०—१९५५
३ मद्रास	२८—६—१९५५
४ उड़ीसा	२३—११—१९५५

भाग 'बी' के राज्य

१ मसूर	२५—५—१९५५
२ मध्यभारत	२६—५—१९५५
३ हैदराबाद (दक्षिण)	११—५—१९५५
४ पेप्पू	२८—५—१९५५
५ सौराष्ट्र	२३—८—१९५५
६ ट्रेवनकोर कोचीन	३—६—१९५५
७ मध्यप्रदेश	११—३—१९५५

(१) अवकाश वेतन से विभिन्न वेतन तथा भत्तो का प्रभार —

एकाउण्टेंट कोड भाग प्रथम के परिशिष्ट ३ के भाग 'बी' के सेक्शन प्रथम में दिये गये नियम पूर्णतया लागू होंगे ।

(२) अवकाश वेतन का प्रभार—(क) अस्थायी स्थानांतर — उधार देने वाली सरकार द्वारा निधागित दरा से अवकाश वेतन प्रशदान वसूल कर लेने पर अवकाश सम्बन्धी दातव्य समाप्त हो जायगा । अवकाश-प्रशदान की वसूली विशेष असमर्थता अवकाश का छाड़कर प्रतिनियुक्ति की अवधि में अर्जित अवकाश का भविष्य कालीन समस्त दातव्य समाप्त कर देगी । विशेष असमर्थता अवकाश के विषय में बटवारा एकाउण्टेंट कोड भाग प्रथम के परिशिष्ट ३ के भाग 'बी' के सेक्शन द्वितीय के नियम ६ द्वारा शासित होगा ।

(ख) स्थायी स्थानांतर — अवकाश वेतन का बटवारा एकाउण्टेंट कोड भाग प्रथम के परिशिष्ट ३ के भाग 'बी' के सेक्शन द्वितीय नियम ३ अथवा नियम ६ के अनुसार इस आधार पर किया जायगा कि उक्त सरकारी कर्मचारी आया मूल नियमों

के अथवा सशोधित अवकाश नियम १९३३ के अधीनस्त है। "सशोधित अवकाश नियम १९३३ (या उसके समकक्ष)" होने की स्थिति में उधार देने वाली सरकार के दातव्य में सरकारी कर्मचारी के स्थाई स्थानांतर की तारीख को उनके खाते में जमा "अर्जित अवकाश" तथा "अध वेतन अवकाश" दोनों सम्मिलित होंगे।

मद्रास सरकार ने अधवेतन अवकाश सम्वन्धी बटवारे पर सहमति प्रदान नहीं की है।

टिप्पणी

किसी राज्य से स्थानांतर होने के समय यह तय किया जायगा कि आया उक्त सरकारी कर्मचारी राज्य सरकार में सेवा करते हुए मूल अवकाश नियमों के समक्ष अधीनस्त अथवा मगाधिन अवकाश नियम, १९३३ के अधीनस्त समझा जावे। जब इनमें से कोई भी नियम उचित रूप में लागू नहीं किये जा सकें तो दोनों सरकारें यथा सम्भव इन नियमों के आधारभूत सिद्धान्तों के अनुरूप, इस प्रश्न का स्थानांतर के समय तय करेंगी।

(ग) अस्थाई स्थानांतर की दशा में तथा स्थाई स्थानांतर की दशा में, शाना में अवकाश जो देय न हो उसकी स्वीकृति ग्रहण करने वाली सरकार समस्त मामलों में पहले ऐसे अवकाश के लेख मार बहन करेगी परन्तु ऐसे अवकाश से सौटने पर काय सेवा द्वारा यह अवकाश पूर्णतया अर्जित होने से पूर्व उक्त सरकारी कर्मचारी का स्थानांतर अथवा सरकार की ही जाने की दशा में भार का समायोजन इस प्रकार स किया जायगा जिसके निष्पत्ति दोना राज्य सहमत हो।

(३) पेसेज के मूल्य का प्रभार —एकाउण्ट कोड भाग प्रथम के परिशिष्ट ३ के सेक्शन ततीय के प्रावधानानुसार पेसेज अशदान की वसूली द्वारा यह दातव्य समाप्त हो जायगा।

(४) उपरोक्त दो में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण पेशन के बटवारे के सम्बन्ध में भा किया जायगा। अथ शब्दों में अस्थाई स्थानांतर के समस्त मामला में उधार देने वाली सरकार द्वारा निवारित पेशन अशदान उधार लेने वाली सरकार से प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए वसूल किया जायगा परन्तु अवकाश की अवधि के लिए कोई अशदान देय नहीं होगा। उधार लेने वाली सरकार का दातव्य उधार देने वाली सरकार के प्रति किसी सरकारी कर्मचारी के स्थाई रूप से स्थानांतर हो जाने पर समाप्त हो जाता है परन्तु उधार देने वाली सरकार सरकारी कर्मचारी के उन पेशन प्रभारों के लिए उत्तरदायी रहगी जो अस्थाई स्थानांतर में पूर्व उसके अधीन की गई सेवा के सम्बन्ध में हैं, जिसमें मेवाकाल तथा अवकाश सम्मिलित हैं जिसके लिए अशदान की वसूली की जा चुकी है। इस दातव्य का पेशन स्वीकृत हो जाने पर अनुपातिक पेशन का भुगतान कर देन पर परिपालन हो जायगा जिसका बटवारा मेवाकाल की अवधि तथा एकाउण्ट कोड भाग प्रथम के परिशिष्ट ३ के सेक्शन चतुर्थ में निर्धारित नियमों के आधार पर आवश्यक परिवर्तन सहित किया जायगा। यदि पेशन अपनी पेशन को परिवर्तित (Commuted) करान का हकदार है तो परिवर्तन (Commuation) का प्रभाव एकाउण्ट कोड भाग प्रथम के परिशिष्ट ३ के सेक्शन चतुर्थ के

नियम ३२ के अनुसरण में उसी क्रम से विभिन्न सरकारी के लेखे अथवा मविलकरण या व्यय करने का होगा जिस क्रम में ये प्रश्न निम्नतर राशि से उच्चतर राशि तक उठते हैं।

(५) जो कमचारी बोनस की शर्तों में नियुक्त हों उनके सम्बन्ध में बोनस की राशि का प्रभार — एकाउंट बोर्ड भाग प्रथम के परिशिष्ट ३ व संवर्धन पंचम में दिया गया सिद्धांत ग्रहण किया जायगा। अथवा शब्दों में, उधार देने वाली सरकार में उधार देने वाली सरकार में ऐसा वानम अथवा शर्त वसूल करगी जिसके लिए दाना सरकारी के बीच सहमति हो जाय।

(६) आई० सी० एस० फमिली पेंशन निधि में सरकारी अथवा शर्तों का भार — यह प्रश्न जहाँ भी तथ्य जहाँ भी उठे प्रत्येक मामले में पारस्परिक सहमति से तय किया जायगा।

(७) आई० सी० एस० अथवा शर्तीय सदस्यगण भविष्य निधि में सरकारी अथवा शर्तों का भार — दातव्य का निपटारा २० २० मासिक अथवा शर्तीय रूप से अथवा शर्तों के रूप में निश्चित करके चालू बमुली द्वारा किया जायगा।

मद्रास सरकार ने इस व्यवस्था के लिए सहमति प्रदान नहीं की है।

(क) अथवा शर्तीय तथा हिसाब की पुस्तकें रखने में व्यय का भार।

(ख) भूमि प्रदान तथा हस्तांतरण का भार।

(ग) रेलवे पर उत्तरकालीन कृत्यों के व्यय का प्रभार जिसमें रेलवे के पुलों का सुरक्षित रखने की कीमत सम्मिलित है।

(घ) सीमाओं के सम्बन्ध में विवाद के विभाजन चिह्न कायम रखने के व्यय का भार।

(ङ०) सेना अथवा जलसेना की सेवा करते हुए सैनिक तथा जलसैनिक पदाधिकारियों तथा असैनिक पदाधिकारियों की परिवार पेंशन के सम्बन्ध में भार।

(च) वदेशिक सेवा पर उधार दिये गये कमचारियों के सम्बन्ध में वसूल किया गया अवकाश वेतन तथा पेंशन अथवा शर्तों का भार।

मद्रास सरकार ने इस पर सहमति नहीं की है और पञ्जाब तथा बिहार सरकारों ने प्रविष्टियाँ (ङ०) तथा (च) के सम्बन्ध में व्यवस्था के लिए सहमति प्रदान नहीं की है।

एकाउंट बोर्ड भाग प्रथम के परिशिष्ट ३ में निर्धारित सारभूत नियम आवश्यक परिवर्तन सहित ग्रहण किये जायेंगे।

अवकाश वेतन तथा पेंशन व्यय के लिए अथवा शर्तों की दरें सामान्यतया वही होगी जो वदेशिक सेवकों के द्वीय सरकारी कमचारियों पर लागू होती हैं।

राजस्थान सरकार का निर्णय

१ नवम्बर, १९५६ से राज्या के पुन संगठन तथा अभी तक की भाग ए तथा भाग बी के राज्यों के अन्तर्धान हो जाने के फलस्वरूप यह तय किया गया है कि प्रति

नियुक्ति पर आये हुए तथा केन्द्रीय सरकार से स्थानांतरित अथवा इससे विपरीत सरकारी कमचारियों के अवकाश वेतन, पन्शन आदि का भार १ नवम्बर, १९५६ से कम्पट्रोलर तथा महालेखापाल द्वारा जारी किये गये एकाउंट कोड भाग प्रथम के परिशिष्ट ३ में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमित होंगे। १ नवम्बर, १९५६ से पब्लिक सर्विस आयोग के विषय का भार राजस्थान सेवा नियम के परिशिष्ट १३ में समाविष्ट प्रक्रिया के अनुसार जहाँ वही भी इस तारीख से पहले लागू थे, नियमित होंगे और उत्तराधिकारी राज्यों के बीच दातव्यो का विभाजन स्टेट्स री ओर्गेनिजेशन एक्ट १९५६ के प्रावधानों के अनुसार होगा। इसके उपरि सिद्धांतानुसार जो भी अशदान केन्द्रीय सरकार से १ नवम्बर १९५६ से केवल उपरोक्त परिशिष्ट १ में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वसूल किया गया है वह उन मामलों में वापिस करना होगा जिनमें एकाउंट कोड भाग प्रथम के परिशिष्ट ३ में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन अशदान भुगतान करने से केवल विभिन्न तरीकों के अनुसार दातव्य तथा करना अपेक्षित हो।”

राजस्थान सरकार का निर्णय

वर्तमान आज्ञाओं आदेशों का अतिक्रमण करते हुए यह आज्ञा दी गई है कि जसा कि राजस्थान सरकार तथा निम्नलिखित राज्य सरकारी के बीच पारस्परिक सहमति हुई है। राजस्थान सरकार से प्रतिनियुक्ति या स्थानांतर पर निम्नलिखित सरकारों में गये हुए अथवा इसके विपरीत आये हुए सरकारी कमचारियों के अवकाश वेतन पन्शन आदि का भार १ नवम्बर १९५६ से कम्पट्रोलर तथा भारत के महालेखापाल द्वारा जारी की गई एकाउंट कोड भाग प्रथम के परिशिष्ट ३ में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमित होगा। राजस्थान सेवा नियम के परिशिष्ट १३ में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार से वसूल किया गया कोई अशदान ऐसे मामलों में वापिस करना पड़ेगा जिनमें दातव्य एकाउंट कोड भाग प्रथम के परिशिष्ट ३ में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन अशदान के भुगतान से विभिन्न निपटारा करना अपेक्षित हो। राज्यों के नाम -

(१) मध्यप्रदेश

(२) मेसूर

(३) महाराष्ट्र

(४) गुजरात

(५) पंजाब

(६) बिहार

१ वित्त विभाग स एफ ७ ए (४३) एफ डी (ए) मन्स / ५८, दिनांक १२-८-६१ तथा दिनांक १५-१२-१९६१ द्वारा जोड़ा गया।

२ वित्त विभाग आर्गन स एफ ७ ए (४३) एफ डी /-ए (मन्स) ५८, दिनांक २३-८-१९६२ द्वारा जोड़ा गया।

(७) आन्ध्रप्रदेश

(८) मद्रास

(९) केरल

(१०) असम

(११) पश्चिम बंगाल

(१२) उत्तर प्रदेश

(१३) उड़ीसा

परिशिष्ट १४

सूची 'क'

विमानाग्राह्यको की सूची (अपम अंशों)

- १ एडवोकेट जनरल (महाविपत्ता)
- २ अध्यक्ष, राजस्व मण्डल
- ३ मुख्य वन संरक्षक [चीफ कमन्डरेडर आफ फॉरेस्ट]
- ४ मुख्य अभियन्ता विद्युत एवं यांत्रिकी
- ५ मुख्य अभियन्ता, भवन एवं सड़क
- ६ मुख्य अभियन्ता, सिंचाई
- ७ आयुक्त, आबकारी एवं करारोपण, राजस्थान
- ८ आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग
- ९ मुख्य निर्वाचन अधिकारी (ग्रुपवाई)
- १० मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार
- ११ अपर आयुक्त, बिक्रीकर एवं कृषि आयकर, राजस्थान
- १२ निदेशक, शिक्षा विभाग
- १३ निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
- १४ सैन्य आयुक्त [डिवीजनल कमिशनरी]
- १५ निदेशक, खान एवं भूगर्भ विज्ञान
- १६ निदेशक, कृषि एवं साख आयुक्त राजस्थान
- १७ समुक्त विकास आयुक्त
- १८ विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव
- १९ महानिरीक्षक पुलिस
- २० महानिरीक्षक, कारागार
- २१ महानिरीक्षक, पञ्जीयन एवं स्टाम्प
- २२ जागोर आयुक्त
- २३ थम आयुक्त
- २४ विधि परामर्शदाता [लीगल रिमेम्बरन्सर]
- २५ सदस्य औद्योगिक यायाधिकरण

- २६ पजीयक, सहकारी समितियाँ
- २७ (सेटलमेंट) भूप्रबन्ध प्राप्ति
- २८ निदेशक, परिवहन विभाग
- २९ भ्रष्टाचार निवारण अधिकारी
- ३० निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उस अवधि तक के लिए जब तक कि यह पद बरिष्ठ आई ए एस [अधिकारी] द्वारा धारण किया जाए।
- ३१ प्रबन्धक, गगाननर शुगर फक्ट्री
- ३२ अपर निदेशक, शिक्षा
- ३३ निदेशक, तकनीकी शिक्षा
- ३४ निदेशक बीमा
- ३५ प्रायुक्त देवस्थान
- ३६ निदेशक जोत एकीकरण [डाइरेक्टर आफ कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग्स]
- ३७ प्रधानाचार्य, अधिकारी प्रशिक्षण लय जोधपुर।
- ३८ मुख्य लेखाधिकारी चम्बल परियोजना
- ३९ विशिष्ट महानिरीक्षक, पुलिस
- ४० निदेशक पशुचिकित्सा एवं पशुपालन विभाग
- ४१ अध्यक्ष तकनीकी शिक्षा मण्डल
- ४२ अध्यक्ष राष्ट्रीयकरण पाठ्य पुस्तक मण्डल
- ४३ मुख्य अभियन्ता राजस्थान नहर परियोजना
- ४४ द्वितीय मुख्य अभियन्ता, सिंचाई
- ४५ निदेशक, जिला मजेटिस
- ४६ प्रायुक्त, उपनिवेशन चम्बल परियोजना, कोटा
- ४७ निदेशक, रोजगार कार्यालय।
- ४८ सचिव, राजस्थान नहर मण्डल [केवल मण्डल के कार्यालय के लिए]
- ४९ अध्यक्ष, राजस्थान नहर मण्डल एवं प्रशासक राजस्थान नहर परियोजना
- ५० प्रायुक्त, खाद्य रसद एवं पत्तेन शासन सचिव
- ५१ उपनिवेशन प्रायुक्त राजस्थान नहर परियोजना
- ५२ मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान नहर परियोजना जोधपुर
- ५३ सचिव राजस्थान विधान सभा
- ५४ सदस्य भारतीय-मायाधिवरण परिवहन विभाग राजस्थान
- ५५ प्रधानाचार्य, राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर [समस्त संस्थाओं एवं २ वि शिक्षा एवं अनुसन्धान से संबंधित मण्डल के अधीन मण्डलों के सम्बन्ध में]
- ५६ मुख्य अभियन्ता, राणा प्रताप सागर बांध
- ५७ सहाय एवं भवन सहायता विभाग
- ५८ निदेशक, उपनिवेशन चम्बल परियोजना कोटा

- ५६ प्रधानाचार्य, राजस्थान महाविद्यालय, जयपुर
 ६० मुख्य प्रशिक्षता, लोक निर्माण विभाग [स्वास्थ्य] राजस्थान, जयपुर
 ६१ निदेशक, राजस्थान मूलज जन मण्डल
 ६२ सचिव, राजस्थान सनिक, नाबिक एवं वमानिक मण्डल

सूची "ख"
 विभागाध्यक्षों की सूची (प्रथम श्रेणी के प्रतिरिक्त)

- १ अवर जमीन आयुक्त
- २ मुख्य साक्षिकी अधिकारी
- ३ मुख्य अधीक्षक, पुरातत्व एवं संग्रहालय
- ४ मुख्य अधीक्षक, मृदा एवं सेलन सामग्री
- ५ अध्यक्ष, आयुर्वेदिक व यूनानी सिस्टम के रेजिस्ट्रेशन का मण्डल
- ६ सहाय अधिकारी (निष्कायण सम्पत्ति) (Evacuee Property) जयपुर
- ७ मुख्य पचायत अधिकारी
- ८ जिलों के जिलाधीश
- ९ कमाण्डेंट, मेसनल कैडिट फोर
- १० निदेशक आयुर्वेदिक विभाग
- ११ निदेशक, सावजनिक सम्पत्ति विभाग
- १२ निदेशक स्थानीय निवाय (लोकल बाडीज)
- १३ निदेशक, समाज कल्याण विभाग
- १४ निदेशक, सारनिवेशन, (कोवोनाइजेसन) हनुमानगढ़
- १५ जिला एवं सत्र न्यायाधीश
- १६ परीक्षक, स्थानीय निधि अवेक्षा (लोकल फंड वाडिट) विभाग
- १७ पुरातत्व मंदिर का प्रधान
- १८ प्रबंधक, आयुर्वेदिक फार्मसीज
- १९ स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य
- २० प्रधानाचार्य फोर्ट काउण्टेशन प्रशिक्षण केंद्र, छत्रपुरा (कोटा)
- २१ प्रधानाचार्य एम बी एम इंजिनियरिंग कालेज, जोयपुर
- २२ पजीमक राजस्थान उच्च न्यायालय
- २३ विशेष अधिकारी, नगर सुधार मण्डल एवं सचिव, नगर सुधार मण्डल
- २४ सचिव, लोक सेवा आयोग
- २५ मेड एवं ऊन सुधार अधिकारी

- २६ अधीक्षक गजेटियर
- २७ अधीक्षक, प्रायुर्वेदिक स्टडीज
- २८ प्रधानाचार्य, पशुचिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर
- २९ प्रधानाचार्य, एस के एन कृषि महाविद्यालय, जोधनेर
- ३० प्रशासनिक अधिकारी, विद्युत एवं यात्रिकी विभाग, वित्त विभाग के आदेश सं० एक १८ (११) एक ११/५५ दिनांक १३-१०-५६ में वर्णित मरी के सम्बन्ध में)
- ३१ निदेशक, अकाल सहायता विभाग
- ३२ विशिष्ट अधिकारी, राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर
- ३३ विशिष्ट शिक्षा अधिकारी, आयोजना, निम्न योजनाओं के सम्बन्ध में
(क) उद्गु उद्घोषीय स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूल
(ख) केंद्रीय, समायीय एवं जिला स्तरीय पुस्तकालय
(ग) समाज शिक्षा ।
- ३४ विशिष्ट अधिकारी राजस्थान कालेज
- ३५ उपनिवेशन अधिकारी, राजस्थान नहर परियोजना, बीकानेर
- ३६ उपनिवेशन अधिकारी चम्बल परियोजना कोटा
- ३७ सचिव राजस्थान मण्डल (भू अमितेक्ष) केवल पशु गणना काय के मामले में
- ३८ उप शासन सचिव नियुक्ति (ख) सचिवालय के अधीनस्थ लिपिक वर्गीय कमचारियों एवं अन्य श्रेणी कमचारियों के सम्बन्ध में ।
- ३९ वक्फ आयुक्त
- ४० सचिव राष्ट्रीयकरण पाठ्य पुस्तक मण्डल
- ४१ प्रधानाचार्य पोलोटेकनीक
- ४२ प्रधानाचार्य एडोसनल एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर सुमेरपुर
- ४३ निदेशक सहायता एवं पुनर्वास
- ४४ निदेशक सस्त्रुत शिक्षा
- ४५ निदेशक आर्थिक एवं औद्योगिक सर्वेक्षण
- ४६ प्रधानाचार्य लेखा प्रशिक्षणालय जयपुर
- ४७ निदेशक राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर
- ४८ प्रधानाचार्य सवाईमानसिंह मेडिकल कालेज, जयपुर
- ४९ उपनिवेशन अधिकारी, राजस्थान नहर परियोजना, बीकानेर
- ५० विद्युत निरीक्षक
- ५१ जनरल मैनेजर राजस्थान राज्य परिवहन
- ५२ निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

- ५३ जनरल मनजर राजस्थान लवण स्रोत
- ५४ प्रधानाचार्य व्यायाम शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर
- २५५ उपशासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान, राजस्थान के सरकट हाउसों एवं राजस्थान हाउस न्यू देहली एवं गवर्नमेण्ट होस्टल जयपुर के सम्बन्ध में ।

परिशिष्ट १५

ड्यूटी पर स्थानांतरण अथवा अवकाश से वापसी जैसे मामलों में अंतिम वेतन प्रमाण पत्र की तैयारी को विनियमित करने हेतु निम्नवत् और महालेखा निरीक्षक द्वारा निम्नित नियम —

१ ड्यूटी पर स्थानांतरण दो प्रकार का हो सकता है —

(1) सरकारी कर्मचारी एक अवेक्षण सर्किल या क्षेत्र से दूसरी अवेक्षण सर्किल या क्षेत्र में ड्यूटी पर खाना हो सकता है ।

(11) सरकारी कर्मचारी उसी अवेक्षण सर्किल या क्षेत्र में ड्यूटी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाना हो सकता है ।

(२) पहले प्रकार की स्थिति में उक्त प्रमाण-पत्र निम्न प्रकार दिया जाना चाहिये —

(अ) यदि सरकारी कर्मचारी महालेखाकार के अपने क्षेत्र के स्टेशन पर ही नियोजित है तो यह प्रमाण पत्र उसी अधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिये वशत कि प्राडिट आफिस में पूर्व अवेक्षा (प्री आडिट) के बाद भुगतान करने की पद्धति का अनुसरण किया जाता हो अन्यथा नीचे के अनुच्छेद व में दी हुई प्रक्रिया का ही अनुसरण किया जायेगा ।

(ब) यदि सरकारी कर्मचारी को अपने नये क्षेत्र को जाते समय उस स्टेशन से रास्ते में गुजरना पड़ता हो तो प्रमाण-पत्र उस अधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिये जो उस कोषागार का प्रभारी अधिकारी है जहाँ से कर्मचारी का पिछड़ा वेतन उठाया और महालेखाकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो ।

(स) यदि सरकारी कर्मचारी महालेखाकार के स्टेशन पर न तो नियोजित हो है और न उसे वहाँ होकर गुजरना ही पड़ता है तो यह प्रमाण-पत्र कोषागार के प्रभारी अधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिये और उसकी एक अनुलिपि कोषागार अधिकारी द्वारा महालेखाकार के प्रति हस्ताक्षर हेतु एवं स्थानांतरित किये हुए सरकारी कर्मचारी के नये क्षेत्र के महालेखाकार को भेजे जाने हेतु अग्रपिप्त की जानी चाहिये ।

अपवाद — पूर्वगत नियमों के अपवाद स्वरूप एक आडिट सर्किल या क्षेत्र से दूसरे आडिट सर्किल या क्षेत्र में स्थानान्तरित अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी का अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र कार्य-समाप्ति द्वारा दिया जा सकता है और सम्बद्ध महालेखाकार द्वारा उसके प्रतिहस्ताक्षरित होने की कोई आवश्यकता नहीं है किन्तु भारत से बाहर स्थानांतरण होने की स्थिति में अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र पर महालेखाकार के हस्ताक्षर होने ही चाहिये ।

(३) स्थानांतरण के दूसरे मामलों में सरकारी कर्मचारी को उस कोषागार के प्रभारी अधिकारी से ही अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र देना होगा जहाँ से उसने पिछला वेतन उठाया हो, अथवा यदि वह अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी है तो उस कार्यालय-पक्ष से लेना होगा जिसके अधीन पिछली बार नियोजित था ।

(४) इपूटी पर वापस होने से पूर्व जिस सरकारी कमचारी ने भारत में ही अपना अवकाश-वेतन उठाया हो तो उसे उस महालेखाकार से अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहिये जिसके द्वारा अथवा जिसके क्षेत्राधिकार में उसका पिछला अवकाश वेतन भुगताया गया हो ।

(५) ऊपर अंतिम सभी मामलों में “अंतिम-वेतन प्रमाण पत्र” अनुलग्नक में दिखाये गये फॉर्म में तैयार किया जायेगा । इस फॉर्म में फण्ड की कटौती के विवरण दिये जाने की भी व्यवस्था है, यद्यपि उनके सही होने के लिये विल तैयार करने वाला अधिकारी ही उत्तर दायी है, किंतु अंतिम वेतन प्रमाण पत्र तैयार करने वाला अधिकारी जाने वाले सरकारी कमचारी से किसी कानूनी अदालत द्वारा दिये गये वेतन की कुर्की के आदेश, जिसका कि उस कमचारी को उक्त प्रमाण-पत्र स्वीकार करने से पूर्व नोटिस मिल चुका हो के अधीन की जाने वाली वसूलियों सहित अन्य समस्त भागों को ही प्रमाण-पत्र में अंकित करने का उत्तरदायी नहीं है अपितु ऐसी भागों की वसूली की सूचना उस कोषागार कार्यालय या वेतन उठाने वाले कार्यालय को देने का भी उत्तर दायी है जहाँ से भविष्य में वह सरकारी कमचारी अपना वेतन उठायेगा ।

(६) उसी ब्राडिट सर्किल में एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण के सभी मामलों में अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में पिछला नियमित या मासिक भुगतान विशेष रूप से अंकित होना चाहिये तथा जहाँ किसी सरकार के कोषागार नियमों या वित्तीय नियमों में कुछ विरुद्ध प्रावधान हो उन मामलों को छोड़कर अन्य सभी में जिस माह में स्थानांतरण किया गया है उसका पूरा वेतन नये जिले में ही भुगताया जाना चाहिये ।

(७) किसी भी रैंक के ऐसे सरकारी कमचारियों के वेतन बिलों पर केवल राज पत्रित सरकारी कर्मचारियों के हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर ही इन नियमों की खातिर अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र माने जा सकते हैं जिन्हें कि सरकार के मुख्यालय के किसी पहचानी स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर जिसे कि तत्समय सरकार ने मुख्यालय घोषित कर दिया हो जाना पड़ता हो ।

कटौतियाँ

३ उ होने दिनाक को पूर्वाह्न । मध्याह्न मे के पद का काय भार सीप दिया है ।

४ इस सरकारी कर्मचारी के वेतन से 'प्रतिलोम' मे अन्तिम वसूलिया की जानी हैं ।

५ इन्हें निम्नानुसार अवकाश-वेतन भुगता दिया गया है । प्रति लोम मे अन्तिम कटौतिया कर ली गई हैं ।

अवधि	दर	राशि
दिनाक से दिनाक	तक	५ प्रतिमास की दर से
दिनाक से दिनाक	तक	५ प्रति मास की दर से
दिनाक से दिनाक	तक	५ प्रति मास की दर से

६ ये निम्नलिखित मोहरण करने के हकदार हैं —

७ ये दिन की कार्य ग्रहण अवधि के भी हकदार हैं ।

८ चालू वर्ष की आरंभ तिथि से इनसे वसूल किये गये आयकर का विवरण प्रतिलोम मे प्र कित कर दिया गया है ।

दिनाक	१६	(हस्ताक्षर) (पद)
-------	----	---------------------

प्रतिलोम (रिवर्स)

वसूलियों का विवरण

वसूली का स्वरूप

राशि	५ ।
	किस्तों मे वसूल किया जाते हैं ।

अवकाश वेतन मे से की गई कटौतिया —

के कारण दिनाक	से दिनाक	तक	५
के कारण दिनाक	से दिनाक	तक	५
के कारण दिनाक	से दिनाक	तक	५

महीना के नाम	वेतन	अर्चुइटी शुल्क आदि	निधि तथा अन्य कटौतिया	वसूल किये गये आयकर की राशि	विशेष विवरण
--------------	------	--------------------	-----------------------	----------------------------	-------------

अप्रैल १६

मई १६

जून १६

जुलाई १६

अगस्त १६

सितम्बर १६

अक्टूबर १६

नवम्बर १६

दिसम्बर १६

जनवरी १६

फरवरी १६

मार्च १६

परिशिष्ट १६

महगाई भत्ते की दरें तथा महगाई भत्ता उठाने के लिये नियम

महगाई भत्ता एक क्षति पूरक भत्ता है और राजस्थान सेवा नियम भाग १ के नियम ४२ के अधीन महगाई भत्ता और विशेष अनाज भत्ता, स्वीकार करने के लिये जारी पिछले सभी आदेशों का अधिक्रमण करत हुए महगाई भत्ता सभी सरकारी कम चारिया को मजूर किया गया है।

भत्ते की दरें तथा प्रयोज्यता—नीचे दी हुई महगाई भत्तों की दरें दिनांक १४ १९५० से राजस्थान राज्य के सभी सरकारी कमचारियों पर लागू होगी।

वेतन	महगाई भत्ते की दरें
३६ रु प्रति माह तक	१२ रु प्रति माह
४० रु से ६६ रु प्रति माह तक	१५ रु प्रति माह
१०० रु से १६६ रु " "	२० रु प्रति माह
२०० रु से ४६६ रु " "	२५ रु , "
५०० रु से ९६६ रु " "	३० रु " ,
७०० रु से १००० रु , ,	४० रु , ,

जिन सरकारी कमचारियों को १००० रु मासिक से अधिक वेतन मिलता है उन्हें महगाई भत्ता इतना ही मिलेगा जो कि वेतन के साथ मिलकर १०४० रु मासिक की राशि हो सके।

टिप्पणियाँ

वेतन में विपक्ष वेतन व्यवस्था वेतन-सहा कान्स्टबल और हैंडकास्टेबल के मामले में लागू होता भत्ता सम्मिलित है।

-(२) किन पर लागू नहीं है—यह आदेश निम्न सरकारी कमचारियों पर लागू नहीं होगा—

- (अ) ठेके पर सेवा करने वाले कमचारी
- (ब) जिन की सेवाएँ दूसरी सरकार से उधार ली गई हैं
- (स) जो अथवा कालिदास कमचारी है या जिन्हें फुलकर मद से वेतन प्राप्त होता है।
- (द) भू राजस्व या अन्य विभागों के वे कमचारी जिनकी कि अधिसूचना जारी की जाये।

(य) सरकारी मुद्रणालयों जल एवं विद्युत प्रतिष्ठानों और सावजनिक निर्माण विभाग की कमशालाओं के औद्योगिक कमचारी (अर्थात् प्रशासनिक, अधिशासी, लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के कमचारियों को छोड़कर अन्य कमचारी)

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या एक १० (३३) की ए/५० दिनांक १२ जुलाई १९५० द्वारा सम्मिलित।

राजस्थान सरकारों का निर्णय

१ इकाई महगाई भत्ते को स्वीकार्यता — वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ८ (१७) आर/५५ दिनांक ६.६.५५ के अनुच्छेद २ की सीमा के सम्बंध में पुराने इकाई मान से पूर्व प्रसिद्ध कमचारियों के महगाई भत्ता उठाने के विषय में सन्देश उत्पन्न होने पर निर्णय किया गया है कि केवल वही सरकारी कर्मचारी जो राजस्थान सिविल सेवा (वेतन मान एकीकरण) नियम एवं अनुसूची १६५४ के नियम ४ के अधीन अंतिम रूप से एकीकृत वेतन मान को अपेक्षा इकाई-वेतन को ही स्वीकार करत हैं वही उक्त आदेश की शर्तों में पुराने इकाई मान से महगाई भत्ता उठाने के हकदार हैं उपर्युक्त आदेश की संस्था यह नहीं है कि यह लाभ उन सरकारी कर्मचारियों को भी दिया जा सके कि जिन्होंने एकीकृत वेतन मान दिनांक १-४-५४ के बाद की तिथि से स्वीकार किया है।

२ सशोधित करें एवं उनकी प्रयोज्यता — सरकारी आदेश संख्या १ में स्वीकृत महगाई भत्ते की दरों की वजह से यह आदेश दिया जाता है कि दिनांक १ जनवरी १९५१ से महगाई भत्ते की निम्नलिखित दरें राजस्थान सरकार को अधिकार देने वाले नियम के अधीन सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगी —

वेतन	महगाई भत्ते की दरें
४० रु मासिक से कम	१५ रु प्रति माह
४० रु या इससे अधिक किंतु	२० रु प्रति माह
६० रु मासिक से कम	
६० रु या इससे अधिक किंतु	२५ रु प्रति माह
१०० रु मासिक से कम	
१०० रु या इससे अधिक किंतु	३० रु प्रति माह
२०० रु मासिक से कम	
२०० रु या इससे अधिक किंतु	३५ रु प्रति माह
५०० रु मासिक से कम	
५०० रु या इससे अधिक किंतु	४० रु प्रति माह
१००० रु मासिक से कम	
१००० रु से १००० रु मासिक तक	५० रु प्रति माह

जिन सरकारी कर्मचारियों को १००० रु से अधिक वेतन मिलता है वह महगाई भत्ते की राशि इतनी दी जायेगी कि जो वेतन के साथ मिलकर कुल राशि को १०५० रु कर देंगी।

१ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ८ (१७) आर/५५ (एफ डी) ए/ रजि. दिनांक ७ मार्च १९५७ द्वारा मम्मिलित किया गया।

२ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ७ (१) आर/५१ दिनांक ११ जनवरी १९५१ द्वारा समाविष्ट

२—किन पर लागू नहीं है —यह आदेश निम्न सरकारी कमचारियों पर लागू नहीं होगा —

- (अ) ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी ।
- (ब) जिनकी सेवायें दूसरी सरकार से उधार ली गई हैं ।
- (म) जो अशकालिक कमचारी हैं या जिन्हें फुटकर मद से वेतन प्राप्त होता है ।
- (द) भू राजस्व या अग्न विभागों के वे कमचारी जिनकी कि अधिसूचना जारी की जाये ।
- (य) सरकारी मुद्रणालयों, जल एवं विद्युत प्रतिष्ठानों और सावजनिक निर्माण विभाग की कर्मशालाओं के औद्योगिक कमचारी (अर्थात् प्रशासनिक, अधिशासी लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के कर्मचारियों को छोड़कर अग्न कमचारी) ।

१२ (I) (अ) सरकारी आदेश सख्या-२ मे स्वीकृत महगाई भत्ते की दरों को अशत सशोधित करते हुए यह आदेश दिया गया था कि जिन सरकारी कमचारियों परिलाभ (यानी वेतन और महगाई भत्ता दोनों) १०० रु प्रति मास से अधिक न हो उह दिनांक १ ४ ५७ से महगाई भत्ते मे ५ रु मासिक की तदर्थ वृद्धि निम्नानुसार दी जायेगी —

वेतन	महगाई भत्ते की दरें
४० रु मासिक से कम	२० रु प्रति माह
४० रु या इससे अधिक किन्तु	२५ रु प्रति मास
६० रु मासिक से कम	
६० रु या इससे अधिक किन्तु	३० रु प्रति मास
७० रु मासिक तक ।	

जिन सरकारी कमचारियों को ७० रु प्रति मास से अधिक वेतन मिलता हो उन्हें महगाई भत्ते की यह तदर्थ वृद्धि उस राशि के बराबर दी जायेगी जिससे कि महगाई भत्ता और वेतन दोनों मिलकर १४० रु प्रति मास से कम हो जाय । यह तदर्थ वृद्धि केवल उन्ही कमचारियों को स्वीकार्य होगी जिनकी वर्तमान महगाई भत्ते की दर उही के समान वेतन पाने वाले केद्रीय सरकार के कमचारियों को मिलने वाले महगाई भत्ते की दरों से कम हैं ।

१२ (I) (ब) अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को कुछ और राहत देने के प्रयत्न स्वरूप राज्यपाल सह्य आदेश प्रदान करते हैं कि सरकार को अधिकार प्रदान करने वाले वित्त विभाग के आदेश स एफ १ (१८२) ए/वल्स/५६ दिनांक २० ३ १९५७ के

१ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (१८२) ए/वल्स/५६ दिनांक २०-३-५७ द्वारा सम्भावित

२ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (१८२) एफ डी ए/वल्स १५८ दिनांक २-१०-५८ एवं सख्या एफ १ (२) एफ डी ए १५६ दिनांक २७-४-६० द्वारा सम्भावित

साथ पठित आदेश सख्या एफ. ७ [१] आर/दिनांक- ११-१-१९५१ के नियम के अधीन २५० रु मासिक तक वेतन पाने वाले, जिन सरकारी कर्मचारियों पर उक्त आदेश लागू हैं उन्हें दनांक १-१०-१९५८ से ५ रु मासिक की तदर्थ वृद्धि मंहगाई भत्ते में और स्वोकाय होगी। मंहगाई भत्ते में उक्त तदर्थ वृद्धि के फल स्वरूप मंहगाई भत्त की सशोधित दरें निम्नानुसार होगी —

वेतन	नई दरें
१ ४० रु से कम	२५ रु
२ ४० रु या इससे अधिक किन्तु ६० रु से कम	३० रु
३ ६० रु या इससे अधिक किन्तु ७० रु तक	३५ रु
४ ७० रु से अधिक किन्तु १०० रु कम	३० रु

टिप्पणी

वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ—(१८२)/रूल्स/५६ दिनांक २० ३ ६७ के अधीन मंहगाई भत्ते में तदर्थ वृद्धि के कारण भोपातिक समाधान के अधिकारी कमचारी उक्त ५ रु की तदर्थ वृद्धि के प्रतिरिक्त यह लाभ तब तक पाने के हकदार बने रहेंगे जब तक कि उनका वेतन ७५ रु तक पहुँचता है। यह दिनांक १-१०-१९५८ से प्रभावशील होगा।

५ १०० रु या इससे अधिक किन्तु २०० रु से कम। ३५ रु

६ २०० रु या इससे अधिक किन्तु २५० रु तक। ४० रु

टिप्पणी

जिन सरकारी कर्मचारियों को २५० रु से अधिक किन्तु २५५ रु से कम वेतन मिलता हो उन्हें मंहगाई भत्ते की इनकी राशि मिलगी कि जो वेतन सहित २६० रु हो सके।

(२) मंहगाई भत्ते की तदर्थ वृद्धि उन कर्मचारियों को स्वीकार्य होगी जिनका वर्तमान मंहगाई वेतन सहित मंहगाई भत्ते का मान केन्द्रीय सरकार के उसी के समान वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले मंहगाई भत्ते के मान से कम है।

१३ अल्प वेतन भोगी सरकारी कर्मचारियों को और राहत देने के प्रयत्न स्वरूप यह आदेश दिया गया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों पर वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १, (१८२) एफ डी /ए/रूल्स/५६ दिनांक २० ३ १९५७ एय २ १० १९५८ के साथ पठित वित्त विभाग का आदेश स एफ ७ (१) आर/५१ दिनांक ११-१-५१ जैसा कि वित्त विभाग के आदेश स एफ १ (सी) (२) एफ डी /ए/रूल्स/५६ दिनांक २७ ४ ६० द्वारा सशोधित है, लागू होता है और जा ३१५ रु प्रति मास तक कुल परिनाम प्राप्त

१ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (सी) (१२) एफ डी (ए) रूल्स/६० दिनांक १८ १० ६० द्वारा सम्मोचित।

करते हैं, उन्हें दिनांक १ जुलाई १९६० से ५ रु प्रति मास की तदर्थ वृद्धि महगाई भत्ते में दी जा सकती है। यदि ये कुल परिलाभ ३१५ रु से ज्यादा है किन्तु ३२० रु से कम है तो इस तदर्थ वृद्धि की राशि इतनी होगी कि कुल प्राप्त परिलाभ ३२० रु हो सके।

इस आदेश के प्रयोजनार्थ 'परिलाभों' का तात्पर्य (जिसा कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम ७ (२४) में परिभाषित है) वेतन और महगाई वेतन सहित महगाई भत्ते से है।

ऊपर स्वीकृत तदर्थ-वृद्धि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा शर्तों का संरक्षण) नियम १९५७ के नियम १४ के अधीन सरक्षित महगाई वेतन पाने वाले व्यक्तियों को स्वीकार्य नहीं होगी।

१४ राजस्थान सरकार का निर्णय सख्या ४ - ऑरत के सर्विथान की धारों ३०६ के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार के कर्मचारियों को स्वीकार्य महगाई भत्ते की दरे निम्न प्रकार सशोधित की जायेगी

वेतन	महगाई भत्ता
१५० रु से नीचे	१०) ६०
१५०) और इससे अधिक	२०) ६०
किन्तु ३००) से कम	
३००) और इससे अधिक	ऐसी राशि जिससे वेतन ३००) से कम न हो सके

आदेश सख्या जी ए डी क्रमांक एफ १० (२५) जी, ए/५० दिनांक १२ ७ १९५०, वित्त विभाग के आदेश स एफ ७ (१) आर/५१ दिनांक ११ १-१९५१, एफ १ (१८२) ए/आर/५६ दिनांक २० ३ ५७, एव २१० १९५८, एफ १ (सी) (२) एफ डी/ए/५९ दिनांक २७ ४ १९६० और एफ १ (सा) (१२) एफ डी/ए/६० दिनांक १८ १० १९६० में निर्धारित दरो का अधिक्रमण करते हुए उक्त दरे दिनांक १ सितम्बर १९६१ से प्रभावशील होगी एवं उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी जो राजस्थान सिविल सेवाओं (सशोधित वेतन) नियम १९६१ के अधीन सशोधित वेतन मान स्वीकार करते हैं या जिन्हें सशोधित वेतन मान में हो लगा दिया जाता है। महगाई भत्ते की सशोधित दरो की कोई भी अंश किसी भी प्रयोजन से वेतन जैसा नहीं माना जायेगा।

जो सरकारी कर्मचारी राजस्थान सिविल सेवाओं (सशोधित वेतन) नियम १९६१ के अधीन चालू वेतन मान ही रखना स्वीकार करते हैं, उन्हें फिर भी दिनोंक ३१ अगस्त १९६१ को प्रभावशील दरो पर ही महगाई-भत्ता तब तक दिया जाता रहेगा जब तक कि वो वर्तमान वेतन-मान में ही वेतन प्राप्त करते रहेंगे। उन सरकारी कर्मचारियों के मामले में जिन्हें कि महगाई भत्ता पुरानो दरो पर ही धरुल करने की आज्ञा है उन पर किही प्रयोजनो के लिये महगाई भत्ते के कुछ हिस्सा को वेतन माने

जाने वाले एव समय समय पर साशोधित वित्त विभाग के आदेश स ४६४१/४८/एफ ७ ए (१४) एफ डी १/ए/आर/५८ दिनांक ३-३-१९५६ के प्रावधान ही लागू होते रहने।

महगाई भत्ता चाहे उपयुक्त अनुच्छेद १ में अंकित नई दरों पर वसूल किया जाय या दिनांक ३१ अगस्त १९६१ को प्रभावशाल दरो पर, दोनों ही स्थितिया में इसकी स्वीकृति महगाई भत्ता वसूल करने के लिये राजस्थान सेवा नियम भाग II की परिशिष्ट १० में दिये हुए नियमों के अनुसार, जिनको कि समय समय पर साशोधित अथवा स्पष्ट किया जाता रहा है निम्नलिखित मामलों का छोड़कर विनियमित जी जायेगे —

(1) जो सरकारी कर्मचारी नि शुल्क आवास तथा भोजन की रियायत पाने के अधिकारी हैं और यह उन्हें सेवाओं की शत के रूप में प्राप्त होती हैं और जो १ सितम्बर १९६१ से लागू साशोधित वेतन मान स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार का महगाई भत्ता नही दिया जायेगा।

(ii) अवकाश के दौरान महगाई भत्ता अवकाश वेतन के आधार पर नई या पुरानी दरों पर जैसा कि अवकाश वेतन नई या पुरानी वेतन दरों पर, प्राप्त होगा, ही दिया जायेगा। ऐसी मामलों में जहाँ कि सरकारी कर्मचारी ने अवकाश से पूर्व दस महीने के दौरान वेतन तथा महगाई भत्ता कुछ पुरानी दरों पर और कुछ नई दरों पर प्राप्त किया है तो वहाँ पर अवकाश वेतन, अवकाश से पूर्व दस माह के दौरान उठाये गये साशोधित दरों के वेतन तथा पुरानी दरों पर उठाये गये वेतन एवं महगाई भत्ते के औसत के बराबर ही होगा। ऐसी स्थिति में महगाई भत्ते का राशि ऊपर अनुच्छेद १ में अंकित दरों पर इस पर फलित अवकाश वेतन के आधार पर ही गणना करके दिया जायेगा।

१५ वित्त विभाग के आदेश स एफ, १ (१८२) एफ डी (ए) रुत्स/५६ दिनांक २-१०-१९५८ में निर्धारित शर्तों की सीमा के सम्बन्ध में कुछ सन्देह प्रकट किये गये हैं। मामलों की जाच की गई है और यह स्पष्ट किया गया है कि दिनांक ३१ १० १९५६ को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू महगाई भत्ते की दरें ही उक्त आदेश के अनुच्छेद २ के प्रयोजनार्थ काम में ली जानी चाहिये तथा दिनांक १ ११-१९५६ की या इसके बाद भारत सरकार द्वारा स्वीकृत महगाई भत्ते की उत्तर वर्ती वृद्धि का काम में नहीं लिया जाना चाहिये।

उक्त स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए जिन व्यक्तियों ने दिनांक १-१०-१९५८ को या इसके बाद राजस्थान सेवाओं (सेवा शर्तों का सरक्षण) नियम १९५७ के अनुसार उन्हीं दरों पर जो कि दिनांक १-११-१९५६ की स्वीकार्य थी, महगाई भत्ता उठाया या वह उपयुक्त आदेश द्वारा स्वीकृत महगाई भत्ते में ५ रु० की तदर्थ वृद्धि नहीं दी जायेगी। वे इसके हकदार नहीं होंगे।

१ वित्त विभाग का आदेश रुत्स/एफ १ (सी) (७) एफ डा नियम/६० I दिनांक ६ १ १९६२

१६ वित्त विभाग के आदेश स एफ १ (सी) (१२) एफ डी (ए) नियम/६० दिनांक १८ १० १९६० के अनुच्छेद ३ द्वारा इस आदेश के अधीन स्वीकृत महगाई भत्ते की तदर्थ वृद्धि उन कर्मचारियों को स्वीकाय नहीं थी जो राजस्थान सिविल सेवायें (सेवा शर्तों का संरक्षण) नियम १९५७ के नियम १४ के अधीन संरक्षित महगाई वेतन प्राप्त करते थे।

मामले पर पुनर्विचार करके यह आदेश दिया गया है कि यद्यपि इन कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों की अपेक्षा दिनांक १-४ १९५८ से महगाई भत्ते की उच्च राशि स्वीकृत होने से (महगाई-वेतन को छोड़कर) वित्त विभाग के आदेश स ४६४१/५८ एफ ७ ए (१४) एफ डी (ए) नियम/५८ दिनांक २३ १९५८ के अनुच्छेद १२ (१) के अनुसार संरक्षित महगाई वेतन के अलावा भी लाभ हुआ था किंतु विशेष प्रकरण मान कर उक्त दिनांक १७-१९६० से वित्त विभाग के आदेश स एफ १ (सी) (१२) एफ डी (ए) नियम/६० दिनांक १८ १० १९६० में दी हुई शर्तों के अधीन महगाई भत्ते की ५४ की तदर्थ वृद्धि दी जा सकती है। तदनुसार ऊपर प्रसंगित दिनांक १८ १० १९६० की सरकारी आदेश का अनुच्छेद ३ निरस्त माना जाये।”

२७ वित्त विभाग के आदेश स एफ १ (१८२) ए/नियम/५६ दिनांक २० ३ १९५८ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। एक प्रश्न यह उठाया गया है कि उपर्युक्त आदेश से स्वीकृत महगाई भत्ते की तदर्थ वृद्धि भूतपूर्व अजमेर राज्य के कर्मचारियों को, जिन्हें कि अजमेर के वेतन मान में ही वेतन मिलता है भी स्वीकाय है या नहीं। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त अंकित आदेश में दी हुई शर्तों के अधीन भूतपूर्व अजमेर राज्य के कर्मचारियों को भी यह तदर्थ वृद्धि स्वीकाय है।

३८ एक प्रश्न यह उठाया गया है कि वित्त विभाग के शापन सख्या एफ १ (सी) (७) एफ डी (ए) नियम/६० दिनांक ७-२-१९६२ के साथ पठित वित्त विभाग के आदेश स एफ १ (१८२) (ए) नियम/५६ दिनांक २०-३ १९५७ के प्रावधान अजमेर के वेतन मान में वेतन पाने वाले एवं राजस्थान (सेवा शर्तों का संरक्षण) नियम १९५७ के नियम १४ के अधीन महगाई वेतन पाने वाले भूतपूर्व अजमेर राज्य के कर्मचारियों पर महगाई भत्ते की तदर्थ वृद्धि की स्वीकृति किस प्रकार लागू की जाये।

इस विषय में यह स्पष्ट किया जाता है कि यह तदर्थ वृद्धि केवल उन कर्मचारियों को ही स्वीकाय होगी जिनके परिलाभ (यानी राजस्थान की दरो पर प्राप्त वेतन, संरक्षित महगाई वेतन एवं महगाई भत्ता सब मिलाकर) १०० रु० मासिक से अधिक न हो।

दिनांक २० ३-१९५७ के वित्त विभाग के उक्त प्रसंगित आदेश का अंतिम वाक्य अधिष्ठीत माना जाना चाहिये।

१ वित्त विभाग का आदेश सख्या एफ १ (सी) (७) एफ डी (ए) नियम/६० दिनांक १८ १० १९६२

२ वित्त विभाग का शापन सख्या एफ १ (सी) (७) एफ डी नियम/६० दिनांक ७-२ १९६२

३ वित्त विभाग का शापन सख्या १ (सी) (७) एफ डी (ए) नियम/६० दिनांक २० ३ १९६२

१६ एक प्रश्न यह उठाया गया है कि जो सरकारी कमचारी सशोधित वेतन मान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं एवं जो सेवा की शर्तों के अनुसार नि शुल्क आवास और भोजन की रियायत पाने के हकदार हैं किन्तु जिन्हें नि शुल्क आवास प्रावहित नहीं है तो क्या उन्हें नियम २ के नीचे राजस्थान सरकार के नियम सख्या ४ के अधीन महगाई भत्ता दिया जा सकता है ।

मामले की जाच की गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों को नि शुल्क आवास प्रावहित नहीं किया गया है और जिन्हें सशोधित वेतन मान में वेतन प्राप्त होता है तो उन्हें उपयुक्त अंकित आदेश के अनुसार महगाई भत्ता दिया जा सकता है ।

२१० यह आदेश दिया जाता है कि दिनांक १-२-१९६४ से ५ ६० मासिक की महगाई-भत्ते की तदर्थ वृद्धि उन कमचारियों को स्वीकार की जा सकती है जो श्रम कानूनों के अधीन आते हैं तथा राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों में नियोजित हैं । किन्तु यह वृद्धि 'यूनियन मजदूरी अधिनियम १९४७ के अधीन गठित सशोधन-समिति की रिपोर्ट के आधार पर एतद पश्चात् स्वीकृत महगाई भत्ते की दरों में वृद्धि के साथ समायोजन के अधीन ही दी जा सकती है ।

ये आदेश राज्यसरकार के प्रतिष्ठानों के इन कमचारियों पर लागू नहीं होते हैं । जिनकी मजदूरी केंद्रीय मजदूरी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार विनियमित होती है ।

३११ नियम २ के नीचे राजस्थान सरकार के नियम सख्या ४ को अंशतः सशोधित करते हुए यह आदेश दिया गया है कि राजस्थान सिविल सेवाये (सशोधित वेतन) नियम १९६१ के अधीन 'सशोधित वेतन मान में ३०० मासिक तक वेतन पाने वाले सरकारी कमचारियों को दिनांक १ मार्च १९६४ से महगाई भत्ते की ५ ६ मासिक की तदर्थ वृद्धि दी जा सकती है । उपयुक्त महगाई भत्ते की तदर्थ वृद्धि के फलस्वरूप महगाई भत्ते की सशोधित दरें निम्नानुसार होगी —

वेतन	महगाई भत्ते की सशोधित दरें
१५० रु से कम	१५ रु
१५० रु और इससे अधिक किन्तु ३०० रु से कम	२५ रु
३०० रु और इससे अधिक	ऐसी राशि जिससे वेतन ३२५ रु से नीचे हो रहे ।

आगे यह भी आदेश दिया गया है कि कथित दिनांक १ मार्च १९६४ से ५) मासिक की महगाई भत्ते की तदर्थ वृद्धि उन सरकारी कमचारियों को भी दी जा सकती है जो कि राजस्थान सिविल सेवाये (सशोधित वेतन) नियम १९६१ में परिभाषित

- १ वित्त विभाग का ज्ञापन मख्या एफ१(६१) एफ डी ए (नियम) ६२ दिनांक १३ १ १९६४
- २ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ१(४) एफ डी (ई धार) ६४ दिनांक ४ ३ ६४ द्वारा निविष्ट
- ३ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ१(६) एफ डी (एक्स क्लस) ६४ I दिनांक १० ३ ६४ द्वारा निविष्ट

करते हैं कि राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों, दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की समस्त शाखाओं के आकस्मिक कर्मचारियों एवं अन्य विभागों के कर्मचारियों को महगाई भत्ता निम्न प्रकार दिया जायेगा —

१ सरकार के वे नियमित सिविल कर्मचारी जिनकी सेवा शर्तें राजस्थान सेवा नियमों द्वारा विनियमित की जाती हैं इस विभाग के आदेश स एफ १ (४) एफ डी (व्यय नियम)/६४ I दिनांक ३० मार्च १९६४, आदेश स एफ १ (६) एफ डी (व्यय नियम)/६४ I दिनांक २३ सितम्बर १९६४ और आदेश स एफ १ (१४) एफ डी (व्यय नियम)/६५ दिनांक २७ ३-६५ के अनुसार महगाई भत्ता प्राप्त करेंगे।

२ जो कर्मचारी राजस्थान सेवा नियमों के अधीन तो नहीं हैं किन्तु उसी प्रकार की ड्यूटी अदा करने वाले नियमित सरकारी कर्मचारियों पर लागू बतन-मान में बतन (महगाई भत्ते या संचित निधि के पृथक् अंश सहित) प्राप्त करते हैं तथा जिनमें राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) सहित वागात, मिर्चाई जलकल और आयुर्वेदिक विभाग के दैनिक मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के सेवा नियम १९६४ के नियम १२ की सीमा में आने वाले व्यक्ति सम्मिलित हैं वे महगाई भत्ते की तदर्थ वृद्धि वित्त-विभाग के आदेश स एफ १ (६) एफ डी (व्यय-नियम)/६४-I दिनांक ३० ३-६४ एवं एफ १ (६) एफ डी (व्यय-नियम) ६४-I दिनांक २३ ६-६४ और आदेश स एफ १ (४) एफ डी (व्यय-नियम)/६५ दिनांक २७ ३-६५ के अनुसार प्राप्त करेंगे।

३ दैनिक मजदूरी पाने वाले तथा आकस्मिक रूप से कार्य करने वाले कर्मचारियों को महगाई भत्ता निम्नलिखित आधार पर प्राप्त होगा —

(1) दिनांक १ ३-६५ को एक वर्ष या इससे १० ६० एक मुश्त

अधिक अवधि की लगातार सेवा करने वाले बतमान कर्मचारी।

(2) दिनांक १ ३-६५ को ६ महीने या

इससे अधिक किन्तु एक वर्ष से कम

३० ६ एक मुश्त तथा दिनांक

अवधि की लगातार सेवा वाले बत १ ३-६५ से १५ ६ और।

मान कर्मचारी।

अधिकृतित आदेश स एफ १ (४) एफ डी (ई गार)/६४ दिनांक ४ ३-६४ और स एफ १ (४) एफ डी (ई गार)/६४ दिनांक २३ ६-६४ के अनुसरण में उक्त श्रेणी (1) एवं (2) के व्यक्तियों को पूर्ण ही स्वीकृत महगाई भत्ता इन आदेशों के अनुसार देय राशि में समायोजित किया जायेगा।

२ श्रेणी (२) और (३) के व्यक्तियों की भुगतान योग्य समस्त परिलाभों की न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसरण हेतु संचित मजदूरी माना जायेगा।

३, यह आदेश राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों के उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिनकी मजदूरी के द्रोय मजदूरी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार विनियमित होती है

उदाहरणार्थ—गगानगर, सुगर कम्पनी लिमिटेड (सुगर मिल्स प्रा.) के कर्मचारी लोगो पर ।

१७ वित्त विभाग के आदेश स एफ डी (व्यय-नियम)/६५ दिनांक २७ १ १९६५ को अशत सशोधित करते हुए राज्यपाल सहाय आदेश प्रदान करते हैं कि राजस्थान सिविल सेवा (सशोधित वेतन) नियम १९६१ के अधीन सशोधित वेतन मान में जो सरकार कर्मचारी ५८५ रु प्रति माह से कम वेतन प्राप्त करते हैं उह महगाई भत्ते में दिनांक १४ १९६६ से निम्नोक्ति दरो पर अस्थई वृद्धि दी जायेगी —

वेतन प्रति माह	महगाई भत्ते में अस्थायी वृद्धि की दर
६० रु से कम	५ रु प्रति माह
६० रु या इससे अधिक किन्तु ५७५ रु से कम ।	१० रु प्रति माह
५७५ रु और इससे ऊपर	इतना राशि जिससे कि वेतन ५८५ रु से कम ही रहे ।

२ राज्यपाल सहाय यह भी आदेश प्रदान करते हैं कि कथित दिनांक अर्थात् सा० १४ ६६ से महगाई भत्ते की निम्नलिखित अस्थायी वृद्धि उन सरकारी कर्मचारियों को भी दी जायेगी जो वर्तमान वेतन मान में, जैसा कि राजस्थान सिविल सेवा (सशोधित वेतन) नियम १९६१ में परिभाषित है, वेतन प्राप्त करते हैं और जिनके परिलाभ ५८५ रु प्रति माह से कम है ।

परिलाभ प्रतिमास	महगाई भत्ते की अस्थायी वृद्धि की दर
११५ रु से कम	५ रु प्रति माह
११५ रु और इससे अधिक किन्तु ५७५ रु से कम	१० " " =
५७५ रु और इससे अधिक	इतनी राशि जिससे परिलाभ ५८५ रु से कम ही रहे ।

इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ 'परिलाभ' का अर्थ राजस्थान सेवा नियम के नियम ७ (२४) में परिभाषित वेतन और महगाई भत्ते (महगाई वेतन सहित) में है ।

३ राज्यपाल सहाय आदेश प्रदान करते हैं कि महगाई भत्ते उपयुक्त अ कित अस्थायी वृद्धि जिला मुख्यालयों और तहसीलों के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में जिला मुख्यालयों पर पद स्थापित कर्मचारियों से उस समय हटा ली जायेगी जबकि एव जैसे ही सरकार द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय में उपरोक्ता भण्डार खोल दिये जायेंगे । इसी प्रकार यह वृद्धि जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त अन्य ग्रामीण एव नगर क्षेत्रों में पद स्थापित

१ वित्त विभाग के आदेश स एफ १ (८) एफ डी (व्यय नियम)/६६/१ दिनांक २४ ४ ६६ द्वारा समाविष्ट ।

कर्मचारियों से भी उस समय हटा ली जायेगी जबकि एवं जैसे ही सरकार द्वारा जिला मुख्यालयों पर तहसीलों को छोड़कर अन्य तहसील मुख्यालयों पर उपभोक्ता भण्डार खोल दिये जायेंगे ।

११८ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १(४) एफ डी (व्यय नियम)/६४ दिनांक ११-६-१९६५ का अंशतः सशोधन करते हुए राज्यपाल सहित यह भी आदेश प्रदान करते हैं कि सौवर्जनिक निर्माण विभाग की सभी शाखों एवं अन्य विभागों के आर्कैटिक रूप से कार्य करने वाले कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाले उन कर्मचारियों को, जिनको दिनांक १ अप्रैल १९६६ को छ माह से कम की निरन्तर सेवा हो, दिनांक १४-६-६६ से महंगाई भत्ते की अस्थायी वृद्धि नौचे दी हुई शर्तों और दरो पर ही दी जा सकेगी —

(1) ऐसे कर्मचारियों को, जो नियमित स्वीकृति पद धारण न कर रहे हों और इसीलिये राजस्थान सेवा नियमों के अधीन नहीं हों किन्तु उसी प्रकार का कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर लागू वेतन मान में जो वेतन प्राप्त कर रहे हों (और जिन्हें महंगाई भत्ते का अंश अलग से या सचि त रूप में मिलता हो) तथा जिनमें राजस्थान सावजनिक निर्माण विभाग, (भवन एवं पथ) सहित बागात मिर्चाई, जलकल और आयुर्वेदिक विभाग के दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के सेवा नियम १९६४ के नियम १२ की सीमा में आने वाले व्यक्ति भी सम्मिलित हैं उह महंगाई भत्ते की अस्थायी वृद्धि वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ/ (८) एफ डी [व्यय नियम]/६६ दिनांक २५ अप्रैल १९६६ के अनुसार प्राप्त करने की अनुमति होगी ।

(11) छ माह के अधिक की निरन्तर सेवा करने वाले दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाले और आर्कैटिक कर्मचारों निम्नलिखित दरो पर महंगाई भत्ते की अस्थायी वृद्धि प्राप्त करेंगे —

मासिक [सचित] मजदूरी की राशि	महंगाई भत्ते में अस्थायी वृद्धि की दर
११५ रु से कम	५ रु प्रति मास
११५ रु और इससे अधिक किन्तु ५७५ रु से कम	१० - - -
५७५ रु और इससे अधिक	ऐसी राशि जिसे मिलाकर मासिक सचित मजदूरी ५८५ रु से कम हो रहे ।

२ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसरण के प्रयोजनाय उक्त श्रेणी (i) एवं (ii) के व्यक्तियों को देय ममस्त 'परिलामों' की मजदूरी माना जायेगा ।

वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (८) एफ डी (एक्स नियम) ६१ 11 दिनांक २५ ४ ६६ द्वारा निविष्ट

३. राज्यपाल आगे यह आदेश भी सह्य प्रदान करते हैं कि जिला मुख्यालयों और तहसील के अधीन जिला मुख्यालयों पर ग्रामीण क्षेत्रों में पद स्थापित कमचारियों के सम्बन्ध में महगाई भत्ते की उक्त अस्थायी वृद्धि उस समय हटाली जायेगी जबकि एव जैसे ही सरकार द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर उपरोक्ता मण्डार खोल दिये जायें। जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त ग्रामीण और नगर क्षेत्रों में पदस्थापित कमचारियों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार महगाई भत्ते की यह अस्थायी वृद्धि उस समय हटाली जायेगी जबकि एव जैसे ही जिला मुख्यालयों पर स्थित तहसीलों को छोड़कर अन्य तहसीलों के मुख्यालयों पर सरकार द्वारा उपरोक्त मण्डार खोल दिये जायें।

१९. निम्न हस्ताक्षरकर्ता को इस विभाग के ज्ञापन संख्या एक १ (८) एक डी (व्यय नियम) / III दिनांक २५ ४ ६६ (प्रतिलिपि सलग्न) के प्रसंग की ओर ध्यानाकर्षण करने एवं सशोधित आदेश सं० एक १ (१६) एक डी (व्यय नियम) / ६६ I दिनांक १०-६-६६ और एक १ (१६) / एक डी (व्यय नियम) / ६६-II दिनांक १०-६-६६ की प्रतिलिपि सलग्न करने का निर्देश प्राप्त हुआ है एवं छ माह से कम की सेवा वाले आकस्मिक कमचारियों के अतिरिक्त अन्य दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाले कमचारियों और सरकारी कर्मचारियों को पूर्व आदेश संख्या एक १ (८) एक डी (व्यय नियम) / ६६-I दिनांक २५ ४ ६६ एवं एक १ (१८) एक डी (व्यय नियम) / ६६ I दिनांक २५ ४ ६६ के अधिकरण में महगाई भत्ता स्वीकार करते हुए आपका यह निवेदन करने का भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि आप अपने स्तर पर इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करें।

२०. वित्त विभाग के आदेश संख्या एक १ (८) एक डी (व्यय नियम) / ६५ I दिनांक २५ ४ १९६६ का अधिकरण करते हुए राज्यपाल सह्य आदेश प्रदान करते हैं कि दिनांक १ ४ ६६ से राजस्थान सिविल सेवा में (सशोधित वेतन) नियम, १९६१ के अधीन सशोधित वेतन-मानों में वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर महगाई भत्ते की लागू होने वाली दरें निम्न प्रकार सशोधित की जायेगी -

वेतन प्रतिमास	महगाई भत्ते की प्रतिमास दर
७० रु से कम	३३ रु
७० रु और इससे अधिक किन्तु ११० रु से कम	३६ रु
११२ रु एवं इससे अधिक किन्तु १५० रु से कम	४३ रु
१५० रु एवं इससे अधिक किन्तु २१० रु से कम	६० रु
२१० रु और इससे अधिक किन्तु ३५० रु तक	६५ रु

१ वित्त विभाग के आदेश सं० एक १ (१६) एक डी (व्यय नियम) / ६६-II दिनांक २५ ६ ६६ द्वारा निविष्ट।

२ वित्त विभाग के आदेश सं० एक १ (१६) एक डी (व्यय-नियम) / ६६-I दिनांक १० ६ ६६ द्वारा निविष्ट।

३८० „ से अधिक किन्तु ४०० रु से कम	ऐसी राशि जिससे वेतन ४४५ रु से कम हो रहे।
४०० रु और इससे अधिक किन्तु २२०५ „ तक	४५ रु
२२०५ „ से अधिक	ऐसी राशि जिससे वेतन २२५० रु से कम हो रहे।

१२ राज्यपाल आगे यह आदेश भी सह्य प्रदान करते हैं कि कथित तिथि यानी दिनांक १ अप्रैल १९६६ से निम्न दरा पर महगाई भत्ते में वृद्धि उन सरकारी कम कारियों को भी स्वीकृत की जा सकती है जो राजस्थान सिविल सेवा (सशोधित वेतन) नियम १९६६ में परिभाषित वत मान वेतन मानों में वेतन प्राप्त करते हैं —

परिलाभ प्रतिमास

महगाई भत्ते में वृद्धि प्रतिमास (इसमें वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ१(१६) एफ डी (व्यय नियम) ६६ I दिनांक २५.४.६६ द्वारा स्वीकृत महगाई भत्ता भी शामिल है)

६५ रु से कम	८ रु
६५ „ और इससे अधिक किन्तु १३५) से कम	११ „
१३५ „ और इससे अधिक किन्तु १७५ „ से कम	१८ „
१७५ „ „ „ २४५ „ „	२५ „
२४५ „ „ „ ४१५ „ „	३० „
४१५ „ „ „ ४३५ „	इतनी राशि जिससे परि लाभ ४४५ रु से कम हो रहे
४३५ „ „ „ ५७५ „ „	१० रु
५७५ „ „ „ २२०५ „ „	४५ „
२२०५ „ से अधिक	इतनी राशि जिससे वेतन २२५० रु से कम हो रहे।

३ इस आदेश के अनुच्छेद २ के प्रयोजनाथ परिलाभो का अथ राजस्थान सेवा नियम के नियम ७(२४) में परिभाषित वेतन और महगाई भत्ते (इसमें महगाई वेतन भी शामिल है) को मिलाकर है।

४ ये आदेश दिनांक ३०.६.६६ तक ही प्रभाव शील रहेंगे।

१ वित्त विभाग के आदेश सं एफ १ (१५) एफ डी (व्यय-नियम) /६६ I दिनांक १८.६.६६ द्वारा प्रतिस्थापित।

१२१ वित्त विभाग के आदेश स० एफ १ (८) एफ डी (व्यय नियम)-६६ II दिनांक २५-४-६६ के अधिक्रमण में राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं कि दिनांक १४-६६ को आकस्मिक कर्मचारियों को छोड़कर दैनिक मजदूरी पर काय करने वाले जिन कर्मचारियों की सेवायें ६ माह से कम हैं उन्हें महगाई भत्ते में वृद्धि दिनांक १४-६६ से सावजनिक निर्माण विभाग तथा ग्राम्य विभागों की समस्त शाखाओं में निम्नलिखित शर्तों और दरों में दी जायेगी —

(i) जो कर्मचारी नियमित स्वीकृत पद धारण नहीं कर रहे हैं और इसीलिये राजस्थान सेवा नियम के अधीन नहीं हैं किन्तु उसी-जैसा काय करने वाले नियमित सरकारी कर्मचारी पर लागू वेतन मानी में वेतन-महगाई-भत्ते के अलग अथवा सचिव सहित प्राप्त कर रहे हैं और जिनमें सावजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) सहित बागात, सिचाई, जलकल और आयुर्वेदिक विभाग के दैनिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों के सेवा नियम १९६४ के नियम १२ की सीमा में आने वाले कर्मचारी शामिल हैं, उन्हें महगाई भत्ता वित्त विभाग के आदेश स एफ १ (१६) एफ डी (व्यय नियम)/६६ I दिनांक १०-६-६६ के अनुसार दिया जायेगा ।

१(ii) दैनिक मजदूरी पर काय करने वाले और आकस्मिक कर्मचारियों को जिनकी निरन्तर सेवा में ६ माह से अधिक की है, महगाई भत्ते की वृद्धि निम्न दरों पर दी जावेगी —

मासिक मजदूरी (सचिव) की राशि	आदेश स एफ १ (१६) एफ डी (व्यय नियम)/६६ II दिनांक २५-४-६६ में स्वीकृत महगाई भत्ते सहित महगाई भत्ते में वृद्धि की दर ।
₹५६० के कम	८६०
₹५६०, और इससे अधिक किन्तु	११ " "
₹६४०, से कम	
₹६४०, और इससे अधिक किन्तु	
₹७२०, से कम	१८० " "
₹७२०, और इससे अधिक किन्तु	
₹८००, से कम	२२० " "
₹८००, और इससे अधिक किन्तु	
₹८८०, से कम	३०० " "
₹८८०, से ऊपर किन्तु	
₹९६०, से कम ।	इतनी राशि जिससे परिलाभ ₹४४५ रु से कम रहे ।
₹९६०, और इससे अधिक किन्तु	
₹१०४०, से कम	१०० रु
₹१०४०, और इससे अधिक किन्तु	
₹११२०, से कम	४५० रु

१ वित्त विभाग के आदेश स एफ १ (१६) एफ डी (व्यय नियम)/६६-II दिनांक १०-६-६६ द्वारा निविष्ट ।

२ वित्त विभाग के आदेश स एफ १ (१६) एफ डी (व्यय नियम)/६६ I दिनांक १०-६-६६ प्रतिस्थापित ।

मासिक (सचिव) मजदूरी की राशि जिसमें वित्त विभाग के आदेश दिनांक १०-६-६६ एवं १८-६-६६ के अधीन स्वीकृत महगाई भत्ता भी सम्मिलित है।

महगाई भत्ते की प्रतिरिक्त राशि

१०३ रु० से कम	२० रु०
१०३ रु० और इससे अधिक किंतु १४६ रु० से कम	५ रु०
१४६ रु० और इससे अधिक किंतु १६३ रु० से कम	७ रु०
१६३ रु० और इससे अधिक किंतु २७० रु० से कम	६ रु०
२७० रु० और इससे अधिक किंतु ५८५ रु० से कम	११ रु०

२. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसरण के प्रयोजनाय उक्त श्रेणी (i) एवं (ii) के व्यक्तियों को देय समस्त परिलाभों की सचिव मजदूरी माना जायेगा।

२४. राज्यपाल सहय आदेश प्रदान करते हैं कि राजस्थान सिविल सेवा (सशोधित वेतन) नियम १९६१ के अधीन (अद्यावधिक परिशोधित) सशोधित वेतनमाना में वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी कमचारियों को दिनांक १ जनवरी, १९६७ से महगाई भत्ते में तदव्य वृद्धि निम्न प्रकार दी जा सकेगी —

वेतन परिसर (प्रति मास)	दिनांक १-१०-६६ से देय महगाई भत्ते की दर	दिनांक १-१०-६६ से देय महगाई भत्ते के प्रतिरिक्त दिनांक १-१-६७ से तदव्य वृद्धि।
१	२	३
७० रु० से कम	३५ रु० तदव्य	१२ रु०
७० रु० से ऊपर किंतु ११० रु० से नीचे तक	४१ रु०	६ रु०
११० रु० से १५० रु० से नीचे तक	५० रु०	२० रु०
१५० रु० से २१० रु० से नीचे तक	६६ रु०	२१ रु०
२१० रु० से ३८० रु० से नीचे तक	७६ रु०	३४ रु०
३८० रु० से ४०० रु० से नीचे तक	इतनी राशि जिससे समस्त परिलाभ ४५६ रु० से कम रह	ऐसी राशि जिससे समस्त महगाई भत्ता १०० रु० हो सके।

१	२	३
४०० रु से १००० रु से नीचे तक	५६ रु	६४ रु
१००० रु और इससे अधिक किंतु २२५० रु तक	५६ रु या इतनी राशि जिससे वेतन २२५० रु से नीचे ही रहे ।	इतनी राशि जिससे समस्त महगाई भत्ता १०० रु हो सके ।
(म) २२५० रु तक		इतनी राशि जिससे वेतन २२५० रु से कम रहे ।
(ब) २२५० रु से ऊपर		

२ *राज्यपाल यह आदेश भी सहर्ष प्रदान करते हैं कि कथित तिथि यानी दिनांक ११ १९६७ से निम्नलिखित दरो पर महगाई भत्ते की अतिरिक्त वृद्धि उन सरकारी कर्मचारियों को भी दी जा सकेगी जो राजस्थान सिविल सेवा (सशोधित वेतन) नियम, १९६१ में परिभाषित वर्तमान वेतनमानों में वेतन प्राप्त कर रहे हैं और जिनके परिलाभ २३५० रु प्रतिमास से कम हैं ।

परिलाभ प्रतिमास	दिनांक ११-१९६७ से अतिरिक्त महगाई भत्ता
१०५ रु से कम	१२ रु
१०५ रु और इससे अधिक किंतु ११५ रु से कम	६ रु
११५ रु और इससे अधिक किंतु २०० रु से कम	२० रु
२०० रु और इससे अधिक किंतु २७६ रु से कम	२१ रु
२७६ रु और इससे अधिक किंतु ४५६ रु से कम	३४ रु
४५६ रु और इससे अधिक किंतु ११०६ रु से कम	६४ रु
११०६ रु और इससे अधिक किंतु २२५० रु से कम	४४ रु
२२५० रु और इससे अधिक	इतनी राशि जिससे कुल महगाई भत्ता १०० रु हो सके ।
२२५० रु से ऊपर	इतनी राशि जिससे परिलाभ २३५० रु से नीचे ही रहे ।

३ इस आदेश के अनुच्छेद २ के प्रयोजनार्थ परिलाभों का तात्पर्य राजस्थान सेवा नियमों के नियम ७(२४) में परिभाषित वेतन और महगाई भत्ते (जिसमें महगाई वेतन भी शामिल है) सहित मिलाकर है ।

२ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (१४) एक डी (व्यय नियम)/६७-II दिनांक ४-३-६७ द्वारा प्रतिस्थापित ।

२५ राज्यापाल सहय यह भी आदेश प्रदान करते हैं कि सावजनिक निर्माण विभाग की सभी शाखाओं और अन्य विभागों में दिनांक १-१-१९६७ का छह माह के कम की सेवा वाले आकस्मिक कमचारियों को छोड़कर अन्य दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाले कमचारियों को चाहे वे कहीं भी नियोजित हो दिनांक १-१-१९६७ महगाई भत्ते को अतिरिक्त वृद्धि निम्नलिखित शर्तों और मानों में दी जायेगी —

(i) ऐसे कमचारी जो नियमित स्वीकृत पद धारण नहीं किये हुए हैं और इसलिए जो राजस्थान सेवा नियमों के अधीन तो नहीं हैं किंतु उसी जसा कार्य करने वाले सरकारी कमचारियों पर लागू वेतनमानों में वेतन (महगाई भत्ते के अलग में सहित या संचित महित) प्राप्त कर रहे हैं और जिनमें राजस्थान सावजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) सहित बागात सिंचाई जलकल और आयुर्वेदिक विभाग १ दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के सेवा नियम १९६४ के नियम १ की सीमा में आने वाले कमचारी भी सम्मिलित हैं उन्हें वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (४) एफ डी (व्यय नियम)/६७-I दिनांक ३-२-१९६७ के अनुसार महगाई भत्ता दिया जा सकेगा ।

(ii) दिनांक १-१-१९६७ को दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाले तथा आकस्मिक रूप से कार्य करने वाले जिन कमचारियों की निरन्तर सेवायें छ माह से अधिक की हैं, उन्हें महगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर दिया जा सकेगा —

समय समय पर स्वीकृत महगाई भत्ते सहित मासिक अतिरिक्त महगाई भत्ता मजदूरी (संचित) की राशि

१०८ रु से कम	१२ रु
१०५ रु और इससे अधिक किंतु १५१ रु से कम	६ रु
१५१ रु और इससे अधिक किंतु २०० रु से कम	२० रु
२०० रु और इससे अधिक किंतु २७६ रु से कम	२१ रु
२७६ रु और इससे अधिक किंतु ४५६ रु से कम	१४ रु
४५६ रु और इससे अधिक किंतु ५६६ रु से कम	६४ रु

२ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसरण के प्रयोजनाय उक्त श्रेणी (i) एवं (ii) के व्यक्तियों को देय समस्त परिलाभों की संचित मजदूरी माना जायेगा ।

२६ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (५१) एफ डी ए/प्रार/६१, दिनांक १८-१२-६१ (जो राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतन) नियम १९६१ के पष्ठ

१ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (४) एफ डी (व्यय नियम)/६७-II, दिनांक ४-१-६७ द्वारा सन्निविष्ट ।

२ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (१६) एफ डी (व्यय नियम)/६६, दिनांक १०-१-६८ द्वारा प्रतिस्थापित ।

१ वित्त विभाग आदेश संख्या एफ १ (१५) एफ डी (ई प्रार)/६७, दिनांक २६-४-६७ द्वारा सन्निविष्ट ।

४० १४१ पर प्रकाशित हुआ है) के अनुच्छेद ४(१) का परिवर्तन करते हुए राज्यपाल हए आदेश प्रदान करते हैं कि सरकारी विधित्सालयों का 'नर्सिंग स्टाफ, जिह कि न शुल्क भाजन गया इसकी जगह मौसिंग भत्ता) और नि शुल्क आवास उनकी नियुक्ति शत के रूप में मिलता है और जो अब तक बिना महगाई भत्ते के सशोधित वेतन मानों में (जो समय समय पर सशोधित होते रहे हैं) वेतन प्राप्त करते रहे हैं उह दनाक १ ४-६६ से आगे महगाई भत्ता नीचे दी हुई दरों पर दिया जा सकता है —

वेतन प्रतिमाह	महगाई भत्ते की मासिक दर	कालम २ के अधीन स्वीकृत महगाई	कालम २ एवं ३ में स्वीकृत महगाई भत्ते में बढ़िया
	दि १४ ६६ से	दि १-१० ६६ से	दि १-१ ६७ से
	दि ३१-१२ ६६ तक	आगे समय में	
१	२	३	४
७० रु से कम	८ रु	२ रु	१२ रु
७० रु और इससे ज्यादा किंतु			
११० रु से कम	११ रु	५ रु	६ रु
११० रु और इससे अधिक किंतु	—	—	—
१५० रु से कम	१८ रु	७ रु	२० रु
१५० रु और इससे अधिक किंतु			
२१० रु से कम	२५ रु	८ रु	२१ रु
२१० रु और इससे अधिक किंतु			
३८० रु से कम	३० रु	११ रु	३४ रु
३८० रु से अधिक किंतु	ऐसी राशि जिससे	११ रु	ऐसी राशि
४०० रु से कम	वेतन ४१० रु से		जिससे कुल महगाई भत्ता ७५ रु हो सके।
— — — — — कम है			
४०० रु और इसमें अधिक किंतु			
४४० रु तक	१० रु	११ रु	६४ रु

१७२ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (४) एफ डी (व्यय नियम) १६७ I दिनांक ४ ३ १८६७ द्वारा सशोधित वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (४) एफ डी (व्यय-नियम) १६७ I, दिनांक ३ २ १८६७ में अशत परिवर्तन करते हुए राज्यपाल सहए आदेश प्रदान करते हैं राजस्थान सिविल सेवा (सशोधित वेतन) नियम १८६१ के अधी

२ वित्त विभाग आदेश सख्या एफ १ (६४) एफ डी (व्यय-नियम)/६७, दिना २६ १० ६७ द्वारा संनिविष्ट।

सशोधित वेतन मानो (जैसा कि समय समय पर सशोधित किये गये हैं) में वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों को देय महगाई भत्ते की दरें निम्न प्रकार होगी —

वेतन प्रतिमाह	दिनांक १२ १९६७ से प्रतिमाह महगाई भत्ता	दि० १०१० ६७ से प्रतिमास महगाई भत्ता
११० रु से कम	५३ रु	५६ रु
११० रु और इससे अधिक		
किंतु १५० रु से कम	७७ रु	८४ रु
२१० रु और इससे अधिक किंतु १५० रु , , १८८ रु		१०६ रु
२०१ रु , , ४०० रु से कम ११६ रु और इससे अधिक किंतु ४०० रु और इससे अधिक किंतु ४४६ रु तक १३० रु		१४० रु
४५० रु से ४५८ रु तक	इतनी राशि जिससे वेतन ५७६ रु से कम ही रहे	
४५० रु से ४६८ रु तक		ऐसी राशि जिससे वेतन ५८६ रु से कम ही रहे ।

इससे उच्चतर वेतन परिसरो में वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों को देय महगाई भत्ते की वर्तमान दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

२ (१) राज्यपाल यह भी आगे सहप आदेश प्रदान करते हैं कि राजस्थान सिविल सेवा (सशोधित वेतन) नियम १९६१ में परिभाषित वर्तमान वेतन मानों में वेतन प्राप्त करने वाले जिन सरकारी कर्मचारियों के समस्त परिलाभ दि० १२ १९६७ को ५७८ रु और दिनांक ११० ६७ को ५८८ रु से ज्यादा नहीं हैं उन्हें उपर्युक्त दरों पर लागू महगाई भत्ते में निम्नलिखित वृद्धि और दो जा सकती है —

(अ) परिलाभ प्रतिमास	दिनांक १२ ६७ से महगाई भत्ते में वृद्धि
१५७ से नीचे	६ रु
१५७ रु और इससे अधिक किंतु २२० से कम	७ रु
२२० रु , , ३०० से	८ रु
३०० रु , , ५१० से ,	९ रु
५१० रु , , किंतु ५२६ एक	१० रु
५७० रु से ५७८ तक	इतनी राशि जिससे परिलाभ ५७६ रु से कम ही रहे ।

(ब) परिलाभ प्रतिमास	दिनांक १ १० ६७ से महगाई भत्ते में वृद्धि
१६३ रु से कम	६ रु
१६३ रु और इससे अधिक किन्तु २२७ रु से कम	७ रु
२२७ , , , ३०७६	८ रु
३०८ , , , ५१६	९ रु
५१६ , , , ५७६	१० रु
५८० रु से ५८८ रु तक	इतनी राशि जिससे परिलाभ - ५८६ रु में कम ही रहे

(11) इस अनुच्छेद के प्रयोजनाथ परिलाभ का तात्पर्य राजस्थान सेवा नियमों के नियम ७ (२४) में परिभाषित वेतन और महगाई भत्ते (जिसमें महगाई वेतन भी शामिल हैं) को मिलाकर ही माना जायेगा।

१ राज्यपाल यह भी सहप्रादेश प्रदान करते हैं कि महगाई भत्ते में वृद्धि के कारण जो रकम राज्य कमचारियों को १-२-१९६७ से ३० सितम्बर १९६७ तक की अवधि के लिये देय होगी उसकी वक़ाया राशि उक्त नक़द न दी जाकर प्रत्येक कमचारी के भविष्य निधि लेख में जमा करादी जायेगी जो कि सामान्य भविष्य निधि (राजस्थान सेवाओं) नियम दिनांक १ अक्टूबर १९६७ के लागू होने वाले नियमों के अधीन होगी।

जो सरकारी कमचारी सामान्य भविष्य निधि के सदस्य नहीं हैं, उनको उक्त वक़ाया राशि उक्त निधि के लेख में तब जमा कराई जायेगी जब और जैसे ही ऐसी निधि का खाता खोला जायेगा। इस प्रकार जमा राशि पर दिनांक १ १० ६७ से सामान्य भविष्य निधि पर लागू दरा पर ब्याज भी दिया जायेगा।

इस प्रकार जमा कराई गई राशि में से आधी राशि सरकारी कमचारी द्वारा दिनांक १ १० ६६ को या इसके बाद वापस ली जा सकती है और शेष आधी राशि दिनांक १ १० ७१ को या इसके बाद उनकी इच्छानुसार। परन्तु यदि सरकारी कमचारी नौकरी छोड़ देता है या नौकरी में रहते समय मर जाता है तो उक्त सारी राशि उसे पूरी तरह नौकरी छोड़ने समय या मृत्यु के समय जैसी भी स्थिति हो वापस दी जा सकती है।

४ उक्त अनुच्छेद १ व २ के प्रावधान उन सरकारी कमचारियों पर भी लागू होते हैं जो इन प्रादेशों के जारी होने से पूर्व सेवा निवृत्त हो जाते हैं नौकरी छोड़ देते हैं या जो मर जाते हैं। महगाई भत्ते में वृद्धि के कारण उक्त इन प्रादेशों के अधीन हो जाने वाली राशि एक साथ ही दी जाती है।

२८ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (६४) एफ डी (व्यय-नियम)/६७ दिनांक १६ १०-६७ का अधिष्ठापन करते हुए एव वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १

वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (६६) एफ डी (व्यय नियम)/६७ दिनांक २६ १० ६७ द्वारा मन्त्रिपरिषद्।

(४) (व्यय नियम)/६७ I, दिनांक ४ ३-६७ द्वारा सशोधित वित्त विभाग के आदेश स-या एफ १ (४) एफ डी (व्यय नियम)/६७-I, दिनांक ३ २ ६० में अंशत परिवर्तन करते हुए राज्यपाल सहस्र यह निगम करते हैं कि उन सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में, जो राजस्थान सिविल सेवा (सशोधित वेतन) नियम १९६१ के अधीन सशोधित वेतनमानों में (जो समय समय पर सशोधित होती रही है) वेतन प्राप्त करते हैं महगाई भत्ते की दरें दिनांक १-२-६७ और दिनांक १ ६-१९६७ के निम्न प्रकार सशोधित की जाती है —

वेतन प्रतिमास

दिनांक १-२-६७ से दिनांक १-६-६७ से प्रति
प्रतिमास महगाई भत्ता मास महगाई भत्ता

११० = से नीचे	२३ रु०	५६ रु०
११० रु० और इससे अधिक कि तु १५० रु० से कम	७७ रु०	८४ रु०
१५० रु० और इससे अधिक कि तु २१० रु० से कम	९८ रु०	१०६ रु०
२१० रु० और इससे अधिक कि तु ४०० रु० से कम	११६ रु०	१२८ रु०
४०० रु० और इससे अधिक कि तु ४४६ रु० तक	१३० रु०	१४० रु०
४४६ रु० से ४५८ रु० तक	ऐसी राशि जिससे वेतन ५७६ रु० से कम हो रहे	X
४५८ रु० से ४६८ रु० तक	X	ऐसी राशि जिससे वेतन ५८६ रु० से कम हो रहे

इसमें अधिक उच्चतर वेतन-परिसरों में वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को देय महगाई भत्ते की दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

२ (1) राज्यपाल सहस्र यह भी आदेश प्रदान करते हैं कि राजस्थान सिविल सेवा (सशोधित वेतन) नियम १९६१ में परिभाषित वर्तमान वेतनमानों में वेतन प्राप्त करने वाले जिन सरकारी कर्मचारियों के परिलाभ दिनांक १-२-६७ को ४७८ रु० और दिनांक २-६-६७ को ५८८ रु० से ज्यादा नहीं होते हैं उन्हें उपयुक्त दिनांक को देय महगाई भत्ता के निम्नानुसार दी जा सकती है —

(अ) परिलाभ प्रतिमास

दिनांक १-२-१९६७ से महगाई भत्ते में वृद्धि

१५७ रु० से कम	६ रु०
१५७ रु० और इससे अधिक कि तु २२० रु० से कम	७ रु०
२२० रु० और इससे अधिक कि तु ३०० रु० से कम	८ रु०
३०० रु० और इससे अधिक कि तु ५१० रु० से कम	९ रु०
५१० रु० और इससे अधिक कि तु ५६६ रु० तक	१० रु०
५६६ रु० से ५७८ रु० तक	इतनी राशि जिससे परिलाभ ५७६ रु० से कम हो रहे।

(ब) परिलाभ प्रतिमास दिनांक १-६-१९६७ से महगाई भत्ते में वृद्धि

१६३ रु० से कम	६ रु०
१६३ रु० और इससे अधिक किन्तु २२७ रु० से कम	७ रु०
२२७ रु० और इससे अधिक किन्तु ३०८ रु० से कम	८ रु०
३०८ रु० और इससे अधिक किन्तु ५१६ रु० से कम	९ रु०
५१६ रु० और इससे अधिक किन्तु ५७६ रु० तक	१० रु०
५८० रु० से ५८८ रु० तक	इतनी राशि जिससे परिलाभ ५८० रु० से कम नहीं रहे ।

(11) इस अनुच्छेद के प्रयोजनाय परिलाभों का तात्पर्य राजस्थान सेवा नियमों के नियम ७ (१४) में परिभाषित वेतन और महगाई भत्ते (महगाई वेतन सहित) को मिलाकर ही माना जायेगा ।

३ - राज्यपाल यह भी सहय आदेश प्रदान करते हैं कि महगाई भत्ते में वृद्धि के कारण जो रकम सरकारी कर्मचारियों को दिनांक १-१२-१९६७ से ३०-६-१९६७ की अवधि के लिए देय होगी उसकी बकाया राशि उन्हें नकद न दी जाकर प्रत्येक कर्मचारी के भविष्य निधि लेखों में जमा करा दी जायेगी । यह भविष्य निधि सामान्य भविष्य निधि (राजस्थान सेवाओं) नियम दिनांक १-१०-१९६७ के लागू होने वाले नियमों के अधीन होगी ।

जो सरकारी कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि के सदस्य नहीं हैं उनकी उक्त बकाया राशि उक्त निधि के लेखों में तब जमा कराई जायेगी जब और जैसे ही ऐसी निधि का खाता खोला जायेगा । इस प्रकार जमा राशि पर दिनांक १-१०-६७ से सामान्य भविष्य निधि पर लागू दरों पर ब्याज भी दिया जायेगा ।

इस प्रकार जमा कराई गई रकम में से आधी राशि सरकारी कर्मचारियों द्वारा दिनांक १-१०-६६ का या इसके बाद वापस ली जा सकती है और शेष आधी राशि दिनांक १-१०-७१ को या इसके बाद उनका इच्छानुसार वापस ली जा सकती है परन्तु यदि सरकारी कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है या नौकरी में रहते समय ही मर जाता है तो उक्त सारी राशि उसे पूरा तरह नौकरी छोड़ते समय या मृत्यु के समय जैसी भी स्थिति हो वापस दी जा सकेगी ।

४ उक्त अनुच्छेद १ एवं २ के प्रावधान उन सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जो इन आदेशों के जारी होने से पूर्व सेवा निवृत्त हो चुके हैं नौकरी छोड़ चुके हैं या जो मर चुके हैं । उन्हें इन आदेशों के अधीन महगाई भत्ते में वृद्धि के कारण दी जाने वाली राशि सारी एक साथ दी जा सकेगी ।

२६ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १(४) एफ डी (व्यय नियम)/६७-11 दिनांक ४ १ ६७ को प्रसूत परिवर्तन करत हुए राज्यपाल सहय यह आदेश प्रदान

७ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (६४) एफ डी (व्यय-नियम)/६७, दिनांक ११ १०-६७ द्वारा सन्निविष्ट ।

करते हैं कि सावजनिक निर्माण विभाग की समस्त शाखाओं और अन्य विभागों में आवश्यक रूप से काम करने वाले कर्मचारियों के अतिरिक्त दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले उन कर्मचारियों की जिनकी नियमित निरंतर सेवाएँ १२-१९६७ एवं १-६-६७ को छु महीने से कम का है दिनांक १२-६७ एवं १-६-६७ से अतिरिक्त महंगाई भत्ता निम्नलिखित माना और शर्तों के अनुसार दिया जा सकेगा —

(i) जो कर्मचारी नियमित स्वीकृत पद धारण नहीं कर रहे हैं और इसलिए जो राजस्थान सेवा नियम के अधीन नहीं हैं किन्तु उन्हीं जसा काम करने वाले अन्य नियमित कर्मचारियों पर लागू वेतनमाना में वृद्ध (महंगाई भत्ते के अलग अलग या संचित महित) प्राप्त कर रहे हैं और जिन्हें राजस्थान सावजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) सहित भागा, निष्ठाई, जमकल और प्रायुर्भोजन विभाग के दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले कर्मचारियों के सेवा नियम १९६८ के नियम १२ की सीमा में आने वाले व्यक्ति भी सम्मिलित हैं उन्हें महंगाई भत्ता वित्त विभाग के प्रादग सम्मेलन १ (१४) एक डी (अध्य नियम)/६७ दिनांक २६-१०-६७ के अनुसार ही दिया जा सकेगा।

(ii) दैनिक मजदूरी पर आकस्मिक रूप से छ माह में अधिक की निरंतर सेवा वाले कर्मचारियों की अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिनांक १२-६७ एवं १-६-६७ से निम्न दर पर दिया जा सकेगा —

(अ) समय-समय पर स्थापित महंगाई भत्ता सहित दैनिक मजदूरी की (मरिच) राशि	दिनांक १२-६७ से अतिरिक्त महंगाई भत्ता
--	---------------------------------------

१५७ रु म कम	६ रु
१५७ रु और इसमें अधिक किन्तु २२० रु के कम	७ रु
२२० रु और इसमें अधिक किन्तु ३०० रु के कम	८ रु
३०० रु और इसमें अधिक किन्तु ३१० रु के कम	९ रु
३१० रु और इसमें अधिक किन्तु ३१६ रु के कम	१० रु
३१० रु से ३१६ रु तक	ऐसी राशि जिसमें परिवर्तन ३१६ रु के कम हो रहे।

(ब) समय-समय पर स्थापित महंगाई भत्ता सहित दैनिक मजदूरी की (मरिच) राशि	दिनांक १२-६७ से अतिरिक्त महंगाई भत्ता
--	---------------------------------------

१५७ रु म कम	६ रु
१५७ रु और इसमें अधिक किन्तु २२० रु के कम	७ रु
२२० रु और इसमें अधिक किन्तु ३०० रु के कम	८ रु
३०० रु और इसमें अधिक किन्तु ३१६ रु के कम	९ रु
३१६ रु और इसमें अधिक किन्तु ३१६ रु के कम	१० रु
३१६ रु से ३१६ रु तक	ऐसी राशि जिसमें परिवर्तन ३१६ रु के कम हो रहे।

७ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधिन निधारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसरण के प्रयोजनार्थ उक्त धरेखी (1) एवं (II) के व्यक्तियों को देय समस्त परिलाभा का सचित मजदूरी माना जायेगा ।

३ राज्यपाल यह आदेश भी सह्य प्रदान करते हैं कि महगाई भत्ते में वृद्धि के कारण जो रकम सरकारी कर्मचारियों को दिनांक १-२ १९६७ से ३० ६ ६७ तक की अवधि के लिए देय होगी उसका बकाया राशि उह नकद न दी जाकर दैनिक मजदूरी पर काय करने वाले प्रत्येक कर्मचारी के भविष्य निधि लेखे में जमा करा दी जायगी । यह भविष्य निधि सामान्य भविष्य निधि (राजस्थान सेवायें) नियम दिनांक १ १०-६७ के लागू होने वाले नियमों के अधीन होगी । इनकी उक्त बकाया राशि उक्त निधि के लेखे में तब जमा कराई जायगी जब और जसे हो ऐसी निधि का खाता खोला जायेगा । इस प्रकार जमा राशि पर दिनांक १ १० ६७ से सामान्य भविष्य निधि पर लागू दरो पर ब्याज भी जोड़ा जायेगा ।

इस प्रकार जमा कराई गई रकम में से आधी राशि सरकारी कर्मचारी द्वारा दिनांक १-१० ६६ को या इसके बाद और शेष आधी राशि दिनांक १-१०-७१ को या इसके बाद उनकी इच्छानुसार वापस निकाला जा सकेगा, परन्तु यदि सरकारी कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है या सेवा में रहत ही मर जाता है तो उक्त सारी राशि उसे पूरा तरह नौकरी छोड़ते समय या मृत्यु के समय, जैसी भी स्थिति हो वापस दी जा सकेगी ।

४ उक्त अनुच्छेद १ एवं २ के प्रावधान उन सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू हान हैं जो इन आदेशों के जारी होने से पूर्व सेवा निवृत्त हो चुके हैं नौकरी छोड़ चुके हैं या जो मर चुके हैं । उह इन आदेशों के अधीन महगाई भत्ते में वृद्धि के कारण दी जाने वाली बकाया सारी राशि एक साथ ही दी जायेगी ।

झापन

३० १ एक प्रश्न यह उठाया गया है कि किसी सरकारी कर्मचारी को देय विशेष वेतन की राशि जो उमी मद में नहीं उठाई गई है जिस बजट-मद में उसका वेतन उठाया जाता है तो क्या उसके विशेष वेतन की राशि को वेतन और क्षतिपूर्क भत्तो जसे महगाई भत्ता भवान किराया भत्ता आदि के साथ वेतन में ही माना जाये या नहीं जिससे वेतन में ही विशेष वेतन ी सम्मिलित हो सके ।

इस मामले की जाच की गई और यह स्पष्ट किया गया है कि यदि विशेष वेतन किसी अन्य बजट मद में उठाया जाता है जिसमें कि सरकारी कर्मचारी का वेतन नहीं उठाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके विशेष वेतन और क्षतिपूर्क भत्तो यथा महगाई भत्ता भवान किराया भत्ता आदि में मिला दिया जा सकता है और इन्हीं उसी बजट-मद में से उठाया जा सकता है जिसमें कि उसका मूल वेतन उठाया जाता है ।

१ वित्त विभाग के गणन सख्या एफ १ (३५) एफ दो (न्यय नियम)/६७, दिनांक २२ १. ६७ द्वारा सविष्ट ।

परिलाभ प्रतिमास

दिनांक १११ ६७ स महगाई
भत्ते मे वृद्धि

१६६ रु से कम	६ रु
१६६ रु और इससे अधिक किंतु २३४ रु से कम	७ रु
२३४ रु और इससे अधिक किंतु ३१६ रु से कम	८ रु
३१६ रु और इससे अधिक किंतु ४९८ रु से कम	९ रु
४९८ रु और इससे अधिक किंतु ५६० रु से कम	१० रु
५६० रु और इससे अधिक किंतु ६१६ रु से कम	३३ रु
६१६ रु से अधिक किंतु ६५१ रु तक	

इतनी राशि जिससे परि
लाभ ६५२ रु से कम ही रहे।

३ उक्त अनुच्छेद २ के प्रयोजनाथ परिलाभो का तात्पर्य राजस्थान सेवा नियमो के नियम ७ (२४) में परिभाषित वेतन और महगाई भत्ता (महगाई वेतन सहित) को मिलाकर माना जायेगा।

३३ वित्त विभाग के आदेश सख्या एक १ (६४) एफ डी (व्यय नियम)/६७, दिनांक ३१० ६७ के सिलसिले में राज्यपाल सहय आदेश प्रदान करते हैं कि सावजनिक निर्माण विभाग की समस्त शाखाओं और अन्य विभागों के दिनांक १११ ६७ को छ माह से कम की सेवा वाले आकस्मिक कर्मचारियों के अतिरिक्त दैनिक मजदूरी पर काय करने वाले सभी कर्मचारियों को चाहे वे कहीं भी नियोजित हो अतिरिक्त महगाई भत्ता दिनांक १११ ६७ से निम्नलिखित शर्तों और दरो पर दिया जा सकेगा —

(1) जो कर्मचारी नियमित स्वीकृत पद तो धारण नहीं कर रहे हैं और इसी कारण जो राजस्थान सेवा नियमों के अधीन नहीं आते हैं किंतु उसी प्रकार का काम करने वाले नियमित कर्मचारियों पर लागू वेतनमान में वेतन (महगाई भत्ते के अलग या संचित अथवा सहित) प्राप्त कर रहे हैं और जिनमें राजस्थान सावजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) सहित बागान सिंचाई जल ल और प्रायुर्वेदिक विभाग के दैनिक मजदूरी पर काय करने वाले कर्मचारियों के सेवा नियम १९६४ के नियम १२ की सीमा में आने वाले कर्मचारी भी सम्मिलित हैं उन्हें वित्त विभाग के आदेश सख्या एक १ (६४) एफ डी (व्यय नियम)/६७, दिनांक १११ ६६ के अनुसार महगाई भत्ता दिया जा सकेगा।

(11) छ माह से अधिक की निरंतर सेवा वाले दैनिक मजदूरी पर काय करने वाले आकस्मिक कर्मचारियों को दिनांक १-११-६७ से अतिरिक्त महगाई भत्ता निम्न लिखित दरो पर दिया जा सकेगा —

समय समय पर स्वीकृत महगाई भत्ते सहित मासिक मजदूरी (संचित) की राशि

दिनांक १-११-६७ से अनि रित्त महगाई भत्ता

१७८ रु से कम	६ रु
१७८ रु और इससे अधिक किंतु २३४ रु से कम	७ रु
२३४ रु और इससे अधिक किंतु ३१६ रु से कम	८ रु
३१६ रु और इससे अधिक किंतु ४२८ रु से कम	९ रु
४२८ रु और इससे अधिक किंतु ५६० रु से कम	१० रु
५६० रु और इससे अधिक किंतु ६१६ रु से कम	३३ रु
६१६ रु से अधिक किंतु ६५१ रु से कम	ऐसी राशि जिससे परिलाभ ६२५ रु से कम हो रहे ।

२ उक्त श्रेणी (i) और (ii) में अंकित व्यक्तियों को देय समस्त परिलाभो को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसरण क योजनाय संचित मजदूरी ही माना जायेगा ।

३४ श्रद्धा विभाग के आदेश सन्म्यः एफ १ (१५) एफ डी (व्यय-नियम)/६७, नाक २६४ ६७ और सन्म्यः एफ १ (१५) एफ डी (व्यय नियम)/६७ दिनांक २४-११-७ में स्वीकृत महगाई भत्तो को दरों की बजाय सरकारी चिकित्सालयो के ऐसे नर्सिंग आफ को जिहें नियुक्ति की शत के रूप में नि शु क भोजन (या इसकी बजाय मैसिंग ता और नि शुलक आवास की सुविधा प्राप्त है और जो (समय समय पर सशोधित ए) नये सशोधित वेतन भत्तों में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, राज्यपाल द्वारा सह्य आदेश दान करने के कारण दिनांक १ ११ ६७ में नीचे लिखी दरों पर दिनांक १ ११ ६७ से महगाई भत्ता दिया जा सकेगा —

वेतन प्रतिमास	दिनांक १ ११ ६७ से महगाई भत्ते की प्रतिमान
११० रु से कम	४० रु
११० रु और इससे अधिक किंतु १५० रु से कम	६६ रु
१५० रु और इससे अधिक किंतु २१० रु से कम	७६ रु
२१० रु और इससे अधिक किंतु ४०० रु से कम	१०२ रु
४०० रु और इससे अधिक किंतु ४५० रु से कम	११५ रु
४५० रु और इससे अधिक किंतु ४६६ रु से कम	११८ रु
४६६ रु से ऊपर किंतु ५३२ रु से नीचे	इनकी राशि जिससे वेतन ६१७ से कम हो रह ।
५३२ रु और इससे अधिक किंतु ५४० रु तक	८५ रु

२ श्रद्धा विभाग के आदेश सन्म्यः एफ १ (१५) एफ डी (व्यय-नियम)/६७ दिनांक १३ ३-६८ द्वारा मन्त्रिच्छ ।

१३५ वित्त विभाग आदेश सरया एफ १(६४) एफ० डी० (एक्मप रूल्स ६७) दिनांक २६ अक्टूबर १९६७ के अनुच्छेद ३ में यह उल्लेख है कि फरवरी, ६७ से सितम्बर, ६७ तक की अवधि में महगाई भत्ते में वृद्धि की गई राशि का भुगतान नकद में न किया जाकर कमचारियों के संबंधित सामान्य प्रावधिक निधि लेखा में जमा किया जावे। इसी प्रकार जो कमचारी सामान्य प्रावधिक निधि के सदस्य नहीं हैं उनके लेखा खाले जाकर उपर्युक्त राशि सामान्य प्रावधिक निधि में जमा की जायेगी। इस मामले में पुन विचार किया जाकर राज्यपाल महोदय उपरोक्त आदेश के अनुच्छेद ३ में वर्णित प्रावधानों में आंशिक परिवर्तन करते हुए आदेश प्रदान करते हैं कि महगाई भत्ते की बढ़ी हुई राशि सामान्य प्रावधिक निधि में जमा नहीं की जाकर निम्नलिखित मद में जमा की जावे—

घा—अनिधि बद्ध ऋ १

अर्थ लेखे—

क—राज्य सरकार की बीमा निधि

महगाई भत्ते की बकाया निक्षेप आय

२ उपरोक्त आदेश को श्रियावि त करने हेतु संबंधित आहरण व राशि वितरण अधिकारी (ड्राईंग व डिस्बर्सिंग ऑफिसर) महगाई भत्ते के बिल तयार करके संबंधित कोषागारों के इसी वित्तीय वर्ष में भेजेंगे। यह रकम वास्तव में प्राप्त न की जाकर उपरोक्त अनुच्छेद १ में वर्णित पद में जमा (By book adjustment) की जायेगी।

३ (अ) संबंधित आहरण व राशि वितरण अधिकारी महगाई भत्ते के बिल को कोषागारों में भेजने के पूर्व सलग्न काम की पूर्ति करेंगे व इसकी दो प्रतिया तैयार करेंगे। एक प्रति बिल के साथ कोषागारों को भेजेंगे व दूसरी प्रति कार्यालय में रखेंगे।

(ब) उपरोक्त (अ) के आधार पर संबंधित आहरण एवं राशि वितरण अधिकारी सलग्न काम सग्या २ की पंजिका तयार करेंगे और उसमें प्रत्येक कमचारी का लेखा रखा जावेगा।

४ राजपत्रित अधिकारी जो स्वयं अपने वेतन इत्यादि के बिल तैयार कर रकम प्राप्त करते हैं उनके बारे में महालेखाकार संबंधित अधिकारियों को पे स्लिप जारी करेंगे व इसके आधार पर संबंधित अधिकारी अपना बिल तैयार करेंगे और सलग्न काम न० १ की पूर्ति करेंगे व इसकी ३ प्रतिया तयार करेंगे। कोषाधिकारी इन प्रतियों में से एक संबंधित अधिकारी को ट्रेजरी वाउचर अकीत कर वापस करेंगे व दूसरी महालेखाकार को भेज देगे। तीसरी प्रति कोषागार में रहेगी। राजपत्रित अधिकारी की नकद राशि न दी जा कर इसका जमा खच कोषाधिकारी उपरोक्त बजट मद में

स्वयं करेगा व फार्म २ की पत्रिका में लेखा रखेंगे महगाई भत्ते की राशि का जमा खच चालू वित्तीय वर्ष में किया जावेगा।

५ उपराक्त महगाई भत्ते की राशि को चुकारा किये जाने के बारे में भ्रम से आदेश प्रसारित किये जावेंगे।

१३६ इस विभाग के समसंग्यक आदेश दिनांक १३ ३-६८ के अंतिम अनुच्छेद में निम्न दिया गया था कि महगाई भत्त की बकाया राशि का समायोजन चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावे। परंतु इस विभाग के ऐसे मामले ध्यान में लाए गए हैं जिसके अनुसार कई विभागों ने उक्त राशि के बिल को समायोजन हेतु प्रस्तुत किया है।

इस संबंध में निम्न लिया गया है कि ऐसे बिलों का जमा खच चालू वर्ष के बजट प्राविजन में से किया जाव। इस खच की राशि के लिये सम्बन्धित विभाग अति रिक्त फंड की राशि निश्चित करवाने हेतु नियमित विधि से वित्त विभाग (बजट) से सम्पर्क स्थापित करें।

१३७ वित्त विभाग के आदेश सं० एफ० १(६४) वित्त (नियम) ६७, दिनांक १३ ३-६८ द्वारा यह आदेश प्रसारित किये गये हैं कि फरवरी ६७ से सितम्बर ६७ तक की अवधि में महगाई भत्ते में वृद्धि की गई घनराशि तगद में भुगतान न की जाकर 'धा—अनिधि वृद्ध ऋण अथ लेखे राज्य सरकार की बीमा निधि महगाई भत्ते की बकाया निम्न अर्थ' के मद में जमा (by book adjustment) की जायगी।

२ कोषाधिकारी उपरोक्त मद के शिड्यूल की एक प्रति अविव तैयार करेंगे जो निर्देशक राज्य बीमा विभाग को भेजी जायगी।

३ गिला के साथ सलग्न फार्म १ (जिसमें कि कमचारी बाइज महगाई भत्ते की घनराशि का विवरण अंकित होगा) भ्रम किये जाकर धा अनिधि वृद्ध ऋण अर्थ लेखे राज्य सरकार की बीमा निधि—महगाई भत्ते की बकाया अर्थ' के शिड्यूल के साथ सलग्न किये जाकर महालेखाकार, राजस्थान जयपुर को प्रेषित किये जायेंगे।

४ निर्देशक, राज्य बीमा विभाग के कार्यालय में कोषाधिकारीयों से प्राप्त शूनों की सहायता से, इस मद का मिलान (reconciliation) किया जायगा तथा मिलान करते समय यदि कोई त्रुटि का निवारण नियमानुसार कोषाधिकारी के द्वारा महालेखाकार, राजस्थान जयपुर को लिखकर करेंगे।

फार्म १

माह फरवरी ६७ में सितम्बर ६७ तक के बकाया महगाई भत्ते की राशि के जमा/चुकारे का विवरण वित्त विभाग आदेश सख्या एफ १ (६८) एफ० डी० (एकमपे सन्म)/६७ दिनांक २६ अक्टूबर १९६७

१ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (६४) वित्त (नियम)/६८ दिनांक २४ २-६८

प्राप्त गया।

मात्रा सख्या एफ १ (६८) वित्त (नियम)/६७, दिनांक ३० २-६८

किसी खास अवधि के लिए वस्तुतः प्राप्त वेतन पर अतः किसी महीने की टूटो अवधि के लिए या महीने की उस अवधि के लिए जिसमें कि वेतन की भिन्न भिन्न दरें प्राप्त हुई हो दोनों के लिए महगाई भत्ते की राशि महीने के दौरान स्वीकाय विभिन्न मासिक दर के वेतन पर ड्यूटी पर बिताये दिना को सरया के लिए गणना की राशि के बराबर होगी ।

(७११) पुनः नियोजित पेशनस को महगाई भत्ता — जो सेवा निवृत्त मरकागी कमचारी फिर से काम पर लगाए गए हैं लगाए जाने वाले ह और जि ह अपनी पेशन के अतिरिक्त वेतन प्राप्त करने की स्वीकृती है तो उह महगाई भत्ता प्राप्त करने का स्वीकृति तभी होगी जब उनका वेतन और पेशन दोनों मिलाकर निर्धारित आर्थिक सीमा से अधिक न हो ऐसे मामलो मे भत्ते की गणना निम्नानुसार की जाएगी —

- (अ) उन अधिकारियों के मामला मे जिनका वेतन और पेशन मिलाकर पद के स्वीकृत अधिकतम वेतन से ज्यादा होता भत्ता उम अधिकतम वेतन पर फैलाया जाएगा ।
- (ब) अथ मामलो मे भत्ता वेतन और पेशन की मिली हुई राशि पर फैलाया जायेगा ।
- (स) जा अधिकारी अवकाश पर है उनके लिए भत्ता केवल अवकाश वेतन पर ही लगाया जाएगा (पेशन को छोड़कर) । पर इसमे शर्त यह है कि ऊपर के अनुच्छेद (अ) और (ब) की सीमा मे आने वाले मामलो मे महगाई भत्ता उस राशि तक सीमित होगा जो कि संचालित की हुई महगाई भत्ते की राशि मे स सरकार द्वारा अपना पेशनस को समय समय पर स्वीकृति राहत की राशि को कम करने पर ठहरती हो ।

(७१११) वेतन के अतिरिक्त किसी अन्य सरकार से किसी अन्य प्रकार के परिलाभ प्राप्त करने वाले लोगो को महगाई भत्ता — इस सरकार से वेतन के अतिरिक्त किसी अन्य सरकार से वेतन अवकाश वेतन या पेशन जैसे विभिन्न प्रकार के परिलाभ प्राप्त करने वाले सरकारी कमचारियों का महगाई भत्ता प्राप्त करने की पात्रता के लिये समस्त परिलाभो की निर्धारित सीमा से अधिक न होने की अवस्था मे उह इस सरकार से प्राप्त वेतन के आधार पर ही महगाई भत्ता प्राप्त हा सकेगा ।

सरकार यह आदेश भी सट्टप प्रदान करती है कि इस संशोधन के जारी होने से आवश्यक होने पर किसी मरकारी कमचारी को स्वीकाय महगाई भत्ते की दरा में काइ परिवर्तन पूव व्याप्ति सहित नागू न होकर केवल दिनांक १ जनवरी १९५३ से प्रभावशील होगा ।

राजस्थान सरकार का निणय

११ मरकारी अधिकारी और शासकीय अधिकारी

होता है कि सरकारी अधिकारिता और शासकीय

प्रश्न पर कुछ सदेह है। इस सम्बन्ध में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। सरकारी कमचारियों को महगाई भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में दिनांक १-४-१९५० से लागू आदेशों के नीचे टिप्पणी सख्या २ (स) के अनुसार (जो कि इस विषय पर पिछले सभी आदेशों के अधिग्रहण में जारी किये गये थे) अशक्त (पाट टाइम) कमचारियों को महगाई भत्ता स्वीकृत नहीं है। चूंकि सरकारी अधिकर्ता, उप एवं सहायक सरकारी अधिकर्ता, शासकीय अभियोक्ता, सहायक शासकीय अभियोक्ता आदि अशक्त कमचारी हैं अतः उन्हें कोई महगाई भत्ता नहीं दिया जायेगा।

१२ सरकारी मुद्रणालयों के औद्योगिक कमचारियों को महगाई भत्ता — असैनिक विभागों के सरकारी कमचारियों को स्वीकृत महगाई भत्ते की एकीकृत दरें सरकारी मुद्रणालयों के पूरा कालिक औद्योगिक कमचारियों (फुटकर भद्र से वेतन पाने वालों को छोड़कर) पर भी लागू हैं और इसके लिये राजस्थान सिविल सेवा (वेतन भागों का एकीकरण) नियम के अधीन वेतन के एकीकृत वेतन मान घोषित किये गये हैं।

२१ सरकार का ध्यान में यह लाया गया है कि महगाई भत्ते की दिनांक १-४-१९५० से पूर्व प्रभावशील दरों पर ही कुछ सरकारी कमचारियों को वित्त विभाग के आदेश स २ में स्वीकार्य दरों की तुलना में अधिक लाभकारी मानकर महगाई भत्ता दिया जा रहा है।

यह तुरन्त रोक जाना चाहिए और विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि सरकारी कमचारियों द्वारा महगाई भत्ता दिनांक ११-१-१९५१ के आदेश के अनुसरण के अतिरिक्त अन्य किसी और आदेश के अनुसरण में तो प्राप्त नहीं किया जा रहा है। यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि सभी आर्हति-अधिकारी इस प्रकार की ज्यादा कमियों के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायी हैं।

२४ दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाले कमचारी संस्थापनाओं में महगाई भत्ता सावजनिक निर्माण विभाग के दैनिक मजदूरी पद धारण करने वाले कमचारियों को महगाई भत्ता दिये जाने सम्बन्धी प्रश्न सरकार के काफी समय से विचाराधीन था। मामलों की जांच की गई है और यह निर्णय किया गया है कि जिन पदों के लिए वेतनों का वेतनमान एकीकरण नियम की अनुसूचि में समय वेतनमान निर्धारित किया गया है उनके तदनुकूली पदों पर नियुक्तियों के मामलों में इन वेतनमानों में उक्त नियुक्तियों सम्बन्धित स्टेज पर ही माना जाना चाहिए जब यह कर लिया जाय तो सरकार के आदेश सख्या २ के अधीन तदनुकूली सिविल सेवाओं के लिए निर्धारित दरों के अनुसार ही महगाई भत्ता भी दिया जाना चाहिए।

१ वित्त विभाग के आदेश सख्या एक ७ (२)-आर/५३, दिनांक ३-३-५२ द्वारा सन्निविष्ट।

२ वित्त विभाग के आदेश सख्या दो २५६५ एक II/५३, दिनांक २-५-५३ द्वारा सन्निविष्ट।

३ वित्त विभाग के आदेश सख्या एक ११ (१६) एक II/५३, दिनांक ६-२-५४ द्वारा सन्निविष्ट।

अध्या २]

१	२	३	४	५	६
२२११	३८	१००	१००	१००	१००
२२१२	३८	"	"	"	"
२२१३	३७	"	"	"	"
२२१४	३६	"	"	"	"
२२१५	३५	"	"	"	"
२२१६	३४	"	"	"	"
२२१७	३३	"	"	"	"
२२१८	३२	"	"	"	"
२२१९	३१	"	"	"	"
२२२०	३०	"	"	"	"
२२२१	२९	"	"	"	"
२२२२	२८	"	"	"	"
२२२३	२७	"	"	"	"
२२२४	२६	"	"	"	"
२२२५	२५	"	"	"	"
२२२६	२४	"	"	"	"
२२२७	२३	"	"	"	"
२२२८	२२	"	"	"	"
२२२९	२१	"	"	"	"
२२३०	२०	"	"	"	"
२२३१	१९	"	"	"	"
२२३२	१८	"	"	"	"
२२३३	१७	"	"	"	"
२२३४	१६	"	"	"	"
२२३५	१५	"	"	"	"
२२३६	१४	"	"	"	"
२२३७	१३	"	"	"	"
२२३८	१२	"	"	"	"
२२३९	११	"	"	"	"
२२४०	१०	"	"	"	"
२२४१	९	"	"	"	"
२२४२	८	"	"	"	"
२२४३	७	"	"	"	"
२२४४	६	"	"	"	"
२२४५	५	"	"	"	"
२२४६	४	"	"	"	"

१	२	३	४	५	६
२२४७	३	१००	१००	१००	१००
२२४८	२	"	"	"	"
२२४९	१	"	"	"	"
२२५०	—	"	"	"	"
२२५१	—	९९	९९	९९	९९
२२५२	—	९८	९८	९८	९८
२२५३	—	९७	९७	९७	९७
२२५४	—	९६	९६	९६	९६
२२५५	—	९५	९५	९५	९५
२२५६	—	९४	९४	९४	९४
२२५७	—	९३	९३	९३	९३
२२५८	—	९२	९२	९२	९२
२२५९	—	९१	९१	९१	९१
२२६०	—	९०	९०	९०	९०
२२६१	—	८९	८९	८९	८९
२२६२	—	८८	८८	८८	८८
२२६३	—	८७	८७	८७	८७
२२६४	—	८६	८६	८६	८६
२२६५	—	८५	८५	८५	८५
२२६६	—	८४	८४	८४	८४
२२६७	—	८३	८३	८३	८३
२२६८	—	८२	८२	८२	८२
२२६९	—	८१	८१	८१	८१
२२७०	—	८०	८०	८०	८०
२२७१	—	७९	७९	७९	७९
२२७२	—	७८	७८	७८	७८
२२७३	—	७७	७७	७७	७७
२२७४	—	७६	७६	७६	७६
२२७५	—	७५	७५	७५	७५
२२७६	—	७४	७४	७४	७४
२२७७	—	७३	७३	७३	७३
२२७८	—	७२	७२	७२	७२
२२७९	—	७१	७१	७१	७१
२२८०	—	७०	७०	७०	७०
२२८१	—	६९	६९	६९	६९
२२८२	—	६८	६८	६८	६८
२२८३	—	६७	६७	६७	६७
२२८४	—	६६	६६	६६	६६
२२८५	—	६५	६५	६५	६५
२२८६	—	६४	६४	६४	६४
२२८७	—	६३	६३	६३	६३

विज्ञान विभाग के प्रादेश स० एफ १ (६४) विज्ञान वि (व्यय-नियम) ६८ दि १ जनवरी १९६८ की द्वार ध्यान धारण कर कहा जाता है कि शास्त्रस्थान सिविल सेवा (परिशोधित वेतन) नियम, १९६१ (मध्य समय पर यथा संगोषितनुसार के प्रयोग वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों पर लागू महगाई भत्ते की दरें दि १ ९ ६८ से निम्न प्रकार सशोधित की जाएगी ।

११० व स नवि	७१ व०
११० व एव इससे अधिक पर १३० व से कम	६८ व०
१५० व एव हमसे ऊपर लेकिन २१० व से कम	१२२ व०
२१० व एव इससे अधिक पर ४०० व से कम	१४६ व०
४०० व एव इससे अधिक पर ४५० व से कम	१६० व०
४५० व एव इससे अधिक लेकिन ४८६ व तक	१६४ व०
४८६ व से ऊपर लेकिन ५४३ से कम	वह राशि जो ६४३ व

१ यह भी ध्यान धीर दिना गया है कि राजस्थान सिविल सेवा (मनोविकास वेतन) नियम, १९६१ में यथा परिभाषित 'व्युत्पन्न वेतन मूल' से वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी जाँची कि पत्रिकाया नं० १६-६६ को १९६३ के समय है उन्हें दि १९६६ से उक्त तारीख का उस पर लागू नियमों के अनुसार महंगाई भत्ते में निम्न वृद्धि स्वीकृत की जाएगी —

१७५ रु से नीचे	६ रु०
१७५ रु एवं इससे अधिक विन्तु २४१ रु से कम	७ रु०
२४१ रु एवं इससे अधिक विन्तु २४५ से कम	८ रु०
२४५ रु एवं इससे अधिक विन्तु ५३७ से कम	९ रु०
५३७ रु एवं इससे अधिक विन्तु ६०० रु से कम	१० रु०
६०० रु एवं इससे अधिक विन्तु ६५२ रु तक	११ रु०

३. उपर्युक्त पैरा के प्रयाजनाय परिलिखित स तालमय राजस्थान सेवा नियमों व नियम ७(२४) के
मया परिभाषित बेटन एवं महानदी भत्ते (महानदी बेटन सहित) से है।

[वित्त विभाग व आदर्श स० एक १ [५६] वित्त वि [नियम] ६८ दि० ६-१२-६८]

विषय— लोक निर्माण विभाग एवं ग्राम्य विभागों के साथ प्रभुन [वर्क चाण्ड] कर्मचारियों को दैनिक भत्ता ।

वित्त विभाग के आदेश सं० एफ १ [६४] वित्त वि [व्यय-नियम]/ ६७ दि० २२-१-६८ के क्रम में यह आदेश दिया गया है कि लोक निर्माण विभाग की सभी छाखाओं में एवं ग्राम्य विभागों में जब उनकी नियुक्ति की जाए, अतिरिक्त महंगाई भत्ता दि० १-६-६८ से उन आकस्मिक कर्मचारियों को जिनकी दि० १-६-६८ की छह माह से कम की सेवा है, ग्राम्य वायप्रभुन कर्मचारियों को निम्न लिखित दर पर तथा निम्न शर्तों के अधीन दिया जाए —

[१] कर्मचारी जो नियमित स्वीकृत पद की धारण नहीं करता है एवं उसके कारण वह राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत नहीं आता है लेकिन अपना वेतन नियमित सरकारी कर्मचारियों पर लागू वेतन मान में [महंगाई भत्ते के अलग हान के साथ या समेकित (Consolidated) रूप में] प्राप्त करता है तथा राजस्थान लोक निर्माण विभाग भवन एवं सड़क व उद्यान, सिंचाई, वाटर वर्क्स एवं प्रायुर्वेदिक विभाग के साथ प्रभुन कर्मचारी सेवा नियम, १९६४ के नियम १२ द्वारा दायित्व व्यक्तियों के समान कृत्यों को कर रहा है तो उसे वित्त विभाग के आदेश सं० एफ १ [५६] वित्त [नियम] ६८ दि० ६-१२-६८ के अनुसार महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जा सकेगा ।

[२] ६ माह से अधिक समय की गिरांतर सेवा करने वाले दैनिक दरों पर नियुक्त कर्मचारियों को दि० १-६-६८ से निम्नलिखित दरों पर अतिरिक्त महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जा सकेगा —

समय समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ते सहित	दि० १-६-६८ से अतिरिक्त महंगाई भत्ता
मजदूरियों [समाकृत] मासिक राशि	
१७५ रु० से नीचे	६ रु०
१७५ रु० एवं इससे अधिक परन्तु २४१ रु० से नीचे	७ रु०
२४१ रु० एवं इससे अधिक परन्तु ३२४ रु० से नीचे	८ रु०
३२४ रु० एवं इससे अधिक किन्तु ५३७ रु० से नीचे	९ रु०
५३७ रु० एवं इससे अधिक किन्तु ६०० रु० से कम	१० रु०
६०० रु० एवं इससे अधिक किन्तु ६५२ रु० तक	११ रु०
६५२ रु० से अधिक किन्तु ६६३ रु० से कम	वह राशि जो ६६३ रु० की परिलब्धि से कम पड़े ।

२ अथवा [१] एवं अथवा [२] में व्यक्तियों की भुगतान करान योग्य कुल परिलब्धि को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुपालन के प्रयोजनार्थ समेकित मजदूरी के रूप में समझा जायगा ।

[वित्त विभाग के आदेश सं० एफ १ [५६] वित्त वि [नियम] ६८ दि० १८-१२-६८]

विषय— नि शुल्क भोजन एवं आवास की रियायत के लिए अधिकृत सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की स्वीकृति ।

वित्त विभाग के आदेश सं० एफ १ [१५] वित्त वि [व्यय-नियम]/ ६७ दि० १३-३-६८ में स्वीकृत महंगाई भत्ते की दरों के बजाए, यह आदेश दिया गया है कि सरकारी अस्पतालों के मेसिज स्टॉफ के कर्मचारी जो कि नि शुल्क भोजन [या उसके बदले भोजन भत्ता] एवं नि शुल्क

भावास की सुविधा अपनी नियुक्ति की बात के रूप में पाने के लिए अधिकृत है, एवं जो अपना वेतन [समय समय पर यथा संशोधित] संशोधित वेतन मान में पा रहे हैं, उन्हें दि० १-६-६८ से तिन दर पर महगाई भत्ता स्वीकृत किया जाएगा —

वेतन प्रति माह	दि० १-६-६८ से प्रति माह महगाई भत्ते की दरें
११० रु० से नीचे	४६ रु०
११० रु० एवं इससे अधिक पर १५० रु० से कम	७१ रु०
१५० रु० एवं इससे अधिक पर २१० रु० से कम	८७ रु०
२१० रु० एवं इससे अधिक पर ४०० रु० से कम	१११ रु०
४०० रु० एवं इससे अधिक पर ४५० रु० से कम	१२५ रु०
४५० रु० एवं इससे अधिक पर ४६६ रु० तक	१२६ रु०
४६६ रु० से अधिक निम्न	वह राशि जो ६२८ से कम पड़े।
[वित्त विभाग के आदेश सं० एक, ११५] वित्त वि० [नियम, ६७ दि० १-६-६८]	

विषय — महगाई भत्ता— १००० रु० से १०१६ रु० आदि के बीच की वेतन श्रेणियों में वेतन पाने वाले व किए गए का समयोत्तरण ।

वित्त विभाग के आदेश सं० एक १५७] वित्त वि० [नियम, ६७-६८ दिनांक ३-२-६७ के परा १ में प्राधिकार स्थापित करते हुए यह आदेश दिया गया है कि संशोधित वेतन मान में १००० रु० एवं इससे अधिक परन्तु १०१६ रु० से नीचे तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों का वर्ग का समायोजन स्वीकृत किया जा सकेगा ताकि वेतन एवं महगाई भत्ता दोनों मिलकर १११६ रु० से अधिक न हो ।

२ उपरोक्त आदेश के परा २ में स्थापित करते हुए यह आदेश दिया गया है कि [समय समय पर संशोधित अनुसार] राजस्थान सिविल सेवा [संशोधित वेतन] नियम १९६१ में यथा परिभाषित 'वर्तमान वेतन' में वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों को जिनकी परिशिष्टा १००० रु० एवं इससे अधिक या १११६ रु० से कम हैं, महगाई भत्ते में वृद्धि उस दर पर स्वीकृत की जाएगी जो का १११६ रु० से कम पड़ती हो ।

३ ये आदेश १-१२-६७ से प्रभावी होंगे ।

[वित्त विभाग के आदेश सं० एक १५७] वित्त वि० [नियम / ६७ दि० ६-१-६८]

विषय — महगाई भत्ते के दश को वेतन के रूप में गिना जाना ।

राज्यपाल ने निर्देश दिया है कि वर्तमान नियमों एवं आदेशों में स्थापित करते हुए नीचे परे २ में निर्दिष्ट महगाई भत्ते की राशि को उन सरकारी कर्मचारियों के मामले में जो कि राजस्थान सिविल सेवा [संशोधित वेतन] नियम १९६१ के अधीन परिशोधित वेतन मान/संशोधित वेतनमान में या राजस्थान सिविल सेवा [नवीन वर्तमान] नियम, १९६६ के अधीन नवीन वेतन मान में वेतन प्राप्त करते हैं, एतद् पश्चात् विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए एवं सीमा तक 'वेतन' रूप में मानी जाएगी ।

२ 'वृत्त' विभिन्न पदों से संबंधित वेतन मान में तथा उस आधार में जिस पर कि महगाई भत्ता मंगलित किया जाता है यदि परिवर्तन नहीं होगा अतः स्वीकार्य महगाई भत्ते में से निम्न निर्दिष्ट राशि को नीचे विनिर्दिष्ट श्रेणियों में वेतन के लिए महगाई वेतन के रूप में गिना जाएगा ।

११० रु० एवं इससे अधिक लेकिन १५० रु० से कम

७० रु०

१५० रु० एवं इससे अधिक पर २१० रु० से कम

१०० रु०

२१० रु० एवं इससे अधिक पर ४०० रु० से कम

११० रु०

४०० रु० एवं इससे अधिक पर ४६६ रु० तक

१२० रु०

४६६ रु० एवं इससे अधिक

वह राशि जो ६१६ रु० के वेतन से कम हो।

पेंशन एवं उपदान (पेंशियटो)

३ महगाई वेतन पेंशन एवं उपदान के लिए 'परिवर्त' में मिनो होगी। इस प्रयोजनाय राजस्थान सेवा नियम के नियम २५० एवं २५० क के अधिन गिनी गई परिलिखित को उक्त परिलिखित के समकल वेतन के अनुकूल महगाई वेतन को जोड़कर बढ़ाया जाएगा तथा उपरोक्त नियमों के नियम २५१ के अधीन अन्तिम शीर्ष परिलिखित उक्त आधार पर निर्दिष्ट की जाएगी।

जो व्यक्ति पैरा ३ के अधीन लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं, उन्हें पेंशन में वृद्धि भी प्रसार की व्यवस्था कृति नहीं की जाएगी।

जोधपुर झ शब्दाधी भविष्य निधी—निधो में सरकारी कमचारियों द्वारा दिए गए अभिमान का राशि एवं सरकारी बोनस की राशि से गणित करने के प्रयोजनार्थ जिस वेतन पर ये आधारित हैं उनके अनुकूल महगाई वेतन को उस वेतन के अंग के रूप में समझा जाएगा। इस प्रयोजनार्थ, ये आदेश १ मार्च, १९६६ से प्रभावी होंगे। फिर भी अतः यह है कि जहां सरकारी कमचारी १ दिसम्बर १९६६ से अभिमान को बढ़ाया राशि का भुगतान करना चाहता हो तो यह रियायत उस तारीख से प्रभावशाली होगी। निधि नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत विंगेट प्रशिक्षण की राशि समर्पित करने के प्रयोजनाय जिस वेतन पर ये प्रशिक्षण आयोजित हैं उससे अनुकूल महगाई वेतन को उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो १-१२-६६ की या उसके पश्चात् सेवा निवृत्त हो रहे हैं उक्त वेतन के भाग III रूप में समझा जाएगा।

क्षतिपूरक भत्ता [मकान किराया भत्ता सहित] आदि

७ महगाई वेतन को निम्न लिखित प्रयोजनाय के लिए वेतन समझा जाएगा।

[क] वित्त विभाग के आदेश सं० एक १ [६] वित्त वि [व्यय नियम] ४ II दि० २३-६-६४ के अधिन स्वीकृत क्षतिपूरक [नगर] भत्ता।

विवरण—जोधपुर में पद एवं पित सरकारी कमचारियों को क्षतिपूरक (नगर) भत्ता की स्वीकृति।

वित्त विभाग के आदेश सं० एक १ (६) वित्त वि० (व्यय नियम) ६४ II दि० २३-६-६४ के अधिन स्वीकृत राजस्थान महोपन्यय आदेश दिया है कि सरकारी कमचारी जो जोधपुर में पदस्थापित किए गए हैं एवं जो (समय समय पर संशोधित अनुसार) राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वन) नियम १९६१ में या राजस्थान सिविल सेवा (नवीन वेतन मान) नियम १९६६ में वेतन प्राप्त कर रहे हैं उन्हें क्षतिपूरक (नगर) भत्ता निम्न दरों पर स्वीकृत दिया जा सकेगा—

५०० रु० से नीचे

वेतन का ५ प्रतिशत विन्तु 'पूतनतम' रु० एवं अधिकतम १० रु०

५०० रु० एवं इससे अधिक वह राशि जो ५०६ रु० के वेतन से कम पड़े।

ये आदेश १-१-७६ से प्रभावी होंगे।

(वित्त विभाग के आदेश सं० एक १ (२७) वि वि (नियम) ६६ दि० ६-६-६६)

(ख) राजस्थान सेवा नियम भाग २ के परिशिष्ट-१७ में अन्तर्लिखित मकान किराया भत्ता।
नियमों के अधीन स्वीकार्य मकान किराया भत्ता ।'

किराए की बसूली

(महगाई वेतन) को सरकारी आवास सुविधा के लिए अधिकृत करने एवं उसने लिए किराए की बसूली के प्रयोजनाय राजस्थान सिविल सेवा (आवासीय सुविधा के किराए का निश्चयन, एवं बसूली) नियम, १९५८ के नियम ३५ में यथा पारितोषित 'परिलिखित' के भाग के रूप में गिना जाएगा। इस प्रयोजनाय ये आदेश १-३ ६६ से प्रभावशील होंगे।

अवकाश वेतन

अवकाश वेतन वसूली की भांति ही (महगाई वेतन को हटाकर) गिना जाएगा एवं तब महगाई भत्ते की दर साधारण तौर से निकाली जानी चाहिए एवं इस प्रकार जो राशि आए उससे एक भाग को वसूली पर २ के अनुसार महगाई वेतन के रूप में गिना जाना चाहिए।

परन्तु ध्यान यह है कि (भारत में अथवा बाहर) सेवा निवृत्ति पूर्व प्रथम बार माह स अधिक के अवकाश कानून में, यदि अवकाश पूर्ण वेतन पर हो तो अवकाश वेतन के माध्यम से प्रभार से हो तो उक्त राशि के साथ वेतन के अनुकूल महगाई वेतन के समस्त राशि का महगाई भत्ता स्वीकृत किया जा सकेगा।

भारत के बाहर प्रतिनिधित्व एवं भारत के बाहर प्रशिक्षण काल में महगाई भत्ते की स्वीकार्यता—

६ किन्तु भी एक देश में प्रतिनिधित्व पर अपने रहने के प्रथम छह माह में भारत के बाहर प्रतिनिधित्व/प्रशिक्षण पर गया सरकारी कर्मचारी को महगाई भत्ता उसी दर पर जिस पर कि यदि वह प्रतिनिधित्व पर रहना न होने पर प्राप्त करते होते तथा उसके बाद प्रतिनिधित्व काल में वेतन के अनुकूल महगाई वेतन के समस्त दरों पर स्वीकृत किया जाएगा।

यात्रा भत्ता

१० महगाई वेतन की यात्रा भत्ता (मूल भत्ते एवं दैनिक भत्ते सहित) वेतन के रूप में गिना जाएगा। फिर भी रेल की सुविधा प्राप्त करने हेतु इसे 'वेतन' के रूप में नहीं गिना जाएगा। यह १ माह, १९६६ से या उसके बाद प्रारम्भ की जाने वाली यात्राओं के लिए लागू होगा।

घरों की नि:शुल्क शिक्षा एवं ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति—

११ महगाई वेतन की बालबालों की नि:शुल्क शिक्षा एवं ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की स्वीकार्यता के लिए वेतन की सीमा निर्दिष्ट करने में वेतन के रूप में गिना जाएगा। इस प्रयोजनार्थ, ये आदेश १-३ ६६ से प्रभावशील होंगे।

अग्रिम

१२ 'महगाई वेतन' की अग्रिमों जैसे सामान्य वित्तीय एवं सेवा नियमों के अधीन भवन निर्माण अग्रिम, वाहन अग्रिम की स्वीकार्यता की मात्रा एवं सीमा की निर्दिष्ट करने के प्रयोजनाय 'वेतन' के रूप में गिना जाएगा। इस प्रयोजनार्थ ये आदेश १-३ ६६ से प्रभावशील होंगे।

लागू होने की तारीख

जब लिखित रूप से अधिसूचना प्रकार से प्रावहित न किया गया हो, ये आदेश १ १२ ६८ से प्रभावशील होंगे।

परिसीमाएँ

१४ इन नियमों में निर्दिष्ट किए गए के अतिरिक्त महगाई वेतन की किसी अन्य प्रयोजन के लिए वेतन नहीं समझा जाएगा। उदाहरण के लिए तो महगाई वेतन को वेतन की बसूली के

लिए या वतन धृद्धि आहरित करने या प्रतिनियुक्ति भत्ता स्थिर करने के लिए नहीं गिना जाएगा और न ही इसे महगाई भत्ते के आहरित करने के लिए गिना जाएगा। इसे न तो वेतन बिलों में और न सेवा अभिलेख में अलग तत्व के रूप में लिखाया जाएगा।

ये आदेश निम्न पर लागू नहीं होंगे—

- (१) धार ए एस एव आई पी एस सेवा के सदस्या के लिए
- (२) ठेके पर नियुक्त व्यक्ति
- (३) व्यक्ति जिसे वेतन की समेकित दर स्वीकृत की जाती है तथा जो महगाई भत्ता प्राप्त नहीं करते हैं।
- (४) व्यक्ति जो अशासकिक कर्मचारी हैं एवं जिन्हें आकस्मिक निधियों (Contingencies) से भुगतान किया जाता है।

(५) अन्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आए हुए व्यक्ति।

१६ वित्त विभाग के आदेश सं० एक १ (७३) वित्त वि/नियम/६२ दि० २८-३-६३ एवं सं० एक ४(४) वित्त वि (व्यय-नियम) ६३ दिनांक १-८-६३ वापिस लिए जाते हैं।

१७ निम्न के सम्बन्ध में अलग आदेश जारी किए जाएंगे—

(१) सरकारी कर्मचारी जो राजस्थान सिविल सेवा (सशोधित वेतन नियम १९६१ (समय समय पर सशोधित अनुसार) में यथा परिभाषित वर्तमान वेतनमान में वेतन पा रहे हैं।

(२) भूतपूर्व मजदूर राज्य के कर्मचारी जिन्होंने पुराने वेतन मान के लिए विकल्प दिया है एवं जो राजस्थान सेवा (सेवा शर्तों का संरक्षण) नियम, १९५७ के नियम १४ के अर्थात्सुसार महगाई वेतन प्राप्त करते हैं।

(३) सरकारी कर्मचारी जो सेवा की शर्तों के रूप में निशुल्क भवन एवं भोजन की सुविधा प्राप्त करने के पात्र हैं।

वित्त विभाग के आदेश सं० एक १ (७) वित्त वि (नियम) १९६९ दिनांक ७-४-६९)

परिशिष्ट १७

मकान किराया भत्ता स्वीकृति के नियम

(देखिये नियम ४२)

१ राजस्थान सेवा नियमों के नियम ४२ में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयपुर जोधपुर, अजमेर, माउंटभावू कोटा, बीकानेर गगानगरटाउन और उदयपुर में पदस्थापित सरकारी कमचारियों को मकान किराया भत्ता स्वीकार करने के नियम —

२ नियम १ लागू होने की सीमा और धारन —

ये नियम उन सरकारी कमचारियों पर लागू होंगे जो जयपुर जोधपुर, अजमेर, माउंट भावू, कोटा, बीकानेर ३ गगानगर टाउन और उदयपुर में पदस्थापित हो या सेवा कर रहे हों।

४ राजस्थान सरकार का आदेश — [विलुप्त किया गया]

राजस्थान सरकार का आदेश सख्या ५ [विलुप्त]

१ स्पष्टीकरण — नियम १ की सीमा के सम्बन्ध में सन्देह व्यक्त किये गये हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि मकान किराया भत्ता केवल जयपुर जोधपुर, आदि नगरों की नगर पालिका सीमाओं के भीतर ही स्वीकार्य है पूरे जिलों में नहीं।

१२ अब स्वीकार्य नहीं है — निम्न को मकान किराया भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा —

(i) सरकार द्वारा जिस सरकारी कमचारी को वास-स्थान प्रदत्त किया गया हो।

या

- १ वित्त विभाग के आदेश सख्या एक ३५ (२) धारा ५१ दिनांक २३-१-५१ द्वारा मन्त्रिपरिषद् तथा आदेश सख्या एक १ (४५) एक डी (व्यय-नियम) / ६५, दिनांक २५-८-६५ द्वारा प्रतिस्थापित।
- २ वित्त विभाग के आदेश सख्या एक १ (५५) एक डी (व्यय नियम) / ६४, दिनांक ११-१-६४ द्वारा प्रतिस्थापित।
- ३ वित्त विभाग के आदेश सख्या एक १ (४५) एक डी (व्यय नियम) ६५, दिनांक २८-८-६५ द्वारा मन्त्रिपरिषद् एवं दिनांक १-८-६५ से प्रभावशील।
- ४ राजस्थान सरकार का नियम सख्या १ वित्त विभाग के आदेश सख्या एक १ (३) एक डी (व्यय नियम) / ६५ दिनांक १८-२-६५ द्वारा विलुप्त तथा दिनांक १-८-६४ से प्रभावशील।
- ५ राजस्थान सरकार का निर्णय सख्या २ वित्त विभाग के आदेश सख्या एक १ (३) एक डी (व्यय-नियम) / ६५ दिनांक १८-२-६५ द्वारा विलुप्त तथा दिनांक १-८-६५ से प्रभावशील।
- ६ वित्त विभाग के आदेश सख्या एक १ (४५) एक डी (व्यय नियम) / ६५ दिनांक ६-१-६६ द्वारा मन्त्रिपरिषद्।

१ राजस्थान सेवा नियमों के नियम ४२ के उप नियम २ (1) की मोमा के विषय में सन्देह व्यक्त किये गए हैं। मामले पर विचार किया गया है और यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को उसे मिलने वाले क्वाटर से भिन्न थोड़ी के क्वाटर मिले और वह उसे लेने से मना कर दे तो इन नियमों के प्रयाजनाथ उमका मना करना।

(11) किसी सरकारी कर्मचारी को सरकार की विशेष स्वीकृति से सरकारी वास-स्थान दिया गया हो और उसने उसे लेने से मना कर दिया हो तो ऐसी स्थिति को छोड़कर मनाही नहीं माना जायेगा।

२ (111) अथवा जहाँ सरकार की विशेष स्वीकृति से किसी सरकारी कर्मचारी ने सरकार से मकान बनवाने के लिए अग्रिम लेकर या अल्प आय-वग के लिए आवास-योजना या किसी अन्य योजना तथा किसी अन्य सरकारी सूत्र से रुपया प्राप्त करके मकान बनवाया हो और उसे बेच दिया हो अथवा किसी अन्य प्रकार से उसका निवृत्त कर दिया हो तो ऐसी स्थिति को छोड़कर उसका मना करना मनाही नहीं माना जायेगा।

टिप्पणी

मकान किराया भत्ता उस समय स्वीकार किया जाता है जब कि मूलतः किसी मकान के लिए अग्रिम स्वीकार किया गया हो और वह मकान बाढ़, आग अथवा अन्य किसी आकस्मिक कारण से नष्ट हो गया हो अथवा किसी पारिवारिक सम्पत्ति में बदलाव होने से वह मकान सरकारी कर्मचारी की सम्पत्ति ही न रहा हो।

राजस्थान सरकार का नियम

३ २ नियम २ के अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी सरकारी वास स्थान में रह रहा है या जिसे सरकारी वास दिया गया है/दिया गया था। किन्तु उसने उसे लेने से मना कर दिया है। कर दिया था तो ऐसी स्थिति में उसे मकान किराया भत्ता नहीं दिया जायेगा। सरकारी वास स्थानों की कमी को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी सरकारी वास में रहने के बाद उसे छोड़ देता है या उसे सरकारी वास दिये जाने पर उसे स्वीकार करने से मना कर देता है तो उसे ३१-१२-७० तक मकान किराया भत्ता दिया जा सकता है यद्यपि कि —

(1) वह अन्य सब प्रकार से नियमों के अधीन मकान किराया भत्ता पाने का पात्र है और

१ वित्त विभाग के आपन सख्या ३५८६/एफ ३५ (२) आर/५१, दिनांक २०-७-५६ द्वारा सप्रतिष्ठित।

२ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ ७(ए) (८) एफ डी ए (स्लम)/५६, दिनांक १५.४.५६ द्वारा सप्रतिष्ठित।

३ वित्त विभाग के आपन सख्या एफ ११ (६) एफ II/५४, दिनांक ५-७-६५ द्वारा सप्रतिष्ठित एवं वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १(३) एफ डी (न्यय नियम) /६५ दिनांक १-६-६५ और १६-५-६७ द्वारा प्रति स्थापित।

11) दिनांक ३१-१२-७० तक उसी स्थान पर पद स्थापित होने पर लिखित में सरकारी वास न मांगने की अपनी सहमति अंकित कर देता है ।

२ यह भी निराय किया गया है कि जिस सरकारी कर्मचारी ने पहले ही सरकारी वास छोड़ दिया है अथवा इस आदेश के जारी होने से पूर्व ही सरकारी वास में रहने से मना कर दिया था और अब मकान किराया भत्ता प्राप्त नहीं कर रहा है तो ऐसे कर्मचारों को दिनांक १-६-६५ में उक्त अनुच्छेद १ में अंकित शर्तों के अधीन मकान किराया भत्ता दिया जा सकता है ।

यह आदेश दिनांक १-६-६५ से प्रभावशील होगा ।

१ स्पष्टीकरण — राज्य सरकार के समक्ष एक मामला प्रस्तुत हुआ जिससे यह जानकारी बाही गई कि क्या मकान भत्ता नियमों (परिशिष्ट १७ राजस्थान सेवा नियम खण्ड २) के अन्तर्गत मकान किराया भत्ता कर्मचारी जो देवस्थान विभागों ईमारतों में रहते हैं पाने के अधिकारी हैं ।

इस प्रसंग में यह स्पष्ट किया जाता है कि एस कर्मचारी जो किसी भी सरकारी इमारत/मकान/भवन (चाहे देवस्थान/सांस्कृतिक निर्माण विभाग आदि के हो) में रहते हैं, मकान किराया भत्ता अंतर्गत नियमों में पाने के अधिकारी नहीं हैं अतः उन्हें मकान किराया भत्ता नहीं मिलेगा ।

३ मकान मालिक पात्र नहीं — इस योजना के अधीन वह सरकारी कर्मचारी जिसका जयपुर या जोधपुर में मकान है, मकान किराया भत्ता पाने का पात्र नहीं होगा ।

४ इस नियम के प्रयोजनाय उक्त नगरों की नगरपालिका सीमाओं में स्थित मकान को मकान मालिक का मकान माना जायगा ।

५ २ विभागाध्यक्ष मकान का अनुमोदन तथा दिये गये किराये का औचित्य प्रमाणित करते समय उम्म यह भी अंकित करेगा कि मकान नगरपालिका सीमाओं में ही स्थित है ।

६ ३ यदि किसी सरकारी कर्मचारी के पास कोई पैतृक मकान है या उसका हिस्सा किसी पतक मकान में है तो इन नियमों के प्रयोजनाय उसे मकान का मालिक माना जायगा और उस मकान किराया भत्ता प्राप्त नहीं हो सकेगा ।

सरकार का निराय

७ ४ यह निराय किया गया है कि यदि सरकारी कर्मचारी मकान उतारने के लिए अग्रिम सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमों के अध्याय १७ के अधीन प्राप्त करता है या अल्प आय वर्ग के लिए आवास योजना/मध्य आयवर्ग के लिए आवास योजना या

१ विरा विभाग के आदेश संख्या एफ १(१५) एफ डी (व्यय नियम) ६५, दिनांक ६ १०-६५ द्वारा मंजूरिष्ट ।

२ विरा विभाग का आदेश संख्या एफ १(४५) एफ डी (ई आर) / ६५ दिनांक १३-७-६६

३ विरा विभाग का व्यय नियम आदेश संख्या एफ १(३६) एफ डी (ई आर) / ६५ दिनांक १४-१२-६५

४ विरा विभाग का आदेश संख्या एफ १(३४) एफ डी ए / एल/ ६१, दिनांक २१ ८-६१ और ११-५-६२ द्वारा पतिस्थापित ।

अपने भविष्य निधि ग्रीमे में से प्लॉट खरीदने या मकान बनाने, के लिए कर्जा प्राप्त करता है तो उसे मकान किराया भत्ता मिलना निम्न प्रकार बाद हो जायेगा —

^१ (१) यदि अग्रिम या कर्ज की राशि किसी श्रोत से एक साथ एक मुश्त में प्राप्त हो तो प्राप्ति के १२ माह बाद । यदि कर्ज या अग्रिम की राशि किश्तों में प्राप्त हो तो

(अ) एक या अधिक श्रोतों से कर्ज या अग्रिम की किश्त प्राप्त होने के १८ महीने बाद या

(ब) किसी एक श्रोत से एक मुश्त और अन्य श्रोत से किश्तों में प्राप्त होने के १८ महीने बाद या

(स) एक से अधिक श्रोतों से एक मुश्त प्राप्त होने के १८ महीने बाद ।

यह आदेश दिनांक १६-३-६४ से लागू होगा ।

मकान बनाने के लिए अग्रिम । कर्ज को प्राप्त करने वाला अधिकारी ही मकान के रहने के लिये तैयार होने का तिथि की सूचना स्वयं के अथवा पत्रित कमचारी होने की स्थिति में विभागाध्यक्ष को और स्वयं राजगणित सरकारी कमचारी होने की स्थिति में नियुक्ति कर्त्ता प्राधिकारी को देने के लिये उत्तरदायी होगा । विभागाध्यक्ष । नियुक्ति कर्त्ता प्राधिकारी मकान किराया भत्ता रोकने का सुनिश्चयन करेंगे एवं राजपत्रित सरकारी कमचारी मकान के रहने के लिये तैयार होने की तिथि से मकान किराया भत्ता वसूल करना बन्द कर देंगे और महालेखाकार को अपनी वेतन पर्ची (पेस्लिप) सशोधित करने के लिये लिखेंगे ।

यदि सरकारी कमचारी को मकान खरीदने के लिये अग्रिम ऐसे स्थान पर स्वीकृत हुआ है जहाँ पर कि उसको इन नियमों के अधीन मकान किराया भत्ता भी स्वीकार्य है तो ऐसी स्थिति में इन नियमों के अधीन मकान किराया भत्ता निम्न प्रकार स्वीकार्य नहीं होगा —

(१) खरीदे हुए मकान में वास्त करने की तारीख से, या

(११) अग्रिम की राशि के प्राप्त होने की तिथि के बाद चार माह समाप्त होने की तिथि से, जो भी पहले हो ।

तथापि अपवादः मकान परिस्थितियों में सरकार इस चार माह की अवधि में आवश्यकतानुसार छूट या तद्वत् दे सकती है जबकि सरकार के सन्तोष में यह साबित हो जाय कि सरकारी कमचारी अपने नियंत्रण से परे कारणों से उस मकान में अग्रिम प्राप्ति के चार माह के भीतर ही रहने के लिये न पहुँच सका हो ।

जो मामले इससे पूर्व तय किये जा चुके हैं उन्हें फिर से उठाये जान की जरूरत नहीं ।

^२ मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ ।

अपने स्वयं के मकान में रहता हुआ माना जायेगा और तदनुसार ही ऐसे कमचारी को कोई मकान किराया भत्ता नहीं मिल सकेगा ।

१ वित्त विभाग के आदेश सख्या एक १(७०) एक डी (व्यय नियम)/६५ दिनांक १५.१२.६४ द्वारा प्रतिस्थापित ।

२ वित्त विभाग आदेश सख्या एक १(८) एक डी (७) क्लर्क/६१ दिनांक २८-३-६१ भो.

४. कब स्वीकार्य है — किसी सरकारी कर्मचारी को यह भत्ता तभी स्वीकार्य होगा जबकि उसने किसी निर्धारित प्रक्रिया में, यदि ऐसी कोई हो, आवास के लिए प्राप्ति पत्र दिया हो किन्तु जिसे ऐसा कोई वास स्थान प्रदान नहीं किया गया हो।

२ सरकारी निस्वयं

१ ठेके पर रहने वाले अधिकारीयों को स्वीकार्य — एक प्रश्न यह उठाया गया है कि मकान किराया भत्ता नियमों के अनुसार किसी ऐसे अधिकारी को भी मकान किराया भत्ता क्या मिल सकता है कि जिसकी सेवाएँ ठेके पर हो।

इस मामले पर विचार किया गया है और यह तय किया गया है कि वैसे तो ठेके के आधार पर नियोजित सरकारी कर्मचारी को मकान किराया भत्ता मजूर करने में कोई एतराज नहीं होना चाहिये किन्तु ठेके की शर्तों के अनुसार इस विषय में विशेष प्रावधान होने चाहिये कि ऐसे मामलों में मकान किराया भत्ता स्वीकार्य होगा या नहीं होगा।

जहाँ वर्तमान ठेका के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान किये गये हों वहाँ ठेके की ऐसी सेवाओं के सम्बन्ध में स्थिति की अच्छी तरह से संबंधित विभागों द्वारा वित्त विभाग के परामर्शानुसार जांच की जानी चाहिये और उचित निर्णय किया जाना चाहिये।

ऐसे मामलों में सम्भावित सदेह उत्पन्न ही न हो सके, इसके लिए ठेके की शर्तों में ही ऐसी किसी स्थिति पर विशेष रूप से निर्णय कर लिया जाना चाहिये।

५ आवास स्थान का माप — उस आवास स्थान का माप जिसमें कि सरकारी कर्मचारी को रहना है यही है कि वह स्थान सरकारी कर्मचारी के स्तर के अनुकूल हो एवं कर्मचारी के घराजपन्नि होने पर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित हो किन्तु कर्मचारी के राजपन्नि होने की स्थिति में विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित हो। यदि सरकारी कर्मचारी स्वयं ही विभागाध्यक्ष हो तो इसका अनुमोदन सम्बन्ध प्रशासनिक विभाग द्वारा किया जाना चाहिये।

३ प्रपवाद — इस नियम के प्रयोजन हेतु पुलिस इन्स्पेक्टर के मामले में रेंज के उप महानिरीक्षक पुलिस सक्षम प्राधिकारी माने जायेंगे।

टिप्पणी

१ आवास का माप सभ्यवली में केवल आवास में सम्मिलित करने को नहीं समझा जायेंगे। किन्तु इनमें अन्य बाजें जैसे कमरे की साइड, लोनेरिटी एवं अन्य सुविधायें और किराया आदि भी मिलेंगे।

२ 'आवास का माप बनाने में किराया एक माप है। अतः आवास का माप स्वीकार करने में मसम प्राधिकारी को स्वीकार्य किराये की उपयुक्तता पर भी ध्यान देना चाहिये और जितना

१ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १(२४)/६२, दिनांक ६-११-६२ द्वारा प्रतिस्थापित।

२ वित्त विभाग के आपन सन्धा एफ II (३६) त्वांक ६-४-६४ द्वारा सन्निविष्ट।

३ प्रपवाद वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ७९(४२) एफ डी (ए) भार/६० दिनांक २०-११-६० द्वारा सन्निविष्ट किया गया।

४ टिप्पणी सं० २ वित्त विभाग के आदेश सं० एफ ३३ (२) भार/५१ दि० १६-६-५१ द्वारा सन्निविष्ट।

किराया दिया जाना वह उचित समझ-उतने को सोमा तब वो उसे अनुमोदन करना चाहिये। यह कम किया हुआ या सीमित किराया ही तब मकान किराया भत्ते की फनावट के लिये आधार माना जायेगा।

१३ इस नियम के प्रावधान उस सरकारी कमचारी पर लागू नहीं होंगे जो ४३३ रु० प्रतिमास तब वेतन प्राप्त करता है। तथापि मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का दावा करने वाले सरकारी कमचारी द्वारा नियम ६ के उपनियम (१) के अधीन इस विषय का एक प्रमाण पत्र देना होगा कि वह किराए पर लिए हुए आवास स्थान में रह रहा है, और बतमान नियमों के अधीन आवास स्थान का माप अनुमोदन करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा, इस प्रमाण पत्र को प्रति हस्ताक्षरित किया जायगा। ऐसे सरकारी कमचारी को सरकारी आवास स्थान प्राप्त न होने का कोई प्रमाण पत्र भी नहीं देना पड़ेगा। इस टिप्पणी के प्रयोजनाय वेतन शब्द का नियम ६ के नीचे दी हुई टिप्पणी में परिभाषित किया जावेगा। (दिनांक १-८-६४ से प्रभावशाल)

अनुदेश — नियम ६ (१) के अधीन मकान किराया भत्ता वसूल करने वाले राजपत्रित अधिकारी के सम्बन्ध में उसके स्वयं द्वारा दिया हुआ यह प्रमाणपत्र कि वह किराये में मकान में रह रहा है आवास स्थान का माप अनुमोदन करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूरातया प्रति हस्ताक्षरित कराकर महालेखाकार को भेजा जाना चाहिए ताकि किराये का भुगतान प्राधिकृत करके उसका आडिट किया जा सके।

इस अनुदेश के प्रयोजन हेतु उप आयुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर का उनके मण्डल में पद स्थापित अधिकारियों के सम्बन्ध में उक्त प्रमाण पत्रों को प्रति हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी माना जावेगा।

३ सरकारी नियम

यह नियम किया गया है कि जब राजपत्रित अधिकारियों का आवास स्थान माप एक बार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो जाय तो उन राजपत्रित अधिकारियों के मकान कि रिया भत्ता का हर छठे महीने किराए को रसीदा के आधार पर निम्न प्राधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाना चाहिए व अर्थात्कि सम्बद्ध राजपत्रित अधिकारी उस निम्न प्राधिकारी के अधीनस्थ है।

४ सरकारी नियम

यह भी नियम किया गया है कि कोई सरकारी कमचारी मकान किराया भत्ता पाने हुए किराए के प्राईवेट मकान को बदल कर सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व स्वीकृति बिना उच्चतर

- १ टिप्पणी सख्या ३ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (३) एक डी (व्यय नियम)/६५ दिनांक १८-२-६५ द्वारा सन्निविष्ट।
- २ वित्त विभाग के आदेश स एफ १ (३) एक डी (व्यय नियम)/६५ दिनांक १३-७-६६ और दिनांक १४४ ६७ द्वारा सन्निविष्ट।
- ३ वित्त विभाग के आदेश स डी १०४४/एफ १ (सी) (४) एक डी ए (नियम) ६० दिनांक ३०-१-६० द्वारा सन्निविष्ट।
- ४ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (१५) एक डी (व्यय नियम)/६६ दिनांक १-६-६६ द्वारा सन्निविष्ट।

किराए के भवनों में चला जाता है तो उसे भवनों के मालिकों से मालिकों के लिए हुए किराए के आधार पर उस तिथि तक लिया जाना चाहिए जिसमें कि सामान्य प्रशासन विभाग में सरकार द्वारा उसके बदले हुए भावों का भाव अनुमोदित किया जाए।

पहले नियम किए हुए विभाग मामलों को फिर से छानने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु विचाराधीन मामलों को इन मामलों के अधीन विनियमित किया जा सकता है।

१३ यदि कोई सरकारी कर्मचारी एक ही भवन में दो मानिकों के दो सलग भवनों में जा हो तो उसके द्वारा चरे हुए किराए के समस्त स्थान का भवन किराया भत्ता स्वीकार करने लिए विचाराधीन से लिया जा सकेगा परन्तु यह है कि वह स्थान सम्बंधित सरकारी कर्मचारी स्तर के अनुक्रम हो।

६ भत्ते की दरें — किराये के भवनों में रहने वाले सरकारी कर्मचारी को शर्तना भत्ता दिया जा सकेगा जो दिए हुए किराये और दिनांक १-३-५४ से ३०० रु प्रति मास से कम वेतन पाने पर उससे वेतन के १०% के अंतर के बराबर हो अथवा दिए हुए किराए और दिनांक १-५-६४ से ४०० रु से कम वेतन पाने पर इस वेतन पाने पर इस वेतन के ७१% के अंतर के बराबर हो। दिए हुए किराये में पर्निचर का किराया या उसका कोई भाग सम्मिलित नहीं है। यह किराया भत्ता निम्नलिखित सीमाओं के अधीन दिया जावेगा —

(अ) सरकारी कर्मचारी का वेतन रु ३००/- रु ४००/- रु प्रतिमास से कम होने पर १०%

(ब) सरकारी कर्मचारी का वेतन ३०० रु/४००/- रु प्रतिमास होने या अधिक हो किन्तु १००० रु प्रतिमास से कम होने पर उपान्त-समझन के अधीन ७१%

(स) सरकारी कर्मचारी का वेतन १००० रु प्रतिमास या इससे अधिक होने पर सरकारी कर्मचारी के वेतन के १०% और १७५ रु से जो अंतर हो उससे बराबर।

२६(अ) दिनांक १-५-६४ से प्रभावशाली भवन किराये भत्ते की संशोधित दरें —

(१) जिस सरकारी कर्मचारी को ५३३ रु प्रतिमास तक वेतन प्राप्त होता है और जो किराये के भावों में स्थान में रहता है तो उसे निम्नांकित दरों के अनुसार भवन किराया भत्ता दिया जा सकेगा जो उसकी वेतन वग के अनुसार इस प्रकार होगा —

१ वित्त विभाग के आदेश संख्या एक १ (१३) एक डी (अध्य-नियम)/६६ दिनांक १-६-६६ द्वारा संप्रतिष्ठित।

२ भवन किराये भत्ते की संशोधित दरें दिनांक १-५-६४ से वित्त विभाग के आदेश संख्या एक १ (३) एक डी/६४ दिनांक १८-२-६५ द्वारा प्रभावशाली।

वेतन वर्ग

स्वीकाय मकान किराया भत्ते की दरे

(i) ६० रु से कम	६ रु प्रतिमाह
(ii) ६० रु और इससे अधिक किंतु ७५ रु से कम	७ ५० रु प्रति माह
(iii) ७५ रु " " " १०० रु " "	१० रु " "
(iv) १०० रु " " " १२५ रु " "	१२ ५० रु " "
(v) १२५ रु " " " १५० रु " "	१५ रु " "
(vi) १५० रु " " " १७५ रु " "	१७ ५० रु " "
(vii) १७५ रु " " " २०० रु " "	२० रु " "
(viii) २०० रु " " " २५० रु " "	२५ रु " "
(ix) २५० रु " " " ३०० रु " "	३० रु " "
(x) ३०० रु " " " ३५० रु " "	३५ रु " "
(xi) ३५० रु से ५३३ रु तक	४० रु " "

(२) जिस सरकारी कमचारी को ५३३ रु प्रतिमाह से अधिक वेतन मिलता है और जो किराये के मकान में रहता है तो उसे किराया-भत्ता उस राशि के बराबर होगा जो उसके दिये हुए किराये और वेतन के १०% के अन्तर को निकालकर बचेगी। दिये हुए किराये में फर्नीचर का किराया या उसका अंश सम्मिलित नहीं है। उक्त अन्तर के बराबर की राशि का किराया भी निम्न भीमाओं के अधीन हो उसे दिया जायेगा —

(अ) उस सरकारी कमचारी को ५३३ रु प्रतिमाह से अधिक किंतु १००० रु प्र माह से कम वेतन प्राप्त होता है। ७३% उपात्त समजन के अधीन

उस सरकारी कमचारी को जिसे १००० रु प्रति माह या इससे अधिक वेतन मिलता हो ७३% अथवा २२५ रु और सरकारी कमचारी के वेतन के १०% में अन्तर, जो भी कम हो।

ये आदेश दिनांक १-७-१९६६ से प्रभावशाल होंगे।

राजकीय निर्णय

१ सशोधित नियम ६ तारीख १-३-१९३४ से प्रभावशील था, परन्तु वास्तव में कतिपय राजपत्रित अधिकारियों के मकान किराया भत्ते की मांगों के सम्बन्ध में लेखापाल कार्यालय द्वारा

१ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (३) एफ डी (व्यय नियम)/६५ दिनांक १८-२-६२ द्वारा सन्निविष्ट एव आदेश सख्या एफ १ (४४) एफ डी (व्यय नियम)/६६ दि १८-६६ द्वारा प्रतिस्थापित।

२ वित्त विभाग गायन स एफ १ (४१) एफ/बी-ए/रुस/६२ दिनांक १६-११-६३ द्वारा अन्तर्गणित किया गया।

११० १९५२ से प्रभावित कर दिया गया। उसने फन स्वरूप कृतिपय मामलों में ११० १९५३ से २८ २ १९५४ की अवधि का भत्ता वापस वसूल कर लिया गया।

महोदय का कहना है कि उपरोक्त उल्लिखित वित्त विभागीय आदेश के अन्तर्गत देय राशि से अधिक किराया भत्ता राशि जो वसूल की गई, वह सम्बन्धित राज्य कमचारियों को लौटा दी जावे।

तदनुसार ऐसा राज पवित्र राजकीय कमचारों को ११० १९५३ से २८ २-१९५४ की अवधि के सम्बन्ध में मकान किराया भत्ते की वसूल गुदा राशि वापस पाने का हक्कादार है, वह ऐसी वापसी के लिये इन आपन के जारी होने की तारीख से ६ मास के भीतर महासेवापाल राजस्थान को सीधा आवेदन कर सकेगा। ऐसा करने समय जहाँ तक समय हो, वह विवरण प्रस्तुत करे, ऐसा कि वसूल की गई राशि खजाने का नाम वसूली की तारीख, वाउचर का क्रमांक जहाँ कि वसूली बिना में से हुई हो, तथा, यदि नकद जमा कराई हो, तो चालान का क्रमांक।

यदि कोई अधिकारी उपरोक्त नियम के भीतर आवेदन नहीं करेगा, तो वापसी की कोई प्रवृत्ति नहीं दी जायगी।

१२ आया प्रश्न की गई है कि ऐसा राजकीय कमचारों को राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिटायर्ड) क्लब के १९६१ अधीन १ — ६ — १९६१ से सशोधित वेतन य सला के लिये निर्वाचित करता है और उपरोक्त नियमों के अधीन २ १५०, प्रति मास से कम वेतन उठाता हो तो यदि भत्ता राशि १-६-१९६१ को सशोधित वेतन पर अनुमति मकान किराया भत्ता से अधिक थी तो उसे जो मकान किराया भत्ता ३१-८-१९६१ को देय था वही १-६-१९६१ से उपातक तक अनुमति होगा जब तक कि वह १-६-१९६१ के पदवात अगली वतन प्रति उपार्जित न करे, या वह ऐसे पद पर नियुक्त न हो जावे। जिसकी वेतन य तथा उससे अधिक हो जो उसे १-६-१९६१ को अनुमति थी-इससे जो भी पहले बटित हो जाय।

ऊपर निर्देशित मकान किराया भत्ता नियम ऊपर बताई गई सीमा तक सशोधित सम्भवे जायेंगे।

यह आदेश १ वित्त १९६१ से प्रभावशील होना सम्भवा जायगा।

टिप्पणी

१ (वित्त विभाग आदेश स एफ ३५ (१०) एफ डी (ई-आर) ५७ दिनांक ११-३-५५ द्वारा सशोधित।)

२ इस नियम के अन्वयेनाय वेतन में वेतन सम्मिलित है। जो राजकीय कमचारों निम्नलिखित है वह मकान किराया भत्ते के रूप में वही राशि उठाने का हकदार होगा जो वह नियम से तुरन्त पूर्व उठा रहा था बल्कि वह यह प्रमाणित करे कि वह किराये के मकान में अब तक रहता है और जिस प्रयोजन के लिये वह स्वीकृत है उसी के लिये व्यय करता है। यह आदेश ७-६-१९६१ से प्रभावशील है।

१ एफ १ (३०) एफ डी/ई-आर/६५, दिनांक ११-८-६१ द्वारा स्थानापन्न किया गया।

२ वित्त विभाग आदेश स एफ १ (८२) एफ डी/ए/क्लब/६२, दिनांक १७-१२-६२ तथा इसी प्रकार ११-१२-६२ द्वारा सम्मिलित किया गया।

३ इन नियमों के प्रयोजनार्थ शब्द 'किराया' से तात्पर्य किसी राजकीय कमचारी द्वारा भुगतान किये गए ऐसे व्यय से है जो उसके द्वारा काबिज असुसज्जित [Unfurnished] मकान के लिये समझा गया हो और इसमें नगर पालिका का गृह-कर और मकान मालिक द्वारा देय नगर विकास यास का नागरीक कर [Urban assesment] सम्मिलित है लेकिन उसमें मलवाहन कर [Consewancy tax] जल-कर विद्युत शुल्क जैसे सेवा कर सम्मिलित नहीं हैं जो बंध रूप से किरायादार द्वारा देय होने हैं ।

१ स्पष्टीकरण — मकान किराया भत्ता नियमों के नियम ६ के नीचे टिप्पणी सख्या २ (वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (३०) एफ डी (व्यय-नियम) । ६६ दि० ११ न ६५ द्वारा सन्निविष्ट) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें कि मकान किराया भत्ता नियमों के प्रयोजन हेतु 'वेतन' शब्द की परिभाषा दी हुई है ।

यह सदेह व्यक्त किए गए हैं कि नियुक्ति विभाग की विज्ञप्ति सरपा एफ १ (९) नियुक्ति (ए० II)/६१ दि० १६-३ ६१ के अनुसार सरकारी कमचारी को स्वीकृत 'योग्यता वेतन' को इन नियमों की खातिर वेतन माना जाए अथवा नहीं ।

मामले पर विचार किया गया है और यह स्पष्ट किया जाता है सरकारी कमचारी को स्वीकृत 'योग्यता वेतन' को इन नियमों के प्रयोजनाथ वेतन ही माना जावेगा ।

२ ६ (अ) [विलोपित]

२ ७ किस प्रकार विनियमित होगा — (1) यदि एक या अधिक वयस्क लोग जो कि सरकारी कमचारी के परिवार से सम्बन्धित नहीं हैं, किसी मकान के हिस्से में रहते हैं अथवा उसी मकान का कोई हिस्सा किसी अशासकीय व्यक्ति को उप-किराए पर दे दिया जाए तो मकान किराए भत्ते की फलावट के लिए वस्तुतः दिये गये किराये की राशि का $\frac{2}{3}$ भाग कम भरा जायेगा ।

(11) यदि किसी मकान का कोई हिस्सा उप-किराए पर दिया जाए या कोई दूसरा सरकारी कमचारी उसमें हिस्सेदार हो तो किराया भत्ते उसी सरकारी कमचारी को प्राप्त होगा जिसने कि पूरा मकान किराए पर लिया है और इन नियमों के अधीन दूसरा सरकारी कमचारी कोई मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा । ऐसे मामले में मकान किराए भत्ते की राशि की फलावट के लिए दूसरे सरकारी कमचारी के वेतन के १०% में से वास्तव में दिए गए किराए को घटा दिया जायेगा ।

१ वित्त विभाग के आदेश सख्या डी ६०४४/एफ I (सी) (४) एफ डी ए (नियम)/६० दिनांक ३० १ ६० द्वारा विलोपित ।

१ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (५६) एफ डी (व्यय नियम)/६२ दिनांक ७-२ ६१ द्वारा प्रतिस्थापित ।

टिप्पणियाँ

(1) यदि पति और पत्नी दोनों ही सरकारी सेवा में हों और दोनों ही ऐसे स्थान पर पद स्थापित हो जहाँ कि मकान किराया भत्ता स्वीकार्य है तो ऐसी स्थिति में दोनों में से जिस को उच्चतर वेतन मिलता है वही मकान किराया भत्ता पाने का हक्कार होगा और उसे उन-नियम (11) के अनुसार मकान किराया भत्ता मगाना करके दिया जावेगा तथा दूसरे को इन नियमों के अधीन कोई मकान किराया भत्ता नहीं दिया जावेगा।

(11) इस नियम के अधीन मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का दावा नियम ८ (घ) और ८ (ङ) में प्रावहित प्रमाण-पत्र सख्या (२) द्वारा समर्थित होना चाहिए।

माने यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संशोधन आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावशील हुये जो मामलें इन संशोधनों में लिए गए तरीकों के प्रतिरिक्त ढंग से पहले ही तय कर लिए हैं उन्हें फिर से छड़ने की जरूरत नहीं है।

¹ **अपवाद**—इस नियम के प्रावधान नियम ६ (१) के अधीन मकान किराया भत्ता दावा का करने वाले सरकारी कर्मचारी पर लागू नहीं हुये। तथापि यदि पति और पत्नी दोनों ही सरकारी सेवा में हों और दोनों ही ऐसे स्थान पर पद स्थापित हों कि जहाँ मकान किराया भत्ता स्वीकार्य है तो उनमें से उच्चतर वेतन प्राप्त करने वाला ही मकान किराया भत्ता पाने का अधिकारी होगा और इन नियमों के अधीन दूसरा कोई मकान किराया भत्ता नहीं पा सकेगा।

टिप्पणी

² जो व्यक्ति कुल पेंशन की राशि इतनी पाता है जो १०० रु० महीने से अधिक नहीं है (इसमें पेंशन की सदस्यई वृद्धि और मृत्यु सह सेवा निवृत्ति-प्रेचुइंग के बराबर पेंशन भी सम्मिलित है) किंतु जो किसी सरकारी कर्मचारी पर किसी प्रकार निर्भर है और उसी के साथ रहता भी है तो उसे उस सरकारी कर्मचारी के परिवार का सहस्य ही माना जावेगा।

३ स्पष्टीकरण

वित्त विभाग के आदेश सम सख्या दिनांक १३-७-६६ के अनुच्छेद II के द्वारा मकान किराया भत्ता नियमों के नियम ७ के नीचे एक अपवाद सतिविष्ट किया गया है। एक प्रश्न यह उठाया गया है कि कौन सी तिथि से यह उपयुक्त अपवाद प्रभावशील माना जाना चाहिये।

मामले पर विचार किया गया है, चूंकि नियम ६ (१) के अधीन वेतन वर्गों के आधार पर मकान किराया भत्ता दिनांक १-८-६४ से दिया जाता है अतः मकान

२ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (३) एफ डी (व्यय-नियम)/६५ दिनांक १३-७-६६ द्वारा सतिविष्ट।

३ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ ७०३ (१)/५६-एफ ७ ए (४३) एफ डी ए (कलब)/५६ दिनांक ७ १२ ५४ द्वारा सतिविष्ट।

३ वित्त विभाग के आदेश स० एफ १ (३) एफ डी (व्यय नियम) ६५ दिनांक २१-१२-६६।

किराया भत्ता नियमों के नियम ७ के प्रावधान ऐसे मामलों पर प्रभावहीन हो गये हैं। तदनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि उपयुक्त कथित अपवाद दिनांक १-२-१९६४ से प्रभावशील माना जाना चाहिये।

१सरकार का नियम

एक प्रकरण सरकार की जानकारी में आया है जिसमें कि उपयुक्त प्रसंगित उपनियम (७) के अधीन दो सरकारी कर्मचारी (पति और पत्नी) मकान किराया भत्ता प्राप्त कर रहे थे। पत्नी रियायती छुट्टी के प्रतिरिक्त अथ किसी अवकाश पर चली गई और इस अवकाश की अवधि में वह किसी भी मकान किराये भत्ते की हकदार नहीं थी। अतः एक प्रश्न यह उठा कि पति का मकान किराया भत्ता दिये गये कुल किराये के आधार पर क्या फिर से फ्लावट करके तय किया जाय। मामले पर विचार करके यह तय किया गया है कि चूंकि वर्तमान नियमों के अधीन स्वीकृत किराया भत्ता दो सरकारी कर्मचारियों (पति और पत्नी) में जो कि एक ही मकान में हिस्सेदार थे उनके वेतन के अनुपात में बंट जायेगा अतः यदि पत्नी छुट्टी पर चली जाय और इस छुट्टी के दौरान वह किसी किराया भत्ते की हकदार नहीं हो तो किराये भत्ते की पुनः फ्लावट करने का दिया हुआ कुल किराये के आधार पर प्रश्न उठता ही नहीं है। दूसरे शब्दों में पति को स्वीकृत मकान किराया भत्ता पत्नी के अवकाश की अवधि में जिसमें कि वह किसी प्रकार का किराया भत्ता पाने की हकदार ही नहीं थी, बढ़ नहीं जायेगा।

जो मामले पहले किसी अन्य प्रकार से तय कर दिये गये हों उन्हें फिर से छड़ने की कदापी आवश्यकता नहीं है।

८ प्रमाण-पत्र —मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के लिये इन नियमों के अधीन उन वेतन विलों के साथ निम्न प्रमाण-पत्र सलग्न किये जान चाहिये जिन में मकान किराया भत्ता उठाया जा रहा हो ताकि भत्ते का दावा समर्थित हो सके —

(अ) कार्यालय/अध्यक्ष द्वारा अगणन/निर्णय अधिकारियों के मामले में हस्ताक्षर किये जाने योग्य —

१ प्रमाणित किया जाता है कि सरकारी कर्मचारी जिसका कि इस बिल में मकान किराया भत्ता उठाया जा रहा है न सरकारी मकान के लिये अर्जों दी थी किंतु उसे ऐसी अभिव्यक्ति जगह रहने के लिये नहीं दी गई है।

२ अनुदेश —नियम ६ (१) के अधीन मकान किराया भत्ता उठाने वाले कर्मचारी के विषय में यह प्रमाण-पत्र देने की वाई जरूरत नहीं है।

३ सरकार द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र सरकारी कर्मचारी से जिसका कि इस बिल में मकान किराया भत्ता उठाया जा रहा है, प्राप्त कर लिये गये हैं तथा में इस बात से सन्तुष्ट हूँ कि यह मकान किराये भत्ते का दावा नियमानुसार है।

१ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ २५ (२) आर/५१ दिनांक ६-७-५८ द्वारा सन्निविष्ट आदेश कि नियम से प्रभावहीन।

२ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (३) एफ डी (यय-नियम)/६५ दिनांक ३१ ७ ६५ द्वारा सन्निविष्ट।

१३ मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मैंने सरकारी मकान के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था किन्तु जिस अवधि का मकान किराया भत्ता उठाया जा रहा है उसमें ऐसी कोई जगह मेरे रहने के लिये सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

हस्ताक्षर

पद "

अनुदेश — यह प्रमाण-पत्र उस सरकारी कर्मचारी के विषय में दिये जाने की जरूरत नहीं है जो नियम ६ (१) के अधीन मकान किराया भत्ता प्राप्त कर रहा है।

(ब) मकान किराया भत्ता प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित होने योग्य —

(१) मैं प्रमाणित करता हूँ कि —

(अ) मेरा " " मे मकान नहीं है। मेरा स्वयं का मकान है किंतु मुझे सरकार के आदेश सरगया " दिनांक " द्वारा किराये के मकान में रहने की इजाजत दे दी गई है।

३(ब) मैं " " मे दिनांक " से दिनांक तक किराये के मकान में रह रहा हूँ (जिसके मालिक मेरे माता या और पिता आदि नहीं है)

(स) मेरे द्वारा दावा की गई मकान किराये भत्ते की " " व की राशि वस्तुतः मेरे द्वारा मकान किराये के लिये दी गई मासिक राशि से कर्मीवर रहित मकान के लिये मेरे वेतन ६० मासिक की ७१% राशि से और कर्मीवर सहित मकान के लिये मेरे वेतन की १०% राशि से अधिक है।

अनुदेश — नियम ६ (१) के अधीन मकान किराया भत्ता उठाने वाले सरकारी कर्मचारी का सम्बन्ध में यह प्रमाण-पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(२) मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि जिस किराये के मकान के लिये मैंने मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का दावा किया है उसके किसी हिस्से को मैंने किसी को उप-किराये पर नहीं दिया है और न उसके किसी हिस्से में मेरे परिवार के और मुझ पर ही पूरातया निर्भर वयस्क व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई अन्य वयस्क व्यक्ति रहता है।

१ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (२४) एफ डी (ए) नियम/६२ दिनांक ८-११-६६ द्वारा सन्निविष्ट।

२ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (२४) एफ डी (पय-नियम)/६२ दिनांक १३ ७ ६६ द्वारा सन्निविष्ट।

३ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (२२) एफ डी (ई भार)/६४ दिनांक २६-६४ द्वारा प्रति स्थापित।

४ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (१३) एफ डी (व्यय नियम) ६५ दिनांक १३ ७ ६६ द्वारा सन्निविष्ट।

^१अनुदेश—नियम ६ (१) के अधीन मकान किराया भत्ता उठाने वाले सरकारी कमचारी के सम्बन्ध में उक्त प्रमाण-पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।

^२(३) में यह भी प्रमाणित करता है कि मने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सरकारी आवास स्थान के लिये प्राथना-पत्र दिया था किन्तु मुझे ऐसी कोई जगह रहने के लिये उस अवधि के दौरान प्रदान नहीं की गई है जिसके लिये मैंने किराया भत्ता पाने का दावा किया है।

^१अनुदेश—नियम ६ (१) के अधीन मकान किराया भत्ता उठाने वाले सरकारी कमचारी के सम्बन्ध में यह प्रमाण-पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

हस्ताक्षर

पद

राजस्थान सरकार का निर्णय

मकान किराया भत्ता नियमा के नियम ८ में कुछ ऐसे प्रमाण पत्र हैं जो कि उस दल के साथ लगाये जाते हैं जिससे सरकारी कमचारी का मकान किराया भत्ता उठाया जा रहा है। बू कि इस भत्ते का दिया जाना उस मकान किराये पर निर्भर है जो कि वस्तुतः सरकारी कमचारी द्वारा दिया जाता है अतः यह वाछनीय है कि किराया की रसीदों के सम्बन्ध से विभागाध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष द्वारा यह जांच की जाती रहनी चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भत्ता सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किये गये नियमों के अनुसार ही दिया जा रहा है। यह जांच अवसर जितनी हो सके यथा संभव की जाती रहनी चाहिये। कुछ कार्यालयों में तो यह रिवाज हो गया है कि किराया की रसीदें हर माह कार्यालय में प्रस्तुत की जाती हैं यह तरीका यथा संभव अपनाया जाना ही चाहिये।

यह सुनिश्चित करने के लिये कि यह काम से काम माह में एक बार किया जाता है। सरकार सहय आदेश प्रदान करती है अराजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में बिल उठाने वाले कार्यालयाध्यक्ष फरवरी और अगस्त के बिलों में एक प्रतिरिक्त प्रमाण-पत्र ऐसा दें कि उन्होंने पिछले जनवरी और जुलाई की किराये की रसीदों की जांच कर ली है तथा इन रसीदों से उन्होंने यह भी चक कर लिया है किराया भत्ता जांच करने पर उन रसीदों के अनुसार सही पाया गया है। राजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी प्रति वर्ष २० फरवरी और २० अगस्त को ऐसा प्रमाण-पत्र अलग से भेजेंगे कि उन्होंने पिछली जनवरी और जुलाई की किराये की रसीदें चक कर ली हैं और यह पाया है कि लिया गया मकान किराया उस राशि से कम नहीं है जिसके आधार पर कि मकान किराया भत्ता स्वीकार हुआ था।

२ महासचिवार राजस्थान ने सरकार की जानकारी में यह बात साई है कि वित्त विभाग के आदेश संख्या डी ३१६०/एफ II १५३ दिनांक ८-८-५३ के उन अनुदेशों का विभागाध्यक्षों

१ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ (१३) एफ डी (व्यय नियम)/६५ दिनांक १३ ७ ६६ द्वारा सन्निविष्ट।

२ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (२४) एफ डी (ए) नियम/६२ दिनांक ६ ११ ६२ द्वारा प्रतिस्थापित।

कार्यालयीयता द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिनके अनुसार कि उन्हें राजपत्रित अधिकारीयो क सम्बन्ध में प्रतिवर्ष २० फरवरी और २० अगस्त को सक्षम प्राधिकारी का इस विषय का एक प्रमाण-पत्र देना होगा है कि उन्होंने पिछली जनवरी और जुलाई की किराये की रसीदों को जांच कर लो है और निया द्वारा किराया सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों के अनुसार ही हैं।

उक्त प्रयावनाथ बनायी गई प्रक्रिया का बहाई के साथ अनुपालन किया जाना चाहिये तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि इस सम्बन्ध में अपेक्षित प्रमाण पत्र महालेखाकार राजस्थान को भविष्य में भेजे जाते हैं इस कार्य के लिये सक्षम प्राधिकारी विभागों के अध्यक्ष है और यदि सरकारी कर्मचारी स्वयं ही विभाग का अध्यक्ष हो तो सरकार का प्रशासन विभाग इस विषय में सक्षम होगा।

१ एक प्रश्न यह उठाया गया था कि समय समय पर मजदूरित एवं वित्त विभाग के जारी किये हुए आदेश सत्या एक ३५ (२) भार/५१ दिनांक २३-६-५१ के अधीन जारी जयपुर और जोधपुर में पद स्थापित या सेवा कर रहे सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया मत्ता स्वीकार करने के लिये नियम ६ के अधीन अपेक्षित प्रमाण-पत्र देना क्या छूटिया स्वीकृत होने या अस्थायी स्थानांतरण की स्थिति में भी आवश्यक होगा जब कि ऐसे कर्मचारी अस्थानांतरणीय हैं।

इस मामले की जांच की गई है और यह निर्णय किया गया है कि कूनि ऐसे कर्मचारियों का छूटों की अवधि समाप्त होने पर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण नहीं हो सकता है भन उनके मामला में उक्त प्रकार के प्रमाण-पत्र दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ऐसे कर्मचारी, जिनका अन्य स्थान पर स्थानांतरण नहीं हो सकता है और जिनके सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रमाण-पत्र दिये जाने की भी आवश्यकता नहीं है अनुसूचक में अंकित हैं

अनुसूचक

- १ मुख्य अभियंता सिविल विभाग।
- २ मुख्य अभियंता सावजनिक निर्माण विभाग (मकान एवं पथ)।
- ३ निदेशक स्वास्थ्य एवं बिजली सेवाओं और उनके डिप्टी।
- ४ महानिरीक्षक पुलिस।
- ५ मुख्य वन सरक्षक।
- ६ राजस्थान सचिवालय सेवा के सहायक सचिव और उप-सचिव पद धारक।
- ७ सचिवालय के अनुभाग अधिकारीगण।
- ८ बीमा विभाग के राजपत्रित अधिकारीगण।

स्पष्टीकरण

एक प्रश्न यह उठाया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया मत्ता मजूर करने के लिये नियम १ के अधीन जो प्रमाण-पत्र अपेक्षित हैं तो क्या वे उस सरकारी कर्मचारी के मकान में भी आवश्यक हैं जो एक पृथक् स्थायी-पद सस्यायी स्थिति में धारण किये हुए है और

- १ वित्त विभाग के आपन सत्या एक १ (३७) भार/५६ दिनांक २१-६-५१ द्वारा सन्निविष्ट।
- २ वित्त विभाग के आपन सत्या एक १ (८) एवं डी (व्यय नियम) ६४ दिनांक २०-३-६४ द्वारा सन्निविष्ट।

जिसको अवकाश स्वीकृत किया जाता है अथवा जिसका अस्थायी रूप से स्थानान्तरण कर लिया जाता है ।

मामले की जांच कर ली गई है और यह नियम किया गया है कि चूंकि ऐसे अधिकारी का वही स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है अतः उसने सम्बन्ध में ऐसे उक्त प्रमाण पत्र अभिलेखित किये जाने की आवश्यकता भी नहीं है ।

१४ वित्त विभाग के आदेश दिनांक ७.१.५६ (जो कि नियम सख्या ८ के नीचे राजस्थान सरकार का नियम सख्या २ के रूप में समाविष्ट है) के अनुसार राजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में प्रति बप २० फरवरी और २० अगस्त को सक्षम प्राधिकारी का ऐसा प्रमाण-पत्र भेजा जाना बाध्यनीय है कि उसने पिछली जनवरी और जुलाई की किराये की रसीदों को चक करके देस लिया है कि उसे किराया भत्ता नियमानुसार दिया जा रहा है ।

महोत्पाकार राजस्थान ने यह बताया है कि उक्त प्रक्रिया से काम सन्तोषजनक ढंग से नहीं हो रहा है क्योंकि किराये की रसीदों की जांच के प्रमाण-पत्र उनका यहां प्रति विलम्ब से भेजे जाने हैं । इस मामले पर फिर से विचार किया गया है और यह नियम किया गया है कि अब आगे से उक्त अनुच्छेद में अंकित प्रक्रिया (यानी प्रति बप २० फरवरी और २० जुलाई को भेजने वाले प्रमाण-पत्र भेजना) समाप्त कर दी जाय और इसके स्थान पर सम्बद्ध राजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में उनसे ऊँचा प्रशासनिक प्राधिकारी किराये की रसीदों के सत्यापन स्वरूप प्रति बप उक्त दिनाम्बर और पून के वेतन बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा । तथापि सम्बद्ध राजपत्रित अधिकारी अपने वेतन बिलों पर इन प्रकार का एक प्रमाण-पत्र दख करेगा कि उसने वस्तुतः माह का २० मकान किराया चुका दिया है ।

२ यह नियम किया गया है कि नियम ६ के उप नियम (१) के अधीन मकान किराया भत्ता वसूल करने वाले सरकारी कर्मचारियों को समय-समय पर सशोधित वित्त विभाग के आदेश सख्या बी० ३१६० एफ ११/५३ दिनांक ८.८.५३ (जो नियम ८ के नीचे सरकारी नियम १ एव २ के रूप में प्रकाशित हुआ है) के प्रयोजनात्मक मकान किराये की रसीदें प्राप्त करने की जरूरत नहीं है । तथापि सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी से इस आदेश का एक प्रमाण पत्र लीया ही जायेगा कि वह किराये के मकान में ही रह रहा है ।

यह आदेश दिनांक १-८-१९५४ से प्रभावशाली होगा ।

१ अवकाश इत्यादि के दौरान स्वीकृतता—मकान किराया भत्ता अवकाश या अस्थायी स्थानान्तरण के दौरान भी दिया जा सकता है जसे

३ सरकारी कर्मचारी को अवकाश । अस्थायी स्थानान्तरण के दौरान उसी दर पर मकान किराया भत्ता दिया जा सकेगा जिस दर कि वह उसे अवकाश पर रवाना होने से पूर्व मिल रहा था कि तु उसे यह प्रमाणित करने पड़ेगा कि—

- १ वित्त विभाग के ज्ञापन सख्या एफ १ (१४) एफ डी (व्यय नियम)/६३ दिनांक १३-३-६३ द्वारा सन्निविष्ट ।
- २ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (३१) एफ डी (व्यय नियम)/६५ दिनांक १८-२-६५ द्वारा सन्निविष्ट ।
- ४ वित्त विभाग के आदेश नं० एफ १ (२६) एफ डी (व्यय नियम)/६४ दिनांक २०-३-६७ से प्रति स्थापित ।

- (1) वह या उसका परिवार या दोनों उस अवधि में, जिसका कि मकान किराया भत्ता वसूल किया गया है, उसी स्थान पर ही रह रहे थे जिससे कि वह छुट्टी पर खाना हुआ था अथवा जहाँ से कि उसका स्थानान्तरण हुआ था। अथवा
- (11) जिस अवधि का किराया भत्ता उठाया गया है उसमें प्राप्त भत्ते को किराये के व्यय के पूरा या अधिकांश अंश के रूप में देता रहा है।

टिप्पणीयाँ

(1) जब उपर्युक्त उप अनुच्छेद (11) के अधीन प्रमाण पत्र दिया जाय तो अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी या स्थानान्तरण करने वाला प्राधिकारी सेवा निदेश कर सकता है कि किराये भत्ते का अंश ही आहरित किया जायेगा। जब उक्त उप अनुच्छेद (1) या (11) के अधीन कोई प्रमाण पत्र दिया जाय तो ऐसा प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी को यह सन्तोष जनक उत्तर देने को कह सकता है कि वह यह बताये कि किराये के बिये गये खर्चों को वह रोक नहीं सकता था उसके लिए यह खर्चा रोझने में या टालने में उसका असमर्थता थी। यदि प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी के इस उत्तर से सन्तुष्ट न हो सके तो वह ऐसा भी निदेश कर सकता है कि किराये भत्ते का कोई अंश आहरित नहीं किया जायेगा।

1(11) अवकाश का अंश सब प्रकार के १२० दिन के अवकाश से है और यदि वास्तविक अवकाश की अवधि इससे अधिक हो तो प्रथम १२० दिन का अवकाश किन्तु इसमें असाधारण अवकाश, अध्ययन अवकाश सेवा निवृत्ति से पूर्व का अवकाश, मना किया गया अवकाश। या सेवान्त-अवकाश जो बाह्य नोटिस की अवधि के साथ चल रहा हो अथवा नहीं, आदि सम्मिलित नहीं है। जब विश्रामकाल या छुट्टियों को अवकाश के साथ मिला दिया जाय तो विश्रामकाल, छुट्टियों और अवकाश की समस्त अवधि को एक ही घंटे में लिया हुआ अवकाश माना जायेगा।

यह आदेश दिनांक १-३-६७ से प्रभावशील होगा

२ अवकाश का तात्पर्य सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश को छोड़ कर लिया हुआ रियायती अवकाश है। निम्न स्थितियों में मकान किराये भत्ते का एक वदस्तूर बना रहेगा —

- (अ) जब मूल अवकाश ४ माह की अवधि से आये बाद में बढ़ाया नहीं जाय, और यदि बढ़ाया ही जाय तो शारी अवकाश की अवधि ४ माह से अधिक नहीं हो एव
- (ब) जब मूल अवकाश या बढ़ाया हुआ अवकाश जो कि अनुच्छेद (अ) में संश्लेषित है चार माह से अधिक न होने पर फिर बाद में और बढ़ाया जाय और इस प्रकार कुल अवकाश ४ माह से अधिक हो जाय तो मूल अवकाश या चार माह के अवकाश से अधिक बढ़े हुए अवकाश की समाप्ति तिथि तक या बाद में बढ़ाये गये प्रथम अवकाश की स्वीकृति तिथि तक जिससे

कि सम्पूर्ण अवकाश की अवधि ४ माह से अधिक हो गई हो, दोना में से जो भी पहले हो ।

३ अस्थायी स्थानांतरण का तात्पर्य दूसरे स्टेशन पर ड्यूटी का बदल जाना है । जिसकी अवधि सामान्यता ४ माह से अधिक न होने पर ही भरती जाना है । इस नियम के प्रयोजनाथ इसमें प्रतिनियुक्ति भी सम्मिलित है । चार माह की सीमा के अधीन यदि अस्थायी ड्यूटी बाद में चार माह से आगे बढ़ाई जाय तो सम्पूर्ण मकान किराया भत्ता ड्यूटी के बढ़ाये जाने के आदेश की तिथि तक बदस्तूर ज्या का त्याग रहेगा ।

४ जब तक कि किसी मामले में स्पष्टतया अन्यथा प्रकार से प्रावधान न किया जाय, उपयुक्त सकेतिक टिप्पणी सरया २ एवं ३ की अवधि में कार्य ग्रहण अवधि भी शामिल की जा सकती है ।

आइटि सम्ब धी अनुदेश

१ (विलोपित)

राजस्थान सरकार का निर्णय

२ (विलोपित)

३५ उपयुक्त नियम का निहित उद्देश्य सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश की छोटकर इन नियमों की टिप्पणी २ में निर्धारित अवकाश की अवधि के दौरान सरकारी कम चारी के मकान किराये भत्ते के हक की प्रतिवधित करना है । अत अवकाश की स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारियों को शीघ्र ही सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के अवकाश के आदेशों की विशेष सावधानी के साथ जाँच करनी चाहिये और जहाँ कहीं किसी प्रकार से नियमों की अवहेलना करके ४ माह या इससे कम का अवकाश लेने का स्पष्ट उद्देश्य नजर आये और ऐसा दिखे कि केवल कुछ दिन ही ज्यूटा पर कर्मचारी वापस आकर सेवा निवृत्त होगा तो उन्हें सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश के अतिरिक्त अथ अवकाश देने से मना कर देना चाहिये ।

आइटि अनुदेश

*समस्त आतिया का निराकरण करने हेतु अवकाश या स्थानांतरण स्वीकृत करने वाले प्राधिकारियों को स्वीकृति आदेशों में इन नियमों के तहत एक प्रमाण पत्र सरकारी कर्मचारी के पद पर या स्थान पर वापस जाने की समाप्ति के सम्बन्ध में जेम्सी की स्थिति दर्शाता देना चाहिये ।

- १ वित्त विभाग की पर्वी १२५ म आदेश न० एफ १ (२६) एफ डी (व्यय नियम/६४) त्तिव १६ ७ ६४ द्वारा विनियमित ।
- २ वित्त विभाग के अधीन सरया एफ १ (२६) एफ डी (व्यय नियम)/६४ दिनांक २१-३-६४ द्वारा विनियमित ।
- ३ वित्त विभाग के आदेश सं० एफ ५ (१) एफ डी (ई. ए. ए.)/५९ त्तिव ११-१-६९ द्वारा विनियमित ।
- ४ वित्त विभाग के आदेश न० डी १६०६ एफ ११/५३ त्तिव १७-६-५३ द्वारा विनियमित ।

महालेखा निरोधक का नियम

१ (विलोपित)

राजस्थान सरकार का नियम

२१ जयपुर और जोधपुर में पद स्थापित सरकारी कर्मचारियों के नियम मकान किराया भत्ता स्वीकृति का विनियमित करने वाले नियम उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं जो दैनिक मजदूरी पर नियोजित किये गये हैं ।

२२ मासिक आधार पर भुगतान प्राप्त करने वाले निर्माण प्रसारित कर्मचारियों पर भी मकान किराये भत्ते के नियम लागू नहीं होते हैं ।

२३ एक प्रश्न यह उठा है कि नियमित किये गये सरकारी कर्मचारी को मकान किराया भत्ता कमूल करने के लिए कौन कौन से प्रमाण-पत्र आवश्यक होंगे तथा जिस कर्मचारी को निम्नान्वये के पदचान फिर से सेवा में लगा लिया जाता है और राजस्थान सेवा नियमों के नियम ५४ के अनुसार जिसका निम्नान्वयि को अवकाश पर बिताई गई अवधि मानें जाने का आदेश दे दिया जाता है तो उस कर्मचारी को मकान किराये भत्ते के लिए क्या प्रमाण-पत्र देने होंगे ।

यह नियम किया गया है कि ऐसे मामलों में सम्बद्ध सरकारों कर्मचारी से नियम २ के अधीन प्रमाण-पत्र मकान किराये भत्ते के सम्बन्ध में आवश्यक समझने करने से पूर्व प्राप्त किया जाना चाहिये यदि ऐसा प्रमाण-पत्र पहले ही प्राप्त न किया गया हो ।

५४ अवकाश से पूर्व या पदचान पढ़ने वाली छुट्टियाँ में मकान किराया भत्ता प्राप्त करने की उसी प्रकार विनियमित किया जाना चाहिए जिस प्रकार कि अवकाश के दौरान दिया जाता है । किन्तु अवकाश से छुट्टी पूर्व या पदचान न पढ़ने वाली छुट्टियाँ के दौरान मकान किराये भत्ते की स्वीकृति उसी प्रकार विनियमित की जायेगी जिस प्रकार की छुट्टी के समय पर की जाती है ।

५५ एक प्रश्न यह भी उठा है कि सरकारी कर्मचारी को काय ग्रहण अवधि (जोइनिंग टाइम) में भी क्या मकान किराया भत्ता दिया जाना चाहिये । इस विषय में यह नियम किया गया है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम १२७ के अनुच्छेद (अ) या (ब) के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर सरकारी कर्मचारी को काय ग्रहण अवधि के दौरान भी मकान किराया भत्ता दिया जा सकता है परन्तु तब यह होगा कि यदि दो पदा पर भत्ते की दरें मिलती हों तो सबसे कम दर पर ही यह भत्ता मिलेगा —

- १ वित्त विभाग की पर्वी १२५ में आदेश सकला एक १ (२६) एक डी (व्यय नियम)/६४ दिनांक १६-७-६४ द्वारा विलोपित ।
- २ वित्त विभाग के आपन मर्या एक ३५ (२८)-धार/५२ दिनांक २७-६-५२ द्वारा सन्निविष्ट
- ३ वित्त विभाग के आपन सत्या एक ३५ (१) एक II/५३ दिनांक २४-१-५३ द्वारा सन्निविष्ट ।
- ४ वित्त विभाग के आदेश नं० एक ७ ए (३२) एक डी (ए) नियम १५८ दि० २४-१०-५८ द्वारा गठित किया गया ।
- ५ वित्त विभाग के आपन सत्या एक १ (२६) एक डी (व्यय नियम)/६४ दिनांक १७-६-६४ द्वारा प्रतिस्थापित ।
- ६ वित्त विभाग के आदेश नं० एक १ (२८) एक डी (ए/नियम)/६१ दिनांक २३-८-६१ द्वारा सन्निविष्ट ।

- (i) पहली बात यह है कि सरकारी कर्मचारी को अपने पुराने पद पर भी मकान किराया भत्ता प्राप्त हुआ हो।
- (ii) स्थानान्तरण ऐसे दूसरे पद पर हुआ हो कि जिस पर यह भत्ता दिया जा सकता हो।
- (iii) किराये के लिये वस्तुतः उसने काय ग्रहण अवधि में खर्चा दिया हो जिससे कि यदि वह झूठी पर होता तो भत्ता प्राप्त करने का हकदार होता।

यह भी निम्न किया गया है कि यदि उपर्युक्त बातें पूरी हो जायें तो यह आवश्यक नहीं है कि सरकारी कर्मचारी को उस पद पर काय ग्रहण के दिन भी मकान किराया भत्ता प्राप्त हुआ हो जिस पर कि उसका स्थानान्तरण हुआ है ताकि वह कायग्रहण अवधि के लिये किराये भत्ता प्राप्त करने का हकदार हो सके।

प्रशासनिक अनुदेश

१ एक प्रश्न यह उठाया गया है कि कोई सरकारी कर्मचारी यदि अपनी पत्नी या बच्चों के मकान में रहता हो तो क्या उसे भी मकान किराया भत्ता पाने का हकदार माना जा सकेगा। ऐसे मामले में यह निर्णय किया गया है कि इसमें मकान किराए भत्ते की स्वीकृति इसको विनियमित करने वाले नियमों के अनुच्छेद ३ के अनुसार नियमित की जानी चाहिए अर्थात् परीया बच्चों का मकान किराया भत्ता स्वीकार करने के प्रयोजन हेतु सरकारी कर्मचारी का ही मकान माना जाना चाहिए।

स्पष्टीकरण

२ एक प्रश्न यह उठाया गया है कि कोई सरकारी कर्मचारी यदि किसी स्थान विशेष पर स्थान के आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा हो तो क्या उसे ऐसी पद स्थापन आदेश की प्रतीक्षा अवधि में मकान किराया भत्ता दिया जा सकेगा।

मामले पर विचार कर लिया गया है और यह स्पष्ट किया जाता है कि जो कि पद स्थापन के आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को झूठी ही माना जाता है अतः इस अवधि में किराया भत्ता स्वीकार्य होगा परन्तु धर्त यह है कि सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी नियमों के अधीन अवस्था प्रसार से भी किराया भत्ता पाने का हकदार हो।

आदेश

अधे आदेश दि० १ अक्टूबर १९६४ से प्रभावशील होंगे और दि० ११० १९६४ को किराया भत्ता सम्बन्धी दावों के विचाराधीन मामले इन आदेशों के अधीन ही विनियमित किए जावेंगे। सुरक्षा संगठनों में सरकारी कर्मचारियों को भर्ती होना हेतु प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित सुविधायें देने के आदेश लिए जाते हैं—

- १ यदि कोई व्यक्ति सरकारी मकान में रह रहा हो तो उसके परिवार को भी वाजिब किराए पर उसी मकान में रहने की इजाजत दी जा सकेगी।
- २ यदि किसी व्यक्ति को मकान किराया भत्ता मिल रहा है तो ऐसा भत्ता उसे दिया जाता रहेगा।

- १ वित्त विभाग के आदेश सं० एफ ३५(३१) धार/५२ दिनांक २१ ७ ५२ द्वारा सन्निविष्ट।
- २ वित्त विभाग के ज्ञापन सं० एफ (३८) एफ डी (व्यय नियम)/६४ दिनांक १६ १० ६४ द्वारा सन्निविष्ट।
- ३ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश सं० एफ ४ (७६) जी ए/ए/६२ जी धार १ दिनांक १२ ४ ६२ द्वारा सन्निविष्ट।

परिशिष्ट १८

‘प्रपत्र “अ”

अध्ययन-अवकाश पर रवाना होने वाले स्थायी सरकारी कमचारियों के लिये बंध-पत्र (बांड)

इन लेखों द्वारा सभी को विदित हो कि मे - निवासी
जिला वतमान में के कार्यालय में के रूप में नियोजित
राजस्थान सरकार को (जो एतद पश्चात् आगे सरकार कहलायेगी) मागे जाने पर
ह० की राशि (अको - ह०) सरकारी ऋण पर तत्समय
लागू एवं मागे जाने की तिथि से सरकारी दरों पर देय व्याज सहित भुदा करने के लिये
और यदि यह भुदायगी भारत के अलावा किसी और देश में होती है तो भारत और
उस देश के बीच तय की गई मुद्रा परिवर्तन की सरकारी दरों पर परिवर्तित उस देश
की मुद्रा में उक्त राशि के बराबर राशि लौटाने तथा सरकार द्वारा किये गये/किये
जाने सभी खर्चों एवं वकील और मुवक्किल के बीच तय किये गये महेनताने आदि सहित
लौटाने के लिये एतद द्वारा स्वयं को, अपने उत्तराधिकारियों को तथा निष्पादकों और
प्रशासकों को आवद्ध करता है।

यह आज दिनांक माह सन् एक हजार नौसी
को लिखा गया।

और चूंकि उक्त आवद्धकर्ता श्री को सरकार द्वारा अध्ययन-
अवकाश स्वीकृत किया गया है,

और चूंकि सरकार की उचित सुरक्षा हेतु आवद्धकर्ता इसमें आगे लिखी हुई
शर्तों पर इस बंध पत्र को निष्पादित करने के लिये सहमत होगया है

और उपयुक्त लिखित दायित्व की शर्त यह है कि उक्त आवद्ध कर्ता को
के अध्ययन अवकाश की समाप्ति या उसकी अवधि के खतम होने के बाद
ह्यूटी पर वापस उपस्थित हुए जिना सेवा से त्याग पत्र देने या सेवा निवृत्त होने या
ह्यूटी पर उपस्थित होने के वय बाद किसी भी समय ऐसा करने की स्थिति
में वह सरकार को या सरकार द्वारा निर्देश पाकर मागे जाने पर यथा निर्देश कथित
राशि ह० (अकेन ह०) मागे जाने की तारीख से इस पर
तत्समय सरकारी ऋण पर लागू सरकारी दर पर देय व्याज सहित शोध लौटायेगा।

और उपयुक्त आवद्धकर्ता श्री के इस प्रकार रूपया भुदा करने
पर यह लिखित दायित्व शून्य और निष्प्रभ हो जायेगा अन्यथा यह प्रभावकारी होगा
और पूरीतरह इस मामले में लागू माना जायेगा।

राजस्थान सरकार इस वध-पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क वहन करने को सहमत हो गई है ।

निम्न की उपस्थिति में यह

उपर्युक्त आवद्धकर्त्ता श्री

द्वारा सोपा गया और हस्ताक्षर किया गया

१ श्री

२ श्री " "

राजस्थान के राज्यपाल के लिए/और की ओर से द्वारा प्राप्त किया गया ।

अप्रपत्र "ब"

अध्ययन-अवकाश पर रहना होने वाले अस्थायी सरकारी कर्मचारियों के लिये वध-पत्र (घाट)

इन लेखों द्वारा सभी को विदित हो कि हम श्री

निवासी

जिला " वतमान में

के रूप में

के कार्यालय में नियोजित (जो इसमें एतद् पश्चात् आगे 'आभारी' कहलायेगा) की ओर से जामिन

श्री "पुत्र श्री

निवासी

एव श्री

पुत्र

श्री " निवासी

एतद् द्वारा सामूहिक रूप से और प्रथक् रूप से

स्वयं को, अपने पारस्परिक उत्तराधिकारियों, निष्पादकों और प्रशासकों को राजस्थान के राज्यपाल को जो (एतद् पश्चात् इसमें आगे 'सरकार' कहलायेगा) मागे जाने पर २० की राशि (अथवा २०) उस पर मागे जाने की तिथि से

सरकारी ऋण पर तत्समय लागू सरकारी दर पर देय व्याज सहित अदा करने और यदि यह अदायगी भारत के अलावा किसी अन्य देश में हो तो उस देश और भारत के बीच तय की मुद्रा-परिवर्तन की सरकारी दर पर परिवर्तित उस देश की मुद्रा में उक्त वधित राशि के बराबर राशि सौटाने तथा सरकार द्वारा किये गये/किये जाने वाले सभी एव वकील और मुवक्किल के वाच तय किये गये मेहनताने सहित सौटाने के लिये प्रावद्ध करते हैं ।

यह आज दिनांक

माह "

सन एक हजार नौवीं

की

शिला गया ।

और चू कि उक्त आवद्धकर्त्ता श्री

को सरकार द्वारा अध्ययन अवकाश

स्वीकृत किया गया है

और चू कि सरकार की उचित सुरक्षा हेतु आवद्ध कर्त्ता इसमें आगे लिखी हुई शर्तों पर इस वध-पत्र को निष्पादित करने के लिये महमत हा गया है,

और चू कि वधित श्री

और श्री

जामिन के रूप में उक्त

आवद्धकर्त्ता श्री

और श्री

जामिन के रूप में उक्त आवद्धकर्त्ता

श्री

की ओर से यह वध-पत्र निष्पादित कराने के लिये महमत हा गया है,

और उपर्युक्त लिखित दायित्व को जान यह है कि उक्त आवद्धकर्त्ता आभारी

श्री

" के अध्ययन अवकाश को समाप्ति या उसकी अवधि समाप्त हो

बाद ड्यूटी पर वापस उपस्थित हुए बिना सेवा से त्यागपत्र देने या ड्यूटी पर वापस उपस्थित होने क वष बाद किसी भी समय ऐसा करने की स्थिति में आभारी और जामिन सरकार को या सरकार द्वारा निर्देश पाकर मागे जाने पर यथानिर्देश कथित राशि रु० (अनेन रु०) इस पर तत्समय सरकारी ऋण पर लागू सरकारी दर पर देय व्याज सहित शोध लौटायेगे ।

और उपयुक्त कथित आवद्धकर्त्ता आभारी श्री तथा जामिन श्री
एव श्री के इस प्रकार रुपया भ्रदा करने पर उक्त लिखित दायित्व शू य और निष्प्रम हो जायेगा, अथवा यह प्रभावकारी होगा और पूरी तरह से इस मामले में लागू माना जायेगा ।

वर्तते कि इसके अधीन जामिनो की जिम्मेदारी सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समय को अवधि बढ़ा देने या किसी वरति जैसे कार्य करने या न करने से (चाहे यह जामिनो की राय या अनकारी से हो या बिना इसके हो) कभी भी न तो पानन ही हो जयेगी और न इससे उनके इस कार्य में कोई बाधा ही पड़ेगी और न सरकार को उक्त आवद्धकर्त्ता जामिनो श्री पर इसक अधीन देय राशि क निये मुकदमा चलाने से पूर्व कथित आभारी श्री के विरुद्ध मुकदमा चलाना ही जरूरी होगा ।

राजस्थान सरकार इस बंध पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क वहन करने के लिये सह मत हो गई है ।

निम्न की उपस्थिति में उपयुक्त नामांकित जामिन श्री द्वारा
सौंपा गया और हस्ताक्षर किया गया —

१

२

निम्न की उपस्थिति में उपयुक्त नामांकित जामिन श्री द्वारा सौंपा
गया और हस्ताक्षर किया गया ।

१

२

निम्न की उपस्थिति में उपयुक्त नामांकित जामिन श्री द्वारा सौंपा
गया और हस्ताक्षर किया गया ।

१

२

राजस्थान के राज्यपाल के लिये और/की ओर से द्वारा प्राप्त
किया गया ।

१ वित्त विभाग के आपन संख्या एक १० (१०) एफ-II/१३ दिनांक २८-४-९१ द्वारा
प्रतिस्थापित ।

'प्रपत्र 'म''

राजस्थान सेवा नियमों के नियम ६६ (ब) में शिथिलता देकर असाधारण अवकाश स्वीकृत किये गये अस्थायी सरकारी कमचारी के लिये
ब-घ-पत्र (बाण्ड)

इन लेखों द्वारा सभी को विदित हो कि हम श्री निवासि
जिला वतमान में के रूप में के कार्यालय/
विभाग में नियोजित (जो इसमें एतदपश्चात् भागे 'आभारी' कहलायेगा) और श्री
पुत्र श्री निवासी एव श्री पुत्र श्री
निवासी (जो इसमें एतदपश्चात् भागे 'जामिन' कहलायेगा) एतद्वारा
सामूहिक रूप से और पथक रूप से स्वयं को अपने पारस्परिक उत्तराधिकारियों
निष्पादकों और प्रशासकों को राजस्थान के राज्यपाल को (जो इसमें एतदपश्चात्
भागे "सरकार" कहलायेगा) उसके पद के उत्तराधिकारियों और प्रतिनिधियों को भागे
जाने पर ६० की राशि (अकेल रुपये) उस पर भागे जाने की तिथि से
सरकारी ऋण पर तत्समय लागू सरकारी दर पर देय व्याज सहित अदा करने और यदि
यह अदायगी भारत के अलावा किसी अन्य देश में हो तो उस देश और भारत के बीच
तय की गई मुद्रा परिवर्तन की सरकारी दर पर परिवर्तित उस देश की मुद्रा में उक्त
कथित राशि के बराबर राशि लौटाने तथा तथा सरकार द्वारा किये गये/किये जाने
वाले सभी खर्चों एवं वकील तथा मुवक्किल के बीच तय किये गये मेहनताने सहित
लौटाने के लिये आवद्ध करते हैं।

श्री क मरकार ने के रूप में नियोजित उक्त आभारी श्री/श्रीमती/
कुमारो को नियमित अवकाश के पश्चात् माह दिन की
अवधि का अवैतनिक एवं भर्त्ता रहित असाधारण अवकाश दिनांक से आभारी
के निवेदन पर स्वीकार किया है ताकि वह में अध्ययन कर सके

और श्री कि सरकार को/ने श्री/श्रीमती/कुमारी के असाधारण अवकाश
की अवधि में के पद की ड्यूटी पूरी करने के लिये एक स्थानापन्न नियुक्त
करना पड़ेगा/कर दिया है,

और श्री कि सरकार के उचित सरक्षण के लिये उक्त आभारी दो जामिनो सहित
इसमें भागे लिखी हुई शर्तों सहित यह बंध पत्र निष्पादित करने के लिये सहमत हो
गया है,

और श्री कि कथित जामिन आभारी को ओर से जामिनो के रूप में यह बंध पत्र
निष्पादित करने के लिये सहमत हो गये हैं,

अतः अब इस उक्त लिखित दायित्व की शर्तें यह हैं कि उक्त आभारी श्री/
श्रीमति/कुमारी के असाधारण अवकाश की अवधि समाप्त होने पर उसके द्वारा

मूलतः धारित पद पर पुनः उपस्थित होने और पुनः उपस्थित होकर सरकार की ऐसे अवधि तक जा वष से अधिक नहीं होगी सरकार की इच्छानुसार सेवा करने में असफल होने की स्थिति में या सरकार द्वारा चाहे जाने पर किसी अन्य हैसियत से ऐसे वेतन पर जिसे पाने का कि वह नियमानुसार हकदार हो सरकार की सेवा करने से मना करने पर कथित आभारी श्री/श्रीमनी/कुमारी या उनके उत्तराधिकारी निष्पादक और प्रशासक माने जाने पर सरकार को रुपये की कथित राशि उम पर सरकारी ऋण पर समय समय पर लागू सरकारी दर पर देय व्याज सहित तुरन्त भुगत करेगा।

तथा उक्त कथित आभारी श्री या जमिन श्री एव श्री के इस प्रकार भुगतान करने पर उक्त लिखित दायित्व शून्य और निष्प्रभव हो जायेगा अथवा यह सब प्रकार प्रभावकारी होगा और पूरीतरह से इस मामले में लागू माना जायेगा।

वर्तते कि इसके अधीन जामिनो की जिम्मेदारी सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समय की अवधि बढ़ा देने या किसी विरति जैसे कार्य करने या न करने से चाहे यह जामिनो की राय या जानकारी से हो या इसके बिना हो, कभी भी न पालन ही हो जायेगा और न इससे उनके इस कार्य में बाधा ही पड़ेगी और न सरकार का उक्त जामिना श्री और श्री के विरुद्ध, मुकदमा चलाने से पूर्व आभारी के विरुद्ध मुकदमा चलाना ही जरूरी होगा।

यह वध पत्र सभी मामलों में तत्समय प्रभावशील राजस्थान के कानूनों से ही नियंत्रित होगा और इसके अधीन तमाम अधिकार और जिम्मेदारियां, जहां आवश्यकता पड़ेगी, राजस्थान की उपयुक्त न्यायालयों द्वारा तदनुसार ही अवधारित की जायेंगी।

इस दस्तावेज पर देय स्टाम्प शुल्क सरकार द्वारा ही वहन किया जाकर भुगतान किया जायेगा।

यह आज दिनांक माह सन् एक हजार नौ सौ को हस्ताक्षरित किया गया।

श्री की उपस्थिति में उपयुक्त नामांकित आभारी
 श्री द्वारा हस्ताक्षरित किया गया और सौंपा गया।
 श्री की उपस्थिति में उपयुक्त नामांकित जामिन
 श्री द्वारा हस्ताक्षरित एवं अर्पित किया गया।
 श्री की उपस्थिति में उपयुक्त नामांकित जामिन
 श्री द्वारा हस्ताक्षरित एवं अर्पित किया गया।

राजस्थान सरकार के लिये और उसकी ओर से श्री द्वारा प्राप्त किया गया।

परिशिष्ट १६

राजस्थान सेवा नियमों के अधीन अवकाश के लिये प्रार्थना-पत्र

- १ प्रार्थी का नाम
- २ धारित पद
- ३ विभाग, कार्यालय तथा अनुभाग
- ४ वेतन
- ५ मकान किराया भत्ता, सवारी भत्ता या वर्तमान पद पर प्राप्त अन्य कोई क्षतिपूर्ति भत्ता—
- ६ अवकाश की किस्म और अवधि तथा वह तिथि जिससे अवकाश चाहिये
- ७ रविवार और अन्य छुट्टियाँ जो अवकाश के पूर्व या पश्चात् अवकाश में सम्मिलित की जानी हों—
- ८ कारण, जिनसे अवकाश लिया जा रहा है
- ९ पिछलीवार अवकाश से लौटने की तिथि तथा उस अवकाश की किस्म और अवधि—
- १० (अ) मैं अपने रियायती अवकाश/रूपांतरित अवकाश की अवधि के दौरान प्राप्त अवकाशसवेतन और अर्द्ध वेतन अवकाश में स्वीकार्य राशि के अंतर को वापस करने का भी वचन देता हूँ यह अर्द्ध वेतन-अवकाश में स्वीकार्य राशि वह है जो राजस्थान सेवा नियमों के नियम ६३ के उप नियम (स) के अनुच्छेद (iii) के नीचे दिये हुए परन्तुक के प्रावधानों के मेरे अवकाश की अवधि के दौरान या समाप्ति पर सेवानिवृत्ति की स्थिति में लागू न किये जाने पर मुझे स्वीकार्य न होती ।
- (ब) मैं अनर्जित अवकाश की अवधि में प्राप्त अवकाशसवेतन को भी वापस करने का वचन देता हूँ जो मेरे इस अवकाश के दौरान या इसकी समाप्ति पर स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की स्थिति में राजस्थान सेवा नियमों के नियम ६३ (द) के लागू न किये जाने पर मुझे स्वीकार्य नहीं होता ।
- ११ अवकाश में पता

प्रार्थी के हस्ताक्षर दिनांक सहित

१२ नियंत्रण-अधिकारी की अभ्युक्तियाँ और/या सिफारिश

हस्ताक्षर (तारीख सहित)

पद

अवकाश की स्वीकार्यता के लिये प्रमाण-पत्र

(यह राजपत्रित अधिकारियों के मामलों में महालेखाकार द्वारा दिया जाना है)

१३ प्रमाणित किया जाता है कि _____ के नियम _____ के
अधीन दिनांक _____ से दिनांक _____ तक
दिन का _____ अवकाश स्वीकार्य है।
(अवकाश की विस्तृत) _____

हस्ताक्षर (दिनांक सहित)
पद _____

*१४ स्वीकृति कर्त्ता प्राधिकारी के आदेश।

हस्ताक्षर (दिनांक सहित)
पद _____

यदि प्रार्थी को कोई क्षतिपूर्ति भत्ता मिल रहा हो तो स्वीकृति कर्त्ता प्राधिकारी को यह भी उल्लेख करना चाहिये कि प्राया अवकाश की समाप्ति पर प्रार्थी उसी पद पर वापस लौटेगा या किसी अन्य ऐसे पद पर जिस पर कि ऐसा भत्ता दिया जा सकता है।

परिशिष्ट २०

राजस्थान सरकार का निर्णय

महामहिम राजप्रमुख सहृदय आदेश प्रदान करते हैं कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल किशनगढ़ के सभी प्रशिक्षणार्थियों (राजपत्रित और भराजपत्रित दोनों) को प्रति वर्ष छून के महिने में एक माह का विश्राम काल दिया जा सकेगा, यदि यह छून का महिना प्रशिक्षण के बीच पड़ता हो बशर्ते कि यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एक मई के बाद प्रारम्भ न होता हो या ३१ जुलाई के बाद समाप्त न होता हो। तथापि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल किशनगढ़ को विश्रामकालीन विभाग नहीं माना जायेगा और वहाँ का सारा कमचारी वर्ग इस विश्रामकाल में छुट्टी पर उपस्थित रहेगा।

इस विश्रामकाल की स्वीकृति से प्रशिक्षणार्थियों के राजस्थान सेवा नियमों के अन्धीर सामान्यतया स्वीकार्य अवकाशों के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद २ में दी गई यह रियायत प्रशिक्षणार्थियों को उनके प्रशिक्षण के दौरान अति धनसाध्य और कठिन छुट्टी को ध्यान में रखकर एक विशेष प्रकरण समझकर दी गई है।

परिशिष्ट २१

राजस्थान सरकार

नियुक्ति (ग) विभाग

प्रेषक—शासन उप-सचिव
राजस्थान सरकार

प्रेषितो—महालेखाकार
राजस्थान जयपुर

दिनांक, २४ जून १९५४
जयपुर

विषय—ख तथा ग श्रेणी के राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये अधिकारियों की नियुक्ति की शर्तें।

प्रसंग—इस विभाग का ज्ञापन सख्या एफ २ (२१) नियुक्तियां।
(ग)/५०, दिनांक २१-१२-१९५०

क्रमांक एफ ९ (१) नियुक्तियां (ग)/५४—भारत सरकार ने 'क' श्रेणी के राज्यों या केन्द्र से 'ख और ग' श्रेणी के राज्यों में प्रति-नियुक्ति पर भेजे हुए अधिका-रियों की नियुक्ति के लिए पहले शर्तों में संशोधन कर लिया है। भारत सरकार के इस विषय में जारी किये हुए परिपत्र सख्या एफ ४ (३६)—एस/५२ दिनांक १३ मई १९५४ जिसमें उक्त कथित शर्तें निहित हैं सूचनाएं एवं आवश्यक कार्य-वाही हेतु इसके साथ सलान है।

मोहन मुखर्जी
शासन उप सचिव
राजस्थान सरकार

भारत सरकार

राज्य-मंत्रालय, नई दिल्ली (२)

दिनांक १३ मई १९५४

प्रेषक—प्रवर शासन सचिव, भारत सरकार राज्य मंत्रालय नई-दिल्ली (२)

प्रेषितो—मुख्य सचिव, सौराष्ट्र सरकार/मध्य प्रदेश/राजस्थान/पिप्पू/द्रावनवीर-कोचीन/हैदराबाद/मैसूर/जम्मू और काश्मीर/हिमाचल-प्रदेश/विध्य प्रदेश/भोपाल।

मुख्य प्रायुक्त विलासपुर, शिमला
मुख्य सचिव, कच्छ गुज

विषय—ख तथा ग श्रेणी के राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये अधिकारियों की नियुक्ति की शर्तें।

प्रमाण एक ४ (३६) एस/५२—मुक्त यह कहने का निर्देश हुआ है कि क' और/या क' श्रेणी के राज्या से 'ख' श्रेणी के राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे हुए अधिकारियों की नियुक्ति की शर्तों पर इन राज्यों की राजनतिक-संरचना तथा सेवाओं के पुनर्गठन और ख श्रेणी के राज्यों द्वारा सेवाओं के एकीकरण आदि के मामला में की गई प्रगति को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार किया गया है। वत इस मंत्रालय के पत्र संख्या एक २४ (१७) एस/५० दिनांक ५ दिसम्बर १९५० में निहित प्रादेश के अधिकरण में राष्ट्रपति सहर्ष निणय करते हैं कि अब ये उक्त शर्तें निम्न प्रकार होंगी -

(1) एक समय पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया एक वर्ष की स्वीकृत होगी।

(ii) 'ख' श्रेणी के राज्यों में प्रतिनियुक्त जिन अधिकारियों को ऐसी प्रतिनियुक्ति से पूर्व न तो, वरिष्ठ-समय-वेतन मान में पद स्थापित किया गया था और न जिन्हें अब ऐसे वरिष्ठ समय वेतन मान के पद पर स्थापित ही किया गया है उन्हें अपने ग्रेड वेतन के प्रतिरिक्त वर्तमान सेवा में अपने ग्रेड वेतन के २०% के बराबर प्रतिनियुक्ति-विशेष-वेतन दिया जायेगा (इसमें प्राप्त किया जा रहा विशेष वेतन, यदि कोई हो सम्मिलित नहीं होगा) किंतु यह विशेष वेतन अधिकतम ३०० रु० ही होगा।

(iii) यदि प्रतिनियुक्ति के समय किसी अधिकारी को कोई विशेष वेतन मिल रहा था तो प्रतिनियुक्ति की अवधि में भी उसे यह वेतन केवल तभी ५/५ जाता रहेगा जबकि उस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति के समय उसकी मूल सरकार यह प्रमाणित कर कि यदि इस अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जाता तो उसे यह विशेष वेतन यत्ति संगत अवधि तक दिया जाता रहता। तथापि यह विशेष वेतन उसका व्यक्तिगत वेतन माना जायेगा किंतु भविष्य में दी जानेवाली वेतन-वृद्धि में इसे समाविष्ट नहीं किया जायेगा।

(iv) इन अधिकारियों को जिस राज्य से प्रतिनियुक्त किया जा रहा है उसी के प्रभावशील नियमों से इन्हें दिये जाने वाले महंगाई भत्ते को भी विनियमित किया जायेगा।

(v) इन अधिकारियों को कोई निशुल्क आवास गृह नहीं मिलेगा और न निशुल्क कार ही दी जा सकेगी और न सरकारी खर्चों पर इन्हें कोई सवारी ही तब तक दी जा सकेगी जब तक कि ऐसी सुविधायें सेवा की शर्तों के अनुसार उस पद से सम्बन्ध नहीं होंगी। जिस पर कि उक्त प्रतिनियुक्त किया गया है। जिस राज्य में अधिकारी का स्थानांतरण किया गया है उसके नियमों के अनुसार इन अधिकारियों से किराया वसूल किया जायेगा।

२ ये आदेश उन अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे जो या तो अपने स्थानान्तरण से पूर्व वरिष्ठ समय-वेतन मान के पद धारण किये हुए थे या जिन्हें अब ऐसे वरिष्ठ

समय वेतन मान व पदा पर स्थाना भरित किया गया है। ऐसे प्रत्येक मामले में उसके महत्व के अनुसार ही प्रतिनियुक्ति की शर्तें तय की जानी चाहिये।

३. इस पत्र में स्वीकृत सशोधित शर्तें नये प्रतिनियुक्ति के या प्रतिनियुक्ति के नवीकरण के मामले में लागू होंगी। पहली शर्तों पर प्रतिनियुक्ति पर अभी भी लगे-हुए अधिकारियों के मामले में उनकी प्रतिनियुक्ति की चालू अवधि के समाप्त होने तक वर्तमान शर्तें ही लागू होती रहेंगी।

४. मुझे यह और कहना है कि ऐसे अधिकारियों की 'ख' श्रेणी के राज्यों में स्थानान्तरण पर की गई यात्राया और इन राज्यों से प्रतिनियुक्ति की पदावनति पर की गई यात्राया के लिये यात्रा भत्ता उनके मूल राज्य के यात्रा भत्ता नियमों से नियंत्रित होना चाहिये या जिस राज्य में उन्हें भेजा गया है उसके यात्रा-भत्ता नियमों से विनियमित होना चाहिये, यह प्रश्न विचाराधीन है और इस पर निर्णय किया जाने वाला है, अतः ऐसे प्रत्येक मामले में प्रतिनियुक्ति को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व इस प्रश्न को विचाराधान रहने तक मूल सरकार के परामर्श से तय किया जाना चाहिये।

५. ये आदेश केन्द्र और/या क श्रेणी के राज्यों से 'ख' श्रेणी के राज्यों में प्रतिनियुक्ति ऐसे अधिकारियों पर भी लागू होंगे जो अपनी प्रतिनियुक्ति से पूर्व न तो परिष्कृत समय-वेतन मान वाले पद धारण किये हुए थे और न उन्हें ऐसे पदों पर अब प्रतिनियुक्ति ही किया गया है।

६. त्रिपुरा और मनीपुर राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की शर्तों के सम्बन्ध में अलग से आदेश जारी किये जा रहे हैं।

आपका सद्भावी
हस्ताक्षरित—जे सी घोषाल
अवर शासन सचिव
भारत-सरकार

सहित एक ऐसा बन्ध-पत्र निष्पादित करे जिससे कि कथित मृतक श्री की कुल वाजिब देय राशि के होने वाले तमाम दावों की क्षतिपूर्ति दावेदार करे और उसके बाद सरकार से इस राशि को पाने का कोई और हकदार बनकर भाये तो सरकार की क्षतिपूर्ति हो सके एवं ऐसा बन्ध पत्र निष्पादन करने के बाद ही दावेदार को उक्त कथित राशि दी जाय,

अतः अब इस बन्ध-पत्र की शर्त यह है कि यदि उक्त कथित राशि दावेदार को अदा कर देने के बाद सरकार के विरुद्ध इस राशि का दावा करने के लिये कोई व्यक्ति खड़ा हो तो दावेदार या उसके जामिन रु० की कथित राशि सरकार को वापस लौटायेगा या किसी अन्य प्रकार इस कथित राशि के लिये सरकार की क्षतिपूर्ति करेगा/करेंगे ताकि सरकार पर इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व न रहे और ऐसी स्थिति आने पर सरकार को कोई हानी न हो सके और यदि उक्त कथित राशि के सम्बन्ध में सरकार के विरुद्ध कोई दावा किया जाय तो उस दावे के लिये सरकार को मुकदमों का खर्चा न देना पड़े और यह खर्चा ऐसी स्थिति आने पर दावेदार या उसके जामिन स्वयं वहन करेंगे। अतः यदि इस प्रकार किसी दावे के विरुद्ध सरकार को मुकदमे में अपना बचाव करने की स्थिति आये तो यह बन्ध-पत्र या इसमें अंकित आभार पूरी तरह दावेदार या उसके जामिनो पर लागू होगा अन्यथा ऐसी स्थिति न आने पर यह निष्प्रभावी माना जायेगा।

अतः उपर्युक्त लिखित बन्ध पत्र और शर्तों के साक्ष्य स्वरूप हम
 और और आज दिनांक माह
 सन् को इस पर अपने स्वयं के हस्ताक्षर अंकित करते हैं।

परिशिष्ट २४

स्थायी अन्तिम वेतन-प्रमाण-पत्र

I प्रमाणित किया जाता है कि श्री पद विभाग में
दिनांक के पूर्वाह्न/मध्याह्न में सेवा निवृत्त हुए और उह उनके वेतन इस
प्रकार भुगतान कर दिये गये हैं —

स्थायी वेतन	र० मासिक की दर से दि०	से दि०	तक
अवकाश वेतन	र० मासिक की दर से दि०	से दि०	तक
विशेष वेतन	र० मासिक की दर से दि०	से दि०	तक
महंगाई भत्ता	र० मासिक की दर से दि०	से दि०	तक
नोटिस वेतन	र० मासिक की दर से दि०	से दि०	तक

उहें दिनांक से दिनांक तक दिन का एक नोटिस दिया गया और उन्होंने इस अवधि में वास्तव में विभाग में कार्य किया। काय नहीं किया।

जहां तक ज्ञात है उन पर बकाया राशि (नीचे के अनुच्छेद III) में दर्ज की गई है और यह राशि उनसे वसूल की जानी है।

II यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उहें दिनांक से दिनांक तक वेतन " र० और महंगाई भत्ता " र० की दर से दिया जाना है।

इस प्रकार उन्हें देय राशि को उनकी भुगतान कर दिया जायेगा या उन पर बकाया और अनुच्छेद III में नीचे दर्ज की हुई राशि के प्रति समायोजित कर लिया जायेगा या उस राशि के प्रति समायोजित कर दिया जायेगा जो बाद में कभी भी उन पर बकाया पाई जायेगी।

उनका स्थायी अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र यथा समय जारी कर दिया जायेगा। इस अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र या स्थायी अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र के सदृश में या प्रागे कोई और बकाया पाई जाने वाली राशि को उनकी पेशान प्रेबुडटी या किसी अन्य देय राशि में से वसूल करने के लिये उनकी लिखित सहमति इसके साथ सलग्न की जा रही है।

III भव तक ज्ञात बकाया राशि का विवरण इस प्रकार है —

--- -- --
--- -- --
--- -- --

कार्यालयाध्यक्ष
(राजपत्रित अधिकारियों के मामले में महालेखाकार)

परिशिष्ट २५

अवकाश या अस्थायी स्थानांतरण के दौरान सवारी-भत्ता वसूली को नियन्त्रित करने हेतु नियम-

१ राजस्थान सेवा नियमों के नियम ४२ के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार सहर्ष निम्नलिखित नियम अवकाश या अस्थायी स्थानांतरण के दौरान सवारी भत्ता वसूल करने के लिये बनाती है—

२ मोटर या साईकल—मोटर-कार या मोटर साईकल रखे जाने की शर्त पर स्वीकृत किया हुआ सवारी-भत्ता निम्न स्थितियों में स्वीकार्य नहीं होगा—

(अ) काय ग्रहण अवधि, अवकाश अवधि और अस्थायी स्थानांतरण की अवधि के दौरान तथा अवकाश और काय ग्रहण अवधि के पूर्व या पश्चात पड़ने वाली छुट्टियों के दौरान।

(ब) सरकारी कर्मचारी द्वारा रखी गई मोटर कार या मोटर-साईकल एक समय में १५ दिन तक प्रयोग में न आये या इतने दिनों तक पराव पड़ी रहे या इनका उपयोग इतने दिनों तक सरकारी यात्राओं के लिये न किया जाय या किसी अन्य कारण से इतने दिनों तक इनका उपयोग न हो तो इस अवधि के दौरान,

३ राजस्थान सरकार का निर्णय

अवकाश या अस्थायी स्थानांतरण की अवधि में सरकारी कर्मचारियों को साईकल भत्ता दिया जाय अवकाश नहीं इस विषय का प्रश्न पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है। इस मामले की जांच की गई है और यह तय किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को अपनी स्वयं की साईकल रखने या सरकार द्वारा दी गई साईकल रखने के लिये स्वीकृत साईकल भत्ता १५ दिन से अधिक अवकाश की अवधि या अस्थायी स्थानांतरण या कार्यग्रहण अवधि में जसी भी स्थिति हो स्वीकार्य नहीं होगा।

किन्तु वे पुराने मामले जितना निपटारा इस प्रकार न करने किसी अन्य प्रकार किया गया हो दुबारा नहीं देखे जायेंगे।

४२ घोड़ा या अन्य जानवर—घोड़ा या अन्य-जानवर रखे जाने की शर्त पर स्वीकृत भत्ता अवकाश या अस्थायी स्थानांतरण पर भी अवधि के दौर में भी दिया

१ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ४(३८६)एफ II/५२ दिनांक ३-८-५३ द्वारा सन्निविष्ट।

२ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ ८ ए(२) एफ को नियम/४६-II दिनांक ३१-७-६२ द्वारा सन्निविष्ट। यह दिनांक ३१-७-६२ से प्रभावशाली होगा।

३ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १ (२०) एफ को (व्यय नियम/६३) दिनांक १-१०-६३ द्वारा सन्निविष्ट।

४ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ (२२) एफ-डी (व्यय-नियम)/६४ दिनांक १८-५-६५ द्वारा सन्निविष्ट।

जा सकता है वशत कि सरकारी कमचारी यह प्रमाणित करे कि उसने जिस अवधि का यह भत्ता प्राप्त किया है उसमें भी उक्त जानवर रखा है और प्राप्त भत्ते की राशि को इस जानवर के समारक्षण पर हो व्यय किया है।

यह प्रादेश दिनांक १६ ४ ६४ से प्रभावशील होगा।

(१) सवारी रखा जाना अपरिहाय होने पर भत्ता किस प्रकार विनियमित होगा—जब माटर गाड़ी या घोड़ा या अन्य जानवर रखे जाने के दायित्व से सवारी-भत्ता सम्बद्ध नहीं होता यह अवकाश या अस्थायी स्थानान्तरण की अवधि में स्वीकाय नहीं होगा।

टिप्पणी

१ अवकाश का तात्पर्य यहाँ सेवा निर्वात से पूर्व अवकाश के प्रतिरिक्त चार महीने तक की अवधि के लिये हुए अवकाश से है। क्षतिपूर्ति भत्ते का हक निम्न स्थितियों में ज्यों का त्यों रहेगा—

(1) जब प्रारम्भिक चार माह तक का अवकाश बाद में बढ़ाया नहीं जाय या यदि बढ़ाया जाय तो इसकी कुल अवधि ४ माह से अधिक न हो।

(2) जब उक्त उप अनुच्छेद (1) में निर्दिष्ट चार महीने तक का प्रारम्भिक अवकाश बाद में बढ़ाया जाय और इस प्रकार कुल अवकाश की अवधि बढ़े हुए या प्रारम्भिक चार महीने तक के अवकाश की समाप्ति तिथि तक चार महीने से ज्यादा हो या पहल बाद में बढ़ाये हुये उस अवकाश की स्वीकृति तिथि तक जिसके कारण कि कुल अवकाश की अवधि चार माह से अधिक हो जाती है, दोनों में से जो भी पहले हो।

(जब विधायकाल की अवकाश के साथ मिलाया जाय तो विधायकाल और अवकाश की कुल अवधि को अवकाश का एक ही दौर समझा जाना चाहिये)।

(२) इस टिप्पणी में परिभाषित अवकाश में असाधारण अवकाश भी सम्मिलित है।

२ अस्थायी स्थानांतरण का तात्पर्य किसी अन्य स्थान पर झूटी के लिये ऐसी अवधि के स्थानांतरण से है जो चार महीने से अधिक न हो। इन नियमों के प्रयोजनाय इसमें प्रतिनिधुक्ति भी शामिल है। चार महीने की सीमा के प्रधान वाले नियम में अगर अस्थायी झूटी की बाद में चार महीने से अधिक बढ़ाया जाय तो इस अवधि का बढ़ाने के प्रादेशों की तिथि तक क्षतिपूर्ति भत्ते का हक ज्यों का त्यों बना रहगा।

(इस टिप्पणी में दी हुई चार माह की अवधि में कार्य ग्रहण अवधि का भी सम्मिलित किया जा सकता है)

१ आर्किट अनुदेश

और

महानेखा पराक्षव का निर्णय (जिलोयित)

परिशिष्ट २६

वित्त-विभाग

राज-पत्रित अधिकारियों के वेतन, अवकाश सवेतन आदि के सम्बन्ध में
भारत दर्शन हेतु अनुदेश

टिप्पणी

ये अनुदेश वर्तमान नियमों और आदेशों पर आधारित हैं और राजपत्रित अधिकारियों की
सुविधा हेतु जारी किये जाते हैं। तत्सम्बन्धी सम्बद्ध नियमों और इन अनुदेशों में यदि कहीं विरोध
जान पड़े या दोनो में कहीं विरोधाभास की स्थिति बन जाय तो वही तत्सम्बन्धी सम्बद्ध नियम ही
लागू होंगे।

I राज-पत्रित पद पर नयी नियुक्ति होने पर —

(अ) यदि अधिकारी नया प्रवेशी हो तो — निम्नलिखित बातों की पूर्ति होने
पर ही उसकी वेतन पर्ची (पेस्विप) जारी की जायेगी —

- (1) जिस पद पर नियुक्ति की गई है वह एक स्वीकृत पद हो और वह रिक्त
भी होना चाहिये।
- (ii) नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा राज-पत्रित पद पर नियुक्त किये जाने
वाले व्यक्ति का नियुक्ति-आदेश जारी किया जाना चाहिये और यह आदेश
भी वेतन पर्ची के लिये अनिवार्य है।
- (iii) सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा राजपत्रित पद का कार्यभार सभालने की रिपोर्ट
महालेखाकार राजस्थान को भेजी जानी चाहिये (इसका प्रपत्र अनुलग्नक
क" पर सलग्न है)। इस रिपोर्ट में कार्यभार सभालने की तिथि और
पूर्वाह्न या मध्याह्न, जो भी हो समय अंकित किया जाना चाहिये। इसमें
अधिकारी का नाम भी मोटे अक्षरों में अंकित किया जाना चाहिये।

टिप्पणी

कोषागार में अपना प्रथम वेतन बिल भेजते समय अधिकारी को ठसम अपना स्वास्थ्य
प्रमाण पत्र भी सलग्न करना चाहिये।

(ब) यदि अधिकारी को अराजपत्रित-पद से राज-पत्रित (पद पर पदोन्नत किया
गया हो तो —

- (1) उसका वेतन या भत्ता प्राप्त करने के लिये वेतन पर्ची तभी मिल सकेगी
जब कि उपर (अ) (i), (ii) (iii) में अंकित सभी बातों की पूर्ति कर दी
जायेगी।

- (ii) अब तक जिस अधिकारी द्वारा उठाया गया था उससे अपना प्रतिम वेतन प्रमाण-पत्र प्राप्त करके यथाशीघ्र महालेखाकार, राजस्थान को भेजा जाना चाहिये ।
- (iii) अपने पिछले कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अवकाश का अद्यावधिक हिसाब पूरा भरवाकर लिखित रूप में महालेखाकार राजस्थान को यथाशीघ्र भिजवाया जाना चाहिये ।

(स) किसी अन्य राज्य या केन्द्रीय सरकार के अधीन राज-पत्रित पद धारण किये हुए हो यदि राजस्थान में प्रतिनियुक्ति पर आना पड़ा हो तो — राजस्थान के महालेखाकार से अपनी वेतन-पर्ची प्राप्त करने के लिये नियमानुसार करना चाहिये —

- (1) आपको यह बात अच्छी तरह निश्चित पता कर लेनी चाहिये कि जिस पद पर आपको पदास्थापित किया गया है वह एक स्वीकृत और रिक्त पद है ।
 - (ii) इस बात का सुनिश्चयन हो जाना चाहिये कि दोनों सरकारों के बीच आपका प्रतिनियुक्ति की शर्तें अच्छी तरह तय करली गई हैं और महालेखाकार राजस्थान को इनसे पूरी तरह अवगत करा दिया गया है ।
 - (iii) ऊपर (1) में जसा अंकित है उसके अनुसार ही आपको अपनी काय-भार सभाल लेने की सूचना और इसकी रिपोर्ट (चाज रिपोर्ट) महालेखाकार राजस्थान को तुरन्त भेज देना चाहिये ।
 - (iv) अपने पिछले आडिट अधिकारी अर्थात् जिस राज्य से आप प्रतिनियुक्ति पर आये हैं उसके महालेखाकार को लिखें कि वे आपकी निम्नलिखित चीजें महालेखाकार राजस्थान को यथाशीघ्र भेजे —
 - १ वहां के महालेखाकार द्वारा पूरी तरह प्रति हस्ताक्षरित आपका अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र ।
 - २ आपका सेवा विवरण ।
 - ३ आपका अवकाश का लेखा (हिसाब) ।
- यदि यहाँ मान सं पूर्व आप अपने उस राज्य में आराज पत्रित पद पर थे और वहाँ से राजस्थान में प्रति नियुक्ति पर आप राज-पत्रित पद पर आये हैं तो अपने पिछले कार्यालयाध्यक्ष को लिखिये कि वे आपका अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र तैयार करके प्रति हस्ताक्षरित वहाँ के महालेखाकार को भेज दें ताकि महालेखाकार उसे प्रतिहस्ताक्षर करके यहाँ भेज पित कर सकें । अपने पिछले कार्यालयाध्यक्ष को यह भी निवेदन करें कि वे आपका अवकाश का लेखा अद्यावधिक तैयार करके सीधा इसी कार्यालय में भेज दें ।

II. एक राज-पत्रित पद से दूसरे राज-पत्रित पद पर स्थानान्तरण होने पर —

(म) यदि दोनों ही पद एक ही जिले में हों और इससे उस कोषागार में कोई परिवर्तन नहीं होता हो जहाँ से कि आपका वेतन उठाया जाना है तो —

- (1) अपना काय-भार पिछले पद से सौंपने और नये पद पर काय भार सभालने (दोनों की) रिपोर्टें यथा शीघ्र भिजेवाइये ।
- (11) यदि आपका स्थानान्तरण उक्त स्थिति के अतिरिक्त किसी अन्य हैसियत में हुआ हो तो आप अपने नये पद पर पुरानी दरो से प्राप्त वेतन न उठाइये और महालेखाकार राजस्थान से अपनी वेतन पर्ची प्राप्त करने की प्रतीक्षा कीजिये और जब वेतन पर्ची प्राप्त हो जाये तभी अपना वेतन उसके आधार पर उठाइये ।
- (111) यदि आपका स्थानान्तरण उसी स्थिति (हैसियत) में हुआ है जिन स्थिति में आप पहले थे तो अपनी पुरानी दरो पर ही अपना वेतन उठाइये ।
- (ब) यदि इस स्थानान्तरण से आपके वेतन भुगताने वाले कोषागार में भी परिवर्तन होता हो तो —
- (1) उक्त (अ) (1) में लिखे अनुसार अपनी कायभार सौंपने और नये पद का काय भार सभालने की रिपोर्टें तुरन्त भेजिये ।
- (11) पिछले कोषागार से अपना अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र प्राप्त कीजिये और,
- १ यदि स्थानान्तरण उसी स्थिति में हुआ हो तो अपना वेतन इस अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर नये कोषागार से अपना वेतन उठायें ।
- २ यदि स्थानान्तरण किसी भिन्न स्थिति में हुआ हो तो नये पद पर अपना वेतन तब तक न उठाइये जब तक कि आपकी वेतन पर्ची महालेखाकार राजस्थान से प्राप्त न हो जाय ।
- (स) यदि स्थानान्तरण किसी अन्य राज्य में हुआ हो तो —
- (i) कृपया अपना काय भार सौंपने की रिपोर्ट महालेखाकार राजस्थान को भेजिये ।
- (11) कृपया अपने अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र की एक प्रतिलिपि कोषागार से प्राप्त कीजिये और उस कोषाधिकारी को निवेदन कीजिये कि वे इस प्रमाण पत्र की दो प्रतिलिपियां महालेखाकार राजस्थान को भेजें जो कि उन पर प्रति हस्ताक्षर करके एक प्रतिलिपि उस राज्य के महालेखाकार को भेजेंगे जहां पर आपको स्थानान्तरित किया गया है और आप अपने नये पद के वेतन और भत्ते प्राप्त करने के लिये इन्हें सम्पर्क कीजिये ताकि वे आपकी वेतन पर्ची भेजें ।

III (अ) जब अवकाश के हक के लिये आवेदन करना हो —

तो ऐसा प्राथना पत्र (अनुलग्नक ख' पर सलग्न) निर्धारित प्रपत्र पर भर कर महालेखाकार राजस्थान का अपने नियंत्रण अधिकारी की सिफारिश के साथ भेजा जाना चाहिये । यह अच्छी तरह देख लीजिये कि इसका कालम ६ पूरी तरह भरा गया है । इस कालम में नियमित अवकाश (भावस्मिक अवकाश नहीं) से पिछली बार प्रोटने की तिथि अंकित की जानी चाहिये ।

(घ) जब अवकाश पर रवाना होना हो —

- (1) जो महालेखाकार राजस्थान तथा कोषाधिकारी दोनों की अपना काय-भार सौंप देने की रिपोर्टें तुरन्त भेज दीजिये ।
- (II) महालेखाकार राजस्थान को इस बात की सूचना दीजिये कि क्या आप अब तक जिस कोषागार से वेतन उठा रहे हैं उसके अनुरिकत किसी अन्य कोषागार से अपना अवकाश-सवेतन उठाना चाहते हैं । यदि ऐसा ही हो तो अपने कोषाधिकारी से अनिवार्य वेतन प्रमाण पत्र प्राप्त कीजिये ।
- (III) महालेखाकार राजस्थान ■ अवकाश सवेतन-प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना अवकाश सवेतन भत्ता उठाइये । जब यह प्रमाण-पत्र आपको मिल जाय तो इसी के आधार पर अपना अवकाश सवेतन उठाइये और यदि आप यह किसी नये कोषागार से उठा रहे हो तो अपने प्रथम अवकाश सवेतन बिल के साथ अपना अनिवार्य वेतन प्रमाण पत्र अवश्य सलग्न कीजिये ।
- (IV) यदि आप एक स्थायी राज-प्रतिष्ठ अधिकारी नहीं हैं तो अपना अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र प्राप्त करके अपने उस कार्यालय-पक्ष को प्रस्तुत कीजिय जिसके यहाँ आप 'अराज-प्रतिष्ठ-सेवा' में स्थायी हैं । आपका अवकाश सवेतन उसी के द्वारा 'प्रस्थापना बिल' के साथ ही उठाया जायेगा ।

(स) जब अवकाश से वापस उपस्थित होना हो —

- (1) तो अपना काय-भार ग्रहण करने की रिपोर्ट उस पद के सम्बन्ध में भेजिय जिस पर आपको अब पद स्थापित किया गया है ।
- (II) यदि इस पद स्थापना से आपके उस कोषागार में परिवर्तन होता है जहाँ से आपने अपना अवकाश सवेतन उठाया था तो इस कोषाधिकारी से अपना अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र प्राप्त कीजिये । अब अपना वेतन जब तक कि आपको महा-लेखाकार राजस्थान से वेतन-पत्रों प्राप्त न हो न उठाइये जाय और जब यह आपको मिलजाय तो इसी के आधार पर अपना वेतन उठाइये । यदि कोषागार नया हो तो अपने प्रथम बिल के साथ अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र सलग्न कीजिये ।

(IV) जब आप त्याग-पत्र दें या सेवानिवृत्त हों

- (1) तो महालेखाकार राजस्थान को अपना काय-भार सौंप देने की रिपोर्ट भेजिये साथ ही साथ इस रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि कोषाधिकारी को भी भेजा जानी चाहिये ।
- (II) अपने पिछले दावों का यथाशीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिये राज-प्रतिष्ठ अधिकारी अपने नियंत्रण अधिकारी महालेखाकार राजस्थान, सावज

(ह) 'परिवार' में सरकारी कर्मचारी की पत्नी (महिला सरकारी कर्मचारी के मामले में उसका पति) पुत्र, माता पिता भवयस्क माई, बहिनें या पुत्रियाँ विधवा बहिनें या पुत्र वधुएं सम्मिलित मानी जाएंगी अगर वे सब पूरातया सरकारी कर्मचारी पर ही आश्रित हों।

^२टिप्पणी—(१) इन नियमों के नियम ७ के अनुसार सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य राजस्थान में सरकारी कर्मचारी के मुख्यालय के अनिवार्य तथी भी स्थान पर दोमार पडन पर सरकारी एजें पर चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार प्राप्त करने के हकदार हैं। औपधियो और ईजाज के व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनाथ यह ध्यावयन नही है कि बीमारी के समय सरकारी कर्मचारी का परिवार उसके साथ ही रहता हो।

^३(२) ऐसे मामले में जहाँ पति और पत्नी दोनों का सरकारी सेवा में हो वहाँ के तथा उनके आश्रित पात्र उनकी पदवी (स्टेटस) के अनुसार चिकित्सा सुविधाया का लाभ प्राप्त करने की अनुमित हैं। इस प्रयोजन के लिये उन्हें अपने प्रशासनिक प्राधिकारियों का एक समुक्त घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना चाहिये कि पति/पत्नी तथा बच्चों की स्वास्थ्योपचार और चिकित्सा पर व्यय बिधे हुए एजें की प्रतिपूर्ति के दावे दोनों में से कौन शायर करेगा। उक्त घोषणा पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा और दोनों के कार्यालयों में दोनों के व्यक्तिगत रिवाइड में इसको एक एक प्रति लगा दी जायेगी। राजपत्रित अधिकारियों/सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस समुक्त घोषणा पत्र की एक प्रति महासचिव, राजस्थान को भी भेजी जानी चाहिये। यह घोषणा पत्र तब तक प्रभावशील रहेगा जब तक कि दोनों की स्पष्ट प्राथना पर दोनों में से किसी के भी पदोन्नति स्थानांतरण त्याग पत्र आदि की स्थिति में इसे संशोधित न किया जाय। ऐसे समुक्त घोषणा पत्र के प्रभाव में पति की पदवी (स्टेटस) के अनुसार ही पत्नी तथा बच्चों की चिकित्सा सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी।

समुक्त घोषणा पत्र

हम पति और पत्नी श्री
दोनों जमश
एव बीमती
के और
के
कार्यालय में नियोजित एतद्वारा घोषणा करत हैं कि हम अपने स्वयं के तथा अपने परिवार के सदस्यों के चिकित्सा उपचार के व्यय की प्रतिपूर्ति दिनांक से
के कार्यालय से प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करते हैं। यह प्रमाणित किया जाता है कि ऐसी प्रतिपूर्ति का दावा
के कार्यालय से प्राप्त नहीं किया गया है।
कर्मचारियों के हस्ताक्षर

प्रति हस्ताक्षरित

१

१ सा प्र वि के आदेश सख्या एफ ४ (२२) जो ए/ए/ जो धार/II/६० दिनांक २३ ६-६२ द्वारा सन्निविष्ट।

२ सा प्र वि के आदेश सख्या एफ ४ (२२) जो ए/ए/ जो धारII/५७ दिनांक ६-६ ६१ द्वारा शामिल किया गया।

३ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (५१) एफ डी (व्यय-नियम)/६६ दिनांक ३० ११ ६६ द्वारा सन्निविष्ट।

विमागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

“परामर्श बुक्त” से तात्पर्य सरकारी कर्मचारों से रोगी के निवास स्थान पर परिचर्या के लिये राजस्थान सेवा नियमों की परिशिष्ट १० की अनुसूची क में वर्णित) दर पर प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्राप्त फीस से है ।

(ब) सरकारी कर्मचारों के सम्बन्ध में ‘स्वास्थ्य-उपचार’ से तात्पर्य प्राधिकृत चिकित्सक के निदानगृह या चिकित्सालय में ग्रन्थवा बीमारी को ऐसा होने पर रोगी को उसके घर पर रहने के लिये बाध्य करे सरकारी कर्मचारों के निवास स्थान पर, प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा की गई परिचर्या से है । इसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित है

(१) राज्य में सरकारी चिकित्सालय या प्रयोगशाला में उपलब्ध और प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा आवश्यक समझकर किये गये रोग निदान के प्रयोजनाय व्याधौकिय (पथोलोजिकल) जीवाणु विज्ञान सम्बन्धी (बैक्टीरियोलोजिकल), शरिरिकीय (रेडियोलोजिकल) जैसे परीक्षण या ऐसे ही अन्य तरीकों से किये गये परीक्षण ।

(२) प्राधिकृत चिकित्सक के परामर्श से राज्य सेवा के किसी अन्य चिकित्सक या विशेषज्ञ से इस सोमा तक और ऐसे तरीके से किये गये परामर्श जो वे निर्धारित करें और जिन्हें कि प्राधिकृत चिकित्सक आवश्यक प्रमाणित करें ।

(छ) ‘रोगी’ से तात्पर्य उस सरकारी कर्मचारी में है जिस पर ये नियम लागू होते हैं एवं जो बामार पड़ गया हो ।

(ज) ‘इलाज’ से तात्पर्य सरकारी चिकित्सालय में उपलब्ध उन समस्त चिकित्सा और शल्य क्रिया सम्बन्धी सुविधाओं से है जिसमें रोगी का उपचार किया जाय तथा इनमें निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं —

(१) प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा आवश्यक समझे गये व्याधौकिय (पथोलोजिकल) जीवाणु विज्ञान सम्बन्धी (बैक्टीरियोलोजिकल) एवं शरिरिकीय (रेडियोलोजिकल) तथा अन्य साधनों का प्रयोग ।

(२) अहा शारीरिक निदान (फिजियोलोजिकल) ग्रन्थवा अन्य अनुपुष्टता (डिसेजिलिटी) जिससे कि रोगी पीड़ित है यह प्रकट करे कि दात ही शारीरिक पांडा के मूल कारण हैं वहाँ दत उपचार बसते कि यह उपचार किसी वदे किस्म का हो उसे कि जबदे की हड्डी का रोग दातों का पूरी तरह निवाला जाना आदि ।

टिप्पणी — इस सर्जिकल मापदण्ड में भी लिखें कि पूने हुए मसूदा (आडो-टोम्स) या कसूर में ही हुई घटकल दाद (विजडमटूष) आदि के लिये आवश्यक समझा जाय,

१. ए० प्र० वि० का अधिमूर्चना सख्या एफ० ४ (२२) की ए० ए/५७ दिनांक ६५ ११-६० द्वारा मरिदविल ।

२. बिना विमाग की विमर्दि सख्या एफ० १ (७८) वि० वि० (नियम) ६५ दि० १६ ११-६० द्वारा प्रतिनिरावित किया गया ।

बड़ी किस्म के दात-उपचार की श्रेणी में आते हैं। मसूडों के छोटे फोडों (गमबोइल्स) का उपचार मुख सम्बन्धी शल्य क्रिया (सजरी) में आता है अतः वह इन नियमों के अधीन स्वीकार्य है। दातों के पायरिया अथवा मसूडों की सूजन का उपचार तथापि, इनके अधीन नहीं आता।

(111) ऐसी औपधियों, सेरा, वैक्सीन अथवा रोग हरन वाले अन्य पदार्थों का वितरण जो साधारणतः सरकारी चिकित्सालयों में इस राज्य में उपलब्ध हो।

(114) ऐसी औपधियों, वैक्सीन, सेरा अथवा रोग हरने वाले अन्य पदार्थों का वितरण जो इस प्रकार साधारणतः उपलब्ध न होते हो जसा कि प्राधिकृत चिकित्सक लिखित में पुनः स्वास्थ्य प्राप्ति के लिये अथवा रोगी को दशा में गंभीर गिरावट को रोकने के लिये आवश्यक प्रमाणित करें।

टिप्पणी

यह सुविधा पत्नी या पति, जसी की स्थिति में हो तथा माता पिता, बच्चे एवं सौतेले बच्चे सरकारी कर्मचारी पर पूणतः आश्रित हो को प्राप्त हो सकेंगी।

व्याख्या

(1) 'माता पिता' पद के अन्तर्गत सौतेले माता पिता सम्मिलित नहीं हैं तथा 'माता पिता' के मामले में 'पूणतया-आश्रित' शब्दों से तात्पर्य है कि माता पिता का कोई भी अन्य बालिग पुत्र नहीं हो तथा आय का कोई भी अन्य साधन भी नहीं हो। यदि माता पिता को ५० व० मासिक वेतन मिलती हो तो वे पूणतया-आश्रित माने जायेंगे।

(11) 'बच्चे' शब्द में कानूगन गोद लिये हुए बच्चे भी सम्मिलित हैं।

(111) 'पत्नी' शब्द में एक से अधिक पत्नी सम्मिलित होगी।

चिकित्सा परिचय

वित्त विभाग आदेश सख्या एफ १ (२६) वि० वि० (व्यय नियम) ६७ दिनांक २६ जून १९६७ की धोर ध्यान आश्रित किया जाता है कि जिसने अनुसार माता पिता को बिबिरमा पर किया गया व्यय उक्त आदेश में उल्लेखित शर्तों के पुरा होने पर पुनः भरण किया जाता है। उक्त आदेशों में उल्लेखित शर्तों को पूर्ण जांच हेतु निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं —

१ प्रत्येक राज्य कर्मचारी जो अपने माता पिता को चिकित्सा पर किये गये व्यय का पुनः भरण मांगे उसको प्रति वर्ष क्लर्क वर के प्रारम्भ में निम्न फार्मों में घोषणा पत्र भरकर अपने विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी को देना होगा।

१ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (२६) एफ डी (व्यय नियम) १६७ दिनांक २६ ६-१९६७ द्वारा प्रतिस्थापित।

२ वित्त विभाग (नियम) परिपत्र क्रमांक फ (२६) वि० वि० (व्यय नियम) ६७ दिनांक १६ मई १९६८।

१स्पष्टीकरण

महिला सरकारी कमचारी के मामले में 'इलाज' का मत प्रसव तथा प्रसवपूर्ण ज मोतर उपचार भी सम्मिलित है। ऐसे मामले में यदि रोगी को एक चिकित्सालय से दूसरे चिकित्सालय में चिकित्सा परीक्षणों के उद्देश्य से ले जाया जाय और अगर रोगी वाहना (एम्बुलेस) सरकारी या उस चिकित्सालय की न हो जिसमें वह रोगी को भर्ती किया गया है या जब इसका उपयोग उस समय किया जाय जब कि रोगी को चिकित्सालय से उसके निवास-स्थान पर पहुँचाया जाय तो ऐसी स्थिति में किया गया सर्वा अपिसी के योग्य है।

राजस्थान सेवा (स्वास्थ्य उपचार) नियम, १९५८ के नियम २ (ज) (iv) के नीचे दी हुई टिप्पणी ४ पर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो कि (वित्त विभाग की अधिमूचना सख्या एफ १ (६२) एफ डी (यय नियम) ६५ दिनांक २४ ११ ६५ द्वारा सन्निविष्ट की गई है) एवं जिनमें यह प्रावहित है कि सुनन के उपकरणों या शरीर के कृत्रिम अंगों का मूल्य पूरा या अंशत एफ मुक्त राशि के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है। इस विषय में स देह व्यक्त किये गये हैं कि क्या उक्त कथित नियम २ (ज) (iv) के नीचे टिप्पणी ४ के अधीन कृत्रिम अंगों को बदलने की कीमत भी प्रतिपूर्ति के योग्य है।

मामले की जाँच की गई है और यह तय किया जाता है कि राजस्थान सेवा (स्वास्थ्य-उपचार) नियम, १९५८ के नियम २ (ज) (iv) के नीचे की टिप्पणी ४ के अधीन कृत्रिम अंगों को बदलने की कीमत भी प्रतिपूर्ति के योग्य है।

३स्पष्टीकरण

एक प्रश्न यह उठ या गया है कि क्या सरकारी कमचारी द्वारा रक्षित-आधान (अन्य ट्रान्सपोजन) के लिये किया गया व्यय प्रतिपूर्ति योग्य है या नहीं? मामले की जाँच की गई और उचित विचार करने के बाद यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी कमचारी द्वारा रक्षित-आधान पर किया गया खर्चा प्रति पूर्ति के योग्य है।

(v) रहने के का प्रावधान स्थान जसा कि नीचे वर्गीकृत किया हुआ है, बगलें कि स्थान उपलब्ध हो-

(अ) ७५० रु मासिक तथा इससे अधिक वतन प्राप्त करने वाले अधिकारी	डोलकस या कान्ज बाड
(ब) ७५० रु मासिक से कम वतन प्राप्त करने वाले राज पत्रित अधिकारी तथा २५० रु से अधिक वेतन पान वाले अराजपत्रित अधिकारीगण	काटज बाड

- १ वि० विभाग के आदेश सख्या एफ १ (६२)एफ-डी (यय नियम)/६५ दिनांक २४ ११ ६५ द्वारा सन्निविष्ट किया गया।
- २ वित्त विभाग की अधिमूचना सख्या एफ १ (६२) एफ डी (ईआर)/६५ दिनांक २८ १० ६५ द्वारा सन्निविष्ट किया गया।
- ३ सा प्र वि के आदेश सख्या एफ ४ (२२) जी ए/ए/५७ दिनांक २४ ७ ५६ द्वारा सन्निविष्ट।

- (घ) २४६ रु मासिक तथा इससे कम परन्तु
११ रु मासिक से अधिक वेतन प्राप्त
करने वाले सराजपत्रित अधिकारी

निम्नतम श्रेणी के
किराये के बार्ड

टिप्पणी

१ सम्बद्ध सरकारी कमचारी के स्तर के अनुकूल रहने का स्थान उपलब्ध न होने की स्थिति में उसे उससे उच्च श्रेणी का स्थान भी दिया जा सकता है बशर्ते कि चिकित्सालय के चिकित्सक अधीक्षक द्वारा यह प्रमाणित किया जा सके कि —

- (i) रोगी के प्रवेश के समय उसकी उचित श्रेणी का स्थान उपलब्ध नहीं था तथा
- (ii) उसके स्वास्थ्य की ख़तरों के बिना चिकित्सालय में रोगी का प्रवेश तब तक के लिये नहीं रोका जा सकता था जब तक कि उसे उचित श्रेणी का स्थान उपलब्ध न हो जाय ।

१२ सरकारी कमचारियों को चिकित्सालय इत्यादि में रहने का सरकारी स्थान (बारड) नियमानुसार नि गृहक देने के प्रयोजनाय "महगाई-वेतन" को वेतन का ही भाग समझा जाना चाहिये ।

स्पष्टीकरण

एक प्रश्न उठाया गया कि— सरकार द्वारा दि० १-१२-१९६८ या इसके बाद में महगाई भत्ते के कुछ भाग को महगाई वेतन के रूप में मानने के कई आदेश जारी हुये हैं उसे उपरोक्त प्रयोजन [Note 2 below Rule 2 (b) (v)] हेतु 'वेतन' माना जावेगा या नहीं ?

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि—वित्तविभाग के आदेश सं० एक १ (७) दि० दि० (नियम) ६६ दि० ७-४-१९६६ के अर्थ में महगाई भत्ता का जो भाग महगाई-वेतन माना गया है उसे उपरोक्त पैरा (१) के प्रयोजनाय "वेतन" माना जावेगा ।

स्पष्टीकरण

३१ एक प्रश्न यह उठाया गया है कि निलम्बन अवधि के दौरान सरकारी कमचारी को निशुल्क रहने का स्थान देने के लिये वेतन की किस राशि की गणना की जानी चाहिये । मामले की जाच की गई है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि नियम २ (ब) (v) के अधीन जिस श्रेणी के रहने के स्थान का सरकारी कमचारी अधीकारी है उसके निश्चय करने के लिये उस कमचारी को निलम्बन से तुरत पूर्व दिया गया वेतन इसके लिये गणना में शुमार किया जाना चाहिये ।

४२ सरकारी चिकित्सालय में किराये के स्थानों में निशुल्क प्रवेश की सुविधा के प्रयोजन हेतु सरकारी कमचारी के परिवार के सदस्यों में वह कमचारी, उसकी पत्नी (महिला सरकारी

- १ सा प्र वि के आदेश सख्या ४ (२२) जी ए/ए/२७ दिनांक ५.५.६१ द्वारा सन्निविष्ट ।
- २ वित्त विभाग के भीमो सं० एक १ (७) (नियम) ६६ दि० १७-५.६६ द्वारा सन्निविष्ट ।
- ३ निदेशक चि० एव स्वा० विभाग के नापन सख्या एक १ (३०) (३) एम-बी एच/५६/ए डी एच दिनांक १२/१७.१.५६ द्वारा सन्निविष्ट ।
- ४ सा प्र वि के आदेश सख्या एक ४ (२२) जी ए/ए/५७ दिनांक १०.६.१९६० द्वारा सन्निविष्ट एव दिनांक १०-६.१९६० से प्रभावशील ।

कर्मचारी के मामले में उसका पति), पुत्र, माता पिता, भ्रम्यस्व भाई अविवाहित पुत्रिया या बहिन भ्रम्यया विधवा बहिन या पुत्रवधुएँ सम्मिलित हैं किन्तु यह है कि वे सब सरकारी कर्मचारी पर ही पूर्णतः प्रार्थित हों। इससे भलावा निम्न सुविधायें भी प्राप्त हो सकती हैं —

(११) साधारण नसिंग सुविधायें जहाँ की किसी सरकारी चिकित्सालय में उपलब्ध होती है।

(१२) उस सरकारी कर्मचारी के मामले में खुराक जिसका कि वेतन १५० रु० मासिक से अधिक नहीं है वशतः कि चिकित्सालय में रागियों की भाजन व्यवस्था हो।

टिप्पणी

महिला सरकारी कर्मचारी के मामले में इलाज में प्रसव भी सम्मिलित है जहाँ कि सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के मामले में होता है।

३ (क) इन नियमों में परिभाषित स्वास्थ्य उपचार और इलाज के लिये सरकारी कर्मचारी नि शुल्क हक्दार होगा।

वशतः कि प्राधिकृत चिकित्सक की निर्धारित की हुई ऐसी औषधियाँ जो कि भोज्य प्रसाधन दार्शनिक अधिक खाद्य सारता रखनेवाली नि सक्कामक तथा इसी प्रकार की अन्य सानग्री जहाँ समझी जाय उनके लिये सरकार द्वारा कोई प्रति पूति नहीं की जायेगी।

टिप्पणी

इन नियमों के अधीन प्राप्य सुविधायें सरकारी कर्मचारियों को नियन्त्रण के दौरान भी स्वीकार्य होगी।

*सरकारी अनुदेश — यह देखा गया है कि प्रायः सरकारी कर्मचारी अपने उपचार व्यय की प्रतिपूति के दावे इलाज पूरे होने के बाद काफी विलम्ब से, साथ ही साथ अशो में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रश्न की जाच की गई है और यह निश्चय किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने उपचार व्यय की प्रतिपूति के दावे इलाज पूरा होने की तारीख से (एक वर्ष) के अन्दर ही करना है। एक बार में प्रस्तुत कर देन चाहिये किन्तु अशो में नहीं। किन्तु एक बार के १५० रु० या अधिक राशी के बिल चिकित्सा पूर्ण होने से पहले भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

स्पष्टीकरण

१ एक प्रश्न यह उठाया गया है कि क्या राजस्थान सेवा (स्वास्थ्य-उपचार) नियम १९५८ सवानिवृत्ति के पदवात् पुनः सरकारी सेवा में नियोजित व्यक्तियों पर भी लागू होगे तथा कि राजस्थान सेवा (स्वास्थ्य उपचार) नियम १९५८ इस सम्बन्ध में योजन हैं। इस मामले की जाच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान सेवा (स्वास्थ्य उपचार) नियम १९५८ स्थायी

- १ सा प्र वि क आदेश सख्या दिनांक १८-१०-६५ द्वारा सन्निविष्ट।
- २ सा प्र वि के आदेश सख्या एक ८ (२२) जो ए/ए/६७ दिनांक २३-७-५६ से सम्मिलित।
- ३ सा प्र वि० के आदेश सख्या एक ४ (२२) जो ए/ए/५७ दिनांक २४-१०-५६ द्वारा सन्निविष्ट।
- ४ सा प्र वि के आदेश सख्या एक ४ (२२)/जो ए/ए/१७ दिनांक २३-७-१९५६ द्वारा सन्निविष्ट।

या अस्थायी सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होना है । पुन नियोजित व्यक्ति पू कि अस्थायी सरकारी कर्मचारी होते हैं अत ये नियम उन पर भी लागू होने है ।

सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया है असाधारण अवकाश प्राप्त करने वाले अस्थायी सरकारी कर्मचारी भा इन स्वास्थ्य उपचार नियमों से ही नियंत्रित होते हैं । आगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो सरकारी कर्मचारी असाधारण अवकाश पर हो और इस अवकाश में उसे सरकार द्वारा किसी अन्य सरकार या अन्य नियोजक के अधीन सेवा स्वीकार करने की अनुमति दी जाय तो ऐसा कर्मचारी चाहे स्थायी हो या अस्थायी उसे स्वास्थ्य-उपचार प्राप्त नहीं हो सकेगा ।

(ख) नियम ३ (क) के अधीन जहां किसी सरकारी कर्मचारी को स्वास्थ्य उपचार और इलाज नि शुल्क प्राप्त करने का हक है वहां उसके द्वारा स्वास्थ्य उपचार और और इलाज पर खर्च की गई किसी भी राशि की सरकारी कर्मचारी को लिखित में प्राधिकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जा सकेगी । यह प्रमाण-पत्र निम्नलिखित प्रपत्र पर होना चाहिये —

परमाण्वरूप प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री जो विभाग में नियुक्त है चिकित्सालय/इन्डोर आउटडोर में मेरे परामर्श कम में मेरे उपचार में रहे हैं/रही हैं । इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा निर्धारित निम्नलिखित औषधियों रोगों का दशा में हो रही गम्भीर गिरावट को रोकने/रोगी के पुन स्वास्थ्य होने के लिये परमावश्यक हैं/थी । ये औषधियाँ बाहर के रोगियों को देने के लिये मे सग्रहीत नहीं की जाती और इनमें ऐसी प्रोप्राइटरी औषधियाँ प्रिप्रेरेशनम् सम्मिलित नहीं है जिनके लिये समान गुण वाले जेनरल टिक मूल्य के सस्ते पदार्थ प्राप्य हैं अथवा जा मूलत भोज्य प्रसाधन या नि सनामक थ एणो में आते हैं ।

बीजक सख्या व तारीख	औषधियों का नाम	मूल्य	
		रुपये	पैसे

योग
रुपये

चिकित्सालय में रोगी के प्रभारी चिकित्सक
अधिकारी के हस्ताक्षर

प्राधिकृत चिकित्सक के हस्ताक्षर एवं
पद

२ प्रमाणित किया जाता है कि रोगी
और तारीख से तब मेरे उपचार में है/था । यह भी
से पाठित है/या

१ वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ १ (४६) एफ डी (व्यय नियम)/६६ दिनांक १८ ८ ६६ द्वारा संश्लिष्ट ।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त रोग, रतिरोग, वनेरियल, सन्निपात, डिलीरियम उपचार प्रसव पूर्व/जन्मोत्तर सम्बन्धी बीमारियों में नहीं आता ।

३ रोगी के चिकित्सालय में रहने की आवश्यकता थी/नहीं थी/यह मामला निश्चित रूप से लम्बे उपचार का है/नहीं है/या/नहीं था ।

४ प्रमाणित किया जाता है कि उपचार कार्य पूरा हो चुका है ।

चिकित्सालय में रोगी के
प्रभारी चिकित्सा-अधिकारी के
हस्ताक्षर

प्राधिकृत चिकित्सक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट 'क'

सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार के उपचार तथा/अथवा चिकित्सक (मेडीकल-ग्रैजुएट) के सम्बन्ध में किये गये चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये प्रार्थना पत्र

सूचना — प्रत्येक रोगी के लिये भलग प्रपत्र का प्रयोग किया जाना चाहिये ।

१ राज्य कर्मचारी का नाम व पद (बड़े प्रक्षरो में)

२ कार्यालय जिसमें नियुक्त हैं—

३ राज्य कर्मचारी का राजस्थान सेवा नियमों में परिभाषित वेतन तथा अन्य उपलब्धियाँ (ऐमोल्यूमेन्ट्स) (इन्हें भलग से दिखाया जाना चाहिये)

४ काय स्थान

५ वास्तविक निवास स्थान का पता —

६ रोगी का नाम तथा उसका राज्य कर्मचारी से सम्बन्ध —

सूचना — रोगी यदि बालक हो तो उसकी आयु भी लिखनी चाहिये ।

७ रोगी के रोग ग्रस्त होने का स्थान —

८ मागी गई राशि का विवरण —

(१) चिकित्सा परिचर्या

(11) परामश शुल्क — नीचे लिखा विवरण भी दीजिये —

(क) जिस चिकित्सा अधिकारी से परामश किया गया है उसका नाम अस्पताल व डिस्पेंसरी का नाम जिससे वह संबंध है ।

(ख) परामश की सख्या व तारीखें तथा प्रत्येक इन्जेक्शन के लिये दिया गया शुल्क ।

(ग) इन्जेक्शन की सख्या तारीखें तथा प्रत्येक इन्जेक्शन के लिये दिया गया शुल्क ।

(घ) परामश और/या इन्जेक्शन किस स्थान पर दिये गये—अस्पताल में, चिकित्सा अधिकारी के परामश कक्ष में या रोगी के निवास स्थान पर—

(11) पथोलोजिकल, बक्शेरियोलोजिकल, रेडियोलोजिकल या अन्य प्रकार के परीक्षण/जो निदान के लिये किये गये/पर किया गया व्यय—

(क) अस्पताल या प्रयोगशाला का नाम जहाँ परीक्षण किये गये थे ।

(ख) क्या परीक्षण प्राधिकृत-चिकित्सक के परामर्श से कराये गये थे । यदि हाँ तो इस विषय में एक प्रमाण पत्र सलग्न किया जाना चाहिये ।

४ बाजार से खरीदी गई औषधियों का मूल्य, औषधियों की सूची । कश मीमो और परमावश्यकता प्रमाण पत्र सलग्न किये जाने चाहिये ।

अस्पताल का उपचार ।

अस्पताल का नाम ।

अस्पताल में उपचार का व्यय । निम्नलिखित के लिये किये गये व्यय का अलग अलग विवरण दीजिये ।

(1) रहने का स्थान ।

क्या रहने का स्थान राज्य कर्मचारी के स्तर या वेतन के अनुसार था और यदि स्थान राज्य कर्मचारी के स्तर से ऊँचा था तो एक प्रमाण-पत्र इस विषय का सलग्न किया जाय कि राज्य कर्मचारी के स्तर का स्थान उपलब्ध नहीं था ।

(11) भोजन ।

(111) शल्य चिकित्सा (सर्जिकल आपरेशन) या चिकित्सा उपचार या प्रसूति (कनफाइनमेंट)

(112) पथोलोजिकल बैक्टीरियोलोजिकल रेडियोलोजिकल या अन्य इसी प्रकार के परीक्षण का विवरण ।

(क) अस्पताल या प्रयोगशाला का नाम जहाँ परीक्षण किया गया/किये गये ।

(ख) क्या परीक्षण अस्पताल में रोग के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से कराये गये थे । यदि हाँ तो इस विषय का एक प्रमाण पत्र सलग्न किया जाना चाहिये ।

५ औषधियाँ—

६ विशेष औषधियाँ ।

(औषधियों की सूची, केशमीमो और परमावश्यकता प्रमाण-पत्र सलग्न किये जाने चाहिये)

७ सामान्य परिचर्या—

८ मिटाया गया—

९ रोगी वाहन (एम्बुलेंस का व्यय)

‘कहाँ से कहाँ यात्रा की’ इसका विवरण दीजिये ।

१० कोई अन्य व्यय जैसे बिजली का प्रकाश, पसा हीटर वातानुकूलित सुविधायें आदि । यह उल्लेख किया जाय कि क्या सामान्यतया ये सुविधायें सभी रोगियों को दी जाती हैं और रोगी के लिये उसकी इच्छा से कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई थी ।

नोट—१ यदि उपचार नियम ३ (घ) के अधीन राज्य कर्मचारी के निवास स्थान पर किया गया हो तो ऐसे उपचार का विवरण दोजिये और नियमानुस र प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक का प्रमाण पत्र सलग्न कीजिये ।

२ यदि उपचार राजकीय अस्पताल के अतिरिक्त अन्य अस्पताल में किया गया हो तो प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक का इस विषय का प्रमाण पत्र कि आवश्यक उपचार पास के किसी राजकीय अस्पताल में उपलब्ध नहीं था । सलग्न किया जाना चाहिये ।

३ विशेषज्ञ परामर्श—प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक के अतिरिक्त अन्य विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी को दिये गये शुल्क का विवरण

(क) जिस विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी से परामर्श किया गया उसका नाम पद अस्पताल का नाम जिससे वह सम्बद्ध है ।

(ख) परामर्श की सग्या व तारीखें तथा प्रत्येक परामर्श का शुल्क ।

(ग) क्या परामर्श अस्पताल विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी के परामर्श वक्त या रोगी के निवास-स्थान पर हुआ था ।

(घ) क्या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी से परामर्श प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की सलाह से हुआ था और क्या जिला चिकित्सा अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई थी, यदि हाँ तो इस विषय का एक प्रमाण पत्र सलग्न किया जाना चाहिये ।

६ मागी गई राशि का योग

१० सलग्न पत्रों की सूची

घोषणा जिस पर राज्य कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे—मैं घोषित करता हूँ कि कि इस प्राप्तिना पत्र के विवरण जहाँ तक मेरी जानकारी व विश्वास है, सही हैं और रोगी जिस उर चिकित्सा व्यय किया गया है पूरातया मुझ पर ही आधारित है ।

राज्य कर्मचारी के हस्ताक्षर, पद

दिनांक

१६६

एवं कार्यालय जिससे सम्बद्ध है

११ आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियाँ, जो बघ/हामा द्वारा निर्धारित की जायें, कि प्रतिपूर्ति केवल अनुमोदित औषधियाँ के लिये ही की जायेगी । राज्य सरकार ने अनुमोदन से निदेशन आयुर्वेदिक विभाग राजस्थान द्वारा एनी औषधियाँ की एक अधिनूचित सूची अनुमोदन 'क' पर दी गई है ।

२ परिपा

एवं मः ह यह व्यक्त किया गया है कि क्या उर द्वारा यूनानी औषधियाँ और हकीम द्वारा आयुर्वेदिक औषधियाँ निर्धारित की जा सकती हैं अथवा नहीं । इस विषय में सरकार की जानकारी

१ सा प्र वि के घाटे सग्या ४ (२२) जी ए/ए/जी आर/II/१७ दिनांक २४ १-६२ द्वारा प्रतिस्थापित ।

२ विस्त विभाग के सग्या एफ १ (१८) एफ ए/अध्य नियम/६७ दिनांक १५ ४-६५ द्वारा

॥ लया गया है कि वैभक्त स्वागत पर सुविधा के कारण दोनों ही प्रकार की एमी सप्रहीत और योग्यता प्राप्त एवं अनुभव वैधा य हूँगा द्वारा निर्धारित औपधियाँ से लते हैं और जिन वधो या हकीमो ो इस प्रकार की दानो हो औपधिया का ज्ञान है व यह निर्धारित कर दते हैं । तथापि, अ धुर्वेदिक और यून नो पद्धति का औपधिया में को भारी अन्तर भी नही है । यत इस मामले पर विचार किया गया है और यह स्पष्ट किया जाता है कि आयुर्वेदिक विभाग के निदेशक द्वारा प्राधिकृत ऐसे वध जिन्हें यूनानी दध भी की जानकारी हो और ऐसे हकीम जिन्हें आयुर्वेदिक औपधिया की जानकारी हो वे सब ऐसा दोनों ही प्रकार की औपधियाँ निर्धारित कर सकते हैं ।

२० जिन ऐनोपैथिक दवाईया और औपधिया की प्रतिपूर्ति नियम ३ के उपनियम (क) के परन्तुक के अन्तर्गत नही हो सकते उनको सूची निम्नलिखित विविधता एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान द्वारा सरकार के अनुमोदन से अधिमूर्चित की जायेगी और वह इसमें अनुलग्नक "ख" के रूप में सलगन हैं ।

परिपत्र

२(ग) परिशिष्ट ख में उल्लिखित इस प्रयोजन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर ही दावा की वापसी के लिये प्रायना पत्र लिया जायेगा ।

टिप्पणी

३(१) चिकित्सा ध्यय की प्रतिपूर्ति के लिये विन के साथ हमेशा निर्धारित प्रायना पत्र सलगन किया जाना चाहिये ।

२ चिकित्सा विभाग के साथ सलगन किये हुए दवाईया के खरीदने के कसमीमोज पर हमेशा दवाईया निर्धारित कानन के अनुसार के प्रतिहस्त लागू किये जाने चाहिये तथा परमावश्यकता प्रमाण पत्रो में सभी निर्धारित औपधिया के नाम मोटे अक्षरों में लिखे जाने चाहिये एवं उनमें औपधियों की खरीद में किया हुआ व्यय भी अलग से अंकित किया जाना चाहिये ।

* राजस्थान सरकार का निर्णय

॥ यह देखा गया है कि कभी कभी सरकारी कर्मचारी अपने चिकित्सा-ध्यय की प्रति पूर्ति के लिये को को काफी विमर्श प्रस्तुत करने के साथ साथ उन्हें चिकित्सा पूरी होने के बाद कई हिस्सों में प्रस्तुत करते हैं । इस प्रश्न की जाँच की गई है और यह निराकरण किया गया है कि सरकारी

१ परिपत्र सख्या एफ २ (४६) जी ए/ए ६३/जी आर/II दिनांक ३०-४-६४ द्वारा समिविष्ट ।

२ सा प्र वि के आदेश सख्या एफ ४ (२२) जी ए/ए/५७ दिनांक २५-७-१९५६ द्वारा समिविष्ट ।

३ सा प्र वि के आदेश सख्या एफ ४ (२२) जी ए/जी आर/II/५७ दिनांक २७-१०-६१ द्वारा समिविष्ट ।

४ सा प्र वि के आदेश सख्या एफ ४ (२२) जी ए/ए/५७ दिनांक २३-७-५६ द्वारा समिविष्ट ।

४ (१) जिस स्थान पर कोई रोगी बीमार पड़ता हो और वह स्थान प्राधिकृत-चिकित्सक का मुख्यालय न हो तो—

(अ) मुख्यालय तक पहुँचने और वहाँ से वापिस आने तक की यात्राओं के लिये रोगी यात्रा-भत्ते का हकदार होगा, या

(ब) यदि रोगी इतना बीमार है कि वह यात्रा नहीं कर सकता तो जहाँ पर रोगी बीमार है वहाँ पर जाने और वहाँ से वापिस लौटने की यात्राओं के लिये प्राधिकृत चिकित्सक यात्रा-भत्ते का हकदार होगा ।

वर्षों कि दत्त चिकित्सक या पत्र रोग विशेषज्ञ से उपचार कराने हेतु की गई यात्राओं के लिये रोगी यात्रा भत्ता पाने का हकदार नहीं होगा ।

(२) उप नियम (१) के अधीन यात्रा भत्ते के लिये आवेदन-पत्र प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा लिखित में यह उक्त करते हुए कि स्वास्थ्य उपचार आवश्यक था तथा यदि आवेदन पत्र उप नियम के खण्ड (ख) के अधीन है, तो यह व्यक्त करते हुए कि रोगी इतना अधिक बीमार था कि यात्रा नहीं कर सकता था, प्रमाणपत्र सहित भेजा जायेगा ।

५ यदि प्राधिकृत चिकित्सक की राय में रोगी की हालत ऐसी गंभीर हो या ऐसी विशेष किस्म की हो कि उनके स्वयं के प्रतिरिक्त किसी अन्य सरकारी अधिकारी द्वारा चिकित्सा परिचर्या की अपेक्षा हो तो वह रोगी को समीपस्थ विशेषज्ञ अथवा अन्य सम्बद्ध चिकित्सक के पास भेज सकता है । इन नियमों के अधीन किसी दूसरे स्थान पर भेजा गया रोगी प्राधिकृत चिकित्सक के लिखित प्रमाण पत्र देने पर दूसरे चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के स्थान तक जाने और वापिस लौटने की यात्राओं के लिये दोरी पर की गई यात्राओं की भाँति बिना विश्राम भत्ता पाये यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा ।

१ चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के प्रयोजनाथ वायुयान द्वारा अथवा वातानु-कूलित थ्रेणी में की गई यात्रायें, बिना इस बात का विचार किये हुए कि सम्बद्ध अधिकारी सरकारी ड्यूटी पालन करने के लिय अपने स्वविवेक से वायुयान द्वारा अथवा वातानुकूलित थ्रेणी में यात्रा करने का अन्य प्रकार से हकदार है अथवा नहीं स्वीकार्य नहीं होगी ।”

टिप्पणी

जिला चिकित्सा अधिकारी से नीचा थ्रेणी के चिकित्सा अधिकारी को जहाँ रोगी की अवस्था ऐसी जान पड़े वहाँ उस अन्य चिकित्सालय या चिकित्सक के पास भ्रजन से पूर्व अपने से वरिष्ठ थ्रेणी के चिकित्सा अधिकारी (जो जिला चिकित्सा अधिकारी या इससे उच्च थ्रेणी का हो) की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिये ।

६ (ग) स्वास्थ्य-उपचार अथवा चिकित्सा सुविधायें नि शुल्क पाने के हकदार रोगियों को इन नियमों के अधीन प्राप्त होने वाली सेवाओं में सम्मिलित अथवा खर्चों को 'स्वास्थ्य-उपचार' अथवा 'इलाज' में सम्मिलित न हो, वे सब प्राधिकृत-चिकित्सक द्वारा निर्धारित किये जायेंगे और उनका भुगतान रोगी द्वारा ही किया जायेगा।

(व) घ्याख्या—कोई सेवा चिकित्सा सुविधा अथवा स्वास्थ्य-उपचार में सम्मिलित हुआ नहीं यदि ऐसा कोई प्रश्न उठे तो उसे वित्त-विभाग में सरकार के महा भेजा जाना चाहिये और उस पर बहा किया गया निणय ही अन्तिम माना जायेगा।

७ सरकारी कमचारियों के परिवार के लिये स्वास्थ्य उपचार और इलाज —

१ (अ) चूंकि सरकारी कमचारी के परिवार के सदस्य सरकारी खर्च पर सरकारी चिकित्सालय में कमचारी का नियमों के अधीन स्वोकार्थ दरो और शर्तों पर स्वास्थ्य-उपचार और इलाज पाने के अधिकारी हैं किंतु इस रियायत में निम्नलिखित स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर चिकित्सा एवं परिचर्या सम्मिलित नहीं होगी —

१ किसी सरकारी चिकित्सालय में अथवा

२ प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा अपनी व्यवस्था से चलाये जा रहे पगमशों-कक्ष में

बशर्त कि गंभीर मामलों में जहां प्राधिकृत चिकित्सक परिवार के सदस्य को चिकित्सालय में ले जाना उसके जीवन के लिये खतरनाक अथवा धातक समझे वहाँ रोगी के निवास स्थान पर भी स्वास्थ्य उपचार और इलाज किया जा सकेगा।

टिप्पणी

इस उप नियम के परन्तुक के प्रयोजनाय परिवार शब्द में केवल पत्नी (महिला सरकारी कमचारी के मामले में उसका पति) बच्चे साथ रह रहे, भौतले बच्चे जो उसी पर पूणतया निर्भर हैं सम्मिलित होंगे और नियम २ (ड) में परिभाषित परिवार के अन्य सदस्य नहीं।

१ (ब) सरकारी कमचारी के परिवार का सदस्य जब उपनियम १ (अ) के परन्तुक के अधीन अपने निवास स्थान पर स्वास्थ्य उपचार और इलाज प्राप्त कर रहा हो तो सरकारी कमचारी उपचार और चिकित्सा पर किये गये खर्चों की उसी प्रतिपूर्ति के लिये ही हकदार होगा जो वह नियमों के अधीन नि शुल्क ही प्राप्त करता किंतु शर्त यह है कि इसके लिये उसे परिशिष्ट 'ग' में निर्धारित प्रमाण पत्र निम्नी विस्त में से किसी प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित तथा निम्नांकित चिकित्सकों के अतिरिक्त मामला में उनके बरिष्ठ चिकित्सक के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित करवा कर सलग्न करना होगा —

(१) मेडिकल—

जयपुर जोधपुर उदयपुर अजमेर १ प्रधानाचार्य आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और बीकानेर अदि नगरों में सम्बद्ध चिकित्सालयों का नियन्त्रक एवं

१ वित्त विभाग के आदेश सं० १ (८२) एफ डी (व्यय नियम)/६६ दिनांक २२-११-६६ द्वारा सम्बिष्ट।

उप प्रधानाचार्य और अधीक्षक सवाई-
मानसिंह चिकित्सालय ।

२ आचार्य, अवर आचार्य और आयुर्विज्ञान
महाविद्यालय के रीडर ।

३ जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ।
प्रधानचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी ।

अन्य स्थानों पर

(11) आयुर्वेदिक —

१ आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रधानाचार्य ।

२ आयुर्वेदिक विभाग के नोरीयक ।

परिशिष्ट—'ग'

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पुत्र/पत्नी/पुत्री/पति श्री/
श्रीमती आयु जो विभाग का/की है
बीमारी से दिनांक से पीड़ित था/थी तथा मेरे उपचार मे
था/थी । मैंने उसके घर पर दिनांक को वजे वीक्षण किया/
किये क्योंकि उसकी अवस्था गंभीर थी तथा उनको चिकित्सालय मे ले जाना उसके
जीवन के लिये हानोकारक तथा घातक होता । मैंने अपने वीक्षण के लिये
रु० प्राप्त किये ।

प्रति हस्ताक्षरित
वरिष्ठ चिकित्सा-अधिकारी के
हस्ताक्षर और पद

प्राधिकृत चिकित्सक के
हस्ताक्षर और पद ।

२ परिवार के सदस्यों का नियम ४ एवं ५ में निर्दिष्ट मामलों में प्राधिकृत
चिकित्सक से परामर्श करने हेतु की गई किसी यात्रा के लिये कोई भी यात्रा भत्ता
नहीं दिया जायेगा ।

अपवाद — यदि प्राधिकृत चिकित्सक की सम्मति से दो वर्ष से कम उम्र के
बच्चे को उपचार के लिये किसी स्थान पर ले जाया जायेगा तो बच्चे के साथ जाने
वाले परिचारक या मागरक्षक को नियम ५ के नीचे दी हुई टिप्पणों (२) में निर्धारित
दर पर यात्रा भत्ता दिया जा सकेगा ।

३ उप नियम (१) में सदर्भित स्वास्थ्य उपचार एवं इलाज के अधीन
चिकित्सालय में सरकारी कर्मचारी की पत्नी का प्रसव, प्रसव पूर्व और जन्मोत्तर
उपचार भी सम्मिलित समझा जायेगा ।

राजस्थान सरकार का नियम

यह निश्चित किया गया है कि राज्य सरकार के कमचारियों को रेलवे मन्त्रालय के कार्यालय ज्ञान सत्पाटी सी II/२१८३/५६ दिनांक ६-११-१९५६ (जा) यहाँ नीचे दिया हुआ है) के द्वारा स्वीकृत रियायतों का लाभ अपनी उपयुक्त श्रेणियों को सीटा या उससे नीचे की श्रेणियों को सीटा पर यात्रा करके उठाना चाहिये। इन सरकारी कमचारियों को यात्रा-भत्ता उपयुक्त प्रादेश में स्वीकृत सीमा तक नियम ७ के प्रयोजन स्वीकार्य रियायतों के बदले में दिया जाना चाहिये।

रेलवे मन्त्रालय (रेलवे बोर्ड) के कार्यालय ज्ञान सत्पाटी सी II/२१८३/५६ दिनांक ६-११-१९५६ की महानिर्देशक, स्वास्थ्य सेवाओं नई दिल्ली की प्रेषित प्रतिलिपि —

विषय टी बी और कैंसर के रोगियों को रेल की रियायतें —

निम्न हस्ताक्षरकर्ता को स्वास्थ्य सेवाओं के महा निर्देशालय के पत्र संख्या २-१२-५६ सी एन एम II (17) दिनांक २७-१०-५६ का उल्लेख करते हुए यह कहने का निर्देश हुआ है कि ममस्त टी बी और कैंसर के रोगियों को किसी अस्पताल/सनेटोरियम/रास्थान/क्लिनिक में प्रवेश हेतु जाने, वहाँ से छुट्टी पाकर वापस अपने निवास तक आने ऐसे अस्पताल/सनेटोरियम/रास्थान/क्लिनिक में पुनः परीक्षण या सामयिक जाच के लिये जाने और वापस लौटने के लिये निम्नलिखित रियायतें स्वीकार की जाती हैं —

किनको प्राप्य हैं

रियायतों की किस्म

- (1) किसी परिचारक के साथ यात्रा करने वाला रोगी।

जिस श्रेणी में यात्रा की जा रही हो उसका रोगी के लिये एकल (सिंगल) यात्रा भाड़ा देने पर रोगी और उसके परिचारक की यात्रा के लिये एक संयुक्त सादा कागजी टिकट

- (11) अकेले यात्रा करने वाला रोगी

सामान्यतः देय किराये का ३/४ किराया देकर एकल (सिंगल) यात्रा टिकट।

इन रियायतों और इन्हें प्राप्त करने के तरीकों की विस्तृत जानकारी कोचिंग हैरिफ नं० १७, आई आर सी ए के नियम ११८ के अनुलग्नक के प्रमाण १० अ और १० ब पर दी हुई है। इसकी एक प्रति सभी रेलवे स्टेशनों पर मूलभूत है एवं महासचिव इण्डियन रेलवे काफ़ेस ऐशोसियेशन चैम्स फाउ रोड नई दिल्ली से कीमत देकर भी प्राप्त की जा सकती है।

२ टी बी और कैंसर के पीडित सरकारी कमचारियों को रेल की रियायतें दिये जाने के लिये कोई विशेष अनुदेश रेलवे मन्त्रालय ने जारी नहीं किये हैं। तथापि वे निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करके उक्त रियायतों को सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

८ (1) सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु अनुमोदित अभ्यासिका को स्वास्थ्य परीक्षा के लिये निर्भूक्ति कर्ता प्राधिकारी द्वारा भेजा जाना चाहिये तथा यह स्वास्थ्य परीक्षा नि शुल्क होगी।

स्पष्टीकरण

एक प्रश्न यह उठाया गया है कि राज्य से बाहर स्थित किसी सरकारी पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती किये गये अभ्यर्थी को किसी ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी के पास स्वास्थ्य परीक्षा के लिये भेजा जाये जो कि राज्य सरकार की सेवा में न हो तो ऐसी परीक्षा का शुल्क किसी सीमा तक प्रतिपूर्त किया जाना चाहिये। चूंकि ऐसे अभ्यर्थी को स्वास्थ्य परीक्षा नि शुल्क ही की जानी अपेक्षित है अतः यह स्पष्ट किया जाता है यदि बाद में अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त कर दिया जाय तो चिकित्सा अधिकारी। बोर्ड द्वारा लिया गया शुल्क प्रतिपूर्त किया जा सकता है। प्रतिपूत की जाने वाली फीस की प्रतिपूर्ति निम्न प्रकार (अथवा वस्तुतः दी हुई फीस की दर पर, जो भी कम हो) की जायेगी —

ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा निम्नांकित सरकारी कमचारियों की स्वास्थ्य परीक्षा के लिये जो प्रधानचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद से नीचे का न हो —

१	अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य राज पत्रित अधिकारी	१० रु०
२	अधीनस्थ अराजपतिन अधिकारी	५ रु०
३	सिविल असिस्टेंट सजन प्रथम श्रेणी द्वारा उपयुक्त श्रेणियों के अधिकारियों की स्वास्थ्य परीक्षा के लिये	१ रु०
४	सिविल असिस्टेंट सजन द्वितीय श्रेणी द्वारा उक्त श्रेणियों के अधिकारियों की स्वास्थ्य परीक्षा हेतु	२ रु०
५	चिकित्सा मंडल द्वारा समस्त श्रेणी के अधिकारियों या कमचारियों की स्वास्थ्य परीक्षा के लिये	१६ रु०

(२) कार्यालयाध्यक्ष द्वारा चाहे जाने पर अवकाश की पुष्टि के लिये चिकित्सा-प्रमाणपत्र प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा नि शुल्क दिया जायेगा। सक्षम-प्राधिकारी द्वारा चाहे जाने पर चिकित्सा मण्डल द्वारा की गई परीक्षाओं को भी सभी सरकारी कमचारियों के लिये नि शुल्क ही किया जा सकेगा।

*आदेश

राज्यपाल सहय आदेश प्रदान करते हैं कि स्वास्थ्य परीक्षा प्रयोगशाला व्यय एकमरे परीक्षा आदि के लिये सभी सरकारी चिकित्सालयों में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के कमचारियों सहित इन सरकारी कमचारियों से जो इस मण्डल में प्रति नियुक्ति पर हा शुल्क लिया जाना चाहिये और इसकी उचित रसीद दी जानी चाहिये।

ये कमचारी इन रसीदों को प्रस्तुत करके राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल से ऐसी परीक्षाओं पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति करा सकते हैं।

उपयुक्त नियम पचायत समितियों। जिला परिषदों के कमचारियों सहित इन पचायत समितियों। जिला परिषदों में प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए कमचारियों पर भी लागू होंगे।

स्पष्टीकरण

एक प्रश्न यह उठाया गया है कि जसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा चाहे जाने पर चिकित्सा मण्डल द्वारा चिकित्सा परीक्षा के मामलों में होता है, वैसे ही विभागाध्यक्ष/कार्यान्वयक द्वारा कोई भी माँग न करने पर यदि सरकारी कमचारी स्वयं माँग करे तो क्या उस सरकारी कर्मचारी से बीमारी (सिकनस) या सेवा योग्यता (फिटनेस) के प्रमाण पत्र के लिए शुल्क लिया जाना चाहिये प्रत्येक नहीं।

यू कि ऐसे अनुष्ठान हैं कि जब भी एक दिन में अधिक के आक्स्मिन् अवकाश का प्राधान्य पत्र दिया जाय एवं यदि अवकाश का निवेदन चिकित्सा कारणा से किया गया हो तो प्राधान्य पत्र चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ भेजा जाना चाहिये। इसी प्रकार रियायती अवकाश के निर्धारित प्रपत्र में इस प्रकार के अवकाश के निवेदन की पुष्टि में चिकित्सा-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है। अतः विभागाध्यक्ष/कार्यान्वयक को यह मदब आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक मामले में चिकित्सा प्रमाण पत्र की माँग करे तथा इस प्रकार मापारणतया यह माना जा सकता है कि जब कभी कमचारी एक प्राधिकृत चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाण पत्र चाहता हो तो यह इस प्रकार के प्राधान्य पत्र के समय में चाहिए गया है। तन्मूलर ऐसे लिये गये चिकित्सा प्रमाण-पत्र के लिये सरकारी कमचारी में प्राधिकृत चिकित्सक को कोई शुल्क नहीं लेना चाहिये।

(१) प्रमाण-पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी को प्रतिहस्ताक्षर करते समय कोई शुल्क नहीं लेना चाहिये।

२. ८ (अ) तपैदिक (टी बी) और कैंसर से पीडित सरकारी कर्मचारियों को इन नियमों के साथ सलग्न अनुलग्नक में दी हुई विशेष सुविधायें स्वीकार्य होगी।^१

अनुलग्नक

(१) तपैदिक अथवा कैंसर के सदृश पीडित सरकारी कर्मचारियों को प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा निकटतम सरकारी चिकित्सालय में परीक्षण तथा परामर्श के लिये भेजे जा सकेंगे। चिकित्सालय में परामर्श का कोई भी शुल्क उनसे नहीं लिया जायेगा।

(२) सावधानीपूर्वक परीक्षा के बाद यदि मामला द्रुतगामी एवं सक्रिय पाया जाये तो सरकारी कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार देय एवं स्वीकार्य अवकाश मजूर किया जा सकेगा।

(३) सरकारी सैनेटोरियम में प्रवेश हेतु सरकारी कर्मचारी को उपयुक्त सुविधायें और युक्ति-युक्त ग्यायतें दी जा सकेंगी परन्तु शत यह होगा कि रोगी सरकारी सैनेटोरियम में स्थायी उपचार के योग्य समझा जाय।

१ सा प्र वि के आदेश सख्या एफ २ (८) जी ए/ए/बीमार/II/६४ दिनांक २१-७-६४ द्वारा समिविष्ट,

२ सा प्र वि के आदेश सख्या एफ ४ (८) जी ए/ए/बीमार II/३८ दिनांक २२-६-६२ द्वारा समिविष्ट

(४) रोगी के सस्थानीय उपचार की अवधि में सरकारी आरोग्यशाला में सरकारी कमचारी को निम्नांकित सुविधायें भी स्वीकार्य होंगी —

- (क) सरकारी कमचारी को इन नियमों के नियम ३ के अनुसार प्रतिपूर्ति योग्य औषधियों पर व्यय की गई राशि के अतिरिक्त अधिक खर्च सारता वाली ऐसी औषधियों पर व्यय की गई राशि भी, जिसकी कि प्रति पूर्ति नहीं हो सकती है, निम्नांकित शर्तों पर प्रतिपूर्ति की जा सकेगी —
- (1) औषधिया ऐसी हों जो सरकारी सनेटोरियम के चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित की गई हों ।
- (11) इस अनुच्छेद के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि २५ रु० प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी ।
- (111) निम्नलिखित प्रपत्र में उस चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र सहित जो कि रोगी की परिचर्या कर रहा है औषधियों के समस्त वाउचर उसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करके सलग्न किये जाने पर राशि की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी —

विशेष औषधियों का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती जो राजस्थान सरकार के विभाग में नियुक्त हैं तथा श्रीमती/श्रीकुमारी जो श्री/श्रीमती की/का पत्नी/पति/पुत्र/पुत्री हैं, तपदिक/कैंसर के लिये चिकित्सालय/सनेटोरियम/क्लीनिक में दिनांक से दिनांक तक उपचार में थी/था तथा उपयुक्त अवधि के दौरान अधिक खर्च सारता वाली निम्नलिखित औषधियां मेरे द्वारा उसके उपचार के लिये निर्धारित की गई थी । ये औषधियां रोगी को देने के लिये चिकित्सालय/सनेटोरियम/क्लीनिक में संग्रहीत नहीं की जाती हैं —

वाउचर संख्या
एव तारीख

औषधियों के नाम मोटे अक्षरों में

राशि

रोगी की परिचर्या करने वाले चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद

- (ख) सनेटोरियम के चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित विशेष छुराक, यदि कोई हो, के लिये उस सरकारी कमचारी को (जिसका वेतन महगाई भत्ते सहित ३२०) रु० प्रतिमास से अधिक न हो) ३० रु० प्रतिमाह का अधिकतम भत्ता दिया जा सकेगा किन्तु शत यह होगी कि इसके लिये सरकारी कमचारी को स्वयं के निम्नलिखित प्रमाण-पत्र को परिचर्या करने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करके प्रस्तुत करना पड़ेगा —

विशेष खुराक का प्रमाण पत्र

म एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं श्री/श्रीमती राजस्थान
सरकार के विभाग में नियुक्त हूँ तथा कि श्रीमती/श्री/कुमारी
जो मेरी/मेरा पति/पति/पुत्री है— चिकित्सालय/सनेटोरियम/क्लीनिक
के डॉक्टर के इलाज में तपेदिक/कैंसर के लिये रहा था/
रही थी तथा उसकी सलाह से मैंने अपने पति/पति/पुत्री/पुत्र के लिये दिनांक
— से दिनांक तक की अवधि में विशेष खुराक पर
रुपये (अर्केन) रुपये) का व्यय किया है।

सरकारी कमचारी के हस्ताक्षर एवं पद

प्रतिहस्ताक्षरित

चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद

१५) नियम ४ (ख) में अंकित रियायतें अवकाश पर रहने वाले उम सरकारी
कमचारी को भा स्वीकार्य होगी जो सरकारी सनेटोरियम के प्रभारी चिकित्सा-
अधिकारी के परामर्श से बहिरंग रोगों की तरह साता जा रहा हो।

(६) (क) सरकारी सनेटोरियम के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से रहने के
स्थान का अनुपूर्णाधिक प्रमाण पत्र पा लेने के पश्चात् जब सरकारी
कमचारी राजस्थान में किसी प्राईवेट सनेटोरियम में भर्ती किया
जाय तो सरकार निम्न खर्चों के भुगतान में उम सरकारी कमचारी
को ऐसी मामलों में सहायता करेगी जिसका महंगाई भत्ते सहित
वेतन २० रु० प्रतिमाह से अधिक नहीं है —

- (१) उसके द्वारा यदि प्राईवेट सनेटोरियम में रहने के स्थान के लिये कुछ
खर्चा दिया गया हो तो उसमें साधारण स्थान के खर्चों के लिये २५ रु०
प्रतिमाह तक की राशि दी जायेगी।
- (११) सनेटोरियम के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित विशेष
खुराक के मूल्य के लिये ३० रु० प्रतिमाह तक अधिकतम राशि
उपयुक्त अनुच्छेद ४ में दी हुई शर्तों के अधीन ऐसे कमचारियों के
लिये दी जा सकेगी।
- (१११) उपयुक्त अनुच्छेद ४ में ऐसे खर्चों के लिये दी गई शर्तों के अधीन
अप्रतिपूर्ति योग्य औषधियों के लिये २५ रु० प्रतिमाह तक अधिकतम
खर्चा दिया जा सकेगा।
- (ख) प्राईवेट सनेटोरियम में सस्थानीय उपचार के दौरान नियमों के अधीन
प्रतिपूर्ति योग्य साधारण औषधियाँ भी सनेटोरियम के प्रभारी
चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने पर प्रतिपूर्ति योग्य मानी
जा सकेंगी।

टिप्पणी

ऐसा भोसम्भव है कि सरकारी कर्मचारी विना औपधिया खरादन बचवा अनटोरियम में खर्च करने या विशेष छुट्टा के लिए एक महीने में अधिक खर्च करे तथा घाते के महीने में कम खर्च करे या इससे विपरीत ढंग से खर्च करे। अतः ऐसे मामला में सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी को उसके द्वारा हर मास के बीच किये गये वास्तविक खर्चों के बराबर रियायत-उल्लिखित प्रत्येक समय के महीने की अवधि की सीमा को अंत पर देनी चाहिये तथा उसके बाद यदि उसके द्वारा वास्तविक किये गये खर्चों के आधार पर यह जान पड़े कि उाचार की अवधि के अंततः के आधार पर वह उससे अधिक प्राप्त करने का हकदार है अतः कि उसको अनुमान दिया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में उसको इसके अन्तर की राशि का ही अनुमान कर दिया जायगा।

(७) उपयुक्त अनुच्छेदों में दी गई रियायतें सरकारी कर्मचारियों के परिवार को भी उन शर्तों के अधीन स्वीकार्य होंगी जिनके अधीन वे स्वयं सरकारी कर्मचारियों को भी स्वीकार्य हैं। इस अनुच्छेद के प्रयोजनाथ परिवार में सरकारी कर्मचारी की पत्नी/पति, जैसी भी स्थिति हो पुत्र अधिवाहित एवं आश्रित पुत्रियाँ शामिल मानी जायेंगी।

१—परिभाषा —इन नियमों में अन्तर्निहित कोई भी बात —

(i) किसी सरकारी कर्मचारी को उसके द्वारा उपलब्ध चिकित्सा-सेवाओं के लिये किये गये किसी खर्चों की प्रतिपूर्ति प्रथम उसके द्वारा की गई किसी यात्रा, किसी ऐसी यात्रा को छोड़कर जो इन नियमों में प्रयोज्य स्पष्टतः प्रख्यात है के यात्रा-भत्ते का अधिवारी बनाने या

(ii) सरकारी कर्मचारी का स्वास्थ्य उपचार या परिचर्या प्रथम उन द्वारा की गई किसी यात्रा के लिये यात्रा भत्ता त सम्बंधित बोर्ड रियायत इन नियमों में जिसे अधिस्त नहीं माना गया है, स्वीकृत करने से सरकार को रोक्ने वाली नहीं मानी जायेगी।

उपयुक्त नियम इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ ५ (७८) जी ए।ए। ५१, दिनांक ७ १२ ५१ में अन्तर्निहित सभी पूर्व नियमों और उत्तरवर्ती संशोधनों का अधिगमण करते हैं।

स्पष्टीकरण

१. अर्थात् या केवल से पारिवारिक सरकारी कर्मचारियों का विविधता उपचार के सम्बद्ध वर्तमान नियम केवल सरकारी कर्मचारियों पर ही लागू होते हैं उन परिवार के सदस्यों पर लागू नहीं होते हैं। एक प्रश्न यह उठाया गया है कि प्राया राजस्थान सेवा (स्वास्थ्य उपचार) नियम १९५८ की परिचार के मन्त्रों पर लागू नहीं होते।

मामल की जोष का कई को और यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी-कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के टी बी (नैटिक) या केवल से केवल हान पर सरकारी कर्मचारी के उन

सुविधायां और लाभों से वंचित नहीं किया जाना चाहिये जो उन्हें राजस्थान सेवा (स्वास्थ्य उपचार) नियम १९५८ के अधीन प्राप्त हैं।

२ यदि सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद मामला सन्निध पाया जाय तो सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम ६३ के अधीन अवकाश स्वीकार किया जाना चाहिये।

३ आकाश पर रहते समय सरकारी कर्मचारी में किसी सरकारी चिकित्सकीय संस्थान में उपचार की प्रवृत्ति को जानी चाहिए अथवा यदि वह ठीक समझे और सुष्ठु चिकित्सा-अधिकारी सहमत हों तो उसे किसी सक्षम प्राइवेट डॉक्टरों चिकित्सा व्यवसायी के अधीन या किसी अनुमोदित अनासक्त तपदिक मनटॉरियम में चिकित्सा करनी चाहिये।

राजस्थान सेवा (स्वास्थ्य-उपचार) नियम, १९५८ के सम्बन्ध में सरकार और निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी किये गये

महत्वपूर्ण परिपत्र और आदेश

जिस विभाग के परिपत्र समस्तस्वक दिनांक ३१ ७ ६६ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिससे यह निश्चय किया गया है कि परमावश्यक प्रमाण-पत्र और दवाइयों पर किये गये व्यय का प्रतिपूर्ति प्राथना-पत्र हिन्दी में ही माया होगा।

शुक्ति अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर के पास लगभग ५० ००० फाम अग्रोजी के उपरान्त हैं अतः समस्त विभागाध्यक्षा तथा कोषाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि परमावश्यक प्रमाण पत्र एवं दवाइयों पर व्यय के प्रतिपूर्ति प्राथना पत्र के लिये राजकीय मुद्रणालय द्वारा अग्रोजी में मुद्रित फार्मों को भी स्वीकार किया जायें।

क्रमांक एक १ ४७ वि वि व्यय नियम/६७ दिनांक २६ ५ ६७।

विषय — प्रणालगाधीन एन सी सी क्वेट और अधिकारियों को चिकित्सा सुविधाओं

जम सम्बन्ध में प्रणालगाधीन एन सी सी क्वेट और अधिकारियों के लिये चिकित्सा सुविधाओं के लिए एक सी कोई पद्धति नहीं है। इस विषय पर सभी राज्य सरकारों को भेज गये गये मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या ००१०/४८/एन सी सी दिनांक ४ १ ५६ के सम्बन्ध में उक्त प्रश्न पर विचार किया गया है और राजस्थान सहाय आदेश प्रदान करते हैं कि जम अवधि के दौरान यदि किसी एन सी सी क्वेट या अधिकारी को नियमित सेना की प्रणाली निर्मात्री इकाई में सम्बद्ध किया जाय तो उन्हें सेना के थोना स घाय सैनिक कर्मचारियों का भाति हो चिकित्सा उपचार को सुविधायें पाने का हक है। जब वे अधिकारी और क्वेट स असैनिक स्थानों में अपनी ही इकाई में प्रणाली पा रहे हों तो असैनिक थोना स किसी विनाय स्थान पर उक्त चिकित्सा उपचार नि गृह हो प्राप्त हो सकेगा।

(क्रमांक एक ४ (२२) जा ए/ए/५७ (II), दिनांक १५ १२ ५८)

विषय — एन सी सी वरिष्ठ राजस्थान स सम्बद्ध नियमित मना क कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधायें —

शुक्ति नियमित मना के कर्मचारी (तथा ज सी आ सी पी आ ड लू आ) तथा उनके समकक्ष और स्थायी कर्मचारियों का भाति एन सी सी के मुख्यालय और इकाई पर

गवर्नमेंट आयुर्वेद कालेज, इन्चार्ज गवर्नमेंट आयुर्वेद फार्मसीज ।

२ ५०० रु० से कम वेतन पाने वाले राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों के लिये ।

१ ५०० रु० से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए अधिकृत अधिकारी ।
२ समस्त 'बी' तथा 'सी' श्रेणियों के राजकीय औपधातमों के चिकित्सक ।

जहाँ पर राजपत्रित अधिकारी एवं 'ए' श्रेणी के चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं वहाँ पर ५०० रु० से ऊपर वेतन पाने वाले राजपत्रित अधिकारियों के आयुर्वेदिक एवं भूतानी औषधियों की प्रतिपूर्ति के लिए 'बी' और 'सी' श्रेणियों के चिकित्सान्तों के इन्चार्ज वर एवं हकीम अधिकृत माने जायेंगे ।

(एफ १(३०) (२) एम पी एच / ५६-I दिनांक ७ ११ १९६०)

विषय — लोये हुए चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का आडिट ।

महालेखाकार, राजस्थान द्वारा राजस्थान सरकार के ध्यान में लाया गया है कि एक तहसील में कार्य करने वाले लिपिक का चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल कोषाधिकारी द्वारा कुछ आपत्तियों के साथ लौटा दिया गया । मूल बिल को लौटाने की अपेक्षा तहसीलदार ने कोषागार में देयक बिल (ड्रॉलीकेट बिल) पेश किया और उसपर यह प्रकृत कर दिया कि बिल इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है अथवा यह कहीं लो गया है । तहसीलदार से कक्षमोमों की देयक प्रतिष्ठा (ड्रॉलीकेट) मांगी गई तो उसने उन्हें प्रस्तुत करने से मना कर दिया ।

सामान्य वित्तीय और लेखा नियमों के नियम १३० के अधीन जहाँ किसी भुगतान के समय में वाउचर या प्राप्तिकर्ता की रसीद प्रस्तुत करना सम्भव नहीं हो वहाँ भुगतान का प्रमाण पत्र वितरण अधिकारी के हस्तलेख में या यदि जरूरी हो तो उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करके उन परिस्थितियों को व्यक्त करते हुए अभिलिखित किया जाना चाहिये जिनके कारण ऐसी व्यवस्था करनी अपेक्षित जान पड़ी है । ऐसा अभिलिखित प्रमाण पत्र और कारण प्रकट करते हुए आपन जहाँ जरूरी हो वहाँ महालेखाकार को भेजा जाना चाहिये ।

समस्त सम्बद्ध अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ऐसे मामलों में वाचों के पूर्ण विवरण नियमित बिल पर अनिवार्य व्याख्यात्मक आपन के साथ प्रमाण पत्र सहित प्रकृत किये जाने चाहिए तथा आह्वयकर्ता या प्रति हस्ताक्षरकर्ता अधिकारियों द्वारा यह भी उसमें प्रमाणित किया जाना चाहिये कि मूल कक्षमोमों और वाउचर इत्यादि प्राप्त किये गये, सत्यापित किये गये और मूल बिल के साथ सलग्न किये गये थे ।

(एफ डी (रैवन्सू और ई ए) आदेश संख्या डी ८८८/एफ डी / ई/ जनरल/६१ दिनांक ८ अप्रैल १९६१)

राजस्थान सरकार ने निश्चय किया है कि उन अनिवार्य सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को, जो वर्तमान आपत्तिक स्थिति में सैनिक सेवा में स्वीकृत कर लते हैं, ठीक उन्ही कर्मचारियों के समान चिकित्सा सुविधायें प्राप्त होनी चाहिए जो समकक्ष असैनिक पदा पर कार्य करने वाले अधिकारियों को प्राप्त होती हैं ।

(सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश संख्या एफ २ (१) जी ए / ए / जी आर. / II /

६२ दिनांक ५-१-६३)

विषय — चिकित्सा बिलों का दो बार उठाया जाना ।

महालखाकार ने सरकारी कमचारियों द्वारा दो बार उठाये गये चिकित्सा-दावों के कुछ मामलों सरकार को सूचित किये हैं । मामलों की जांच की गई तथा यह विचार किया गया है कि यदि नियंत्रण अधिकारी बिलों पर प्रति हस्ताक्षर करते समय उनको उचित जवाब दें तो ऐसे दुहरे भुगतान से बचाव हो सकेगा । यह निश्चित करने के लिए कि मेडिकल स्टोम द्वारा जारी की गई कथमोमो काम में नहीं लगे जा सकें, नियंत्रण अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित तरीका अपनाया जाना अपेक्षित होगा —

१ यह देखा जाना चाहिए कि कथमोमो पर दी गई नियमावली दावे से सम्बंधित अवधि के अन्दर ही है ।

२ कथमोमो के आधार पर लाभ स्थायी है यह नोट लगा दिया जाना चाहिये कि उसके भुगतान का दावा बिल संख्या " " तारीख राशि में किया गया है ।

(सरकारी आदेश संख्या एफ २४ (२०) एनडी (एनडी) / ६२ दिनांक ३-२-६५)

आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या एफ २ (२०) जी ए / ए / जी आर - II / ६४ दिनांक ५-१०-६२ के अनुसार सभी प्राधिकृत चिकित्सकों को इस आदेश में प्रदत्त प्रपत्र में एक पत्रिका संचारित करना अपेक्षित है और उनमें परमावश्यकता-प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करना आवश्यक है । किन्तु इसके सम्बन्ध में यह अभिवेदित किया गया है कि प्राधिकृत चिकित्सकों द्वारा यह आदेश काफी विचित्र से प्राप्त हुआ था अतः इसी कारण इस आदेश के अनुसार दिनांक ५-१०-६४ से अनुपालन सम्भव नहीं हो सका ।

२ इस मामले की जांच की गई है और राज्यपाल सहय आदेश प्रदान करने हैं कि दिनांक ५-१०-६३ से दिनांक ३१-१२-६४ तक की अवधि के बीच के दावों को बिना उक्त अनुदेश के अनुपालन किये ही स्वीकार किया जा सकता है चाहे इन अवधि के परमावश्यकता-प्रमाण पत्रों पर दावों के सम्बन्ध में आदेश में चाहे गये अनुसार पत्रिका के क्रमांक भले ही दर्ज नहीं किये गये हों ।

३ अतः उक्त आदेश की इस अनुच्छेद २ में दी गई सीमा तक के लिये संशोधित माना जा सकता है ।

(क्रमांक एफ १ (४१) व्यव-नियम/६५ दिनांक २६-७-६५)

विषय — राजपत्रित अधिकारियों के लिये वेतन-पत्रों के अभाव में चिकित्सा-व्यय की पर्चियां ।

वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ १६ (६) एफ / ए / ६० दिनांक १८-११-६० की ओर ध्यान आकषिप्त किया जाता है जिसके अनुसार अतन पत्रों की अनुपस्थिति में राजपत्रित अधिकारियों के यात्रा व्यय के दावों का पास किया जाना अनियमित माना गया था । किन्तु

Antismat	Air Rings
Adrenapax	Amorphos
Algipan Ointment	B*
Algochratine Cachets	Bigly cere Pepsin
Allantoin	Brush
Allochrysine Suppositories	Buckfast Tonic Wine
Anaardone Solution	Shustab
Angioxyl	Biochlor Tablet
Antaiby Tablets	Bandage (Not Drug)
Antoxylin	Bathn Complex
Anti Haemophylla Principi	Bog Vaccine
Acriflex	Biphlogistine
Alka Cip Tablets	Broon Liquid C Nebuliser
Alka Seltzer	Bishop s Citrate Of Lithia
Alkia Saltrates	Bendial Solution/Benedict's
Allcock s Porous Plaster	Solution
Almakal	Bidel Compound
Aloes Compound	Bonchiol
Alefrina	Box Of Nutrone
Anne French Cream	Bidello
Abzol Powder	Benzocin Lozenges
Agream	Burnol
Anklozid	Beladonna Pigment
Acid Carholie	Brewer s Yeast Syrup
Adhesive Plaster	Bio-Sal
Abdominal Binder	Bi Shicrobotolinhalant
Acecolex	Borofa
Adrenaline Tablets	Boldine Houde Tablets
Aspergum	Burgoyne s Iodised Sarsa
Aruna Uterin Tonic	Parilia
Antiseptic Cream	Biomim Syrup
Argentum 'Oscol'	Blood Percolator
Absorbent Cotton (Not Drug)	Betalysin
Anadin Tablets	Bacte Dysenterii Phage
Analax Pastilles	Bacte Inseti Phage
Andrew S Liver Salts	B Tex Ointment
Anestan Asthma Tablets	B-Neurophos Elixir
Angier s Emulsion	Bynadol Liquid
Anti Kamnia Tablets	Bertzyme
Ashton & Porson S Infants	Bilogen
Powders	Becantex
Askit	Bronchinson Cough Syrup
Atkinson & Barker's	Becophos
Infants Preservative	Betonin Liquid
Antifluue Tablets	Borax Honey
Ayazol	Burns
Aeri Flame	

Bmag Faste	Brandy
Boroline	Biltone
Bioplex Forte	Bor Henzolan
Bencard Allergy Remes	Bisum Cone Suppository
Banalona	Banaid
Beconex	Brilhan Grease
Benafet	Bahng Powder
Baby Oil	Belt
Bio Malt	Borated Tin
B D Vine	Benzidine
B G Minelxir	B Adhesive
Boric Rectified Spirit	Barracha Biheron
Bisodol Pulves	Bioferbin
Broven Inhaler	Bordox
Brookle Tablets	Bisurated Magnesia Tabs
Bacte Coli Phage	Bisuroids Laxative Tabs
Bis U Mint Ovals	Blair's Gout & Rheumatic Pills
Bisurate Magnesia	Blanchard's Female Pills
Bacte Pyo Phage	Blinblow's Asthma Cure
Bacte Staphy Phage	Blinblow's Eucalyptus & Stramonium Cigarette
Benecardin	Bluelion Fox Nuts (Shadforth's)
Benzoyl Peroxide Wolley	Bonomint Laxative Chewing Gum
Bioglan	Bowden's Indian Balm
Balsamic Emulsion	Bow's (Dr) Liniment
Barker's Liquid Of Life	Box's Herbal Ointment
Bates & Cos Compound	Box's Indigestion Pills
Breastal E	Bragg's Prepared Vegetable Charcol
Baxen Powders	Breches Stimulating Ointment
Baxen Tablets	British Spa Crystal Salts
Beecham's Cough Pills	Brocast Inhalant
Beecham's Lung Syrup	Bromo Saltzer
Beesham's Pill	Bunters Nervine
Beecham's Powders	Burgress Lion Ointment
Beltona Antiaritic Tablets	Burgress Lion Pills
Beltona Lotion	Buxton Rubbing Bottle
Beltona Ointment	Bristacyclin Pediatric Drops
Berorbon Medical Snuff	Barley
Betalax Drops	Barley Pearl
Bilae Pills	Bottle Feeder
Bile Beans	Breast Pump
Bilson's Laxative Cleanser	
Birley's Antacid Powder	
Bishop's Natural Fruit Saline	
Bishop's Varailattes	
Bishop's Varailettes	
Vichy Salts	

Cotton Borie
 Cawtex
 Cotton Wash
 Cold Creams
 Carica Tablets
 Cloth
 Carboxyl
 Casydral
 Cusi Denmozo
 Calogen
 Children Tonic
 Capsules Gelatine
 Crooks Emulsion
 Completone
 Casinone
 Crepe Bandage
 Charim Tablets
 Caliper (including raising in the
 Shoe etc complete elevator)
 Cusi Resolvent
 Caisiloids Tablets
 Calavix Cream
 Calvox Ointment
 Cochine

D'

Durol/Liquid
 D D D Lotion
 Dustin Powder/Antiseptic
 Dendruft Lotion Crooks
 Decholine
 Daya Mineral
 Digestin
 Digest
 Digestive Syrup
 Digesol
 Dagra Honey Syrup
 Duent
 Diabetox
 Deimor
 D K Salt
 Diaphreg in Jelly
 Duphasol Vit-D 3/Vit-A
 Diporosin
 Dinognatol Chesedon
 Duphasol
 ical

Dollorina
 Dextranil-D
 Diorein Cream
 Danish Ointment
 Decomalt
 Dentol Toothache Powder
 Delvit Liquid
 Deschien's Syrup Of Hae-
 moglobin
 With Vit B 12
 Ducogen
 Dressing Surgical
 Degalan Ointment & Sup-
 positories
 Dehydronmase & Rosterone
 Tablets
 Delbiase Tablets
 Deschiens Syrup Hemoglobine
 Deschiens Syrup Hepathemo
 Detensyl Tablets-Vegeto-
 polynor-Monib Hypotensor
 Di Iodotyrosine Tablets
 (Pabyrn)
 Dismensol Tablets
 Duodenin (Palatinoids)
 Duodenin Tablets
 Daisy Powders
 Daisy Tablets
 Damaroids Tablets
 Davis's (Dr) Famous Female
 Pills
 D C L Vitamin B Yeast
 Tablets
 D D D Balm
 D D D Prescription
 Deakin's Lung Healer
 Deakin's Inflammation Remedy
 Dettol Ointment
 Dettol Gargle
 De Witts Antacid Powder
 De Witt's Catarrhal Cream
 De Witt's Kidney & Bladder
 Pills
 De Witt's Little Luxative
 Pills
 Digey's Dr Bateman's Drops
 Digestif Rennies Tablets

Dinneford's Magnesia
Tablets
Dinneford's Pure Fluid
Magnesia
Diotex Tablets
Doan's Backache & Kidney
Pills
Doan's Ointment
Dodd's Kidney Pills
Do-Do Pastilles
Do Do Tablets
Dolchin Tablets
Dol's Voltalise Rub
Drexamin Cream
Drury's Infant's Preservative
Duoformua Tablets
Dutch Drops
Dextrosol
Distilled Water
Depil
Dtopper Eye
Devibiso
D D. T Powder
Ditralka
Diana
Dollorin Cordis
Dietary Supplement
Depilatory Wax

E'

Eledrin Dried Milk
Elixir B C Mineral
Extra Sterilised Pads
Elixir Vital
Ethi Vite Syrup
Elixir Muristanint
Elixir Fevromyn
Eupeptic Tablets
Ex Tross
Enzyindrin Syrup
Elasmin Pearls/Drops
Evaholia Tube
Elixir Thiaden
Eard Alibour
Ecimalt (Everest)
Enhodrvl Capsules
Enden Drops

Elixir Combitone
Elixir Vibeta
Elixir Morhuvine
Emulsion Hypophosphate
Effico Tonic
Elixir Phosferine
E C Lotion
Elixir Vita Com Forte
Eskay B 1
Elixir Keliples
Elluman's Universal Embroca-
tion
Elixir Neo Cordial
Eisocal
Eutheria Cream
Elixir Peptenzyme
Essence of Chirata
Emp Belladonna Liquid
Ext Ergot Liquid
Eye Wash
Ezotone
Enterocurmol
Entero Sulphazyme
Ethobral
Ephomag Elixir/Tablets
Energon
Epcol Cough Syrup
Elixir Utaferon
Elixir Heposim With Extra
Folic Acid & B-12
Ephemix
Elixir B C 50
Elixir Panthor
Elixir Poly B Complex
Elixir Vimelto
Embelix
Elixir Panovin
Elixir Aminoxyl
Elixir A D M
Eve's Cordial
Elixir Lacteena
Elixir Calcylsine
Elixir Gynol
Elixir Combitone
Elixir Vali Vrom Evans
Elixir Val Bromide Smith
Eiasro Grape Bandage

E L A Emulsion Lactoba
 Cillos Acidophilus
 Emge Tablets
 Eade's Antibilious Pills
 Eade's Rhematic & Cont
 Pills
 Eade's Universal Anodyne
 Ecsolent Compound
 Egyptian Salve
 Eko
 Elasto Nature Salve
 Elasto Tablets
 Elliman's Athletic Rub
 Elmbaimskin Ointment
 Eno's Fruit Salt
 E N T Nerve Powders
 Ephedrol Inhalant
 Esobactolin Capsules
 Ex-Lax Chocolate Laxative
 Chlixir Vitabin
 Eskay B Complex
 Elastic Plaster
 Essence Of Chicken
 Ephadibe Oil Drops
 Elastic Bandages
 Elixir Embrocation
 Essence Of Pepermint
 Eledon
 Electric Vaporizer
 Eiosol 10% Drops
 Effervescent Sandostin
 Tablets

'F'

Fever Powder
 Felosol
 Ferro Drakshomalt
 Fero Blimin
 Fervomyin Elixir
 Floss Silk
 F Liquid
 Fosderyl Pills
 Fungex Cream
 Fungus With Prednisolone
 Fruit Lax
 Florozone
 Fchin Solution

Fri Pyrine
 Farex
 Feroglobin
 Feroion
 Foliplex
 Tematone
 Fruitlan
 Felatone Syrup
 F 99 Capsules & Ointment
 Fer Bravais
 Ferrum Oseol
 Fertitol Cream
 Fosfexyl Pills & Syrup
 Fructole Blackcurrent
 & Iodine Pastillas
 Falconer's Golden Compound
 Famel Syrup
 Feedlar Bottle (Not Drug)
 Feenamints
 Fennings Adult Cooling
 Powders
 Fennings ■ Children's
 Cooling Powders
 Fenning ■ Little Healers
 Fenning's Ointment
 Fennings Stomach Stret
 Theners
 Tenning's Rheumatic &
 Erysiales Drops
 Fennings Whooping Cough
 Powders
 Fenning's Worm Powders
 Ferute Elixir
 Fibron Adrenaline Cream
 Firth ■ Cream Salve
 Fission Analointment
 Fissan Anal Suppositories
 Fissan Paste
 Fitilin Revitalising Rub
 Formitoral Formalin
 Psatilles
 Freeman's Chlorodyne
 Fresone Corn Remover
 Fructolax
 Fructole Carpina Co (May
 Fair A Brand)
 Frulgar

Fuller Brand Celery
Perles
Fynnon'salt
Fruitsalt
Fellow's Syrup
Farilan
Fenlexmatt
Ferrylyn
Feeder Grip Tight
Female Cordial
Ferromalt
Finlex

G

Gumpaste (U D Co)
Gumpaint
Glass Urinal
Glycero Pepsin, BI
Gripe Ease
Gripe Liquid
Glycomalt
Grimix
Gharbinol
Gulioix
Gastridine
Gingivitis Powder
(Special)
Gynedol Liquid
Gajjartora
Gripe Water (Warden India)
Gripe Water Carminative
(Woodwards)
Gripe Mixture
Glaxod
Guncetta
Gynedal
Grimault Haemoglobin
Forte
Glucose Solution Crooks
Glucose Tablets
Glucotone
Guy's linctus
Gets-It
Gynosedan
Glucosein
Glycodin Lozenges Gasex
Tablets
Goulard's Lotion

Glysovit
Guitac Ephedrine
Glycomal
Gastrozyme
Gynaecolin
Glycerin Extract Of Red
Bone Marrow Glandoid
Gomeno Essence (Gomenol
Laboratories)
Guipine Pills
G S Tablets
Galloways Family Lung
Syrup
Gar Antiseptic Ointment
Garisoal
Gees Lobelline
Gee's Lobelline Lozenges
Genasprin Tablets
Genosal Nasol Cream
George's Sgravel Pills
George's Pills & Gravel Pills
George's Pills For The Piles
Germolene Blood Purifier &
Tonic
Germolene Ointment
Grasshopper Ointment
Germoline Tablets
Geronyl Tablets
Germoloid's Suppositories
Gilleys (Dr) Herbal
Laxative
Guys Fruit Pills
Guy's Tonic
Gripe Lq
Gluco
Germicide
Gelonic
Galacogeno
Germex
Gincola
Glass Rod
Grape Sugar
Gharbinol
Genatone
Genelinc
Gluco Vita
Glycolactophos

Greenfield's (Dr) Whooping Cough Mixture	Hayward's Tonic Wine
Gauze (Not Drug)	Halcytol
H	Ha Vimin Co Folic Acid
	Health Salt
Hodge's Pessary	Huxleys Wintigen
Hepoferrum	Hydro Protein
Hinco Tonic	Heme Malt
Himco Tonic	Hinutrone
Herbs	Hepsonin Elixir Cextra
Herbal Bitter	Folicacid & Vit B 12
Herbolax	Hemocalvit Elixir
Herbolax Strong (for constipation)	Hicoin Elixir (Cough Syrup)
Hair Lotion Tincture	Haemorrhoidal Ointment
Himrods' Cure	Hemogynol
Hipro Mil	Heposim Cvit B 12
Huxloy's Nervigor	Halabak
H 202 (Hydrogen Peroxide)	Haimo Gerobion
Heart Drops	Hepacod
Hexabe	Hev Itron Liquid
Halibut Oil Capsule Liver	Halmegon Tablets
Halibut Orange Liquid	Histamine B D H Ointment
Hemo Ashoka	Hypotensyl Tablets
Hemostyl Syrup	Hair (DR) Asthma Cure
Haumasbro	Hair s (DR) Asthma Cure Pastilles
Halingol	Hair s (DR) Bronchial Cou
Hemopatp (Grimoult) Elixir	Hhremedy
Haliborange	Hair's (DR) Liver Pills
Hydremim	Hair's (DR) Catarrh Cure Pills
Henopital	Haratox Tablets
Haemopetolb Complex	Harley s Three Salts
Hydrine	Healex Skol Antiseptio
Honey	Health & Heather s Catarrh Pastilles
Hepatone	Harbalene (Lusty s)
Hepoblum	Herbile Pills
Hepa Nima Fort	Hewletts Teething Jelly
Halibutol Orange	Hinksman's Asthma Cig- arettes
Halivitoll Orange	Hinksman s Asthma Reliver
Haliborange Large	Hinksman s Asthma Smo king Mixture
Hepatex Malt Liquid	Hockin s Remedy
Hewlets Mixture	Holdroyd s Gravel Pills
Hewlettsmistura Pepsin	Holloway's Ointment
C-Bismuth Co C Opium	
Haemoglobin Forte	
Haemoglobin Elixir	
Haemoglobin Syrup C B 12	

Halloway's Pills
Honocea Ointment
Hooper's (Dr John) Female
Pills
Hoyle & Pure Vegetable
Viscous Oil
Hytex Pille Balm
Hesanol Ointment
Hot Water Bottle
Haleline Snow
Hydraminos
Hygiene Powder
Haemogastine
Haemogastine Tonic
Haemobin
Hepagest
Hepels Coy
Holins Pray
Hind's Cream
Hermo Be Dozo
Hachemina
Hablouane
Halingol

1

Itinsucrets
Insanity Cure
Iso Calcium
Irrigator
Irrigatorpire
Inted Tablets
Ina Carabin
Influenza Tablets
Inhalur Huxley's
Indu Compound
Iodine Ointment
Iodised Sarsap Anilla
Iversal Longes
Isabgol
Isogel
Iodoform Powder
Iso Glutamalt
Ivi Malt
Iodemex
Ipac Malt
Inositol Capsules
Intrait De Marrond

Inde Dausse Solutionp
Iodine & Blackcurrent
Pastiles
Iodo-Peptune
Indorubid Calcium Ophthal
Mic Ointment Cusi
Ivax
Ideal Warming Liniment
Iglodine
Igolodine Antiseptic Ointment
Indian Oerate
Infants's Friend
Iodine Model Aseptic
Ointment
Ina Carabin
Ionised Iodine (Molson)
Brand
Irvine
Iron Putty Fitting C Pully
Irvona Tablets
Isocol
Iodise Throat Tablets
Iodalbin
Ice
Ice Cap
Irosol Syrup
Ice Collar
Infantone

J

Jackman's Convulsion Cure
Jayakar's Convulsion Cure
Jamins Liver Cure
Jamins Liver Cure Complex
Jyrothericine Chewing Gum
Jackson's Febrifuge
Jenner's (Dr) Absorbent
Nozenge Brand Digestive
Tablets
Jesta Tablets
Jif Neuralgic Powders
Jocigares
Johnson's (MRS) American
Soothing Syrup
Jordan's Gin Pills
Juno-Jumpah Salts (Powders
& Tablets)

Milkan/E H	Malto Vito
Milkan Paste	Maltovit
Massage Oil	Malt-Vitol
Maternity Belt	Malt Vitonin
Meads Protein	Malt Viron
Manestrin Capsules	Mand H Emulsion
Metametrol	Myn Berry's Compound
Minaferrol	Metheryl Testo Viron Tablet
Methofar	Meta Drops
Minvitone	Maltograf
Minavitrol Syrup	Magsulph Cream
Mycodeoyl Powder	Medica Belt
Mycodetyl Pomade	Maclean indigestion Powder
Moryl	Mandles Throat Paint/ Pills Solution
Massy's Nipple Ointment	Miaulks
Masse Nipple Cream	Multivitamin Fipa
Masse Ointment	Mist Feprient Ammin Cit
Mist Seillac	Mitsons Liver
Mixture Tone	Multivitaplex Elixir
Methugun Tablets	Mulvilysin
Mount Malt	Minervin
Meta Metron Tablets	Mebran Elixir
Multi Tone	Multivit Candy
Multi Ionic	Mvrone Tablets
Magsil Tablets	Mistona
Malt Vitex	Maclean Brand Stomach Tabs
Malt Vitex C Iron	Magtriz Powder/Tablet
Malt Iron	Magsilate Tablets
Mivets Tablet	Manzan Pile Remedy
Mivets G Tablets	Marienbad Anti Obesite Tabs
Minaferrol Vit E	Marmola Antifat Tablets
Metacin	Mathews Fullers Earch Cream
Mercolized Wax	Mecca Pailles (Gibson)
Mag Mag	Medilax Laxative Pellets
Mixtures (Only patent mix- tures as Ague Mixture, etc.)	Meggesone Bismuth Dyspep- sia Tablets
Mettaral	Meggesones
Mag Mag Plaster	Melba Iodised Throat Tabs
Magnatone	Mendaco Tablets
Marmite	Mensal Pills
Metules Sandoz Capsules	Magnogone Tablets
M & H Elixir	Mammary Capsules & Tablets
Molvex Compound	Mammary Gland 'Palatinoids'
Mebradal	Manganese Oseol
Massived Drops	
Milko Mag Tablets	
Manner's Gripe Mixture	

Muscle Extract—Oxoid
 Myelin Capsules & Tablets
 Mac Brand Antiseptic Throat
 Sweets
 McClure's Balsam
 McClure's Crescendo Vitamin
 Tonic Syrup
 McClure's Ephedrine Nasal
 Catarrh Specific
 McClure's Oxogen Tablets
 McClure's Glucomel
 McClure's Glucose Tonic
 McClure's Vaposan Outfit
 Maclean Brand Stomach
 Powder
 Musteroide Mustaraed Oin-
 ment
 Multitone
 Milton Tablets
 Milkan cod Liver
 Manola
 Measure Glass
 M & E Pastilles
 Melgodin
 Morhussion
 Mavilot Malt
 Malt Vitex
 Malt Kepler
 Malt Osto
 Malt Compound Navitol
 Malt Nesto
 Malt Easton (if given to
 adults)
 Mackin Toss Sheeting
 M O Towels
 Material (Dressing)
 Massive Vitamin
 Mandy Paint
 Mandol Malt
 Milk of Magnesia
 Malt Extract (cod Liver
 Oil (A & H Co)
 Malt Cod Liver Oil (Allin &
 Haily)
 Malt Extract (Magn Malt)
 Micoren pearls/drops/Capsu-
 les/Tables
 Metatone

Mentex
 Mentholatum Antiseptic
 Nasal Liquid
 Mentholatum Balm
 Mil Par Brand Laxative
 Milton Antiseptic Ointment
 Mistol Drops Ephedrine
 Moffat's (DR) Remedy
 Monsol Throat Pastilles
 Moorland Indigestion
 Tablets
 Morse's (DR) Indian Root
 pills
 Mortons Elder & peppermint
 Life Drops
 Mothersill's Digestive
 Syrup
 M Rex Pile Ointment
 Muller Nutrient (The)
 'N'
 Nutrimea
 Nutritone Capsules
 Nutrone
 Nutroton
 Nutroton Box
 No Pain
 N E Sulphar
 Neo Dentol
 Neuro Phosphates
 Neuro
 Nefer Tablets
 Nefer Tablets
 Nufer Tablets
 Nephrol Tablets
 Nycil Ointment
 Nycil Powder
 Neuro Lecithin
 Navitol Cynos Terol
 Nionate
 Nejdruken Tablets
 Netrada
 Navitol
 Niva Cream
 Nivea Cream
 Necoferin
 Norway Cod Liver Oil
 Nervorite Mine
 Nisho Soap

Nervigor	Needle Hypodermic
Nutrinatal Tablets	Nestargel—
Neo Sedalcer Tablets	Norasirob
Nuroph	Nivea Skin Oil
Nico Flavin	Nursing Powder
Nobedon	Nursing Case Book
Nutro Lysate	Neogynges
Neurona B Comp ex	Nipple Shield or Nipple
Neurophos	Navitol Malt Compound
Noval Gin Quinine	Needle
Neo Kimsyrup	Neadallit
Nephritin Tablets	Nozel Set
Nicamide Solution	Natrisol
Nizin Ophthalmic Ointment	
Susi	
Noviform Ophthalmic	Oriental Balm
Ointment Cusi	Oxygen Cylinder
Nasimint Snuff	Oralt
Nature's Herbal Ointment	Ointment Milkman o Cod
Naturpeat	Liver
Nemakol Brand Nasal	Optibits Abbott
Compound	Oleum Arachis
Nemolin Pile Ointment	Ovoto Line
Nervoids	Olive Oil (External or Inte
NETCQ 444 Pills	rnal)
New Skin	Olive Oil & Cod Liver Oil
New Sphagol 10%	Oralex Liquid
Ointment	Ortho Applicator
Niblett's (DR) Vital Rene	Oonim (Male)
wer	Optrex Eye Lotion
Nigroids	Ossivite
Nipits	Ommicidine
Nonn Tablets	Opicychne Capsule
Normo Gastring Tablets	Oxycede
Nortons Chamomile pills	Optisol Eye Ointment
Nostroline Nasal Remedy	Opimalt
Noxacorn	Opimalt Syrup
Nujol	Optinal Eye Drops
Nurse Harveys Mixture	Oberlin Granules of Chicken
Neko Soap	Embryo
Neson Inhaler	Opo Iodamelis Tablets,
New Dentol	Female & Male Formula
Natrum Phos	Orchie Substance Emplements
Nestomalt	(No 15)
Noviazole	Orohitate (Pabyrn) Lighar
Neutroxides	Pessaries & Tablets
Nixoderin Ointment	Orchitin Palatinoids
Nestrina	Ovacoids Tablets

Ovarian Residue 'Palatinoids'
 Ovarian Substance 'Palatinoids'
 Ovarian Substance Empleta
 Ovarian & Pituitary 'Palatinoids'
 Ovary Residue Tablets
 Ovarian & Mammary 'Platinoids'
 Ovary Whole Gland Tablets & loz
 Desiccated Powder
 Ovesedicyl Drages
 Odds On Liment
 Okasa Tablets
 Omega Oil
 One Day Cold Cure
 Opas Maclean Powder
 Opas Maclean Tablets
 Optrex Eye Lotion
 Oralx Tablets
 Osborne's Mixture
 Owbridge's Lung Tonic
 Owbridge's Lung Tonic Pastilles
 Oxien Nerve Tablets
 Oxien Pills
 Oystrex Tonic
 Orlivit
 Orange Squash
 Oiled Rayon
 Orhaptol/Oratol
 Ohiviford/Oates
 Oleum Araches
 P
 Perandren Linquets/Onitment
 Peranden
 Pablum (Cereals)
 Pepsindon Tablets
 Pessay
 Pepsin B1 Glycerol Paste
 Palmolive Shaving Cream
 Phosphotone
 Phosphomalt
 Powder Antiseptic Dusting
 Powder Dusting

Pyrodent
 Primoderm Mild Cream
 Pulverizator for Oily Liquids
 Pilex
 Petrocil
 Pyson Mouth Wash
 Pyson Gum paste
 Phinl Halycitrol Crookes
 Panovin/Compound
 Phmasine
 Paloll
 P V T Solution
 Pasiso Vitere
 Paragon (Reel)
 Pacto Calcium
 Pacto Malt
 Panthesine Balm
 Poly Malt
 Pilex Ointment/Tablets
 Penetrol Sulpha
 Protine
 Protein Hydrocylal
 Protovine
 Peptovintone
 Pepsinal
 Pepsinol
 Promolan
 Phosphogodine
 Prolypo
 Pharma Compound
 Plaster Zinc Adhesive
 Pearl Barley
 Pho Sferine Syrup
 Pigment Behadona
 Petterson's Oky Pills
 Progneter Cream
 Pepsi Digestive
 Pepsi Digestine
 Pmeal Compound
 Pyrgasol Hozenges/Tablets
 Petromulsion
 Petromulsion C Gualacol
 Polybactrin
 Potchlora Powder
 Potassium Chloride
 Potassium Chlorate

२१ अतिरिक्त सुविधायें — निवास के मकानों में अतिरिक्त सुविधाओं जैसे फर्निचर, उद्यान, वी व्यवस्था निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जायेगी नामाध —

(क) यह कि ऐसी सुविधाएँ मकान में रहने वाले के सरकारी पद, उसके अन्तर्गत समाविष्ट सामाजिक वृत्तव्य तथा अन्य सारभूत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सुविधाओं से अधिक अथवा अधिक व्ययशील नहीं होगी,

(ख) यह कि सिवाय विशेष परिस्थितियों के ऐसी सुविधाएँ उन राजकीय कर्मचारियों को नहीं दी जायेंगी जिनको भुगत मकान मिलने का हक हो, और

(ग) इस प्रकार की सुविधाएँ जैसे टेनिस कोर्ट वेडमिंटन कोर्ट गायों के लिये छ पर मुर्गी खाने आदि सिवाय सामान्य प्रशासन विभागीय सरकार की विशेष स्वीकृति के, नहीं दी जायेगी ।

२२ उद्यान का किराया — (क) इन बगीचों का किराया जो सरकार द्वारा लगाये गये तथा सरकारी देखरेख में रहे जा रहे हों अस्थाई आधार पर निम्नलिखित आधार पर निर्धारित किया जायेगा, और उसमें समस्त व्यय जैसे कि मालियों कुसियों, खाद, बीज तथा बेल जो पानी छोड़ते हों अथवा पानी का अन्य शुल्क सम्मिलित होगा । यह मकान में रहने वाले के वेतन से मासिक वसूल किया जायगा और वह मकान किराये के अतिरिक्त देय होगा —

वार्षिक आवश्यक अस्थाई शुरुक अजमेर जोधपुर, बिकानेर डिवीजनों में	प्रस्तावित अस्थाई दरें	अन्य डिवीजनों में वार्षिक आवश्यक व्यय	प्रस्तावित अस्थाई दरें
४०४	२५	४०८	२२
४०८	३०	३००	१८
३००	११	२०८	११
२४२	१२	२०४	१०

ये दरें इन नियमों के जारी होने की तारीख से एक वर्ष के लिये वसूल योग्य रहेगी और एक वर्ष पश्चात् इन पर पुन विचार किया जायेगा ।

(ख) (१) दूब इत्यादि केवल ए बी' 'सी' तथा 'डी' स्तर के सरकारी बगनों में लगायी और रखी जावेगी जसा की स्थान की अंशो सम्बन्धी नियम में बताया गया है ।

(११) विभिन्न स्तरों के निवास स्थान के लिये बगीचे की सीमा निम्नलिखित मात्राओं से जो विभिन्न अंशों के निवास स्थानों के लिये है अधिक नहीं होगी —

अंश	दूब	भाटियें	फूल की क्यागिया	बाड़े
ए	३०० वर्ग फीट	१०० वर्ग फीट	१२ क्यागिया	१००० वर्ग फीट
बी	२५० वर्ग फीट	८० "	८ क्यागिया	८०० वर्ग फीट
सी	२०० वर्ग फीट	७० "	६ क्यागिया	७०० वर्ग फीट
डी	१५० वर्ग फीट	६० "	४ क्यागिया	४०० वर्ग फीट

(iii) घनावर्ती तथा वार्षिक आवृतक व्यय जो प्रत्येक श्रेणी के मकानों के लिये बगीचे लगाने तथा इनको कायम रखने के लिये किया जावे, वह निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा —

श्रेणी	घनावर्ती	आय	आवृतक	आय डिविजनो
	अजमेर, जोधपुर झोकारे, राजस्व डिविजनो मे	डिविजनो में	अजमेर जोधपुर झोकारे के राजस्व डिविजनो में	मे
ए	३८०	४२०	५०४	४०८
बी	३००	३८०	४०८	३००
सी	२५०	३००	३००	२२८
डी,	२१०	२५०	२५२	२०४

१(ग) बगीचे की रूप रेखा सरकारी उद्यान अधिशासी द्वारा पुराने या नये बगलों के लिये निर्धारित माना मे बनायी जायेगी। मकान मे रहने वाले को यह विकल्प नहीं होगा कि वह ऐसे बगीचे की रूप रेखा के लिये निजी व्यवस्था करे। बगीचे की देख रेख का काय भी मकान में रहने वाले के विकल्प पर अव नहीं किया जायेगा।

२३ उद्यान के अतिरिक्त आय सुविधाएँ — टैनम कोट गाय के छप्पर तथा आय दो गई और कायम रखी जाने वाली सुविधाओं के लिये किराया निम्नलिखित होगा —

(क) सरकार के व्यय पर किये गये पू जी मूल्य की राशियों पर ४ प्रतिशत की दर से ब्याज, तथा

(ख) उसकी वार्षिक देख रेख के लिये राशि जो सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता भवन तथा पथ अनुमानित करे।

(ग) इस नियम के अधीन किराया इन नियमों में निर्धारित आय किरायो के अतिरिक्त होगा।

२४ विजली का पम्पिंग सेट — (१) विजली के पम्पिंग जो कि सरकारी व्यय पर किसी आवास गृह में लगाया गया है किराया मासिक वसूल किया जायेगा जो ४३ प्रतिशत की दर स वष भर के लिये आवश्यक राशि का १२ वाँ भाग होगा, तथा वार्षिक भरभमत के लिये सेट के पू जी मूल्य पर १३ प्रतिशत होगा।

(२) एक दफा जब कि किसी आवास गृह में पम्पिंग सेट लगा दिया गया हो तो उसके किराये का उसमे रहने वाला देन दार हो जायगा चाहे उसको उक्त पम्पिंग सेट की आवश्यकता हो अथवा नहीं अथवा वह उसका उपयोग करता हो या नहीं। उसको चलाने के लिये विजली का खर्चा भी उसी को वहन करना पड़ेगा।

२५ मुक्ति — विशेष परिस्थितियों मे तथा जिनके कारण अभिलेखित होंगे सरकार प्रादेश द्वारा इन प्रकार की सेवाओं के लिये जैसे जन प्रदाय सेनिटरी या विजली की सामग्रियों तथा फिटिंग जैसे पर्नीचर टैनिसकोट, बगीचे गाय के छप्पर

मुर्गी खाने आदि जो गवनमेन्ट के खर्चें पर रखे गये हो उनका अतिरिक्त किराया माफ कर सकेगी या कम कर सकेगी ।

२६ फर्नीचर का किराया —सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार दिय गये फर्नीचर का किराया पूजो मूल्य के १/३ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वसूल किया जायगा और निर्धारित मात्रा से अधिक फर्नीचर देन पर लगे हुए पूजो मूल्य का १/८ प्रतिशत वसूल किया जायगा ।

२७ मीटर के किराये —(१) बिजली पानी तथा अन्य मीटरों के लिये प्रत्येक वर्ग के मीटर के लिये निर्धारित मासिक दर से किराया वास्तविक उपयोग की अवधि के लिये मकान में रहने वाले द्वारा देय होगा जो एक मास से कम के लिये नहीं होगा तथा विच्छेदित अवधियों एक पूरा मास होना माना जायगा ।

(२) खर्च किये गये पानी तथा बिजली की कीमत किरायेदार देगा ।

२८ उपभोगता का किराये के लिये उत्तरदायित्व —जिस सरकारी कर्मचारी को जिसे कोई निवास गृह आवंटित किया गया हो वह इन नियमों के अधीन आवंटन की अवधि के लिये किराये का भुगतान करने के लिये जिम्मेदार होगा, जब तक कि वह बिना किराया मकान पाने का हक्दार न हो अथवा नियम ३२ के प्रावधान के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे मुक्त नहीं कर दिया गया हो ।

२९ (१) आवंटन की अवधि के लिये किराया मासिक अग्रिम रूप से वसूल किया जायगा ।

(२) यदि वह राज्य कर्मचारी है तो कोई भी राशि जो किराये की हो अथवा इन नियमों के अधीन अग्रिम देय हो उसकी वसूली उसके मासिक वेतन में से अथवा मकान में रहने वाले को देय किसी अन्य राशि से कटौती करके वसूल कर ली जायगी ।

३० किराया मुक्त स्थान —विशेष परिस्थितियां तथा कारणों से जो अभिलेखित होंगे, सरकार —

(क) सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी सरकारी कर्मचारी को या सरकारी कर्मचारियों के वर्ग का बिना किराये पर निवास-स्थान दे सकेगी । अथवा

(ख) किसी सरकारी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारियों के वर्ग से वसूल की जाने वाली किराये की राशि में विशेष आदेश द्वारा कमी या बर्फी कर सकेगी । अथवा,

(ग) किसी सरकारी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारियों के वर्ग से वसूल की जाने वाली नगर पालिका तथा अन्य करों की राशियों में जो गृह कर या सम्पत्ति कर की तरह के न हो सामान्य या विशेष आदेश द्वारा माफी या कमी कर सकेगी ।

टिप्पणी

उन सरकारी कर्मचारियों की सूची जो बिना किराये पर मकान पाने के पात्र हैं, परिशिष्ट II में दी हुई है ।

३१ (१) जब कि नियम २८ के उप-खंड (क) के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी को बिना किराये पर मकान दिया गया हो, तो किसी विपरीत प्रभाव वाले राज-प्रादेश के प्रभाव में, किराये से मुक्ति पूरी मुक्ति होना मानी जायगी, अर्थात्

सेनिटरा, जल तथा विद्युत जैसी सेवाओं के लिये, जिनकी कीमत भवन के पूजो मूल्य में सम्मिलित है कोई अतिरिक्त किराया या शुल्क नहीं लिया जायगा।

(२) किराया-मुक्त मकान होने की रियायत में मुफ्त जल प्रदाय तथा विद्युत शक्ति तथा नियम १६ में उल्लेखित अन्य सुविधाएँ सम्मिलित नहीं होगी, जिनका किराया उपा व्यय राजकीय कर्मचारी स्वयं को देना होगा। जल तथा विद्युत मोटरों का किराया भी जिनकी कीमत भवन के पूजो-मूल्य में सम्मिलित की हुई नहीं है, राजकीय कर्मचारी द्वारा ही देय होगा।

३२ विस्तृत भरम्मत चालू होने से या किसी अन्य कारण से जब कोई भवन निवास योग्य न रहे, तो उसके उपयोग के लिये देय किराया मूल्य अभियन्ता माफ करने की स्वीकृति प्रदान कर सकेगा, परन्तु इतना यह है कि यदि इसमें निवास करने वाला यह पाए कि मकान निवास-योग्य नहीं रहा है तो वह उक्त भवन का प्रभार रखने वाले अधिशासी अभियन्ता को इसकी रिपोर्ट तुरन्त करेगा जो उसका मोक्ष निरीक्षण करेगा और इस विषय पर अपनी रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता को प्रेषित करेगा अधिशासी अभियन्ता मामले में ऐसे कदम उठाएगा जो वह आवश्यक समझे और अपनी कायदाओं की रिपोर्टें मुख्य अभियन्ता को करेगा जो तत्पश्चात् यह तय करेगा आया किराये में आशिक या पूरी छूट की प्रस्ताव दी जावे।

मामूनी या साधारण वार्षिक भरम्मत से होने वाली असुविधा किराये में माफी देने के लिये अपर्याप्त है जो केवल तभी प्रदान की जानी चाहिये जब कि ऐसी विस्तृत ईमारतों भग्मन हो गयी हो, जिससे सक्षम प्राधिकारी की राय में भवन रिक्त करना औचित्यपूर्ण हो गया हो।

३३ सम्मिलित निवास तथा कार्यालय —जब कि किसी भवन का कुछ हिस्सा निवास स्थान के रूप में तथा कुछ भाग का उपयोग कार्यालय के लिये किया जाता हो तो, जो भाग निवास के लिये काम में लिया जा रहा है उसके पूजो मूल्य का अनुमान नियम ६ तथा १३ के प्रयोजनार्थ पथक आका जाना चाहिये। निवास स्थान के भाग की देखरेख का व्यय पथक आका जाना चाहिये और उसका भ्रमण से हिसाब रखना चाहिये। यह उस क्षेत्र के आधार पर किया जाना चाहिये जिस पर उक्त ईमारत बनी हुई है।

जब मकान में रहने वाले को कार्यालय के लिये भ्रमण स्थान दे दिया गया हो और जब कि उसके निवास गृह का कुछ भ्रमण कार्यालय या व्यवसाय को प्रयोजनार्थ वैकल्पिक हो, तो इस कारण से किराये में कटौती करना अनुचित नहीं है।

३४ ऐसे सरकारी कर्मचारी जो सरकार द्वारा विशेषतया पुलिस गाढ़ के हकदार समझे जावें, के निवास स्थान पर पुलिस रखको के लिये सरकार स्थान देने की व्यवस्था करेगी। इस प्रकार से दिया गया स्थान उक्त निवास गृह के लिये, नियमों के अधीन, प्रमाणिक किराया निश्चित करने हेतु हिसाब में सम्मिलित नहीं किया जायगा। इन सुविधाओं के लिये जो अधिकारीगण हकदार हैं उनका उल्लेख परिशिष्ट "घ" में किया गया है।

३५ परिभाषाएँ —(१) उपरोक्त नियमों के प्रयोजनार्थ, "उपभोग" (Emoluments) से तात्पर्य है और उस में सम्मिलित है—

अनुसूचि 'ख'

राजकीय आवास स्थान के लिये आवेदन-पत्र का प्रपत्र

सेवा में,

राजकीय आवास स्थान के लिये मैं एतद् द्वारा आवेदन करता हूँ

१ नाम _____

२ पद _____

३ वेतन _____

४ भत्ता, यदि कोई हो (सिवाय भूहगाई भत्ते के)

५ तैनाती के स्थान पर पद ग्रहण करने की तारीख ।

६ परिवार में व्यक्तों तथा बालकों की संख्या (आवेदनकर्ता के साथ सम्बन्ध बताते हुए) ।

७ आया तैनाती के स्थान पर उसके कोई भवन सम्पदा है ।

८ आया उसने गृह निर्माण हेतु कोई ऋण/ग्रामिम राशि उठाई है यदि ऐसा है पिछली उठाई गई किश्त की तारीख ।

हस्ताक्षर

स्थान
दिनांक

पद

विभाग

प्रेषित है

हस्ताक्षर

पद (कार्यालयाध्यक्ष)

अनुसूचि 'ग'

अधिकारियों की प्रतीक्षा सूचि जो धरणी के आवासगृह

के लिये हकदार है, अर्थात् जो वेतन समूह ६०० मे हैं/१९५८

क्रमांक	नाम	पद तथा वेतन	थ तैनाती	वेतन तथा विशेष वेतन	आयामी वेतन वृद्धि की तारीख	वर्तमान आवंटन यदि कोई हो	वर्तमान आवंटन की तारीख	तैनाती के स्थान पर पद ग्रहण करने की तारीख	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०

अनुसूचि 'घ'
राजस्थान सरकार

(विभाग/आवटन प्राधिकारी का कार्यालय)
(आवटन प्राधिकारी)

घोरे से

वास्त

संख्या

(कार्यालय/विभाग
जिसके माध्यम से आवेदन
पत्र प्राप्त हुआ)

दिनांक " " ११

विषय — राजकीय आवासगृह उपलब्ध नहीं होने के विषय में मकान निराशा
भरता नियमों के नियम ४ के अधीन प्रमाण-पत्र ।

सदम — प्रापकी सं०

दिनांक

श्री को देने के लिये अभी कोई उपयुक्त मकान उपलब्ध
नहीं है ।
यह पत्र राजकीय आवास गृह हेतु दिये गये श्री के आवेदन-
पत्र दिनांक के सदम में है ।
उनका नाम श्री को आवासगृह पाने के हकदार व्यक्तियों में
अधिकारियों की प्राथमिकता सूचि के क्रमांक पर स्थित है ।
(आवटन प्राधिकारी)

दिनांक

सं०

का उनके आवेदन-पत्र दिनांक

प्रतिलिपि श्री
के सदम में सूचनाय प्रेषित ।

(आवटन प्राधिकारी)

परिशिष्ट 'स'

राज्यनाम ने प्रसन्न होकर प्राप्ता प्रदान की है कि नीचे लिखे क्षेत्रफल तथा निर्माण व्यय उच्चतम सोमा समझे जायें तथा भविष्य में समस्त राजस्थान में सकल विभक्तियों के राजकीय कमचारियों के लिये आवासगृह का निर्माण करने हेतु इनका प्रयोग में किया जावे। ये माप दण्ड मिनाई, मावजनिक निर्माण विभाग विद्युत तथा यांत्रिकी विभाग तथा अन्य समस्त विभागा तथा आयोजना कार्यों के लिये भी लागू होंगे और सामान्य प्रशासन विभाग में सरकार की स्वीकृति के बिना इनमें कोई बढि नहीं की जायगी —

आवास गृह की श्रेणी	क्षेत्रफल समूह	बने हुए मकान का क्षेत्रफल	निर्माण का व्यय	सर्वेंट (मदनी) का क्वाटर प्रादि
ए-श्रेणी	६० ६० से कम	३०० वर्ग फीट	३०००	कुछ नहीं
जा-श्रेणी	६ ६० से १४६	६०० " "	७२००	"
एफ-श्रेणी	२ १५० से २४६	७७५ " "	६,३००	"
ई-श्रेणी	६ २५० से ४६६	११०० " "	१४४००	"
डी-श्रेणी	६ ५०० से ७४६	१७७० " "	२२२००	एक सर्वेंट क्वाटर
सी-श्रेणी	६ ७५० से			एक सर्वेंट क्वाटर
	६ ६६६	२१८४ " "	२७,४८०	तथा एक गैरेज
बी-श्रेणी	६ १००० से			एक सर्वेंट क्वाटर
	६ १,४६६	२६०० " "	३१,२००	तथा एक गैरेज
ऐ-श्रेणी	६ १,५००	३३२० " "	३६,८४०	दो सर्वेंट क्वाटर्स तथा एक गैरेज

उपरोक्त उल्लिखित माप दण्डों तथा निर्माण के व्यय में सर्वेंट क्वाटर्स गैरेज, पहरेदारों के कमरे, ग्रहाते की दीवारें भूदर की सबकुं सम्मिलित नहीं है जिनके लिये पृथक् तकमीने बनाने चाहियें तथा सरकार के अनुमोदन हेतु भेजे जाने पर प्रलग बताने चाहिये।

सामान्य प्रशासन विभाग आज्ञा सं एक ६(६३) जीए/ए/५७/जी ए/ए/५७/जीए ४६७८/एक ५८ (ए) दिनांक १५-४ १९५८ द्वारा जारी किया गया।

परिशिष्ट 'ग'

(निम्नलिखित ३०)

राजकीय कमचारियों का सर्वत्रिन्को सादरत्रिन्क में दिग्या-मुक्त गृह दिये जाने हैं।

११ (क) कृषि विभाग

१ धान मनेजर,

२ फील्ड एसिस्टेंट तथा फूम मिश्री

३ छात्रावास के वार्डन का कृषि इंजिनियरों के अध्यक्ष -

(i) पूरा समय के निम्न वार्डन/अधीनस्थ का—

विना दिग्या वर्गों कि उत्तरा देवन का रिपायत ध्यान में रखते हुए निम्नित किया गया है या किया जाव।

(ii) धार्मिक समर के निर अधीनस्थ/वार्डन को—विना विग्या वर्गों कि उत्तरा देवन का अधीनस्थ का कार्य करने के निम्न काई विनोद देवन तथा उत्तरा देवन को। यदि विनोद देवन की अनुमति हो तो विग्या-मुक्त गृह की अनुमति नहीं दी जायगी।

) पशु-पालन विभाग

१ फाम मनेजर।

२ अध्यापक तथा मनुष्यक अधीनस्थ पशु-प्रजनन फाम।

३ फील्ड एसिस्टेंट तथा फाम मिश्री।

४ पशु चिकित्सालय के कम्पाउंडर,
(प्रत्येक सम्पत्ति में)।

इसका प्रभाव उस दिन से होना समझा जायगा जिस तारीख से इन विभागों का विभाजन हुआ।

सकट हाउस, निममें

बीकानेर हाउस नई दिल्ली
तथा राजस्थान स्टेट होटल
जयपुर सम्मिलित हैं।

सकट हाउस

सकट हाउस के अध्यापक/मनेजर। स्कूट हाउस अधीनस्थ, बीकानेर, कृषि बीकानेर हाउस, नई दिल्ली राजपुर क. टी. मान्दर हाउस।

१ मेसक एक	अधीनस्थ/मनेजर
२ वरग-एक	द्वारा मनेजर
३ ग्याइया-एक	द्वारा मनेजर
४ फार्म-एक	द्वारा मनेजर
५. कम बीन-एक	

सामान्य प्रचालन विभाग (ए) धारा ५ एड/१८३३ " १९४४ एड ६१ १९६१ एड स्थानांतरित किया गया।

आधारित हैं उन पर लागू उपयुक्त महगाई वेतन को वेतन का अंश समझा जायगा। इस नियम के अधीन रियायतें १-४-१९५८ से प्रभावित होगी बशर्त कि सम्बन्धित राजकीय कमचारी उक्त तारीख से चढ़े की शेष राशि का भुगतान कर दे। निधि नियमों (Fund Rules) के अधीन ग्राह्य विशेष अंशदान की राशि गणना करने के लिये, जिस वेतन पर यह अंशदान आधारित है उन पर लागू उपयुक्त महगाई वेतन को दिनांक १-४-१९५८ की या उसके पश्चात् सेवा निवृत्ति होने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में ऐसे वेतन का एक अंश समझा जायगा।”

मजान किराया तथा यात्रा भत्ते

६ महगाई वेतन को यात्रा भत्ते (जिसमें माइलेज तथा दैनिक भत्ते सम्मिलित हैं) के प्रयोजन के लिये वेतन रूप होता समझा जायेंगे।

७ महगाई वेत को राजस्थान सिविल सर्विसेज (डिटरमिनेशन ऑफ़ रेट ऑफ़ रजिडेंशियल एकोमाडेशन रूल्स १९५८) के नियम ३५ में परिभाषित उपलब्धियों (aemoluments) का एक अंश होना समझा जायगा।

८ महगाई वेतन को भी हाऊस रेंट एलाउंस रूल्स जो वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ ३५ (२) आर/५१ दिनांक २०-६-५१ को जारी हुए और जिस रू में वे समय समय पर संशोधित हुए के प्रयोजनाय वेतन रूप में माने जायेंगे।

यह आज्ञा प्रदान की गई है कि उन राजकीय कमचारी के मामले में जिनको कि किराया मुक्त गृह तथा मुफ्त भोजन की अनुमति है तथा जिनको तदनसार डिपरनेंस एलाउंस दु गवर्नमेन्ट सर्वेयर्स आफ़ राजस्थान सर्विस रूल्स के नियम ४२-IV के नियम ३ (V-A) के अनुसार ५० प्रतिशत महगाई भत्ता ग्राह्य है, उनके महगाई भत्ते को उपरोक्त आज्ञा के तात्पर्य में महगाई वेतन समझा जायगा।

बीमे की किश्तें

९ अनिवार्य बीमे की किश्तें गणना करने के प्रयोजन के लिये भी महगाई वेतन को वेतन में शुमार किया जायगा।

कतिपय प्रावधानों के लागू होने की तारीख

१० अनुच्छेद ६ से ९ में निर्दिष्ट प्रावधान इस आज्ञा के जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

परिसीमायें

११ इस आज्ञा के कथनों के अतिरिक्त महगाई वेतन को वेतन के रूप में, किन्ही अन्य प्रयोजना के लिये नहीं माना जायगा। उदाहरणतः वेतन निश्चित करने या वेतन वृद्धि उठाने के लिये महगाई वेतन की गणना नहीं की जायगी न महगाई भत्ता उठाने हेतु ही इसको गणना में लिया जायगा। वेतन के बिलों में या सेवा के अभिलेखों में भी पृथक् तत्व के रूप में नहीं दर्शाया जायगा।

१ वित्त विभाग आषाढ एफ ६ ए (१४) एफ डी ए (रूल्स)/५८ दिनांक ५.९.५९ द्वारा

राजस्थान सेवा नियम के नियम ४२ के अनुसार में सरकार आदेश देती है कि राजस्थान सेवा (परियोजना में रियायत) नियम, १९६२ के प्रावधान निम्नलिखित विभागों के कर्मचारियों पर भी दिनांक १-६ १९६८ से लागू होंगे —

(१) दृष्टि विभाग के कर्मचारी जो कि राजस्थान नहर क्षेत्र में यू०एन० स्पेशल फण्ड गोदाल सर्वे एवं वाटर मनेजमेंट रिसर्च करने के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

(२) उप निवेशन विभाग के कर्मचारी जो राजस्थान नहर क्षेत्र के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

वित्त विभाग के आदेश सं० एक २ (ख) (१२) वित्त वि (व्यय-नियम) दि० १२-३-६६

परिशिष्ट ३१

पृष्ठ ३८५

नियम ३(६)

राजस्थान सेवा (परियोजनाओं में रियायत) नियम, १९६२ के प्रावधान विषय खासा कार्यक्रम परियोजना विभाग, राजस्थान नहर के स्टाफ पर भी दिनांक १-६-६८ से राजस्थान सेवा (परियोजनाओं में रियायत) नियम, १९६२ के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगे।

१ वित्त विभाग के आदेश सं० एक २ (ख) १२ वित्त वि (नियम), ६६ दि० ७-७-६६

परिशिष्ट ३१

पृष्ठ ३८६

वर्तमान नियम ३(३) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाए —

‘(३) परियोजना भत्ता के प्रतिरिक्त, ‘रेगिस्तान भत्ता’ मूल वेतन के १०% के आधार पर, विश्व खाद्यान्न कार्यक्रम राजस्थान नहर विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर तथा राजस्थान नहर परियोजना (रेगिस्तानी क्षेत्र) में किसी पद पर पदस्थापित कर्मचारी पर भी लागू होंगे जिनका कि मुख्यालय हुमायनगढ़ सूरतगढ़ श्री विजयनगर, या झनूपगढ़ नहीं है तथा मुख्य नहर से ३८ मील से दूर है।

यह रेगिस्तान भत्ता इन नियमों के प्रयोजनार्थ ‘परियोजना भत्ता’ समझा जाएगा।

वित्त विभाग के आदेश सं० एक १ (क) (१३) वित्त वि (व्यय-नियम) ६६/दि० १४-३-६७ द्वारा १-१-६७ से प्रभावी किया गया तथा बाद में वित्त विभाग के आदेश सं० एक २ (ख) (१२) वित्त वि (नियम) ६६ दि० ७-७-६६ द्वारा संशोधित)